

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

१० पृ०, चौ० कॉम० तथा कृषि आदि कक्षा के छात्रों के लिए—कृषि, उद्योग,
अधिकोपण, वित्त तथा व्यापार सम्बन्धी—पचास सामयिक
समस्याओं का महत्वपूर्ण विरलेपण

हमारी आर्थिक समस्याएँ

Our Economic Problems

[Essays on Current Affairs]

लेखक

गिरिराज प्रसाद गुप्त, एम० कॉम०
(स्वर्णपदक प्राप्त)

रामप्रसाद एण्ड सन्स

प्रकाशक : : आगरा

प्रथम संस्करण—अगस्त १९५२

मूल्य ५) मात्र

मुद्रक—धर्मचन्द भागवत, अमृत इलेक्ट्रिक प्रेस, धेलनगंज, आगरा

पूज्य गुरुजनों

को

समर्पित

जिनकी शिक्षा और आशीर्वाद ने

मुझे इस योग्य बनाया

दो शब्द

गत कुछ वर्षों से घटना-चक्र ने कुछ ऐसी करवट बदली है कि आर्थिक समस्याओं ने राजनीति का गला घोटकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। आर्थिक समृद्धि के बिना राजनैतिक स्वराज्य भी पीका समझा जाने लगा है। 'आर्थिक समृद्धि ही सच्चा स्वराज्य है'—पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में बहुत कुछ सत्य है जिसे अधिकांश देशवासी अभी समझ नहीं पाते हैं। राजनैतिक स्वाधीनता के पश्चात् धाज की सबसे प्रमुख समस्या आर्थिक है। आर्थिक-क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत हो गया है तथा उसकी समस्याएँ इतनी जटिल और पेचीदा हैं कि राजनैतिक समस्याओं से साधारण जानकारी रखने वाले सापेक्षितक कार्यक्रमों आर्थिक प्रश्नों पर थोड़े स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख पाते। फिर जनसाधारण का तो कहना ही क्या है ! इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक हमारे देश में राजनैतिक चेतन्य की भाँति आर्थिक चेतन्य न उत्पन्न हुआ है और न उसकी चेष्टा ही की गई है। आर्थिक समृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि जनता में एक देशव्यापी भावना और चेतनता का मंचार हो। सरकार के कितने ही प्रयत्न सब तक सफल नहीं हो सकने जब तक कि जनता भी आर्थिक समस्याओं को भली भाँति समझ कर उनके प्रति सचेत न हो और फिर सरकार के साथ सहयोग न दे। धाज से २० वर्ष पूर्व, जब रूस में पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ किया गया था, समस्त देश में उत्साह और आनन्द की एक नई लहर और नई उमंग पैदा हो गई थी। सारा देश 'पंचवर्षीय योजना चार वर्ष में पूरी करो' के नारे से गूँज उठा था। नर-नारी, छोटे-बड़े, बाल-बूढ़—सभी उस योजना को पूर्ण करने में अपना-अपना योग देने लगे थे। अमेरिका में भी प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट ने घोर आर्थिक संकट के दिनों में जब देश से अपील की थी कि "बैंकों में राशि जमा हो" तब समस्त देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई थी और देश ने आर्थिक संकट हँसने-हँसते पार कर लिया था। इसका एकमात्र कारण था जनता का अर्थ-समस्याओं के प्रति सचेत होना और सरकार को योग देने में जागरूक रहना। अस्तु ! देश की आर्थिक समृद्धि सरकारी कानूनों या योजनाओं पर ही निर्भर नहीं करती। वह करती है जनता के उत्साहपूर्ण सहयोग पर। परन्तु जनता का यह सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसे आर्थिक समस्याओं की स्पष्ट जानकारी न हो।

हमारे देश में नित नई आर्थिक समस्याओं को समझने तथा उनके व्यावहारिक उपायों की खोज करने की बहुत आवश्यकता है। अर्थशास्त्र न उपन्यास कहानी की तरह रोचक विषय है और न राजनैतिक स्वराज्य की भाँति आवेशपूर्ण नारों का विषय है। यह तो एक गम्भीर विषय है और इसीलिए इसका महत्व कम नहीं है। प्रत्येक देशवासी को इस गम्भीर विषय में जानकारी रखकर देश की आर्थिक समस्याओं को समझना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। विद्यार्थियों एवं जन-साधारण को देश की आर्थिक समस्याओं से परिचित कराने के लिए इस पुस्तक में पचास महत्वपूर्ण समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। मेरा विश्वास है कि जब तक जनता को समस्याओं में जानकारी नहीं होगी तब तक वह सरकार के साथ उनको सुलभाने में सहयोग कर ही नहीं सकती। इसी उद्देश्य से उन्हें इस पुस्तक के द्वारा हमारी आर्थिक समस्याओं में जानकारी कराने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक में वर्णित सभी समस्याएँ सामयिक हैं, गम्भीर हैं और आवश्यक भी हैं। आशा है विद्यार्थी और जन-साधारण—दोनों वर्ग इसमें लाभ उठावेंगे।

मुझे यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं कि पुस्तक का विषय कोई नवीन नहीं है। केवल समस्याओं को चुनकर जन साधारण की सूचनार्थ उनका विश्लेषण कर दिया गया है। अधिकांश निबन्ध लेखक व उन लेखों में से तैयार किए गए हैं जो समय समय पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। हाँ, समयानुकूल उनमें आवश्यक संशोधन अवसर कर दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को हमारी आर्थिक समस्याओं के प्रति कुछ जानकारी अवश्य होगी और वे उन्हें हल करने में व्यावहारिक सहयोग देने में समर्थ हो सकेंगे।

पुस्तक-लेखन में मुझे वाणिज्य विभाग के अप्पल प्रो० रामशंकर दासिक् से पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। पाण्डुलिपि तैयार करने में मुझे श्री रामनिवास जाजू व श्री नागरमल 'नागराज' से पर्याप्त सहयोग मिला है जिसके लिए वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं।

विषय-क्रम

संख्या	विषय	पृष्ठ
१	भारतीय कृषि की समस्याएँ	१
२	भूमि का कृषीकरण	१०
३	भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन (नदियों को बहुमुखी योजनाएँ)	१६
४	भारत में खेत-मजदूरों की समस्या	२४
५	ग्रामों का पुनर्निर्माण	३२
६	देश की खाद्य-समस्या	३७
७	'अन्नविषयक अन्तर-ज्वलन' जोषणा (समस्या-ग्राम-समाधान)	४७
८	कृषि का यन्त्रीकरण	५१
९	कृषि की वित्त-समस्या	५३
१०	भारत की पशु-समस्या	६६
११	कृषि-आयोजन की आवश्यकता ?	७४
१२	पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान	७३
१३	भारत में औद्योगीकरण की समस्या	८५
१४	औद्योगिक आयोजन की आवश्यकता ?	९१
१५	औद्योगिक-निर्माण का रूप	९७
१६	उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न	१०६
१७	औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार	११२
१८	कुटीर-धर्मों की समस्याएँ	१२०
१९	औद्योगिक धर्मियों की समस्याएँ	१२३
२०	भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास	१३६
२१	उद्योगों की वित्त समस्या	१४०
२२	पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान	१४८
२३	देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन	१५४

२४	हमारी बैंकिंग-व्यवस्था—कुछ दोष	१६०
२५	भारतीय गाँवों में बैंकों की व्यवस्था	१६६
२६	रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण	१७६
२७	बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न	१८१
२८	स्टैंडिंग-क्षेत्र व्यवस्था	१८२
२९	पाण्डे-पावने तथा उनका भुगतान	१९०
३०	मुद्रा-स्फीति	१९८
३१	डॉलर की समस्या	२०७
३२	रपये का अन्वमूल्यन	२१४
३३	अन्वमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ	२२३
३४	रपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न	२२६
३५	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा रोप और भारत	२३८
३६	विश्व बैंक और भारत	२४८
३७	हमारी वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था	२५५
३८	अन्तर्राष्ट्रीय प्रागण में हमारा खया	२५६
३९	हमारा वैदेशिक व्यापार	२६४
४०	राष्ट्रीय आय	२७०
४१	विदेशी पूँजी का प्रश्न	२७६
४२	पूँजी-निर्माण का प्रश्न	२८८
४३	औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन	२९६
४४	जन-वृद्धि की समस्या	३०५
४५	आर्थिक आयोजन	३११
४६	पञ्चवर्षीय योजना—एक रूपरेखा	३२०
४७	कोलम्यो योजना	३३४
४८	मन्दी की ओर	३४०
४९	वाणिज्य शिक्षण—मूल समस्या	३४७
५०	अर्थ-वाणिज्य की व्यावहारिक-शिक्षा	३५४

१—भारतीय कृषि की समस्याएँ

‘भारत गाँवों में बसता है और कृषि भारत की आत्मा है’ महात्मा गाँधी के इन शब्दों से हमारी कृषि का महत्व स्पष्ट होता है। भारत कृषि प्रधान देश है। उसकी ८० प्रतिशत जनता गाँवों में बसती है और ८० से ८५ प्रतिशत मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि ही हमारे समस्त आर्थिक जीवन में रक्त-संचालित करती है। जिस गति में और जिस माथा में कृषि की उन्नति होगी, भारतीय जनता उतनी ही समृद्धिवाली और सुखी होती चली जाएगी। कृषि उन्नति के प्रश्न को औद्योगीकरण की आवश्यकता की दृष्टि से न देखकर केवल ग्रामीणता की दृष्टि से ही देखा जाय तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वास्तव में यह राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न बन जाता है। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि न तो थोड़े से समय में विशाल उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और न तत्काल ही ग्रामीण उद्योग धंधे पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। कृषि ही ऐसा धन्धा है जिसके सुधार में बहुसंख्यक जनता को लाभ पहुँच सकता है। भारतीय जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उसकी वास्तविक आय बढ़ाना आवश्यक है। तभी यह उपभोग्य पदार्थ स्वरीद भरती है और तभी उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। कृषक की आय तब पूरी हो सकती है जब कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो। कृषि के उत्पादन की समस्या हमारे देश के सामने केवल पेट भरने तक ही सीमित नहीं रही है। कृषिजन्य पशुओं का उत्पादन बढ़ने से उद्योगों की समस्या, मजदूरों की समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विपत्तियाँ—सभी एक साथ सुलभ हो सकती हैं। राष्ट्र के आर्थिक जीवन-रग के कृषि और उद्योग दो पहिए हैं। आर्थिक-जीवन किसी एक के बिना अपूर्ण और रंगु रहता है। अनिष्ट सम्बन्धी उद्योगों को हटाकर अन्य छोटे उद्योगों के लिए। कृषि ही चच्चे

माल की पूर्ति करती है। कपड़ा, पटसन, शक्कर, तेल इत्यादि उद्योग अधिकांश में कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं।

देश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का इतना महत्व होते हुए भी, हमारा यह उद्योग निरंतर अवनति की ओर गिरता रहा है। पिछली दो शताब्दियों में कृषि-हानि का इतिहास चान्तव में भारत का आर्थिक इतिहास बन गया है। उद्योग-धन्यो के विकास के अभाव में जनसंख्या-वृद्धि का भार कृषि पर ही बटता चला आ रहा है। ग्रामीण उद्योग धन्यो के हास के कारण उनमें लगे हुए मनुष्यों को गिराव होकर उदर पूर्ति के लिए कृषि कार्य अपनाना पड़ा। आज भी कृषि पर हमारा आर्थिक जीवन अवलम्बित है। वर्तमान् अन्न संकट ने हमारे समस्त आर्थिक चलेवर का विह्वल बना रखा है। वर्तमान् आर्थिक संकट कृषि के प्रति हमारी उदासीनता का परिणाम है। हमारे देश में कृषि की अनेक समस्याएँ हैं जिनके कारण कृषि का समुचित विकास न हो पाया। प्रश्न होता है कि क्या हमारे देश में भूमि की कमी है? परन्तु यह बात नहीं है। हमारे देश में कुल २४ करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि होती है। १७ प्रतिशत भूमि खेती के लिए प्राप्य नहीं है और १६ प्रतिशत पड़ती पड़ी है। इस प्रकार कोई १८ करोड़ एकड़ भूमि पड़ती पड़ी है। इसलिए यह विचार भ्रमात्मक है कि भारत में अभी और खेती का विस्तार सम्भव नहीं है और भारत की चप्पा-चप्पा भूमि जोत ली गई है। गंगा के तटोदर में तथा अन्य कई राज्यों में सरकार ने ट्रेक्टरों द्वारा खेती आरम्भ करके बता दिया है कि अभी पर्याप्त पड़ती जमीन पड़ी है जो किसानों और हलों की प्रतीक्षा कर रही है। सरकार ने कृषि की इस समस्या को हल करने के लिए नई भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है। ट्रेक्टरों की सहायता से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रान्त, मध्य भारत, मंगाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बंजर भूमि को तोड़ कर कृषि की जा रही है। योजना है कि ३० लाख एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर १० लाख टन अन्न प्रति वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से १ करोड़ डालर का ऋण लेकर ट्रेक्टर खरीदे हैं। यह काम केन्द्रीय ट्रेक्टर रुध के अधीन कर दिया गया है।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर अन्न उत्पादन करने के अतिरिक्त कृषि की

पैदा बढ़ाने का प्रश्न भी हमारे सामने है। हमारे देश में कृषि की उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। अधिक और उत्तम खाद, उत्तम और उन्नत बीज तथा सिंचाई का अनुचित प्रयत्न करके कृषि की उपज बढ़ाई जा सकती है। डाक्टर एम्स का मत है कि धान का उत्पादन ३० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है यदि बीज में ५ प्रतिशत और खाद में २० प्रतिशत सुधार किया जाय और रोग नष्ट करने में ५ प्रतिशत यत्न किया जाय। उनका विश्वास है कि बिना कठिनाई के ५० प्रतिशत धान का उत्पादन बढ़ सकता है। इसके लिए बीज में २० प्रतिशत और खाद में ४० प्रतिशत सुधार करने का आवश्यकता होगी। आपका यह भी मत है कि इस उपाय में गेहूँ की ३० से ७५ प्रतिशत और अन्य धान्यों की ६० प्रतिशत पैदावार बढ़ सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि बीज और खाद में सुधार कैसे हो। योरोप, अमेरिका, चीन और जापान में उत्तम खाद का अधिक उपयोग अच्छी उपज का मुख्य कारण है। हमारे देश में प्राकृतिक खाद का बहुत अधिक परिमाण में उपयोग हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि बिछले कुछ वर्षों से कम्पोस्ट खाद बनाया जाने लगा है; परन्तु लगभग ६००० म्युनिसिपैलिटीयों में अभी केवल ६५० म्युनिसिपैलिटीयों ने ही कम्पोस्ट योजना को चालू किया है और ये प्रति वर्ष ५ लाख टन खाद बनाती हैं जो देश की क्षमता के लिए केवल ७ प्रतिशत ही है। भूमि से अन्न लेने के लिए हमें उसे खाद देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने बिहार में सीधरी नामक स्थान पर खाद बनाने की एक विशाल निर्माणी स्थापित की है जहाँ पर वैज्ञानिक रीति से खाद बनाया जाने लगा है। परन्तु सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि देशी खाद बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय। यह काम म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा भली भाँति किया जा सकता है।

खाद के अतिरिक्त कृषि उत्पादन में उत्तम बीज की भी एक बड़ी समस्या है। आज जो बीज हमारे कृषकों को मिलता है वह न तो उत्तम प्रकार का ही होता है और न पुराना ही होता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि उचित परिमाण में देश के विभिन्न भागों में उन्नत एवं अच्छी धान तथा गेहूँ के बीज भंडार खोले जाएँ। हमारे देश में कोई ५८० लाख एकड़ भूमि में धान तथा २६० लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती होती है। इस सबके लिए १६ लाख

एक लाख तथा १० लाख टन गेहूँ के बीज की आवश्यकता है। इतना बीज तैयार करना कोई कठिन बात नहीं है। सरकार ने अच्छे बीजों की एक योजना बनाकर यह कार्य भारतीय कृषि अनुसंधानशाला को सौंप दिया है। स्थान-स्थान पर कृषि विभाग द्वारा शोध का कार्य चल रहा है। परन्तु सरकार का यह प्रयत्न है कि अच्छे बीजों के वितरण की वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त एक ऐसी योजना बनाई जाय जिससे कृषक स्वयं अच्छा बीज अपने आप पैदा कर सकें। इससे कृषि उत्पादन वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। भारतीय कृषि अनुसंधानशाला के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि धान की अनेक ऐसी प्रकार हैं जिनकी बोने से चावल की पैदावार १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। देश में इसकी परीक्षा भी की गई है। १९४५-४६ में भारत संघ में चावल की कुल रोती के क्षेत्र १५ प्रतिशत में अच्छा और उत्तम बीज बोया गया था जिससे करीब १२ लाख टन अधिक चावल उत्पन्न हुआ। उत्तम बीज उत्पन्न करने की समस्या को हल करने के लिए एक देशव्यापी योजना की आवश्यकता है।

हमारी कृषि की एक मूल समस्या सिंचाई के उत्तम साधनों की अभाव रहा है। भारतीय कृषि सदैव मानसून की कृपा पर निर्भर रही है। परन्तु अब कृषि को मानसून की कृपा का पात्र नहीं रखना चाहिए। अब तक ऐसा देखने में आया है कि यदि वर्षा अधिक हुई तो खेत बह जाते हैं और यदि सूखा पड़ गई तो भी प्रकाल पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय कृषि के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध नहीं है। सिंचाई के साधन, जैसे, नल-चूप, नहरें, बिजली के कुएँ आदि बनाना आवश्यक है। सरकार अब इस ओर ध्यान देने लगी है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा बिहार में कुएँ बनाने की योजना चल रही है। दीर्घ-कालीन योजना में सरकार ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ तैयार की हैं। कई योजनाओं का तो काम भी आरम्भ हो चुका है। इन बहुमुखी योजनाओं में नदियों के बहाव का नियन्त्रित करके बाँध बनाये जाएँगे जिससे सिंचाई हो सके, भयंकर बाढ़ रोक दी जा सके, जल-विद्युत बनाई जा सके नदियों को जहाजरानी के योग्य बनाया जा सके और जन विद्युत के द्वारा उद्योगों को

उपलब्ध किया जा सके। सिंचाई-सहकारी-समितियाँ भी बनाई गई हैं जो सिंचाई को विद्युत द्वारा प्रगति देंगी।

भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की भूमि-व्यवस्था रही है। किसान अनेक यातनाएँ और कठिनाइयाँ उठा कर कृषि करता रहा है परन्तु वह अपने खेत का मालिक नहीं रहा। इस प्रकार भूमिपति और कृषक के बीच एक बड़ी गहरी ग्याई रही है। यह कार्यक्षमता और सामाजिक न्याय दोनों दृष्टि से न केवल अनुचित ही है वरन् अन्यायपूर्ण भी है। अन्य देशों में भूमिपति कृषक भी हैं। सन् १९३६ में, युद्ध के प्रथम वर्ष में, फ्रांस में ६० प्रतिशत, स्विट्जरलैण्ड में ८० प्रतिशत, जर्मनी में ८८ प्रतिशत और चेकोस्लोवाकिया में ९० प्रतिशत भूमिपति जमीन जोतनेवाले किसान थे। अब स्वयं भारत में कृषि की इस मूल समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जमींदारी और जागीरदारी मिटाई जा रही है। किसानों को भूमि का अधिकार दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन नियम पास कर लिए हैं। गैर सरकारी तौर पर भी भूमिहीन किसानों को भूपतियों से भूमि लेकर दी जा रही है। आचार्य विनोबा भावे ने "भूदान यज्ञ" आन्दोलन उठाया है जिसके अन्तर्गत वे देश की पैदल यात्रा करके ५ करोड़ एकड़ भूमि भूपतियों से दान लेकर भूमिहीन किसानों को देने का निश्चय कर चुके हैं। इस समस्या के दल होने पर सहकारिता के आधार पर यदि कृषि की जाय तो कृषि की एक बड़ी समस्या दूर हो सकेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सहकारी कृषि पर अन्य देशों से आँकड़े प्राप्त किए हैं और बताया है कि भारत में भी सहकारी कृषि करने के प्रचुर अवसर हैं।

किसान को भूमि का स्वामी मानने से भी हमारी समस्या मुलभली नहीं है, क्योंकि किसानों की अपेक्षा गेतिहर मजदूरों की संख्या यदि अधिक नहीं तो उनके बराबर अवश्य है। घरेलू व्यवसायों के नष्ट हो जाने से उनकी बराबर वृद्धि हो रही है। यह गेतिहर मजदूर संगठित नहीं हैं; इसलिए न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने पर भी इस अवस्था में विशेष लाभ न होगा। इनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ ही रही है। मद्रास में सन् १९०१ में ३१ हजार ३४५

रोहितावर मजदूर के पर सन् १९३१ में प्रति हजार ४२६ हो गए। बंगाल में भूमि-हीन जनता १८ लाख (१९२१) से बढ़कर २७ लाख (१९३१) हो गई। सन् १९३१ की जनगणना की रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १८८२ में भूमिहीन दिन में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या ७० लाख थी, जो १९२१ में बढ़कर २१५ लाख हो गई और सन् १९३१ में ३३० लाख तक पहुँच गई। १९५१ की जनगणना में वह और भी बढ़ी हुई मिले तो कोई आश्चर्य न होगा। १९४३ के बंगाल के अफाल के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अफाल-प्राइडता की जाँच की थी। इस जाँच से पता लगा कि अफाल प्राइडता में ७२ प्रतिशत व्याक्ति रोहितावर मजदूर अथवा छुटे किसान थे। रोहितावर मजदूर साल में ६ मास तक खाली रहता है। उसकी अवस्था दास के समान है। साधारणतः उनका वतन ४ से ८ रु० तक होता है। खेती के साथ इन रोहितावर मजदूरों की समस्या भी जुड़ी हुई है। इसको हल किए बिना भारतीय कृषि का हल नहीं ढूँढा जा सकता।

हमारे देश में खेतों का क्षेत्रफल छोटा है और खेत छोटे और छिटके होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी खेत जोतने में बैलों को टीन-टीक पुमाया भी नहीं जा सकता। अमेरिका में खेतों का औसत क्षेत्रफल १४५ एकड़ है, डेनमार्क में ४० एकड़, स्वीडन में २५ एकड़, जर्मनी में २२ एकड़, इङ्गलैंड में २० एकड़ और भारत में ५ एकड़ है। मद्रास में औसत जोत ४३ एकड़ है लेकिन कहीं कहीं इससे भी कम है। खेतों के छोटे और छिटके होने से खेती में रुकावट होती है, और खेती में स्थायी सुधार भी नहीं हो सकते। फसलों की देर रेल भी टीन नहीं हो सकती और सिचाई का भी उत्तम प्रबन्ध नहीं हो सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए खेतों की चक्कन्दी होनी चाहिए। खेतों की चक्कन्दी सहकारी समितियों और कानूनों द्वारा की जा सकती है। पंजाब में सबसे पहिले सहकारी समितियों द्वारा चक्कन्दी का काम आरम्भ किया गया था। जुलाई सन् १९४३ में वहाँ १८०० समितियों था और लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि में चक्कन्दी की गई थी। सन् १९३६ में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार दो तहाई जमींदारों की इच्छा से चक्कन्दी अनिवार्य

रूप से की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का कानून सन् १९३६ में बना जिसके अनुसार कार्य हो रहा है।

कृषि की एक और बड़ी समस्या मिट्टी के कटाव की है। नदियों के आस-पास बहुत-सी भूमि वर्षा के पानी की तीव्र गति से कट कर बह जाती है और बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में ऐसा बहुत होता रहता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ८० लाख एकड़ भूमि इस प्रकार बेकार पड़ी हुई है। इस मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं पानी जमा होता रहता है जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि इस प्रकार बेकार हो गई है। इस बात को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के मुख्य दो उपाय हैं। जिस जगह कटाव शुरू हो उससे कुछ ऊपर बांध लगा कर पेड़ लगा दिये जायें। पेड़ उगाने में पानी की गति मंद हो जायगी और मिट्टी का कटाव बन्द हो सकेगा और धीरे धीरे भूमि समतल हो जायगी। पेड़ उगाने का यह काम केवल किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। प्रतिवर्ष “वन महोत्सव” मनाया जाता है जिसके अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर वृक्ष लगाने का काम होता है।

कैवल भूमि की समस्याओं का हल करने पर ही कृषि में सुधार नहीं हो सकता। किसानों की निपुणता बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में दो बातों पर ध्यान देना होगा—किसान की निपुणता और भूमि के साथ उसका सम्बन्ध। भारतीय किसान निर्धन और निरक्षर हैं। वह अणु के भार से दबा हुआ है। उसके विषय में यह कथयन प्रसिद्ध है कि वह अणु में ही जन्म लेता है और उसमें ही उसकी मृत्यु होती है। बंगाल प्रान्तीय वैज्ञानिक जॉन कंस्टी की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के कृषकों पर सन् १९२६ में १०० करोड़ रुपये का अणु था और वह १९३५ में बढ़कर २७५ करोड़ रुपये हो गया था। युद्ध-काल में इसमें कुछ कमी हुई है। कुछ लोगों का मत है कि बंगाल का किसान अणुमुक्त हो गया है। किन्तु यह विचार और धारणा गलत है कि युद्ध-वर्षावों में महगाई से वेदल किसान को ही लाभ हुआ है। महगाई में लाभ अवश्य

हुआ है पर छोटे किसानों को उस मात्रा में लाभ नहीं हुआ है जितना सोना जाता है। दूसरी जीवनोपयोगी सारी वस्तुएँ उस मँहगे दामों—नगर बाजार के दामों पर खरीदनी पड़ी हैं। भारतीय किसान आत्म-निर्भर नहीं हैं, इसलिए वह मँहगी का भी पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कृषि-श्रृंग को समझा लगभग ज्यों की त्यों ही बनी रही। भारतीय किसान की निर्धनता के अनेक कारण हैं; जैसे एक मात्र भूमि पर ही जीविका के लिए निर्भर रहना, भूमि या छोटे छोटे अनुत्पादक टुकड़ों में बँट जाना, भूमि से पैदावार का कम होना, भूमि और अन्य स्रोतों में कम आय का होना, इत्यादि इत्यादि। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को उचित व्याज पर ऋण दिए जाएँ। सहकारी समितियों की संख्या बढ़नी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को अल्प-काल के लिए लगभग ६ प्रतिशत व्याज पर ऋण मिल जाया करे। दमनैड में किसानों को ६० वर्ष के लिए Agricultural Mortgage Corporation में ३½ प्रतिशत व्याज दर पर ऋण मिलता है। हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। १९४६ में गाइगिल बनेटी ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रान्त में एक ऐसी संस्था स्थापित होनी चाहिए जो किसानों को छोड़े व्याज पर ऋण दिया करे।

किसान अपनी वस्तुओं के उचित दाम भी प्राप्त नहीं कर पाते। वे ऐसे समय में अपनी फसल बेचते हैं जबकि कीमतें बहुत गिरी हुई होती हैं। उपभोक्ता जब एक रुपये का माल खरीदता है तो किसान को ८१ आने मिलते हैं। बाकी बीच के दलाल खा लते हैं। किसान अपने श्रम को मण्डियों में नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्हें वहाँ के दिन प्रति दिन के भाव मालूम नहीं रहते। यातायात के साधन भी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उचित सुधार होने चाहिए। माप और तौल निश्चित हो जानी चाहिए। यातायात के साधनों में उन्नति होनी चाहिए। पक्की खेत्तियों का प्रबन्ध होना चाहिए। सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए जिनके द्वारा किसानों को अपना माल बेचने में सहायता मिले।

कृषि की दशा सुधारने में पशुधन की उन्नति भी आवश्यक है। हमारे देश में पशु बहुत निर्बल हैं और कृषि में काम आने वाले औजार भी प्रायः पुराने हैं। बैलों के निर्बल होने से खेतों की जुलाई गहरी नहीं हो पाती।

पशुओं की नस्ल में सुधार होना चाहिए। चारे की उपज बढ़ानी चाहिए। पशु-श्रीपधालय खुलने चाहिए और गैनी के यन्त्र भी नये ढङ्ग के होने चाहिए। हाल ही में सरकार ने गैनी के लिए नये यन्त्रों का उपयोग आरम्भ किया है। सरकार के कृषि विभाग वैज्ञानिक हल किसानों को उधार देने लगे हैं।

कृषि की स्थिति सुधारने में एक अङ्कजन यह भी है कि हमारे किसान निरक्षर और अज्ञान हैं और उनका दृष्टिकोण संकुचित रहता है। निरक्षर होने के कारण वे अपना और कृषि का भला बुरा नहीं सोच पाते। कृषि की उन्नति के लिए कृषकों की मानसिक उन्नति भी आवश्यक है। उनकी शिक्षा का भला पूरा प्रबन्ध हो, शिक्षालय खोले जाएँ, श्रीपधालय बनाए जाएँ और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार योजनाएँ बनाई जाएँ। कृषकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कृषि समस्याओं को दूर करने में तो परिश्रम और लगन ही सफलता ला सकती है। कृषि उद्योग तो एक ऐसा व्यक्तिगत विकेन्द्रित धन्धा है जिसको उन्नत बनाने के लिए भूमि, पशु और कृषक, तीनों में सुधार करने होंगे। अनेक वर्षों से हमारे देश में जो अन्न संकट चल रहा है उसका मूल कारण कृषि सम्बन्धी समस्याओं के प्रति हमारी उदासीनता है। अब हम इन समस्याओं का महत्व समझने लगे हैं और यदि सरकार और जनता ने मिलकर काम किया तो देश की कृषि उन्नत होगी। योजना कमिशन ने भारत की कृषि की समस्याओं को न भुलाकर अपनी पाँच वर्षीय योजना में कृषि उन्नति के कार्यों को पर्याप्त स्थान दिया है। आशा है योजना कार्यान्वित होने के पश्चात् पाँच वर्षों में कृषि की ये समस्याएँ सुलभ होंगी।

२—भूमि का कृषीकरण

जैसे जैसे कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस बात की आवश्यकता होने लगी है कि कृषि के लिए भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाय। भारत जैसे विशाल देश में अब तक जितनी भूमि पर कृषि होती चली आ रही है उतनी भूमि ३५ करोड़ भारतीयों के लिए संपादन रूप से पर्याप्त नहीं है। देश के विभाजन के फलस्वरूप हमारी टूटप भूमि का उपजाऊ भाग पाकिस्तान को चला गया है। इससे भारतीय जनता की आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए भूमि का कृषीकरण और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत में लगभग ६ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर कृषि की जा सकती है परन्तु जो कृषि के काम नहीं आ रही। इस भूमि पर या तो पहाड़ कृषि की गई होगी या विलुप्त नहीं। कहने का अर्थ यह है कि इस विशाल क्षेत्र को यदि समतल बनाकर कृषि के काम में लाया जाय तो अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। खाद्यान्न नीति समिति ने सिफारिश की थी कि देश में कृषि योग्य बंजर भूमि का कृषीकरण करने से ३० लाख टन अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार कृषि योग्य बंजर भूमि अधिक क्षेत्र में फैली हुई है जहाँ पर कोंस, हारयाला या अन्य अनावश्यक प्राकृतिक घास उगती रहती हैं। भारत भर में ऐसी भूमि, जिस पर कोंस उगती है और जो इसलिए कृषि के काम में नहीं आती, १ करोड़ एकड़ है। यह भूमि विशेषतः मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में है। सरकार का अनुमान है कि यदि इसी भूमि का कृषीकरण किया जाय तो अन्न संकट का टालने में काफी सहायता मिल सकती है। केन्द्रीय सरकार के आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग ६ लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिस पर यन्त्रों द्वारा कृषि की जा सकती है। आज से लगभग २२ साल पहले भारतीय कृषि के शाही कमिशन ने भी सिफारिश की थी कि 'विशेषकर मध्य प्रान्त में अन्य एव शक्ति की सहायता से कृषि करने की विशेष आवश्यकता प्रतीत होती

है। इस प्रान्त में विशाल भूमि क्षेत्र कसि आदि घास के उग जाने से बजर पड़े हैं, परन्तु यह सब बजर भूमि यन्त्रों की सहायता से कृषकों को कृषि कार्य के लिए मिल सकेगी, ऐसी आशा है।”

शाही कमीशन की इस सिफारिश का महत्व अब पूर्ण रूपेण समझा जाने लगा है। मध्य प्रदेश ही नहीं भिन्न-भिन्न राज्यों में इस प्रकार की भूमि का कृषि-करण करने की योजनाएँ बन चुकी हैं, कार्य किया जा रहा है और कुछ भूमि का कृषीकरण किया भी गया है। भूमि को समतल तथा साफ करने, कृषि योग्य बनाने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है, परन्तु यह समझने की बात है कि इस विषय में भिन्न-भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न समस्याएँ हैं। मध्य प्रदेश के सागर और होशंगाबाद जिलों में बजर भूमि को तोड़ कर कृषि योग्य बनाने की समस्या गंगा खादर की कृषीकरण समस्या से भिन्न है। गंगा खादर में न जंगल थे, न भाड़ियाँ थीं और न कसि जैसी अन्य कोई जंगली घास ही थी। यहाँ गंगा नदी द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी थी। समस्या केवल यह थी कि मलोरिया आदि रोगों को नियन्त्रित करके भूमि पर कृषि की जाय। मिनाई की भी यहाँ कोई समस्या नहीं थी, परन्तु मध्य प्रदेश में कृषीकरण की समस्या इसमें मिलकूल भिन्न है। यहाँ की बजर भूमि सख्त है और उस पर विभिन्न प्रकार की जंगली घास उगती आई है। कहीं-कहीं भूमि ऊँची-नीची भी है। अतः यहाँ भूमि को तोड़ने का प्रश्न सबसे मुख्य रहा है; परन्तु सरकार ने १९४७-८ में ही बजर भूमि को तोड़ कर कृषि योग्य बनाने का काम आरम्भ कर दिया था और यह काम आज भी चल रहा है।

सबसे पहला प्रयत्न उत्तर प्रदेश में किया गया जहाँ २०० ट्रैक्टरों की सहायता से लगभग ४५ हजार एकड़ भूमि का कृषीकरण किया गया है। सम्पूर्ण कृषि योग्य बजर भूमि के लगभग दसवें भाग को अर्थात् ६५ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर निकट भविष्य में ही कृषि कराने की अल्प-कालीन योजना भारत सरकार के सामने है। लगभग ४० लाख एकड़ भूमि मध्य प्रदेश, बम्बई, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा ओडिसा में कृषि योग्य बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त २२ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर कोई हानिकारक घास तो नहीं उगती परन्तु फिर भी कृषि के काम नहीं आती। इस

भूमि का भी कृषीकरण करने की योजना सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। इस प्रकार भारत सरकार की कृषीकरण योजना ने अन्तर्गत ६२ लाख एकड़ भूमि का कृषीकरण निम्न मरिच्य में ही किया जा रहा है। इस भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य केन्द्रीय ट्रेक्टर सघ के सुपुर्द कर दिया है। इस विभाग ने सम्पूर्ण देश में बजर भूमि की जाँच-पड़ताल का है और पता लगाया है कि सभी राज्या और राज्य सघा में भूमि का इस प्रकार कृषीकरण हो सकता है।

राज्य या राज्य सघ	लाग एकड़
मध्य भारत	१४
उत्तर प्रदेश	१०
मध्य प्रदेश	६
बम्बई	५
उड़ीसा	५
पूर्वी पंजाब	५
विन्ध्य प्रदेश	५
अन्य	४

मध्य प्रदेश में यह कार्य बहुत शीघ्रता से हो रहा है। बम्बई में भी सरकारने पहले केवल चार ट्रेक्टरों की सहायता से कृषि के यन्त्रीकरण का विभाग खोला था, आज इस राज्य के पास १०० से भी अधिक ट्रेक्टर हैं जो १५ जिलों में काम कर रहे हैं और इन्होंने १ लाख एकड़ बजर भूमि को जुताई की है। ट्रेक्टरों के चलाने के लिए कुशल व्यक्तियों के न मिलने के कारण कृषीकरण का कार्य उतना अधिक नहीं बढ़ सका है जितनी कि आशय्यता थी। सरकार को चाहिए कि यातायात के साधनों में सुधार करे तथा कुशल व्यक्तियों को इन ट्रेक्टरों के चलाने की शिक्षा का भी प्रबन्ध करे।

गत महायुद्ध से पूर्ण भारत के कृषि उद्योग में ट्रेक्टरों का इतना अधिक प्रयोग नहीं था जितना अब होने लगा है। अनुमान है कि युद्ध से पूर्ण भारतीय कृषि में केवल २४८ ट्रेक्टर थे जब कि इंग्लैंड जैसे छोटे देश में १५,००० ट्रेक्टरों से काम होता था। रूस में, जहाँ कृषि के यन्त्रीकरण का आदर्श उत्थान

हुआ तथा जिसके कारण उत्पादन में भारी क्रांति हुई, १६२८ में कोठे ६ हजार सात सौ ट्रेक्टर यंत्रों में काम करने थे, परन्तु यही संख्या १६३७ में बढ़कर ८४,५०० हो गई। इससे पता चलता है कि पाश्चात्य देशों में कृषि के यन्त्रीकरण पर कितना जोर दिया गया है और यहाँ ट्रेक्टरों में वैसी काया पलट कर दी है। ट्रेक्टरों के प्रयोग ने समय और शक्ति की बचत होती है और जिस एक हजार एकड़ भूमि पर जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उसी भूमि पर ट्रेक्टरों का प्रयोग करने से ५० या उससे भी कम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

भूमि के कृषीकरण की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत का निर्धन किसान बंजर भूमि को तोड़ने का व्यय कहाँ से उठावे, उसे ट्रेक्टर कहाँ से मिले ? इससे लिए दो मार्ग हो सकते हैं।

१. सरकार स्वयं सरकारी केन्द्र स्थापित करके अपने खर्च पर बंजर भूमि को तोड़कर खेती करे, परन्तु सरकार अभी इस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकती। इस काम में सरकार कुशल कृषक की भाँति कार्य नहीं कर सकेगी। तब तो यह टीका होगा कि सरकार अपने व्यय पर बंजर भूमि को तोड़ कर कृषकों को दे दे जिस पर वे कृषि करते रहें। सरकार ऐसा ही कर भी रही है। मध्य भारत, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सरकार ने स्वयं बंजर भूमि को तोड़कर उस पर शरणार्थियों को बसा दिया है। इसमें शरणार्थियों की समस्या भी हल होती जा रही है और भूमि का कृषीकरण भी होने लगा है।

२. दूसरा उपाय यह है कि कृषकों की सहकारी समितियाँ हों जो बंजर भूमि को तोड़कर कृषि के कार्य को प्रोत्साहन दें। किसी एक व्यक्ति विशेष को नई भूमि तोड़कर कृषि करने का भार सहन करना सम्भव नहीं होगा। अतः कृषकों की सहकारी समितियाँ बनें जो सम्मिलित रूप से सरकारी कृषि विभागों की देख-रेख में काम करें और कृषि विभाग उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। सरकारी समितियाँ बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे छोटे और छिटके छेड़ सम्मिलित रूप से मिलकर इतने बड़े बन सकें कि उन पर यन्त्रों का प्रयोग अच्छी तरह से किया जा सके। प्रत्येक समिति को कुछ ट्रेक्टर और कुछ यन्त्र अपने निजी व्यय से खर्च लेने चाहिए और उनको बनाने के लिए

कुछ कुशल व्यक्ति भी रंग लें। समिति अपने ट्रैक्टरों को सदस्यों के लिए किराए पर भी देती रहें।

इससे अतिरिक्त ट्रैक्टरों का प्रयोग सम्बिदा प्रणाली पर भी बढ़ाया जा सकता है। कोई धनी कुशल कृषक कुछ ट्रैक्टर ले ले और सबिदा का शर्तों के अनुसार कुछ धन राश के बदले अन्य कृषकों को किराए पर दे दिया करे। इस प्रकार शनैः शनैः जब ट्रैक्टरों का महत्व बढ़ता प्रतीत होगा और उनसे कुछ लाभ होता दिखाई देगा तो कृषक वर्ग स्वयं उनका प्रयोग आरम्भ करने लगेगा। सरकार इन टेक्केदारों को ट्रैक्टर खरीदने में सहायता कर सकती है तथा तैल शक्ति का भी प्रबन्ध सरकार को करना होगा। सरकारी कृषि विभाग भी कृषकों को ट्रैक्टर किराए पर देकर कृषकों की सहायता कर सकता है। सरकारी कृषि विभाग अब ऐसा करने लगे हैं।

कृषि यन्त्रों का प्रयोग सफल बनाने के लिए सरकार को कुछ और विशेष कार्य भी करने होंगे। जिन स्थानों पर बजर भूमि के तोड़ने का काम चल रहा हो वहाँ ट्रैक्टर केन्द्र स्थापित कर देने चाहिए जहाँ से कृषक तथा समितियाँ ट्रैक्टर प्राप्त कर सकें और अपने ट्रैक्टरों की टूट फूट की मरम्मत भी करा सकें। इन सरकारी केन्द्रों में कुशल कारीगर भी होने चाहिए जो समय पर कृषकों को यन्त्रों का प्रयोग समझा सकें और उनकी सहायता कर सकें। सरकार को यह भी चाहिए कि देश में ही ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि यन्त्र बनाने का प्रबन्ध करे। सरकार विदेशों से यह यन्त्र मंगाकर अधिक मलानहीं कर सकती। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से श्रृणु लेकर अमेरिका से ट्रैक्टर मंगाये हैं परन्तु आवश्यकता यह है कि देश में ही इनके बनाने का प्रबन्ध हो। बम्बई राज्य में ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना खोला गया है परन्तु अभी ऐसे कारखानों की और आवश्यकता है।

भूमि के कृषीकरण में यन्त्रों का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारतीय कृषकों के मनोविशेष में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषक पुराने विचारों का व्यक्ति है जिसे पुराने रीति रिवाजों का तथा कृषि कार्य-शैली में परिवर्तन

करना सहज ही में भला प्रतीत नहीं होता । इसके लिए शिदा की आवश्यकता है । स्कूलों और कॉलेजों में कृषि के यन्त्रीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए और यदि एक बार भारतीय कृषक भूमि का कृषीकरण करने और कृषि का यन्त्रीकरण करने को तैयार हो जाएं तो उसे सब आवश्यक सुविधाएँ मिलनी चाहिए । भूमि के कृषिकरण में निम्न बातों की आवश्यकता है :—एक, पर्याप्त संख्या में उचित ट्रैक्टरों की प्राप्ति; दूसरा, उन्हें चलाने के लिए कुशल मस्त्रियों तथा तेल-शक्ति का प्रबन्ध; तीसरा, बंजर भूमि को तोड़कर समतल करना; चौथा, समतल बनानेके पश्चात् मरकरी मिट्टान्तों के अनुसार कृषि करना । यदि इस प्रकार देश की बंजर और निटली भूमि को तोड़कर कृषि की जाती रही तो फिर देश को अन्न के लिए विदेशियों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ।

३—भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन (नदियों की बहुमुखी योजनाएँ)

भारत के समस्त प्राकृतिक साधना में नदियों का एक विशेष स्थान है जिनके द्वारा राष्ट्र के आर्थिक क्लेसर को सुदृढ और संतुलित बनाने के लिए 'जल प्रदाय' (Water Supply) तथा 'जल-शक्ति' (Hydro-electricity) दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। जल प्रदाय से कृषि की उन्नति करके अन्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा जल विद्युत से औद्योगिक कारखानों का विकास करने औद्योगिक संगठन बलिष्ठ बनाया जा सकता है। हमारे देश में इन दोनों ही वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहा है। परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश में नदियों का अभाव अथवा नदियों में पर्याप्त जल का अभाव हो। देश में नदियों की संख्या किसी भी अन्य देश से कम नहीं और अनेक नदियाँ तो ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है। देश में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य में एक न एक नदी बहती ही है। अब तक इन नदियों का कोई ६ प्रतिशत जल सिंचाई के लिए उपयोग होता था और शेष ९४ प्रतिशत जल बहकर समुद्र में चला जाता था। इस प्रकार देश की अधिकांश जल सम्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं के काम में आकर व्यर्थ ही नष्ट होती थी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की विदेशी सरकार ने इस जन सम्पत्ति का विदोहन करने के विषय में कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने हमारी नदियों का मूल्य ही नहीं समझा। अंगरेजों के आने से पूर्व नदियों का उपयोग व्यापारिक जल-मार्गों के रूप में होता रहा था जिनके द्वारा नावों से माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। अंगरेजी राज्य काल में नदियाँ में से नहरें निकाल निकाल कर सिंचाई का कुछ काम होता रहा, परन्तु इनका पूरा-पूरा उपयोग करने के विषय में सततता प्राप्ति से पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। सरकार की इस उदासीनता का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि

देश की जल सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग न हो सका और प्रति वर्ष देशवासियों का प्रकृति-कोप का शिकार बनना पड़ा। नदियाँ में भारी-मारी बाढ़ आती रहीं जिनसे सम्पत्ति और जीव दोनों की असीम हानि होती रही, प्रकृति की निधि—नदियों का जल—नष्ट होता रहा और देश में पर्याप्त प्राकृतिक सम्पत्ति के होने हुए भी राष्ट्र समृद्धिशाली न हो सका। सन् १९०१-२ में इस सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए “भारतीय सिचाई कमिशन” को नियुक्ति हुई जिसकी सिफारिशों के अनुसार देश में नहरें बनाने की नई-नई योजनाएँ बनाई गईं और नहरें बनाने का कार्य अधिक तेजी के साथ आरम्भ कर दिया गया। परन्तु अब नदोन्नति की योजनाओं का रूप बदल रहा है। सिचाई हो नहीं, जल सम्पत्ति के विदोहन के लिए बहुमुखी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। अब तक नदोन्नति की योजनाएँ केवल सिचाई तक ही सीमित थीं। कहीं-कहीं पर नदियों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाती थी; परन्तु साधारणतः जल विद्युत तैयार करने के लिए कोई विशेष योजनाएँ नहीं बनाई गईं। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि हमारे देश में विद्युत का उपयोग मंसार के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। देश की आर्थिक समृद्धि तथा देश निवासियों के रहन-सहन के स्तर का ज्ञान प्रायः इस बात से हुआ करता है कि उस देश में यहाँ के निवासी अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यों में बिजली का कितना प्रयोग करते हैं। इस मापदण्ड से हमारा देश पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य देशों की समानता में प्रति वर्ष विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग इस प्रकार है :—

देश	बिजली का उपभोग
कैनेडा	३५८० किलोवाट
नार्वे	३५७६ ”
अमेरिका	१७७५ ”
स्वीडन	१७४३ ”
स्विट्जरलैण्ड	१७१७ ”
इंग्लैण्ड	८५५ ”
भारत	१२ ”

इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में विद्युत का उपभोग कितना कम है। हमारे देश में वर्तमान विद्युत शक्ति लगभग २० लाख किलोवाट का बराबर आकी गई है जिसमें से अभी तक कोई ५ लाख किलोवाट बिजली ही उपभोग की जाती है।

राष्ट्रीय सरकार ने देश की नदियों का विदोहन करने के लिए बहुमुखी योजनाएँ बनाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। बहुमुखी योजनाएँ तभी सही हैं कि नदियों का इस प्रकार विदोहन हो जिससे उनसे एक नहीं अनेक लाभ मिलते रहें—भयंकर बाढ़ रोक दी जा सके जो प्रति वर्ष देश की सम्पत्ति को नष्टप्राप्त कर देती हैं, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें जिससे अन्न तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पन्न किया जा सके, जल विद्युत बनाई जाय जिससे उद्योगों को उत्पन्न किया जा सके तथा प्रायःगमन के लिए नदियों को जहाजरानों के योग्य बनाया जाय। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों के प्रबल वेग को नियन्त्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि नदीनाल के प्रोचाम में केवल सिंचाई तथा जल विद्युत का उत्पादन ही नहीं होना चाहिए बल्कि जल सम्पत्ति का पूर्ण रूप से विदोहन होना चाहिए। योजना बहुमुखी होनी चाहिए। सिंचाई का प्रबन्ध भी किया जाय, नदियों को आरागमन के योग्य भी बनाया जाय, प्रति वर्ष प्राप्ति वाली भयंकर बाढ़ों को रोक कर उनका सदुपयोग किया जाय, नदियाँ च प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाय तथा नदियों को सर्वाङ्ग रूप से राष्ट्र के हित के योग्य बनाया जाय। योजना वर्गीकरण का भी मत है कि नदियों का ऐसा विदोहन एक राजनैतिक बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी अच्छी बात है।

अमेरिका ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ सफल बनाने के लिए ऐसा कार्य किया है जिससे आज सारा रुस्स उसकी निदृष्टता पर आश्चर्य करने लगा है। अबतक अमेरिका की सरकार ने नदी योजनाओं को पूरा करने में कोई ४०१८ मिलियन डालर खर्च किए हैं और अनेक ऐसी योजनाओं पर अभी काम हो रहा है जिनपर ४५६३ मिलियन डालर और खर्च होंगे। अमेरिकी सरकार की

योजना है कि निम्न भविष्य में ऐसी अनेक योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायगा और इन पर १८,६८१ मिलियन डालर खर्च होंगे। अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध बहुमुखी योजना 'टेनेसी घाटी योजना' है जिसके अन्तर्गत टेनेसी नदी का जो पानी पहले इकट्ठा होकर खेती, घर-द्वार, स्कूलों और पुलों को नष्ट करना इत्यादि सर्वनाश का नंगा नाच किया करता था, उसी की आज २० वर्ष बनाकर धर लिया गया है और २० लाखों में भर दिया गया है। इस योजना में कुल ८० करोड़ डालर की पूँजी लगाई गई है और यह योजना १८ वर्षों में तैयार हुई है। इस योजना के अन्तर्गत आज २५ लाख एक्रो-फुट बिजली तैयार होना है जिसमें अब तक कोई २ करोड़ ४० लाख डालर की आय हो चुकी है। अन्य तो यह है कि टेनेसी घाटी योजना ने लाखों व्यक्तियों के जीवन में विविध नानि-मी पैदा कर दी है और देश को मजबूत बना दिया है।

भारत सरकार ने भी अब देश की जल सम्पत्ति का विदोहन करने का हठ निश्चय कर लिया है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में कोई १३५ योजनाओं पर काम हो रहा है। इनके अतिरिक्त १२२ योजनाएँ ऐसी हैं जिन पर या तो जल-पड़ताल हो रही है और या तो पूँजी के अभाव के कारण अटूट पड़ी हैं। अनुमान है कि इन २५७ योजनाओं पर सरकार कोई १६०० करोड़ रुपये व्यय करेगा। उपर्युक्त १३५ योजनाओं में ११ बहुमुखी योजनाएँ हैं, ६० योजनाएँ ऐसी हैं जिनके अन्तर्गत केवल सिंचाई का कार्य पूरा होगा और ६४ योजनाएँ जल विद्युत निर्माण करने की योजनाएँ हैं। १३५ योजनाओं में १२ योजनाएँ एम्पा हैं जिनमें में प्रत्येक पर १० करोड़ रुपये में अधिक राशि व्यय होने की आशा है। १६४६-५० में नदियों की योजनाओं पर सरकार ने कोई ३६,४६,००,००० रुपये व्यय किये थे। अब १६५०-५१ में कोई ७८,५६,००,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है। १६५०-५१ में किण्व जाने वाले कुल व्यय का ३७ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी और शेष राशि १६ राज्य सरकारें देंगी। अनुमान है कि इसी वर्ष से इन योजनाओं में मिलने वाला लाभ मिलना आरम्भ हो जायगा। परन्तु पूरा-पूरा लाभ तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि ये योजनाएँ पूरी न हो जाएँ। उपरिलिखित १३५ योजनाओं में प्रति वर्ष देश को जो लाभ

होगा वह इस प्रकार है :—

वर्ष	सींचित भूमि में बढ़ोत्तरी (दस लाख एकड़)	खाद्यान्न में बढ़ोत्तरी (दस लाख टन)	जल विद्युत में बढ़ोत्तरी (किलोवाट)
१९५१—५२	०.६	०.२	—
१९५२—५३	१.१	०.४	३५१०००
१९५३—५४	२.०	०.७	५५४०००
१९५४—५५	४.३	१.४	५९६०००
१९५५—५६	५.५	१.८	६३६०००
१९५६—५७	६.७	२.२	७०८०००
१९५७—५८	७.५	२.५	७९१०००
१९५८—५९	८.५	२.८	८१७०००
१९५९—६०	९.२	३.१	९१००००
अन्त में	१२.९	४.३	१९९६०००

इस प्रकार इन योजनाओं के द्वारा १९५१-५२ में २ लाख टन अधिक अन्न पैदा होगा और १९५४-५५ तक १४ लाख टन तथा १९५९-६० तक ३० लाख टन अन्न अधिक पैदा हो सकेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं के द्वारा देश में ४३ लाख टन अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा। इसी प्रकार अनुमान है कि कुल २५७ योजनाओं के पूर्ण होने पर देश में ४२ मिलियन एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार देश का वर्तमान खाय सकट ही नहीं दूर होगा वरन् देशवासियों के जीवनस्तर में भी उन्नति होगी। इन योजनाओं पर जो राशि व्यय होगी वह हमारी राष्ट्रीय पूँजी का एक ऐसा विनियोग (Investment) होगा जिससे आगे आने वाली संतान का दार्षिकाल तक लाभ मिलता रहेगा। अगस्त १९४७ से १९५२ के अन्त तक अन्न आयात काने से ५४३ करोड़ रुपये का व्यय अनुमान किया गया है। यह हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का एक बहुत बड़ा भाग है जो हमारी आर्थिक विकास की किसी अन्य योजना पर व्यय करने से अधिक लाभदायक हो सकता था। परन्तु अन्न

आयात करने में ही यह राशि समाप्त हो गई। अब अनुमान है कि नदी घाटी विकास की १३५ योजनाओं पर लगभग ५६० करोड़ रुपये व्यय होंगे। यह व्यय एक प्रकार का दोषकालीन विनियोग होगा जिसका फल भविष्य में देश को मिलता रहेगा। यदि अब तक अब आयात पर व्यय की गई राशि इन योजनाओं में लगाई जाती तो देश का बहुत कुछ हित हो सकता था।

नदीप्रति की भिन्न-भिन्न योजनाएँ अब केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा राज्य संघ सरकारों के नियन्त्रण में चल रही हैं। कुछ बहुमुखी विशाल योजनाएँ, जिन पर हमारे देश की आशाएँ केन्द्रित हैं, इस प्रकार हैं :—

दामोदर घाटी योजना—दामोदर घाटी योजना अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। योजना का प्रधान उद्देश्य पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी की भयंकर बाढ़ों से दामोदर घाटी प्रदेश को रक्षा करना है। बाढ़ नियन्त्रण के अतिरिक्त इससे भूमि सिंचन का काम भी लिया जायेगा। इस योजना पर ५५ करोड़ रुपये खर्च होंगे या अनुमान है। इसमें से २८ करोड़ बिजली के उत्पादन के लिये, १३ करोड़ सिंचाई के लिए और १४ करोड़ बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च होंगे। इस योजना से बर्दवान, पुरी वटावड़ा जिलों में काई ७ लाख ६० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इससे दो लाख किलोवाट तक बिजली पैदा की जा सकेगी। योजना २० वर्षों में समाप्त होने का अनुमान है। योजना के अन्तर्गत दामोदर नदी पर आठ बांध बनाये जाएंगे जिन पर जल विद्युत बनेगी। इसके दो महायुक्त केन्द्र ऐसे होंगे जिनमें २ लाख ४० हजार किलोवाट बिजली बनाने की शक्ति होगी। इसके अतिरिक्त एक भर्मल शक्ति केन्द्र भी होगा। इस केन्द्र को पूरा करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से १८५ मिलियन डॉलर का एक ऋण लिया है। आशा है यह केन्द्र १९५२ के अन्त तक कार्य करने लगेगा। इस योजना को पूरा करने के लिये १९४८ में एक कानून बनाकर दामोदर घाटी कार्पोरेशन बना दिया गया है जिसके प्रबंध में यह काम हो रहा है। योजना पूरा होने पर दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ को रोक जायगा और सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकेंगी; जल विद्युत भी बनेगी और आने-जाने की सुविधाएँ भी मिल सकेंगी।

महानदी घाटी योजना—उड़ीसा में महानदी पर तीन बाँध बनाये जाएंगे। इनके तैयार होने पर लगभग ११ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और ३ लाख ५० हजार किलोवाट बिजली बनने लगी। तब इस नदी में नौसेना भी चलाई जा सकेगी। इस योजना में इतनी श्रमिता आशाएँ हैं कि लोग उड़ीसा को अभी से भारत का “यूक्रेन” कहने लगें हैं। अनुमान है कि इस योजना पर लगभग ४६ करोड़ रुपये व्यय होंगे। योजना समाप्त होने पर ३ लाख ४० हजार टन अन्न तथा ३४ हजार टन अन्य व्यापारिक वस्त्रों का माल पैदा किया जा सकेगा।

भारता नागल योजना—पूर्वा पञ्जाब की दो सम्मिलित योजनाएँ नागल बाँध योजना तथा भारता योजनाएँ हैं। नागल विद्युत योजना के अनुसार नागल स्थान पर सतलज नदी के आर पार एक बाँध बनाया जायगा और एक नहर निकालने की योजना भी है। इस नहर के किनारे चार बिजलीघर बनाये जायेंगे। अनुमान है कि इन योजनाओं से लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी जिसमें ११ लाख ३० हजार टन अन्न और ८ लाख रुई की गाँठें अधिक उत्पन्न की जा सकेंगी। यह भी अनुमान है कि इस योजना में ४ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी जिससे पंजाब, राजस्थान, देहली, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पञ्जाब रियासती रुध को लाभ होगा।

इन विशाल बहुमुखी योजनाओं के अतिरिक्त देश में ऐसी अनेक योजनाएँ हैं जो प्रान्तीय सरकारों के तत्वाधान में कार्यान्वित हो रही हैं। इन योजनाओं में प्रधान योजनाएँ इस प्रकार हैं—बिहार में कोसी बाँध की योजना, मध्य प्रदेश तथा बम्बई में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती तथा बाण गंगा की योजनाएँ, उत्तर प्रदेश में चम्बल तथा सोन घाटी की योजना, रिहाण्ड नायर बाँध तथा गंगा बाँध की योजनाएँ, मद्रास में रामपद सागर तुङ्गभद्रा की योजनाएँ, आदि, आदि।

सतोष की बात यह है कि राष्ट्र इस समय बहुमुखी योजनाओं का जितना पक्षपाती है उतना कभी नहीं रहा। सरकार ने इन बहुमुखी योजनाओं का अनुसंधान करके केवल भयकर बाढ़ों से ही देश की रक्षा नहीं सोची है परन्तु प्रति वर्ष बढ़ती हुई अन्न की कमी की समस्या का स्थायी उपाय भी सोच निकाला।

है। जल सम्पत्ति का विदोहन तो होगा ही, भूमि उपजाऊ बनेगी, अधिक अन्न उत्पन्न होगा, विजली बनने लगेगी और नए-नए औद्योगिक केन्द्र स्थापित होंगे। कुछ योजनाएँ दो या तीन वर्ष में समाप्त होगी, कुछ ५ वर्ष तक पूरी हों, सकेंगी तथा कुछ ऐसी दीर्घकालीन योजनाएँ हैं जिनको समाप्त होने में १०-१५ वर्ष लग जाएँगे। परन्तु योजनाएँ निश्चय ही सफल होंगी, इसमें कोई मन्देह नहीं। सभी बहुमुखी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर दो करोड़ ५० लाख एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई होगी और ४० लाख किलोवाट बिजली अधिक तैयार की जाएगी। देश को इन योजनाओं से अपूर्व लाभ होगा और औद्योगिक विकास की कठिनाई तथा अन्न की विकट समस्या स्थायी रूप से हल हो जायगी।

४—भारत में खेत-मजदूरों की समस्या

हमारे देश में अभी तक उन करोड़ों खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया गया जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं है और जो मजदूरी करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। आज जब कि देश में अन्न-संकट है, देश का विभाजन हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों की दृष्टि से भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है और पटसन तथा कपास जैसे आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल का भी देश में टोटा है, तब हमें अपनी कृषि में समूल परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने अपने कृषि धन्धे में क्रान्तिकारी परिवर्तन न किये और अपने भारतीय किसान को पुराने ढंग से अज्ञानिक खेती करने दी तो न हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का जीवन निर्वाह ही कर सकेंगे और न अपने धन्धा को उन्नत बना सकेंगे। हमें अपनी कृषि में मूलभूत और क्रान्तिकारी परिवर्तन करने ही होंगे। शुद्ध आर्थिक दृष्टि से ही खेत-मजदूरों की आर्थिक व्यवस्था सुधारना आवश्यक है। आज जिस व्यवस्था में खेत मजदूर रह रहा है उस व्यवस्था में रहकर वह कभी भी वैज्ञानिक कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय नैतिक और आर्थिक हित दोनों ही दृष्टिकोणों से हमारे खेत मजदूरों की समस्या बहुत महत्त्वपूर्ण है।

खेत मजदूरों का एक बड़ा वर्ग, जो आज हम अपने गाँवों में देखते हैं, हमारी आर्थिक होनता का परिणाम है। पिछले वर्षों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ी त्यों-त्यों विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशी कुटीर धन्धों की अवनति होने लगी। आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग इस तेजी से नहीं बढ़े कि उनमें देशी कुटीर धन्धों से निराले गए कारीगर काम पा सकते। अतः जनसंख्या का भार एकमात्र कृषि धन्धे पर ही पड़ता गया। जहाँ १९०१ में मंगलित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ५ लाख थी वहाँ ४० वर्ष के पश्चात् १९४१ में वह बढ़कर केवल २२ लाख हो पाई। इसका अर्थ यह है कि मंगलित उद्योगों में जनसंख्या की

वृद्धि की तुलना में बहुत कम लोग काम पा सके। कुटीर-धन्धों के जट्ट हो जाने के कारण तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या शीघ्रगति से बढ़ने लगी। यह बात नीचे निम्नी तालिका से स्पष्ट होती है:—

नगरों में रहने वाली वर्ष	जनसंख्या का प्रतिशत	कृषि में लगी हुई जनसंख्या का प्रतिशत	गेव-मजदूरों की संख्या
१९०१	६.६	६५.८	२०१ लाख
१९११	६.४	७१.१	२५६ "
१९२१	१०.२	७२	२१७ "
१९३१	११.१	७४.८	२४६ "
१९४१	१२.६	७८.६	२५८ "

कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या की वृद्धि होने का परिणाम यह हुआ कि भूमि का अधिकाधिक बँटवारा होता गया और छोटे तथा छिटके गेता की समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया। इन छोटे-छोटे खेतों पर न तो आधुनिक ढंग से ही गेती हो सकती है और न उन पर किसान को पूरा काम ही मिलता है। उसका बहुतसा समय बेकार रहता है। इस कारण कृषक की वार्षिक आय इतनी कम होती है कि उस आय पर उसके परिवार का जीवन निर्वाह नहीं हो पाता। उद्योग-धन्धों की कर्मा के कारण छोटे-छोटे जमींदार भा विचर होकर गेती करने लगे। १९०१ में प्रति १०० किसानों के पीछे ५३ छोटे जमींदार स्वयं खेती करते थे। किन्तु १९३१ में १०० कार्तकाओं के पीछे ७३ छोटे जमींदार स्वयं खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों के हाथ से भूमि निकलती गई और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और वे श्रृंखली बनते गये। १९३८-३९ में ग्रामीण श्रृण कोई १८०० करोड़ से भी अधिक था। इस भीषण श्रृण के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से ढाध धों बैठा और बहुत से छोटे-छोटे कृषक गेव-मजदूर बन गये। गेव-मजदूर नाम का एक वर्ग गाँवों में दिखाई पड़ने लगा।

इन गेव-मजदूरों के पास गेती नहीं होती। यह लोग केवल जुगाई, मुगाई तथा फसल काटने के समय, वर्ष में कुछ महीने, गेवों में काम करते हैं और गेव

दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके, घास छीलकर, समीप के नगरों और फसों में मजदूरी इत्यादि करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उन्हें भर पेट अनाज तक नहीं मिल पाता। उनकी दशा बहुत शोचनीय होती है। ऐसा मालूम होता है कि संसार में भारतीय खेत-मजदूर से अधिक निर्धन जीवन व्यतीत करनेवाला जग शायद ही हो। खेत मजदूरों को उन छोटे-छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है जिनके पास ५-१० बीघा भूमि है किन्तु वह भूमि न तो उनका पालन कर सकती है और न उनको पूरा काम दे सकती है। अतः अपने अग्रकाश के समय में ये लोग भी खेत मजदूरों की सख्या बढ़ाते हैं। याद इन अर्ध खेत-मजदूरों को भी सम्मिलित कर दिया जाय तो खेत-मजदूरों की सख्या देश में सात करोड़ से कम न होगी।

१९३९ में जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो खेत मजदूरों के लिए एक नया ग्रामर आया। वे लोग सेना में भर्ती होने लगे तथा उन्हें युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री बनाने के उद्योग धन्धों में काम मिलने लगा। परिणाम यह हुआ कि खेत-मजदूर वर्ग सेना और बड़े-बड़े उद्योग केन्द्रों की और दौड़ा। जैसे-जैसे युद्ध लम्बा होता गया, गाँवों में खेत-मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती गई। जहाँ युद्ध के पूर्व खेत-मजदूर को गाँव में तीन आने या चार आने प्रति दिन मिलते थे वहाँ १९४६ में पुरुष को १ रुपया, स्त्री को १२ आना और बालकों को आठ आने प्रति दिन मिलने लगा। परन्तु खेत-मजदूरों की आर्थिक स्थिति में इसमें कोई विशेष अन्तर न पड़ा क्योंकि उन्हें अपने भोजन तथा कपड़े मोल लेने पड़ते थे और इनके मूल्य युद्धकाल में आकाश को चूँच गये थे। फिर भी युद्ध के कारण खेत-मजदूरों का काम भी कमी नहीं रही। परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात् फिर वही स्थिति सामने उठ खड़ी हुई है। हो सकता था कि देश में उद्योग धन्धों की उन्नति होती तो इन्हें वहाँ कुछ काम मिल जाता परन्तु ऐसा न हो सका। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी सख्या में शरणार्थी औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रों में बेकार पड़े हैं। उनके रहते खेत-मजदूरों के लिए काम मिलने की अधिक सम्भावना नहीं। साथ ही साथ न तो कृषि-धन्धे की उन्नति की दृष्टि से और न राष्ट्र के हित में यह बात ठीक जान पड़ती है कि इतनी बड़ी सख्या में

खेत-मजदूरों को गाँवों से धकेल कर औद्योगिक केन्द्रों में लाया जाय ।

जहाँ तक बड़े-बड़े कारखानों का प्रश्न है उनकी समस्या यदि तेजी से बढ़ाई भी जाय तो भी वे देश की बहुत थोड़ी जनसंख्या को काम दे सकेंगे । आधुनिक विज्ञान कारखानों की स्थापना हमारे देश में १८६० के पश्चात् से आरम्भ हुई है । आज लगभग ६० वर्षों के पश्चात् जितने भी कारखाने, रेलवे वर्कशाप, चाय, कढ़वा और खर के बाल और कारखाने हैं उनमें देश की वेद प्रतिशत जन-संख्या ही काम वा सकती है । ऐसी दशा में यह आशा करना कि बड़े-बड़े कारखानों में खेत-मजदूरों को पर्याप्त कार्य दिया जा सकता है, दुराशा मात्र है । फिर आज तो बेकार शरणार्थियों को काम देने की समस्या भी हमारे सामने उठ खड़ी हुई है । अतएव खेत-मजदूरों को बड़े-बड़े कारखानों में काम दिया मकने की न तो सम्भावना ही हो सकती है और न राष्ट्र के आर्थिक हित के दृष्टिकोण से फलदायी ही है । ऐसी दशा में खेत-मजदूरों की समस्या का हल हमें गाँव के आर्थिक संगठन में परिवर्तन करके ही निकालना होगा ।

खेत-मजदूरों की स्थिति वास्तव में दासों की भाँति है । उनमें से अनेक तो स्थायी रूप से जमींदारों के श्रमणी रहते आये हैं और रात दिन उनकी हवेली या खेतों में काम करते रहते हैं । अधिकांश खेत-मजदूर सम्पन्न किसानों तथा जमींदारों से ऋण ले लेते हैं और जुताई, बुवाई और फसल काटने के लिए अपने श्रम को बन्धक स्वरूप रख देते हैं । गाँवों में यही समय ऐसा होता है जब श्रम की आवश्यकता होती है और मजदूरी अच्छी मिल सकती है । उस समय गाँवों में मजदूरों की माँग होती है परन्तु उसी समय ऋणी खेत-मजदूर को नाम मात्र की मजदूरी पर अपने ऋणदाता के यहाँ काम करने पर विवश होना पड़ता है । इस विषय में जो कुछ भी गोज़ की गई है उससे पता चलता है कि लगभग ५० प्रतिशत खेत मजदूरों की यही दशा है । इनमें से १५ प्रतिशत मजदूरों को तो पोवाई और फसल काटने के अवसर पर केवल एक समय भोजन मिलता है, शेष ३५ प्रतिशत को भोजन के अतिरिक्त आना दो आना और दे दिया जाता है । कहने का अर्थ यह है कि इन खेत-मजदूरों को गाँव में प्रचलित मजदूरी से बहुत कम मजदूरी मिलती है । जब खेतों में काम नहीं होता तो बेचारे

मजदूर का यह मजदूरी भी नहीं मिलती और तब वह घास खादकर, लकड़ी इकट्ठी करके, टाट बुनकर, डलिया बनाकर, आस-पास के नगरों में मजदूरी करके या भट्टों में काम करके अपना जीवन निर्वाह करता है। इन मजदूरों के पास इतना धन कभी नहीं इकट्ठा होता कि वे अपना ऋण चुका सकें। अतः ऋण पर ब्याज इकट्ठा हो जाता है जिससे वे पाटो दर पीटो अपने मालिकों के दाम बन कर जीवन यापन करते हैं। यह मजदूर कैबल नाम मान का ही स्वतन्त्र होते हैं परन्तु इनकी अस्थिरता दासा से भी पुरी होती है। इन्हें गाँवों के सबसे गन्दे और बुरे स्थान पर बसाया जाता है। न इन मजदूरों का कोई संगठन होता है और न इनमें इतना ज्ञान ही होता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। परम्परा के अनुसार वह बिना विरोध किये ही अपने मालिकों को गुलामी करता रहता है। संगठित न होने के कारण वह कभी आर्थिक दबाव को मुधारने का ध्यान भी नहीं करता। आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार इनकी आर्थिक स्थिति मुधारने की आरम्भ करे।

खेत-मजदूरों की आर्थिक स्थिति मुधारने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि इनकी न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाय जिससे इन्हें जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी मिल सके। परन्तु जब तक हम कृषि पर निर्भर रहने वालों की सख्या कम नहीं कर दें, जब तक गेत मजदूरों को अन्य दूसरे काम दिलाने का प्रयत्न नहीं होता और जब तक कृषि-धन्धा उत्पन्न करके लाभदायक नहीं बनता तब तक न्यूनतम मजदूरी कानून बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता। बात यह है कि यदि कृषि की अस्थिरता ऐसी ही गिरी रहो तो कृषक न्यूनतम मजदूरी देने में असमर्थ रहेगा। साथ ही यदि खेत-मजदूर के लिए गाँवों में ही कोई अन्य काम न मिला तो वह कानून के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में कम मजदूरी पर ही काम करने को विवश हो जायगा। सरकार को यह भी देखना होगा कि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पैदावार का मूल्य ऊँचा है अतएव सम्भव है किसान न्यूनतम मजदूरी दे भी सकें परन्तु यदि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ गिर गया तो किसान के लिए न्यूनतम मजदूरी देना असम्भव हो जायगा। हाँ, जब इस देश की कृषि में सुधार आगा, आधुनिक ढंग से कृषि होने लगेगी और कृषि का लागत व्यय

कम हो जायगा और लाभ अधिक होगा, उस समय किसान न्यूनतम मजदूरी देकर भी कृषि की पैदावार का सस्ते भावों पर बेच सकेगा। हर्ष की बात है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बिल पास कर दिया है, परन्तु केवल कागज़ बनाकर ही रेत-मजदूरों की दशा नहीं सुधारी जा सकती। इसके लिए तो हमें गाँवों का गंगटन ही बदलना होगा। यदि ऐसा न किया जा सका तो इन मजदूरों की दशा सुधारनी सम्भव नहीं हो सकती।

आवश्यकता से अधिक रेत-मजदूरों के लिए काम देने और दिलाने की पहली आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बंजर भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाकर रेत मजदूरों को दें। उस भूमि की सिंचाई के साधन उपलब्ध करें और उस भूमि पर रेत-मजदूरों के सहकारी फार्म स्थापित करें। सरकार को इस नई भूमि को व्यक्तियों में बाँटने की भूल नहीं करनी चाहिए। यदि छोटे छोटे रेत मजदूरों को मिल भी गए तो वे अन्य किसानों की ही भाँति पुराने ढंग की गेती करेंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार बंजर भूमि पर सहकारी फार्म स्थापित करके रेत-मजदूरों को उसका सदस्य बनाकर समादे। चूँकि रेत मजदूरों के पास आज भूमि नहीं है इसलिए वे सहकारी फार्म के सदस्य बनने से कोई आपत्ति न करेंगे। राज्य सरकारों को कृषि यन्त्र तथा खाद इत्यादि उचित मूल्य पर देकर इन फार्मों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार सहकारी फार्म बनने से दो लाभ होंगे; एक, फार्मों में वैज्ञानिक कृषि का जा सकेगा; दूसरे, रेत-मजदूरों को बसाना जा सकेगा। भविष्य में यदि ये सहकारी फार्म लाभदायक मिश्र हुए तो अन्य किसानों को सहकारी फार्म स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। जो किसान सहकारी फार्म स्थापित करें उन्हें सरकार लगान तथा सिंचाई में छूट देकर तथा दस फार्मों के बीच एक बीज तथा खाद तथा अन्य गोदाम स्थापित करके उन्हें उचित मूल्य पर उत्तम बीज, खाद तथा आधुनिक यन्त्र किसानों पर देकर उनकी सहायता कर सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक भारतीय किसान उसी प्रकार पुराने ढंग से छोटे और छिटके टंग पर कृषि करता रहेगा तब तक न तो हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यथेष्ट भोजन दे सकेंगे और न अपने उद्योगों के लिए आवश्यक माषा में कच्चा माल ही पैदा कर सकेंगे। केवल न्यूनतम मजदूरी

कानून बन जाने पर भी कृषि को उन्नत किए बिना खेत मजदूरों की अवस्था नहीं सुधारी जा सकती। सहकारी पामों द्वारा कृषि करने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि चिरपरे हुए खेतों की चमबन्दों की जाय और प्रत्येक किसान को कम से कम आर्थिक जोत दे दी जाय। बिना चमबन्दों किए और आर्थिक जोत किसानों को दिये खेतों की उन्नति भी उन्नति नहीं हो सकती। अन्त में हमें सहकारी कृषि को ही अपनाना होगा।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है खेत मजदूर की समस्या केवल बजर भूमि पर बसा देने से हल नहीं की जा सकती। उसने लिए हमें स्थायक और प्रक धन्ये स्थापित करने हाने। उपभोग्य पदार्थों का उत्पन्न करने वाले धन्यो का प्रिवेन्ट्रीकरण करके उनको छोटा रूप देकर कुटीर धन्यो के रूप में उन्हें गाँवों में स्थापित करना होगा परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आज का तरह वे धन्ये पुराने ढंग से ही चलते रहें। इसके लिए देश में जल विद्युत की उन्नति करनी होगी और बड़े-बड़े बिजलीघर स्थापित करके मिड प्रणाली के अनुसार समस्त देश में बिजली की लाइनों का एक जाल-मा बिछा देना होगा और हल्के छोटे यन्त्रों का निर्माण करा कर उनका गाँवों में प्रचार करना होगा। इन कुटीर-धन्यो का संगठन भी सहकारी समिति के आधार पर करना होगा और तभी यह सफल हो सकेंगे। सतोष की बात है कि सरकार जल विद्युत की ओर विशेष ध्यान दे रही है। जब ये योजनाएँ बनकर समाप्त होंगी तो इनकी बिजली से कुटीर धन्यो तथा कृषि की आशाणीत उन्नति होगी जिससे खेत-मजदूरों और छोटे किसानों को जीवनयापन के पर्याप्त साधन मिल सकेंगे।

खेत-मजदूरों को काम दिलाने का एक यह भी ढङ्ग हो सकता है कि उनकी सहकारी भ्रमिक समितियाँ बनाई जाएँ और जब खेती में बेकारी हो अर्थात् खेत मजदूरों को खेतों पर काम न मिले उन महीनों में ये भ्रमिक समितियाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नहर विभाग तथा नगरपालिकाओं और अन्य विभागों से सड़क बूटने, मिट्टी खोदने तथा अन्य कार्यों के ठेके लें। ठेके देते समय सरकार इन समितियों का विशेष ध्यान रखे। इटली में ऐसी भ्रमिक सहकारी समितियाँ हैं जो बड़े बड़े ठेके लेकर अपने सदस्यों को काम देती हैं। भारत में भी खेत मजदूरों को इस

प्रकार सहकारी समितियों में संगठित करने की आवश्यकता है जिससे बुवाई और फसल कट चुकने के पश्चात्, जब खेत-मजदूरों को खेतों पर काम न मिलता हो, काम दिया जा सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक खेत मजदूरों की दयनीय दशा की ओर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने इन हतभागी मजदूरों की अवस्था सुधारने की ओर कुछ प्रयत्न किए हैं। १९४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास कर दिया गया तथा देश भर में खेत-मजदूरों की आय-व्यय सम्बन्धी, जीवन-व्यय सम्बन्धी तथा मजदूरों के श्रम सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त करने के लिए सरकार ने १९४६ में देश के विभिन्न राज्यों के २७ ग्रामों में खेत-मजदूरों की जाँच पड़ताल की। विभिन्न राज्यों में गाँवों की जाँच पड़ताल इस प्रकार की गई :—

राज्य	गाँवों की संख्या	राज्य	गाँवों की संख्या
आसाम	२	उत्तर प्रदेश	८
पश्चिमी बंगाल	५	मध्य प्रदेश	२
बिहार	४	मद्रास	३
उड़ीसा	२	मैसूर	१

सरकार ने इन गाँवों में जाँच पड़ताल करके खेत-मजदूरों की वास्तविक अवस्था का पता लगा लिया है। सरकार का कहना है कि इस जाँच पड़ताल के आधार पर देश भर में कृषि-मजदूरों की आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक श्रृङ्खला योजना बनाएगी। आशा है इस योजना के बनने पर देश में खेत-मजदूरों की समस्या का हल निकाला जा सकेगा।

५—ग्रामों का पुनर्निर्माण

अज्ञान एवं दक्षिणता भारतीय ग्रामीण समाज के भीषण अभिशाप हैं। रोग, कलह, गन्दगी, विद्रोह एवं अशिक्षा भारतीय ग्रामों को ज्वर की भाँति जकड़े हुए हैं। इतिहास में जिन गाँवों में हम स्वर्ग के वातावरण का वर्णन पाते हैं वे ही ग्राम आज नरक बने हुए हैं। यदि ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर का अध्ययन किया जाय तो एक बड़ी निराशा होती है। मुद्र पूर्व-काल में भारतीय ग्राम की प्रति व्यक्ति औसत आय ४० ६० वार्षिक से कुछ ही अधिक थी। यद्यपि मुद्र के पश्चात् अब उनकी आय में कुछ वृद्धि की सम्भावना मालूम होती है परन्तु वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी आय में कोई विशेष बढाव नहीं मालूम होती। मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं के भाव पहले की अपेक्षा अब चौगुने पँचगुने हैं। अतः वस्तुओं के मात्र दंड से देखने पर आय में अधिक वृद्धि नहीं हुई। यद्यपि कुछ बड़े बड़े कृषकों को मुद्र काल में कभी आमदनी हुई है परन्तु अधिकांश कृषक एवं ग्रामीण मजदूर पहले की अपेक्षा और भी अधिक गण बीते हैं। हमारे देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय की तुलना यदि अन्य देशों की औसत आय से की जाय तो बड़ी निराशा होती है। मुद्र से पूर्व इंग्लैण्ड और अमेरिका की औसत आय ६८० तथा १४०६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के गाँवों का जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है। अधिकांश ग्रामीण तो कभी भी भर पेट और पौष्टिक भोजन नहीं पाते। वे जेट की चमकनी दुपहरी में, भाएण भादों की गम्भीर वर्षा में तथा शिशिर की ठिठुर में तरस्वियों के भाँति अपनी अर्जित भोग्यद्रियों में पड़े-पड़े जीवन के क्षणों का व्यतीत करते हैं। नगे सिर, नगे पैर लाखों यात्री जनवरी के भीषण शीत में गंगा में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। इनमें अधिकांश ग्रामीण होते हैं। इतना बट वे धार्मिक विश्वासों पर उठाते हैं। युग-युगों की दीनता में उनका सतोष निहित है।

हमारे गाँवों में शिक्षा का स्तर बहुत शोचनीय है। गाँव वालों को अपने पशुओं का हाल जानने के लिए मीलों जाना पड़ता है जहाँ वे शिक्षित व्यक्ति से अपने पशुओं को पढ़वा सकें। उन्हें पशुओं को लिखने तो कौन करे, वे अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। भारत की आत्मा गाँवों में है, अतः उन्हें इतनी विद्युद्भी दशा में पशु रखने देना अत्यन्त खेद और क्षाम का विषय है। राष्ट्रीय जागरण के प्रभाव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य तथा समाज सुधारकों का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि भारतीय मामों का पुनरुद्धार करें। हमारे देश की कुल जनसंख्या का आधिकांश भाग गाँवों में बसता है। अतः जब तक इन गाँवों की अवस्था नहीं सुधारी जायगी तब तक आर्थिक या सामाजिक पुनर्निर्माण की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती। गाँवों की उपेक्षा करके राष्ट्र के औद्योगीकरण की चर्चा से चर्ची योजनाएँ भी देश को उन्नत नहीं बना सकती। ग्रामीणों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। अतः सरकार का पहला कर्तव्य कृषि में सुधार करना है। संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। उदाहरणार्थ, भारत में कपास १०० पौंड प्रति एकड़ पैदा होती है जब कि अमेरिका में २५० पौंड प्रति एकड़ तथा मिश्र में ४५० पौंड प्रति एकड़ पैदा होती है। इसके अतिरिक्त भारत में ईंधन १३ टन प्रति एकड़ पैदा होती है जब कि जावा में ईंधन की उपज ५० टन प्रति एकड़ है। नया भारत जैसा कृषि प्रधान देश के लिए, जहाँ प्रत्येक ४ व्यक्तियों में तीन व्यक्ति कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं, यह सच्चा और शोक का विषय नहीं है कि इतना विशाल देश पूरी जनसंख्या की अन्न समस्या को भी सुलभाने में सफल न हो सके। इस असफलता का रहस्य हमारी कृषि के कुछ भयानक दोषों में लुपा हुआ है। छोटे और छिटे रोते, विषम भूमि स्वामित्व, सुगों का अल्प-भार, सिंचाई के साधनों का अभाव, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी खादों की कमी, फसल नियंत्रण तथा उन्नत रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों की आवश्यकतानुसार उगाने की योजनाओं का अभाव, अस्वस्थ और रोगी पशु-धन तथा द्वेषपूर्ण ग्रामीण जीवन, गाँवों की जनता की गरीबी के कारणों में प्रधान है। दीन होन और उपेक्षित गाँववासियों की जड़ में यह दोष गुन की तरह लगे हुए हैं जो उनके जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति को तोड़ना बना

रहे हैं। जब तक भारतीय कृषि इन लोगों से मुक्त नहीं होती तथा सहकारी कृषि का प्रचलन नहीं होता तब तक जनता की दीन हीन दशा नहीं सुधारी जा सकती।

जहाँ तक भूमि-स्वामित्व का प्रश्न है हमारा विश्वास है कि कृषकों को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। परन्तु केवल जमींदारी समाप्त करके ही हम समस्या हल नहीं कर सकते। युग की पुकार है कि छोटे और छिटे खेतों की चकबन्दी करके सामूहिक या सहकारी ढंग पर खेती की जाय। ऐसी बंजर भूमि जिस पर खेती की जा सकती है वैज्ञानिक साधनों के बिना उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती। सहकारी समितियों द्वारा सामूहिक ढंग पर कृषि करने की व्यवस्था करना तथा वैज्ञानिक साधनों एवं उचित मात्रा में खाद का प्रबन्ध करना सरकार का ही काम है।

विदेशों के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जिस देश में जनसंख्या का अधिकांश भाग केवल कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर रहेगा वहाँ की औसत आय नीची रहेगी। इसके विपरीत जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का कुछ भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग धन्यों में लगा रहेगा उस देश की औसत आय कृषि प्रधान देश की अपेक्षा कुछ अधिक रहेगी। प्रो० लुई एचरोन ने लिखा है “चीन की प्रति व्यक्ति औसत आय दुनी की जा सकती है यदि कार्यशील जनसंख्या का १५ प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग धन्यों में लगा दिया जाय। इसके अतिरिक्त यदि १० प्रतिशत जनसंख्या अन्य पेशों में और लगा दी जाय तो औसत आय प्रति व्यक्ति तिगुनी की जा सकती है।” अतः राष्ट्र की बेकार जनसंख्या को उद्योग-धन्यों में लगाने की व्यवस्था करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इस समय सारे देश में जन विद्युत शक्ति की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। अतः घरेलू उद्योगों तथा अन्य प्रकार के उद्योग-धन्यों के प्रचार के लिए इस समय अच्छा अवसर और क्षेत्र प्राप्त है। घरेलू उद्योग-धन्यों की जड़ मजबूत करने के लिए सरकार को विद्युत शक्ति, कच्चा सामान, अर्थ व्यवस्था, विनय व्यवस्था आदि का प्रबन्ध करना आवश्यक है। सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य बड़ी सरलता से हो सकता है। घरेलू उद्योग-धन्यों के द्वारा कृषि व्यवसाय पर निर्भर रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या को काम मिल सकेगा।

गाँवों की सड़कों तथा नालियों की ओर ध्यान देना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इनके सुधार के लिए सरकार को आवश्यक अर्थ व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक गाँवों की सड़कों का समुचित सुधार नहीं हो जाता तब तक भारतीय कृषि की उदय की बिक्री की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह काम भी सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है। सरकार को आदर्श ग्रामों, स्वच्छ नालियों तथा अच्छी सड़कों से पूर्ण आदर्श ग्रामों का निर्माण करना चाहिए। जिला बोर्ड के इंजीनियर की सेवाएँ ग्राम निवासियों को प्राप्त होती हों। प्रत्येक गाँव में सर्प साधारण के उपयोग के लिए चरागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गाँव भर के पशु स्वतन्त्रता से चर सकें।

प्रत्येक गाँव में एक सहकारी समिति, पंचायत, प्राथमिक पाठशाला, वाचनालय तथा औपधालय होना अत्यावश्यक है। अंग्रेजी राज्य काल में सारे शासन का केन्द्रीकरण हो गया था। अब उसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। गाँव-पंचायतों में गाँव के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सभी कामों की देख-भाल करने का इन्हें अधिकार होना चाहिए। पारस्परिक मतभेदों एवं भगड़ों को मुलभूतना, प्रत्येक वर्ण के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन करना, गाँवों की सहकारी समिति का मन्वयन करना, प्रारम्भिक पाठशाला, वाचनालय तथा औपधालय का प्रबन्ध करना पंचायतों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ये पंचायतें गाँव की गलियों, सड़कों और नालियों की मरम्मत कराने में सहायता करें। गाँवों की सहकारी समितियाँ बहुमुखी सहकारी समितियों के आधार पर होनी चाहिए। बहुमुखी सहकारी समितियाँ ही हमारे लिए उपयोगी होंगी जहाँ ऋण का लेन-देन, वस्तु-विक्रय, बीज-वितरण आदि काम एक ही सहकारी समिति कर सके। यह निर्माण तथा नयेतों की चक्रवर्ती के लिए विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ बननी चाहिए। कृषक को अन्न-कालीन तथा दीर्घ-कालीन दोनों प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है। दीर्घ-कालीन ऋणों की पूर्ति के लिए भूमि बन्धक बैंक स्थापित होने चाहिए। ग्रामीण सहकारी बैंकों का केन्द्रीकरण करके उन्हें रिजर्व बैंक में मिला देना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं से ग्रामीण जनता की अर्थ समस्याएँ बहुत कुछ हल हो सकेंगी।

प्रायः ऐसा देखने में आता है कि राज्य सरकारों व तत्सामान्य मंत्रालयों में विनास सम्बन्धी अनेक विभाग काम करते हैं। उदाहरणार्थ, कृषि विभाग तथा सहकारी विभाग दोनों ही बीज गादामों का प्रबन्ध प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इनने अपसरा तथा निरीक्षकों के कार्यों का सम्बन्धीकरण करना परम आवश्यक है। यह अक्सर गाँवों की कृषि, जन्ममरण सम्बन्धी आदि, कृषि पर निर्भर घरेलू उद्योग धन्धा, पानी के विनास की व्यवस्था, सड़कें और गलियाँ का प्रबन्ध, सिंचाई तथा पशुश्रा की समस्या तथा अन्य प्रकार की ग्राम समस्याओं को हल करने में उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ग्राम की पाठशाला का शिक्षित गाँव के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है परन्तु ग्रन्थन्त कम वेतन होने के कारण वह ग्रन्थ साधना में अपनी जीविना कमाने का प्रबन्ध करता है और अपने कार्यों को भी ठीक प्रकार नहीं निभा पाता। सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए।

गाँवों के पुनर्निर्माण में एक बड़ा कठिनाई यह है कि गाँवों का शिथिल और जाग्रत समाज गाँवों से दूर होता जा रहा है। उदाहरणार्थ, गाँव का जमादार गाँव में न बसकर शहरों की ओर दौड़ता है तथा शिक्षित लोग भी प्रायः गाँवों का छोड़ शहरों में बसने लगे हैं। ऐसी दशा में गाँवों का पुनर्निर्माण कौन करेगा ? आज युग की पुकार है एक आवश्यकता है कि 'पुनः गाँवों की ओर लौटो' आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय, परन्तु यह अभी सम्भव है जब कि गाँवों का शिक्षित समुदाय के रहने योग्य बनाया जाय। उन्हें गाँवों में स्वच्छता, प्रेम, चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था तथा वाचनालय आदि की सुविधाएँ प्राप्त हों। गाँवों के पुनर्निर्माण में ये शिक्षित लोग बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने गाँवों का पुनर्निर्माण कर गाँधी के रामराज्य की कल्पना को साकार बना सकेंगे।

६—देश की ग्वाथ-समस्या

गत अनेक वर्षों में हमारे देश में ग्वाथ-समस्या बनी हुई है। घेसे तो युद्ध-काल में भी सारे देश में अन्न की भारी कमी रही। बग़ाय के अकाल को सहन ही नहीं भुकाया जा सकेगा। परन्तु वह सब उस समय की विदेशी सरकार की युद्धजनित राजनीति का परिणाम था। आज युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए, परन्तु अन्न का अभाव क्यों का त्यों बना हुआ है। 'भारत कृषि-प्रधान देश है' 'भारत के साधन असीम हैं', 'भारत की भूमि साना उगलती है' आदि सभी कुछ झोंते हुए भी देश में देशवासियों के खाने भर को अन्न नहीं मिल रहा तथा अन्य देशों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। पछले वर्षोंमें अन्न-उत्पादन की भारी कमी रही। मानसून के अभाव तथा नदियों की चिरराल बाढ़ों ने तैयार फसलों को नष्ट कर दिया यह सत्य है; किन्तु इसके अनिश्चित देश में भूमि की उत्पादनशक्ति भी क्षीण होती जा रही है। सिंचाई के उचित साधन न होने के कारण तथा वैज्ञानिक ग्वाथ एवं कृषि-यन्त्रों के अभाव के कारण कृषि की अवस्था गिरती ही जा रही है। देश के विभाजन में भी भारत मध्य की ग्वाथ स्थिति पर बड़ा घुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान बन जाने के पश्चात् भी भारत को अविभाजित-भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या का पट भरने का प्रयत्न करना पड़ रहा है परन्तु उत्पादन की दृष्टि से भारत के हिस्से में केवल गंगा का उपजाऊ भाग ही आया है जो इस भूमि पर निर्भर जनसंख्या को अर्थार्थ ही है। गेहूँ उपजाने-वाले क्षेत्र का केवल ६५ प्रतिशत तथा चारल उपजाने वाली भूमि का ६६ प्रतिशत भाग भारत को सीमा में है। विभाजन के कलहस्पद ममस्त सिंचित क्षेत्र का ६६ प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में आया जिसमें से गेहूँ पैदा करने वाला भूमि-क्षेत्र तो केवल ५४ प्रतिशत ही रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में खानेवाले व्यक्ति अधिक संख्या में हैं और अन्न उत्पन्न करने वाली भूमि थोड़ी मात्रा में है। जिस पर भी जो कुछ कृषि-योग्य भूमि है उसका पूरा विदोहन नहीं किया जाता। न ग्वाह है, न अच्छे और उत्तम बीज हैं, न सिंचाई

के पर्याप्त साधन हैं और न कृषि-यन्त्रों का प्रयोग हो है। भारत में अन्न उत्पादन मानसून की कृपा का पात्र रहा है। एक और तो अन्न की कमी बर्तती रही है और दूसरी ओर जन संख्या में वृद्धि होती रही है। आज परिस्थिति यह है कि देश की ४१ प्रतिशत जनता का निम्न तथा २० प्रतिशत जनता को निम्नतर भेरी का आहार मिलता है। सम्पूर्ण देश में केवल ३६ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यक मात्रा में पेट भर खाना मिल पाता है। यही नहीं, हमारे देश में दूध का उपभोग औसतन प्रति दिन ७ ग्राम प्रति व्यक्ति है जब कि इंग्लैण्ड में ३६ ग्राम प्रति व्यक्ति, डेन्मार्क में ४० ग्राम प्रति व्यक्ति, न्यूजीलैण्ड में ५७ ग्राम प्रति व्यक्ति तथा फिन्लैण्ड में ६३ ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिवस का औसत आता है।

अन्न की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने विछले वर्षों में हजारों टन अनाज विदेशों से आयात किया है। गत वर्षों में अन्न का आयात इस प्रकार रहा है —

वर्ष	अन्न का आयात (हजार टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
१९४४	६४६	१३.०
१९४५	८५०	२०.४
१९४६	२,२५०	७६.१
१९४७	२,३३०	६८.७
१९४८	२,८४०	१२६.५
१९४९	३,७००	१४८.०
१९५०	४,२००	१६८.५
१९५१	४,७००	१७५.६
१९५२ (अनुमान)	५,०००	—

अधिकांश अन्न दुर्लभ-वस्तु वाले देशों से आयात किया गया जिससे भारत का दुर्लभ वस्तु जो पृथ्वी-वस्तुओं तथा यन्त्रादि पर व्यय करने पर सोचा गया था, खाने में ही समाप्त हो गया। पौष्टिक पावना, जिस पर बुद्धोत्तर

भारत के कृषि-पुनर्निर्माण तथा औद्योगिक-संगठन की आधार-शिलाएँ अवन-मित थीं, पेट भरने में ही समाप्त होता जा रहा है। नदियों में बाढ़ आने से, भयंकर नृपान के कारण तथा कई स्थानों पर अधिक वर्षा और कहीं कहीं पर कम वर्षा के कारण अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। १९४७-४८ में इस संकट को टाँचने के लिये 'कण्ट्रोल तथा राशन' की नीति का पुनः पालन करना आरम्भ किया गया; परन्तु कोई सन्तोषजनक परिणाम न निकला। आस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्रह्मा, चीन, हिन्दचीन, रूस, टर्की, इराक आदि देशों से भारी-भारी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री आयात होती रही। इस संकट के स्थायी निवारण तथा कृषि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाने के लिए अनेक सम्मेलन किए गए। देश व्यापी 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना बनाकर कार्यान्वित की गई। इस योजना के अनुसार लगभग ६,००,००० टन अनाज उत्पन्न करने की बात सोची गई थी परन्तु केवल ७,००,००० टन अनाज ही उत्पन्न किया जा सका जब कि इस योजना पर लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय हुए। ज्ञात होता है कि सरकार को यह योजना अधिक रूपन न हो सकी। सरकार ने इस योजना को प्रान्तों के कृषि विभागों के नियन्त्रण में दिया और इन विभागों के कर्मचारियों ने केवल अपने-अपने कार्यालयों में बैठे-बैठे ही इस सफल बनाना चाहा। परन्तु इस योजना का सफलभूत बनाने के लिए कृषकों के भाग मिलकर काम करने की आवश्यकता थी, उनके साथ मेलों पर जाकर इसका महत्व समझा कर, सुविधाएँ देकर अन्न का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी। कार्य ठीक इसके विपरीत हुआ। वादालियों का काम तो बढ़ता गया परन्तु अन्न उत्पादन का काम उभी अनुशात में न बढ़ सका। परिणामतः 'अधिक अन्न उपजाने' के स्थान पर 'अधिक पशु' उरजाए गए और कार्यालयों में मोटी-मोटी फादलें बन गईं।

सितम्बर १९४८ में रुपये के अचमूल्यन के पश्चात् एक और नई समस्या देश के सामने आगई। पाकिस्तान द्वारा पाक-रुपये का अचमूल्यन न करने से हमारे देश में पाकिस्तान में आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य ४४ प्रतिशत अधिक बढ़ गया। अतः भारत ने रुई और पटसन पाकिस्तान में न मंगाकर अपने देश में ही उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। इसके लिए अन्न

के लिए काम आने वाली भूमि पर अन्न न उपजा कर रुई और पटसन उगाए जाने लगे। इससे अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। इससे अतिरिक्त अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के कारण भी अन्न उत्पादन में कमी होती गई। दिसम्बर १९५० में होने वाले ग्राह्य मंत्रियों के सम्मेलन में अनुमान लगाया गया था कि यदि यही स्थिति चलती रही तो १९५०-५१ में कोई ५५ लाख टन अनाज की कमी रहगी। ठीक ऐसा ही हुआ। अन्न का सङ्कट प्रचण्ड होता गया और गत वर्ष भारत सरकार ने अमरीका से विशेष कानून पास कराके अन्न का स्रण लिया। प्रतिज्ञा की गई कि दिसम्बर १९५१ तक देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया जायगा, परन्तु यह प्रतिज्ञा पूर्ण न हो सकी और यह तिथि मार्च १९५२ तक टाल दी गई। परन्तु अब भी समस्या विकट है और मार्च तक अन्न में आत्मनिर्भर बनने के कोई आसार नहीं दीख पड़ते। ग्राह्य मंत्री ने स्वयं घोषित किया है कि १९५२-५३ में कम से कम ५० लाख टन अन्न आयात करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार आयात किए गए अन्न पर आर्थिक सहायता देकर सस्ते मूल्यों पर बेचने का प्रयत्न करती रही है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है १९४८ में सरकार ने अन्न के आयात पर कोई ३० करोड़ रुपये व्यय किए थे जो देश के कुल आयात का १८ प्रतिशत था। १९४८-४९ में भारत सरकार ने आयात किए गए अन्न पर ३३ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी थी और १९४९-५० में लगभग २५ करोड़ रुपये की सहायता सरकार ने राज्य सरकारों को दी। अब इस वर्ष से भारत सरकार ने यह आर्थिक सहायता न देने का निर्णय कर लिया है।

ग्राह्य समस्या का टालने के लिए सरकार ने बहुमन्त्रा योजना बनाई है जिसमें अनुसार अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का पुनरुद्धार किया जायगा। प्रस्तुत कृषि भूमि पर प्राथमिक अन्न उगाया जायगा तथा बजर भूमि को जो निटल्ली पड़ी है, कृषि योग्य बनाया जायगा जिसमें कृषि-भूमि में क्षेत्रफल विस्तृत हो और अधिक मात्रा में अन्न पैदा किया जा सके। इस योजना के प्रमुख ंग निम्न हैं :—

(१) लगभग ६०,००,००० एकड़ भूमि को, जो चमार वही है परन्तु जो कृषि के काम आ सकती है, समतल करके कृषि योग्य बनाया जायगा। इसके लिए सरकार ने विश्व बैंक से ५ करोड़ डॉलर का ऋण लेकर ट्रेक्टर मंगाए हैं जिनकी सहायता से यह काम पूरा किया जा रहा है। मिस-मिस राज्य सरकारों के नियन्त्रण में भूमि का ट्रेक्टरों तथा हायड्रॉलिक द्वारा पुनिकरण किया जा रहा है। १९४८ में ४,६६,६०५ एकड़ भूमि का पुनः कृषिकरण किया गया था। इस योजना में लगभग ३३६*६५ करोड़ रुपये का व्यय आँका गया है। इसका हिस्सा पूराना 'भूमि का कृषिकरण' नियम में वर्णित।

(२) प्लाथ समस्या को हल करने के लिए कृषि में मिनाई का भीमद्वय सरकार ने समझा है। इसके लिए दीर्घकालीन क्षति योजना तैयार की गई है जिनमें विशाल नदियों के क्षति बनाकर बिजली की उत्पादन का मायमा तथा साथ ही साथ पानी एकत्र करके बाँटें को रोकता जायगा और मिनाई भी की जा सकेगी। इस अनुमान है कि क्षति-योजनाओं के मुक्त हो जाने के पश्चात् लगभग २,५०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर मिनाई हो सकेगी और इससे विशाल जल-विद्युत तैयार होगी जो कृषि तथा उद्योग दोनों के लिए काम आ सकेगी। इसके राज्य में सभी योजनाएँ बन चुकी हैं और बड़े राज्यों में तो काम भी आरम्भ हो चुका है। इसके आन्तरिक बिजली के मुक्त बनाने की भी योजना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य है। मिस-मिस राज्यों, जैसे पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अमल-ीन वर्षों में करीब ८,७५८ बिजली के कुल उत्पादन जायेंगे। इस पर कुल व्यय ६६ करोड़ रुपये आँका गया है। इसी के साथ साथ कृषि का यन्त्रीकरण भी हो रहा है। विदेशों से कृषि यन्त्र आयाकर उनकी सहायता से कृषि कार्य सम्पन्न किया जाने लगा है। कृषि के यन्त्रीकरण से बाँटे साधन में अधिक मात्रा में खर्च उठाना जा सकेगा।

●(३) खाद-मिट्टी-निष्कारण योजना में सरकार ने यह निर्णय किया है कि १९५२-५३ तक १५,२३,००० टन उद्योगिक खाद की प्रदाय बढ़ाई जाय। इस काम के लिए ७१*५७ करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। कृषि-भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि में खाद बनाने का संस्थापन

खाली जा रही हैं। बिहार में ३० करोड़ रुपये की लागत से खाद बनाने का एक विशाल कारखाना गंवाया गया है। पूना में भी वैज्ञानिक रीति से खाद बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्रों में ५२ लाख टन कम्पोस्ट तैयार किया गया था जिससे आशा है कि ५५ लाख मन अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा।

(४) खाद्यान्न की कमी का पूरा करने का लक्ष्य अन्न के स्थान पर, उन भागों में जहाँ मछली का उपभोग किया जाता है, मछली निरालने की उद्देश्य योजनाएँ बनाई गई हैं। इससे अन्न का अभिवाहन कम होगा और मछली का प्रयोग भी हो सकेगा। केन्द्रिय सरकार ने देश के प्रमुख बन्दरगाहों पर, जहाँ पर प्राकृतिक दृष्टि में मछली का आहार है, मछली पकड़ने की सुविधाएँ दे रखी हैं। इन स्थानों पर मछली पकड़ने का केन्द्र बनाए जा रहे हैं। प्रारम्भ में बवई, फाचीन, रिजगापत्तम, चन्द्रगलि तथा फलफला में मछली पकड़ने के केन्द्र खोले गए हैं। इनका व्यय लगभग ६ करोड़ बजट किया गया है।

मछली उद्योग को छोड़ अन्य सभी काम राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकारें ही भूमि का कृषिकरण, कृषि का यन्त्रीकरण तथा कुँए आदि बनाने का प्रबन्ध कर रही हैं। प्रश्न राजस्व का है। इस विषय में यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारें कुल आनुमानिक व्यय में से देश में खर्च होने वाली वह धन-राशि का, जो उच्च योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिए अपने देश में ही व्यय करनी होगी, प्रबन्ध करेंगी तथा केन्द्रिय सरकार इन योजनाओं का फल बनाने के लिए उन आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करेगी जिनका बाह्य देशों से आयात करने की आवश्यकता होगी। सूचना के लिए हम यहाँ पर उच्च योजनाओं पर बजट किए गए धन का विवरण देते हैं जो भारत के अन्दर तथा विदेशों में व्यय करने होंगे और जिनका दायर राज्य तथा केंद्रीय सरकारों पर पड़ेगा।

(करोड़ रुपयों में)

	भारत में व्यय	मटलिंग क्षेत्र	डालर क्षेत्र	योग
भूमि का कृषिकरण	८२.७६	२१.६७	३१.६२	१३६.०५
विद्युत-वृद्ध निर्माण	३३.६५	१६.६२	२२.०८	६८.३५

(करोड़ रुपये में)

भारत में व्यय	मलिंग क्षेत्र	डालर-क्षेत्र	लोग
रसायनिक खाद	२५.८६	३०.४६	१५.२० ७१.५७
मछली-उत्पाद का विकास	३.४५	५.८८	१.१६ ५.१६

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य-सरकारों को भी खाद-संवर्धन निवारण योजना में अधिक राजस्व सहायता देनी होगी परन्तु इस समय क्या यह सम्भव है कि राज्य-सरकारों के राजस्व-विभाग यह सब कुछ कर सकेंगे । इस विषय में यह उचित होगा कि तात्कालिक कार्य को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को राजस्व सहायता दे और यह सहायता तब तक मिलती रहे जब तक ये योजनाएँ कार्यान्वित न हो जायें । भारत सरकार ने कई राज्यों को ऐसी सहायता दी है परन्तु इसमें भी अधिक सहायता की आवश्यकता है ।

निस्सन्देह, वर्तमान सरकार ने इस मस्यौदा को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं । जैसे भी सम्भव हो सका है दुर्लभ-मुद्रा प्राप्त करके विदेशों से अन्न भंगवाया है । समस्या का स्थायी हल निवारण के लिए बाढ़ों को रोकने की योजनाएँ हैं ही, साथ ही साथ सिंचाई भी होगी । नई भूमि कृषि के लिए तैयार जा रही है, यन्त्रीकरण हो रहा है । परन्तु इसी के साथ-साथ कृषिशोध की भी आवश्यकता है । गेरी करने की नई-नई विधियाँ हैं, नए-नए यन्त्रों का प्रयोग हो, उच्च प्रकार के बीजों का अनुसन्धान हो तथा वैज्ञानिक खाद हो । शोध के परिणाम कृषकों को बतलाए जाएँ जिससे वे उनके अनुसार काम कर सकें । गत २० वर्षों में कृषि-शोध पर केवल २३ करोड़ रुपये व्यय हुआ । इसमें हमें तनिक भी संतोष नहीं । शोध कृषि का एक आवश्यक अंग होना चाहिए । संतोष की बात है कि अब भारतीय-कृषि-शोध-परिषद् ने कृषि सम्बन्धी बायों की शोध करने के लिए सम्पूर्ण देश को समान भूमि तथा जलवायु के दृष्टि-कोण से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बाँट लिया है जिनमें समान जलवायु तथा उर्वरता की दृष्टि में रखते हुए शोध की जायगी और प्रचलित किया जायगा कि देश में अन्न की वृद्धि हो । ये प्रदेश इस प्रकार हैं :—

(१) गेहूँ प्रदेश, जिसमें पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा बरार और राजस्थान-सदर का गेहूँ उपजाये वाला कुछ भाग होगा ।

(२) चावल-प्रदेश, जिसमें आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य-प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मद्रास सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश में चावल की फसलों का अनुसन्धान होगा।

(३) मालाबार प्रदेश, जिसमें कर्नाटक, मद्रास, पश्चिमी घाट, मैसूर कुग, ट्रान्सवार तथा काचीन हैं।

(४) २६ प्रदेश, जिसमें भाँसी, मध्य प्रदेश तथा बरार, मध्य भारत की रियासतें, हैदराबाद रियासत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मद्रास, पूर्वी कर्नाटक का प्रदेश, बरोदा तथा मैसूर का कुछ भाग हैं।

(५) हिमालय प्रदेश, जिसमें कुमायूँ, गढ़वाल, नैनाल, भूटान, लहमना की पहाड़ियाँ, कुल्लू, चम्बा तथा काश्मीर राज्य सम्मिलित हैं।

इन प्रदेशों में कृषि की विशेष परिस्थितियाँ तथा कृषि क्रियाओं पर शोध की जायगी। इस प्रकार देश का कृषि विभाजन करने में कृषि-शोध पर ठोस कार्य हो सकेगा। परिणतु ने पशुपक्षिक तथा निरीक्षण और शोध की दृष्टि में भी देश का विभाजन किया है परन्तु उसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। कृषि शोध से हाल ही में तो नहीं परन्तु दूर भविष्य में खाद्य समस्या का एक मात्र स्थायी उपाय निहित है।

केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों के अतिरिक्त राज्य-सरकार ने भी इस समस्या को हल करने के लिए अपनी अपनी अलग-अलग योजनाएँ बनाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सिचाई सम्बन्धी एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है जिसने अनुमान पचास वर्ष में १६,६०,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिचाई की जायगी। इस योजना में ७६०० मोल लम्बी नहरें बनाई जाएँगी। अब तक सिचाई सम्बन्धी जो काम किया गया है उससे राज्य को २५००० टन अधिक अन्न मिलने लगा है। राज्य में अब कुल मिलाकर १६५६ नल कूप हैं 'परन्तु अधिक अन्न उपजाओ याजना' के अन्तर्गत ६०० और नल कूप बनाए जा रहे हैं। इनसे २,४०,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिचाई होगी जिससे ५४,००० टन अधिक अन्न उपजाया जा सकेगा। सरकार ने तकारी ऋण देकर तथा उत्तम बीज तथा ग्याद वितरण करने अन्न का उत्पादन

ये भी प्रयत्न किए हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है और परिणाम भी सन्तोषजनक मिले हैं।

प्रस्तुत समस्या यह है कि वर्तमान खाद्य संकट को दाल कर अभी देश को अन्न के मामले में आत्म-निर्भर कैसे बनाया जाय ? वास्तव में देखा जाय तो हमारा खाद्य-संकट केवल उत्पादन की समस्या ही नहीं है वरन् अन्न संग्रह और वितरण की समस्या भी है। अन्न के भाव ऊँचे होने के कारण सरकार आवश्यक मात्रा में उत्पादकों से अन्न-गुन्ती (Procurement) नहीं कर पाती। ऊँचे भाव होने से उत्पादक सरकार को अन्न न देकर चोरी से बेचने लगे हैं जिससे सरकार की राशन-पद्धति सफल न हो सकी। आवश्यकता इस बात की है कि अन्न का उत्पादन भी बढ़े और वितरण की विपमता भी भी दूर हो। अन्न सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के लिए मुनाफ़ और उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए जिससे विश्वसनीय आंक प्राप्त किए जाकर उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कोई योजना बनाई जा सके। जनता को भी चाहिए कि वह अन्न का उपयोग सीमित करे और अन्न नष्ट होने से बचाये। कहा गया है कि देश में १० प्रतिशत अन्न की कमी है। इसे पूर्ण करना कोई अधिक कठिन काम नहीं। अधिक अन्न उपजाकर, वितरण की विपमता दूर करके, अन्न को नष्ट होने से बचाकर तथा आवश्यकताओं का सीमित करके इस काम को सरलता से दूर किया जा सकता है। हमें अपनी सब शक्तियों को इस बात में जुटा देना चाहिए कि अन्न के मामले में देश विदेशों पर आश्रित न रह कर आत्मनिर्भर हो जाय। जब तक देश में अन्न या अन्न के राशन तथा मूल्य-नियंत्रण रहना आवश्यक है परन्तु राशन पद्धति का प्रबन्ध ईमानदारी तथा सन्तोषजनक रीति से चलना चाहिए। भारत जैसे देश में, जहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है राशन पद्धति में बढिनाइयाँ होना स्वाभाविक है। परन्तु तो भी इस बात का प्रत्यक्ष होना चाहिए कि चोर बाजारी, संग्रह तथा बेईमानी न हो। इसके लिए सरकार और जनता की सहयोग की आवश्यकता है—बिना दोनों के पारस्परिक सहयोग के यह काम सरल नहीं हो सकता। अन्न संग्रह करने की सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए जिससे अन्न सुरक्षित रखा जा सके। हमारी उपयोग सम्बन्धी किराओ में भी फेर-बदल की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम कम से कम

अन व्यय करें और सम्भवत उत्सर्ग पर अधिक अन्न काम मन लावें। प्रत्येक कार्य सरकार का ही करने का नहीं है। हम भी अपने कर्तव्य को समझें। सरकार कानून बना सकती है परन्तु उसको पालन करने सफल बनाना जनता का ही कार्य है। हम हर प्रकार से देश को अन्न में स्वावलम्बी बनाना बाछनीय है।

७—‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना

समस्या एवं समाधान

पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें “अधिक अन्न उपजाओ” के नाम पर भारी-भारी धन राशि व्यय करती रही हैं, परन्तु परिणाम अधिक संतोषजनक नहीं रहे हैं। १९४६-५० में इस योजना पर केन्द्रीय सरकार ने १३३२ करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा उसमें अगले वर्ष ३१७६ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार १९४३ से लेकर अब तक भारी-मारी राशि व्यय होती रही परन्तु अन्न उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई। कृषि-भूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ता रहा परन्तु अन्न की मात्रा न बढ़ी बल्कि कभी-कभी कम भी होनी गई। योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के क्षेत्रफल, प्रति एकड़ उपज तथा कुल उत्पादन की स्थिति इस प्रकार रही :—

	(१००,०००)		
	कृषि-भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (टन)	प्रति एकड़ उपज (पीएड)
१९३६-३७ से १९३८-३९			
की औसत	१५८'८	४०'६	५७७
१९४२-४३	१६८'०	४४'०	६०३
१९४३-४४	१६६'०	४५'०	६१२
१९४४-४५	१८३'०	४६'०	५६४
१९४८-४९	१८६'६	४८'०	५२३
१९४९-५०	१९५'६	४५'६	५२५

इन आँकड़ों से शत होता है कि इस योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु उत्पादन उस गति से न बढ़ा—इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रति एकड़ उपज कम होती गई। इसका भेद जानने के लिए रिज़र्व बैंक के कृषि विभाग ने बम्बई राज्य की ‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना की जाँच-

पड़ताल कर एव रिपोर्ट प्रकाशित की जिससे याजना सम्बन्धी निम्न बातें सात होती हैं —

(१) योजना के अन्तर्गत कृषि योग्य बजरा या पड़ती भूमि पर कृषि करने का प्रयत्न नहीं किया गया। जितनी भूमि पर युद्धपूर्व काल में कृषि होती थी उतनी ही भूमि पर कृषि होती रही।

(२) कुछ प्रदेशों में विस्तृत-कृषि अरक्ष्य की गई परन्तु ऐसा करने के लिए अधिकारियों ने रुड की खेती की जाने वाली भूमि पर अन्न उपजाना आरम्भ कर दिया था। इससे रुड की खेती पर उल्टा प्रभाव पड़ा।

(३) याजना के अधीन कृषि-भूमि का क्षेत्रफल सा बढ़ता गया परन्तु प्रति एकड़ उपज कम होती गई जिससे इस आन्दोलन में खर्च किये गए धन के अनुपात में उत्पादन न बढ़ाया जा सका। व्यय राशि के अनुपात में बाहुनीय परिणाम न मिलने के निम्न कारण रहे :—

प्रथम तो बात यह थी कि इस विशाल योजना के लिए सरकार के पास साधन सीमित थे और जो कुछ भी थे उनका सुचारु ढङ्ग से संचालन करके महत्तम उपयोग नहीं किया जा सका। क्षेत्र विज्ञान था जिसके अन्तर्गत भूमि की उत्पादन क्षमता के अनुसार साधनों का उपयोग न किया जा सका। कृषकों को सहायता देने के लिए सरकार के पास आवश्यक साधन न थे जिससे सभी लोगों को उन साधनों का लाभ नहीं मिल पाता था।

योजना के अधीन काम करनेवाले तथा काम करानेवाले प्रबन्धकों की संख्या कम थी और जो कुछ भी लोग थे वे लगन के साथ काम नहीं करते थे। अधिकांश लोग कार्यालयों में बैठे-बैठे काम करते थे जबकि उन्हें कृषकों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। ये लोग कार्यालयों में बैठे बैठे पाइलों की संख्या बढ़ाते रहे, परन्तु उत्पादन की ओर कोई ध्यान न दिया। बहुत से लोग तो अन्न को छोड़ अन्य सामग्री उपजाते रहे और उनकी अधिकांश शक्ति चोर-बाजारी आदि कार्यों में लगी रही।

सरकार के पास कोई ऐसा साधन न था जिससे उस समय यह पता लगाया जा सके कि व्यय राशि के अनुकूल उत्पादन भी मिल रहा है या नहीं। सरकार यह भी नहीं जान पाती थी कि वे कृषक, जो सरकार से इस योजना के

अधीन सहायता ले रहे हैं, उचित मात्रा में और उचित दक्ष का माल उतार भी कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार सरकार की अधिकांश शक्ति गृथा नष्ट होती रही।

सरकार की अधिकांश शक्ति इस योजना के विभाजन मात्र में ही समाप्त होती रही। सरकारी कर्मचारियों का औचित्य-अनीचित्य का बिलकुल ज्ञान न था। सरकार एक और तो नए-नए बुँए बनाने को प्रवृत्त होती जा रही थी और दूसरी ओर पुराने कुत्तों की मरम्मत की ओर बिलकुल ध्यान न था। इसी भाँति अनेक चीजें होती रही जिनसे अधिकांश साधन नष्ट होते रहे।

समुचित आयोजन एवं प्रबंध सम्बन्धी दोषों के कारण यह आन्दोलन स्थल न हो सका। योजना सम्बन्धी अन्य उप-योजनाओं का समूहिक क्रम भली प्रकार न बनाया गया। सरकारी विभागों में न पारस्परिक सहयोग था और न आवश्यक ज्ञान ही—प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी अलग-अलग नीति बनाकर काम करता रहा जिससे अन्धे परिणाम न मिले।

इन दोषों के अतिरिक्त कुछ वित्त-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी थीं। कृषकों को आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त धन-साहाय्य नहीं मिल पाती थी। श्रमिकों के पास पशुओं का अभाव था। वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वे अन्धे और उपयोगी पशु नहीं खरीद पाते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास दल तथा वृद्धि सम्बन्धी अन्य औजारों का भी अभाव था। ये वस्तुएँ उन्हें ऊँचे-ऊँचे दरों पर खरीदना पड़ती थीं और वह भी आवश्यकता के समय नहीं मिल पाती थीं।

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूमि का कटार, अपर्याप्त यानायात के साधन आदि अनेक ऐसी कठिनाइयाँ भी जिनके कारण इस आन्दोलन के अन्तर्गत अधिक अन्न उपजाया जा सका।

इस योजना के अन्तर्गत अधिक अन्न उपजाने के लिए हमारे पास कुछ सुभाव हैं जो यहाँ दिए जा रहे हैं:—

१. यह योजना केवल उन्हीं प्रदेशों में कार्यान्वित की जाय जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो या सिंचाई के अन्धे और उत्तम साधन उपलब्ध हों। सिंचाई के साधन मिलने से अधिक अन्न उपजाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। जिन स्थानों में यह योजना लागू की जाय वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का भली प्रकार अध्ययन करके एक समुचित

योजना और अन्य उप-योजनाएँ बना ली जाएँ। इन उप-योजनाओं का भिन्न-भिन्न विभागों के अधीन कर दिया जाय। इन सब विभागों में पारस्परिक सहयोग और सम्मेलन हों और सभी यात्राओं का एक सामूहिक धर्म बना दिया जाय। कृषकों की सहायता देने के लिए शिक्षित और समझदार शिक्षक रखे जाएँ जो प्रस्तुत साधनों का उपयोग करने में उनकी सहायता करें। पसल बोलने तथा काटने का काम वैज्ञानिक दृष्टि पर किया जाय। कई-कई गाँवों को मिलाकर एक इकाई निर्धारित कर दी जाय और इस इकाई का सामूहिक सहायता देकर सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय।

२. सरकार छोटे छोटे कृषकों का साग पर धन देकर अथवा अन्य आवश्यक वस्तुएँ देकर सहायता करे। इनका भुगतान लेने में सरकार किसी प्रकार की जबरदस्ती न करे वरन् पसल के समय अन्न-बखूनी करते समय भुगतान चुकले।

३. अन्न की उपज बढ़ाने के हेतु कृषि सुधार तथा कृषि के पुनर्निर्माण सम्बन्धी एक समुचित योजना तैयार की जाय। नई भूमि का तोड़कर कृषि के काम में लाया जाय। सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएँ और बीज तथा खाद के वितरण का समुचित प्रबन्ध हो। ऐतों की चकबन्दी की जाय तथा कृषि साग संगठन को बल दिया जाय।

अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य वस्तुओं की कृषि बन्द करके उस भूमि पर अन्न उदादि भी न पैदा किया जाय क्योंकि तब अन्य वस्तुओं की कमी होने लगेगी। इसके लिए तो यह आवश्यक है कि नई भूमि का ही कृषिकरण किया जाय। इन सुझावों से अन्न की पैदा बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। ऐसा करने से पहले सरकार को चाहिए कि यह देश के भिन्न भिन्न भागों में इस आन्दोलन सम्बन्धी जाँच-पड़ताल करके यह मालूम करले कि वहाँ मानवीय और भौतिक शक्तियाँ किस प्रकार मिलकर काम कर रही हैं। ऐसा करने से सरकार को यह ज्ञात हो जायगा कि वहाँ किन किन बातों का अभाव है और उस अभाव को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। यदि ऐसा करके एक संगठित योजना बनाई गई तो अत्यन्त ही इस योजना द्वारा अधिक अन्न उपजाया जा सकेगा।

८—कृषि का यन्त्रीकरण

हमारे देश में कृषि-उत्पादन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय कृषक कृषि कार्यों में प्राचीन, भद्दे और अयोग्य यन्त्रों का प्रयोग करते हैं। यह ठीक है कि ये यन्त्र उनके जीवन-स्तर के अनुकूल हैं परन्तु उत्पादन बढ़ाने में ये नितान्त निरर्थक ही हैं। आज भी, जब कि संसार में विज्ञान और यन्त्र-विद्या ने इतनी प्रगति कर ली है, भारतीय किसान गेत जोतने के लिए पुराने हल्लों पर, फसल काटने के लिए दराही पर और अन्न बरसाने के लिए प्राकृतिक वायु पर आश्रित बना हुआ है। इसके विपरीत संसार के अन्य प्रगतिशील देशों में, विशेषकर अमेरीका और रूस में, कृषि कार्यों के लिए यन्त्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा उन देशों की कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। उन्नत यन्त्रों का प्रयोग करके उन देशों की कृषि-उत्पत्ति में आश्चर्यातीत वृद्धि हुई है। भूमि का कृषीकरण करने में तथा जल से जल तक सभी कृषि-क्रियाओं में उन्नत और उत्तम यन्त्रों का प्रयोग होता है जिससे वर्तमान उत्पादन-धन्य भी कम हो गया है तथा समय और मानव-शक्ति भी बचत होती है। यन्त्रीकरण ने वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक भारी परिवर्तन करके वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा बना दिया है।

भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के विषय में प्रकार-प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय कृषि में उन्नत यन्त्रों का प्रयोग वांछनीय और आवश्यक है। उनका कहना है कि विज्ञान के युग में यन्त्रों का प्रयोग न करके देश की संपत्ति का पूरा दोहन सम्भव नहीं क्योंकि इन यन्त्रों के प्रयोग द्वारा ही देश का उत्पादन बढ़ाकर जनता का जीवन-स्तर उठाया जा सकता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का विचार है कि हमें अपने पुरातन हल-बैल को त्याग कर आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। ये लोग यन्त्रों के नाम-माय से ही डरने लगे हैं। उनके विचार में हमारे देश में कृषि का यन्त्रीकरण न आवश्यक है और न वांछनीय है। ये सोचते हैं कि कृषि में

यन्त्रों के प्रयोग से मानव शक्ति का हास होता है और बेकारी पैलती है। इस प्रकार के विपरीत विचारों से इस विषय में निश्चय करना कुछ कठिन ही है परन्तु फिर भी देश की उर्वर भूमि को देखते हुए, कृषकों की गरीबी को देखते हुए तथा देश की खाद्य समस्या को देखते हुए यह आश्चर्य नहीं जाता है कि इस विषय में कोई न कोई स्थायी मत निर्धारित किया जाय। इसने लिए पहिल हमें यह समझ लेना चाहिए कि क्या हमारे देश में कृषि के यन्त्रीकरण के लिए आवश्यक क्षत्र और सुविधाएँ उपलब्ध हैं? प्रधानतः कृषि के यन्त्रीकरण में हमें निम्नलिखित अनुविधाएँ हैं —

(१) हमारे देश में खेत छोटा और छिटेके हैं जिसमें उनमें यन्त्रों का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता।

(२) कृषि में यन्त्रों का प्रयोग करने से कृषि पर आधारित मजदूर-वर्ग विचलित होकर बेकार हो जायगा जिससे देश में एक और समस्या उठ खड़ी हो जायगी। दूसरे, जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में मजदूर मिल सकते हैं और उनकी मजदूरी को दर कम है तब तक यन्त्रों का प्रयोग करने इन्हें बेकार बनाने में कोई लाभ नहीं।

(३) भूमि के यन्त्रीकरण के लिए यन्त्र खरीदने में जितनी पूँजी की आवश्यकता होगी उतनी पूँजी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है।

(४) यदि यन्त्रों का प्रयोग आरम्भ भी कर दिया जाय तो समस्या यह है कि उनके लिए तैल शक्ति कहाँ से प्राप्त की जाय। इसके लिए फिर देश को विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

(५) देश में कुशल कारीगरों और मस्तित्रियों का भी अभाव है जो इन यन्त्रों का प्रयोग कर सकें और उनका प्रयोग कृषकों को समझा सकें। यन्त्रों की टूट पूट की मरम्मत कराने की सुविधाएँ हमारे पास प्राप्त नहीं हैं।

जहाँ तक खेतों के क्षेत्रफल का सम्बन्ध है यह ठीक ही है कि हमारे यहाँ खेतों का क्षेत्रफल छोटा है और इन खेतों में यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। रूस में, जहाँ कृषि का यन्त्रीकरण शिखर पर माला जाता है, खेतों का औसत क्षेत्रफल १६०० एकड़ है। इसी प्रकार अमरीका के खेतों का औसत क्षेत्रफल १५६ एकड़ और वेनेडा में २३४ एकड़ है। इसके विपरीत हमारे खेतों का

औसत क्षेत्रफल तीन एकड़ है। ऐसी स्थिति में यन्त्रीकरण करना कैसे सम्भव हो सकता है ? परन्तु फिर भी, चाहे हम यन्त्रीकरण करें या न करें, हम अपने गेहों को चक्कन्दी करके उनका क्षेत्रफल तो विस्तृत बनाना ही है क्योंकि ये रेत हमारे किसी भी काम के लिए अनाधिक है। इसका उपाय यह है कि सम्मिलित और सहकारी कृषि की प्रथा का पालन किया जाय। यदि छोटे छोटे कृषक अपने-अपने गेहों को मिला कर मिलकर कृषि करें तो यन्त्रीकरण की यह कठिनाई सहज ही में हल हो जायगी। तब कृषि में यन्त्रों का प्रयोग भरल ही नहीं बरन् आवश्यक हो जायगा। इस कार्य में यद्यपि कुछ समय लगेगा परन्तु भविष्य के लिए यह एक नीति बन जायगी। निश्चय ही, यन्त्रीकरण का प्रश्न हँसकर टालने का नहीं है, बरन् यह वह प्रश्न है जिस पर भारी भारत की भारी कृषि नीति अवलम्बित होगी। इस समय भी देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ यन्त्रों का सफल प्रयोग हो सकता है। ऐसे प्रदेशों में यन्त्रों का प्रयोग कर देना चाहिये। जमीन तोड़ने के लिये तो ट्रैक्टरों का प्रयोग आरम्भ हो ही चुका है। अब इस बात की आवश्यकता है कि कृषि के हर एक पालू में यन्त्रों का भरपूर प्रयोग किया जाय।

कृषि में यन्त्रों के प्रयोग को इसलिए टुकराया जाता है कि इनसे गेहों में काम करनेवाले लोग बेकार हो जाएँगे और देश में बेकारी फैल जायगी। यदि यह मानकर चलें कि यन्त्रीकरण के पश्चात् ४ व्यक्तियों का काम एक ही व्यक्ति कर लिया करेगा तो अनुमान है कि कोई ६,७०,००,००० व्यक्ति बेकार हो जाएँगे और तब इतनी बड़ी जन-संख्या के लिए कोई काम देना असम्भव रहेगा। विशाल उद्योगों में, जिनोंनेगत २० वर्षों में इतनी प्रगति की है केवल ३०,००,००० व्यक्ति ही काम पा सके हैं। अतः यदि यन्त्रीकरण के पश्चात् भारी जन-संख्या बेकार हो गई तो समाज का क्या हाल होगा ! हमरीक और रूस में तो कृषि के यन्त्रीकरण की इसलिए आवश्यकता हुई कि वहाँ काम करनेवाले लोगों की कमी थी। परन्तु हमारे देश की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। हमारे घाटों भूमिजों की कोई कमी नहीं तो फिर उन्हें बेकार क्यों रिया जाय ? अतः कहा जाना है कि जब तक देश में काम करनेवालों की कमी नहीं तब तक कृषि का यन्त्रीकरण करना अवांछनीय है। परन्तु समस्या पर यदि गम्भीरता

से सोचा जाय तो वस्तुस्थिति सरलता से समझी जा सकती है। यन्त्रीकरण से बेकारी फैलने का भय नितान्त भ्रमात्मक है। कृषि के यन्त्रीकरण से देश का आर्थिक विकास होगा जिसमें उत्पादन और वस्तु निर्माण के नए नए साधन, निम्न पड़ेंगे और इन्हीं उत्पादों में कृषि से प्रचलित जन-संख्या को रोजगार मिलता रहेगा। इससे अनिश्चित यह भी याद रखना चाहिए कि कृषि पर जन संख्या का भारी दबाव है। यद्यपि लोगों को कृषि पर काम मिला हुआ है परन्तु उनकी उत्पादन शक्ति बहुत नगण्य है। ऐसी स्थिति में ऐसे रोजगार से क्या लाभ जिसमें भरा पूरा उत्पादन न मिल सके। हमें केवल रोजगार पाने के उद्देश्य को लेकर ही रोजगार नहीं लेना है बल्कि अपने जीवन-स्तर को बढ़ाने तथा सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए रोजगार लेना है। इस दृष्टिकोण से तो आज भी पराक्त रूप में बेकारी है। यन्त्रीकरण ने यह बेकारी दूर होकर जनसंख्या अन्य साधनों में जुट जायगी। इसी के साथ साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि कृषि सम्बन्धी अनेक काम ऐसे हैं जिनसे कृषकों के स्वास्थ्य पर बहुत दबाव पड़ता है। कभी कभी तो कृषकों को दिन रात काम करना पड़ता है। यन्त्रीकरण से यह दोग दूर हो जायगा और कृषकों को अपने हास-परिहास के लिए तथा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पर्याप्त समय भी मिलता रहेगा। बहुत सी स्त्रियाँ और बच्चे भी कृषि कार्यों से छुट्टी पा जाएंगे। अतः किसी भी प्रकार से यन्त्रीकरण द्वारा बेकारी की समस्या से डरना निर्मूल है। एक बात और है। कृषि में काम करने वाले पशु कृषि में उत्पादित बहुत सी सामग्री स्वयं खा जाते हैं जिससे मानव आवश्यकताओं के लिए माल की कमी हो सकती है। यदि ट्रैक्टरों तथा अन्य मशीनों का प्रयोग किया जाय तो यह सामग्री मानवी आवश्यकताओं के लिए प्राप्त हो सकती है। अनुमान है कि अमरीका में कोई १,२०,००,००० घोड़े और खर हटायर ट्रैक्टरों से काम लिया गया जिससे लगभग ३,३०,००,००० एक्ड़ भूमि की बचत हुई जिस पर इनके लिए घास-चारा उपजाया जाता था।

कुछ लोगों का मत है कि यन्त्रीकरण से भूमि की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ती। उनका यहना है कि एक बार तो गहरी जोत से उत्पादन बढ़ जाता है, परन्तु यन्त्रों के द्वारा बार बार गहरी जोत करने से उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती।

अतः यन्त्रीकरण के द्वारा अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता जबकि इसी की हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। परन्तु यह बात भ्रमात्मक प्रतीत होती है। वास्तव में देखा जाए तो भूमि की उत्पादन-शक्ति केवल सटरी ज़ोन पर ही निर्भर न होकर अन्य अनेक कारणों पर निर्भर होती है। मिट्टी, जलवायु, मिलाई, बीज, खाद, कृषकों के काम करने की योग्यता और जलसिंचाई, वृष्टि का आयोजन आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर कृषि-भूमि की उर्वरता निर्भर रहती है। इन सब बातों का एक दूसरे के साथ भूमि पर प्रभाव डालना है और तभी उर्वरा शक्ति घटती बढ़ती है। अगर किसी देश में, जहाँ यन्त्रों का प्रयोग होता हो, उत्पादन अधिक हो और अन्य देश में, जहाँ यन्त्रीकरण न हो, उत्पादन कम हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पहिले देश का उत्पादन केवल यन्त्रों के प्रयोग के कारण ही अधिक है। अन्य अनेक कारण होते हैं जिनसे बजट से उत्पादन घटना-बढ़ना है। रूस में यन्त्रीकरण के पश्चात् कृषि की प्रति एकड़ उपज में काफी वृद्धि हो गई है जो निम्न अंशों में स्पष्ट होती है—

प्रति एकड़ उपज

	१९१३	१९३७
चना	६८ फंडरबेट	७४ फंडरबेट
कपास	८६ "	९८ "
चूरुन्दर	६७ "	७३ "
जई	२३.२ बुराल	३५.२ बुराल
जौ	१७.८ "	२१.२ "

इससे ज्ञात होता है कि यन्त्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु इस भी उत्पादन-वृद्धि और यन्त्रीकरण का अकेला कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहिए। तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि यन्त्रीकरण विस्तृत पैती के साथ ही सम्भव हो सकता है और विस्तृत पैती में साधारणतः उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन व्यय कम होता है। यही कारण है कि हमारे देश में स्थान स्थान पर होता कृषि-यन्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं क्योंकि इस प्रकार उनका उत्पादन व्यय कम होता है। दूसरे, यन्त्रों की सहायता से काम शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। विशेषतः उन देशों में जहाँ की श्रमशक्ति जल्दी-जल्दी

बदलती है समय की बचत का बहुत महत्व है। हमारे देश में ऋतु परिवर्तन के कारण यन्त्रीकरण का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

कृषि के यन्त्रीकरण में पूँजी की बहुत आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से कृषि यन्त्रादि खरीदे जा सकें। भारतीय कृषक का पास इतनी पूँजी नहीं कि वह इतने महंगे यन्त्र खरीद सके। वह तो स्वयं ऋण में जम लेता, ऋण में पलता है, और ऋणी हो मर जाता है। परन्तु यह कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है जिससे कारण यन्त्राकरण की लाभप्रद योजना में ही टाल दिया जाय। आजकल भारतवासी एक प्रकार के दूषित चक्र से घिरे जा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ा हुई है और इसलिए हम बचत नहीं कर सकते, और चूँकि हमारे पास पूँजी नहीं है इसलिए हमारी आर्थिक अवस्था हीन है। हमें किसी प्रकार से इस दूषित चक्र में तोड़ना चाहिए। इसका एक उपाय यह है कि कृषक उपभोग्य पशुओं से उपजाऊँ पूँजीगत माल भी पैदा करें। रूस और जापान ने इसी प्रकार अपनी आर्थिक गड़बड़ें पार की थीं। यहाँ अनियमित बचत योजनाएँ लागू की गई थीं तथा पूँजीगत माल उत्पादन करने पर कृषकों को बाध्य किया गया था। परन्तु कहा गया है कि ऐसा काम अपने देश में सम्भव नहीं हो सकता। यहाँ के निवासियों का अनियमित बचत करने की बाध्य करना ठीक नहीं होगा। तो दूसरा उपाय यह है कि विदेशों से ऋण लेकर यन्त्रादि खरीदे जाएँ। भारत सरकार ने विदेशों से ऋण लेकर यन्त्र खरीदना आरम्भ कर दिया है। आशा है इस काम का और अधिक प्रगति मिलेगी।

यन्त्रीकरण में हमारे लिए एक गड़बड़ यह होगी कि यन्त्रों को चलाने के लिए तैल शक्ति प्राप्त करने में हमें विदेशों पर आश्रित रहना पड़ेगा। परन्तु यह कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है जिससे मुलम्ताया न जा सके। तैल के स्थान पर अन्य प्रकार के दहन्य तैल द्वारा यन्त्र चलाए जा सकते हैं। चीनी की मिला में शीरा से स्प्रिट बनाकर भी मशीनों का चालू रखता जा सकता है। कुछ चीनी की मिला ने स्प्रिट बनाकर ट्रेक्टरों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। इससे हमारी कृषि के यन्त्रीकरण में काफी सहायता मिलती रहेगी।

प्रायः कहा जाता है कि हमारे कृषक अशिक्षित हैं। वे कृषि काया में यन्त्रों का समुचित प्रयोग करना नहीं जानते। दूसरे, हमारे यहाँ यन्त्रों को चलाने तथा

उनकी सम्मान करनेवाले मिलानों की भी कमी है। जहां यंत्रीकरण सरलता पूर्ण नहीं निभाया जा सकेगा। फिर यह बात भी निर्मूल है। यद्यपि हमारे कृषकों ने यंत्रों का प्रयोग नहीं किया है परन्तु इसका कारण यह नहीं कि वे अज्ञान में सीप भी नहीं सकते। यदि योजना बनाकर उन्हें इस काम की शिक्षा दी जाय तो यह प्रश्न हल हो सकता है। कारण में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वे विदेशी कर्मों से सम्मेलन करके कृषि यंत्रों के स्थानीय चरों जहाँ कृषकों को कम्पों का प्रयोग कराया जाय तथा उन्हें इस बात की शिक्षा भी दी जाय। सरकार ने हाल ही में ट्रेक्टर बनाने का कारखाना खोला है जहाँ से देश की ट्रेक्टरों की आवश्यकताएँ पूर्ण होगी।

जान में हम यही यह सकते हैं कि भारतीय कृषि का यंत्रीकरण करने के मार्ग में ओ कठिनाइयों से भरी जाती है वे निर्मूल और निरर्थक है। ठीक है कि पहिले कुछ सामुदायिक होनी परन्तु उनको सरलता और साधनानि से पार किया जा सकेगा है। छोटे-छोटे खेतों की सबसे बड़ी कठिनाई है। फिर कुछ लोगों को, ओ बेकार होगे काम भी सहाय करना पड़ेगा। पूर्ण की भी आवश्यकता होगी। इन सब कठिनाइयों से यंत्रीकरण के काम में कुछ प्रलम्ब हो सकता है परन्तु मोड़-से आयोजना और प्रयत्नों से यह काम भी भीत सम्पन्न होने लगेगा। यह निश्चित है कि कृषि का यंत्रीकरण बिना बिना देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन नहीं उपजाया जा सकेगा। आज देश में अल्पवय वृद्ध संघट है तथा बच्चे साल की भी कमी है। यंत्रीकरण के द्वारा इन दोनों समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। कृषकों की आय बढ़ जायगी तथा उनका सामाजिक जीवन-मतर भी अच्छा उठ जायगा। कृषि के यंत्रीकरण से हमारा साधन व्यवस्था के प्रयोग से ही नहीं होना चाहिए परन्तु खेत में, फसल काटने में, सिंचाई करने में, यातायात आदि सभी कृषि क्रियाओं में आधुनिक यंत्रों का भापूर प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि इस समय हम विषय में साक्षात् ही कोई विशेष उन्नति सम्पन्न नहीं हो सकती परन्तु यह निश्चित है कि दीर्घकालीन योजना में कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक है।

और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। परन्तु यंत्रों का वास्तविक प्रयोग करने से पहिले हमें कुछ और काम करने होंगे—जैसे यंत्रों की कार्यशैली को समझाने का प्रबन्ध करना होगा तथा कृषकों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करना होगा जिससे वह अपने पुरातन हल—बैल वगैरह यंत्रों का प्रयोग करने लगें। इसके अतिरिक्त यन्त्रीकरण के कुछ प्रयोग भी करने होंगे अन्यथा नासमझी से काम करने पर यंत्र हमारी कृषि को पातक भी सिद्ध हो सकते हैं।^१

^१ "Modern agricultural machines are very powerful tools which can either bring great benefits by appropriate and timely use, or if applied improperly and untimely, may cause irreparable danger to the soil."

६—कृषि की वित्त-समस्या

भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए सुभगटित वित्त-व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारतीय कृषक को कृषि-ऋण के गहन भार से इतना मुक्त कर देना होगा कि वह अपने जीवन-स्तर को उच्च बनाकर कृषि-कार्यों के लिए उचित तथा आवश्यक धन-राशि प्राप्त कर सके। परन्तु दुर्भाग्य है कि अब तक हमारे देश में इस विषय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ हम इस समस्या को वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाना चाहिए।

कृषि में वित्त की आवश्यकता दो अवसरों पर होती है। एक, उस समय होती है जब भूमि में कृषि-उत्पादन का कार्य आरम्भ किया जाय। उस समय कृषि-श्रौजार, बीज एवं खाद खरीदने तथा भूमि में आवश्यक सुधार करने के लिए धन-राशि की आवश्यकता होती है। दूसरे, उस समय होती है जब फसल को काटने के पश्चात् बेचने के लिए मण्डियों में ले जाया जाय। कृषि के लिए वित्त की आवश्यकताएँ प्रायः अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। बीज एवं खाद खरीदने के लिए तथा फसल काटने के लिए और लगानादि शुगाना करने के लिए धन की जो आवश्यकताएँ होती हैं वे अल्पकालीन कहलाती हैं। इन कामों के लिए कृषक जो ऋण लेता है वह माल बिकते ही तुरन्त लौटा देता है। कभी-कभी कृषक को कृषि-श्रौजार खरीदने तथा अपनी भूमि में छोटे-मोटे सुधार कराने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इन कामों के लिए वह जो ऋण लेता है वह अपेक्षाकृत कुछ लम्बे काल के पश्चात् चुकाता है। इस ऋण को मध्यकालीन ऋण कहते हैं। कभी-कभी कृषक को अपना कृषि-भूमि में स्थायी सुधार कराने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह अपनी जमीन को आइरन कर लम्बे काल के लिए ऋण लेता है, जिसे शनैः शनैः वार्षिक किस्तों में चुकाना रहता है। यह दीर्घकालीन ऋण कहलाता है।

जहाँ तक व्यापारिक बैंकों का प्रश्न है ये बैंक तो कृषकों को सीधा ऋण देकर सहायता करते ही नहीं हैं। ये बैंक कृषि उपज की जमानत पर रेगुल अल्पकालीन ऋण देते हैं और वह भा पसन व अरसर पर, अन्य अवसरों पर नहीं। इन बैंकों का कृषकों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। ये बैंक स्वदेशी बैंकों को ऋण देते हैं और स्वदेशी बैंक इस ऋण से कृषकों को सहायता करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक कृषकों की परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि ये बैंक कृषकों की सीधी सहायता करने लगें तो इसने लिए हमें कुछ विशेष परिस्थिति बनानी होगी। हुआड़ी बाजार को संगठित करना पड़ेगा जिससे हुआड़ियों की जमानत पर ये बैंक राशि उधार दे सकें। साथ ही साथ बाजारों में माल के नाप-तौल व साधनों में भी सुधार करने होंगे, उपज का संग्रह करने व लिए गादाम बनवाने होंगे, और उपज की किस्म में भी उत्थिति जरूरी होगी। तभी ये बैंक कृषकों को वित्त सहायता दे सकती हैं।

रिजर्व बैंक बनने के पश्चात् कुछ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होने लगा है कि इस बैंक को भी कृषि को वित्त सहायता में कुछ काम करना चाहिए। अतः हम यहाँ दूँगे कि रिजर्व बैंक ने इस विषय में क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक ने कृषि साख को संगठित करने के लिए जो काम किए उनका विचार तो हमें देश की विशेष परिस्थितियों को तथा अन्य ऐसे ही कृषि प्रधान देशों में केन्द्रीय बैंक की क्रियाओं को दृष्टि में रखकर करना होगा। रिजर्व बैंक का स्थापित करते समय निम्नलिखित यह बात सोची गई थी कि देश के केन्द्रीय बैंक का कृषि साख में विशेष कार्य करना होगा और इसी लिए इस बैंक में कृषि साख विभाग का निर्माण किया गया। कृषि साख विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख सम्बन्धी प्रश्नों को अध्ययन करके कृषि सन्थाओं को समय समय पर मार्ग प्रदर्शित करना है। इससे अतिरिक्त यह विभाग अपनी क्रियाओं द्वारा प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं में कार्य-संगठन भी करता है। सन् १९३५ में इस विभाग का स्थापित करने समय यह बात मुझाई गई कि यह विभाग ३१ दिसम्बर १९३७ तक रिजर्व बैंक के सचालक-मण्डल के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करेंगे, जिस प्रकार कृषि साख पर स्थिति की उन्नति करने के लिए कानून की धाराओं का सुधार, महानजद तथा

अन्य ऐसे ही लोगों पर लागू की जा सकती है। स्मरण रहे कि यह विभाग केवल कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने तथा कृषि-संस्थाओं को नए नए सुभाष देने के लिए ही बनाया गया था। आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय बैंक की भाँति इसको कृषकों को धन-राशि देने के लिए कोई वित्त-कोष नहीं सौंपा गया था। इसके बिना रिजर्व बैंक अन्य देशों की भाँति कृषि-साग्न-क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। इस विभाग ने भारत तथा अन्य देशों की कृषि-सार सम्बन्धी सामग्री इकट्ठा कर ली है। समय समय पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में कृषि विभाग ने सरकार के सामने सुभाष रखे हैं कि कृषकों को साल-सुविधाएँ देने के लिए साहूकारों और महाजनों, जो, जो हमारे देश में कृषि-साग्न के सबसे बड़े प्रदाता हैं, नियमबद्ध करना होगा और सहकारी साग्न आंदोलन का पुनर्निर्माण भी करना होगा। हमें देगना यह है कि इस विभाग ने क्या क्या काम किए हैं :—

सबसे पहिले अगस्त सन १९३७ में एक योजना तैयार की गई जिसमें भारतीय-केन्द्रीय-बैंकिंग-जॉन्-समिति के प्रस्तावों पर आधारित नये सुभाष रखे गए कि अन्य बैंकों की भाँति महाजनों को भी रिजर्व बैंक द्वारा निपजों की कटौती की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। परन्तु ये महाजन भारतीय-कम्पनी कानून के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखेंगे। महाजनों को कहा गया कि वे सुचारु लेखा-विधि का पालन करें तथा लेखा पुस्तकों की जॉन् समय-समय पर रिजर्व बैंक के अधिकारियों से करावें। योजना के अनुसार रिजर्व बैंक को उनके बैंकिंग कार्य की निरीक्षण करने का भी अधिकार मिलना था और महाजनों को भी अधिकार मिला कि उनका नाम रिजर्व बैंक की बैंक-पुस्तक में स्थीकार होने के पाँच वर्ष तक वे अपना लेखा रिजर्व बैंक में गोल सकते हैं। परन्तु उनकी रिजर्व बैंक में पूँजी जमा करने को तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता तब तक कि उनका अधि-देय तथा अभियानन-देय दोनों मिलाकर उनकी व्यापार में लगी पूँजी से पाँच गुना या उससे अधिक न हो। योजना के अनुसार केवल उन्हीं महाजनों के नाम रिजर्व बैंक की बैंक-पुस्तक पर लिखना निश्चित किया गया जिनकी पूँजी कम से कम १२ लाख रुपये हो। यह योजना

केवल पाँच साल के लिए निश्चित की गई। इस योजना के अनुसार इन महा-जनों को विपत्तियों के कटौती की वे सब सुविधाएँ प्राप्त होंगी, जो रिजर्व बैंक के तालिका बद्ध बैंकों को प्राप्त हैं। इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यही था कि कृषि-साख का सबसे भारी दूरण—महाजन—को कानून ने बाँधा दिया जाय जिससे महाजन मनमानी व्याज-दर पर रुपया उधार दे-दे कर कृषकों का शोषण न कर सकें। परन्तु महाजनों ने इस योजना का सर्वांश तो कांजीकार नहीं किया। उन्होंने परिकल्पना-व्यापार को तो छोड़ने का निश्चय किया परन्तु केवल बैंकिंग व्यापार तक ही सीमित रहने का स्वीकार न किया। मन् १९४१ में रिजर्व बैंक ने फिर 'मम्बई शराफ. एसोसिएशन' से प्रश्न किया कि बैंकिंग-व्यापार के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यापार का छोड़ कर रिजर्व बैंक में सम्बन्ध रखने के लिए कितने महाजन तैयार हो सकते हैं। 'शराफ. एसोसिएशन' ने यह मुझार रक्खा कि अगले पाँच वर्षों में शने शने बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग व्यापार अलग-अलग किए जा सकेंगे और उक्त योजनानुसार लेगा-बर्न भी रखकर लेखा पुस्तकों का निरीक्षण रिजर्व बैंक द्वारा कराया जा सकेगा; परन्तु एसोसिएशन ने ऐसे महाजनों की संख्या के टोच-टोच अर्द्ध रिजर्व बैंक के सामने प्रस्तुत नहीं किए। बैंक ने इस योजना को कार्यान्वित करना ठीक न समझा क्योंकि कृषकों के हित में यह बैंक तत्काल ही बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग व्यापार महाजनों द्वारा अलग कराना चाहता था। साथ ही साथ यह भी आश्चर्यक था कि महाजनों की अधिकांश संख्या इस योजना को स्वीकार करे। परन्तु सभी महाजन ऐसा करने को तैयार न थे और अधिकांश महाजनों को नियम-बद्ध किए बिना योजना के सहो और वांछित परिणाम सम्भव नहीं थे। इस प्रकार महाजनों को कानून में न बाँधा जा सका। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि महाजनों को किसी प्रकार नियमबद्ध किया जाय और सभी कृषि साख-क्षेत्र में आरक्षक सुधार हो सकेंगे।

दूसरा प्रयत्न जो रिजर्व बैंक ने किया वह है महाजन द्वारा कृषि-उपज के विव्रय करने के लिए वित्त-सहायता देने का। १९३२ में बैंक ने स्वीकृत महा-जनों के द्वारा कृषकों को उनकी कृषि-उपज की सार पर अग्रिम राशि उधार देने के लिए लिखे गए कृषि-बिजों को तालिका-बद्ध बैंकों के द्वारा योंही कटौती-

दर पर ही कटौती करना स्वीकार किया जिसने कटौती की वचत का लाभ कृषकों को मिल सके और वे अपना मान बचने तक आवश्यक धन-राशि प्राप्त कर सकें। अब तक कृषकों को महाजन से अत्यधिक व्याज-दर पर रुपया उधार लेकर अपनी उपज की विपणन होकर महाजन के हाथ बेचना ही पड़ता था क्योंकि महाजन इस प्रकार अपने ऋण की वसूली भी कर लेता था। बचार कृषकों का मान महाजन मन-माने भाव पर गरीब लेने थे। परन्तु रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया कि तालिका-बैंक बैंक रिजर्व बैंक की कटौती दर से २% अधिक लिया करेंगे और महाजन २ प्रतिशत अधिक मिलाकर धन राशि कृषकों को दिया करेंगे। इसका अर्थ यह होता कि कृषकों को रिजर्व बैंक का कटौती-दर से केवल ४ प्रतिशत अधिक व्याज-दर पर धन मिल सकता था और वे महाजनों के चपुलसे बच सकते थे। परन्तु तालिका-बैंक बैंकों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे महाजनों को कृषकों के लिए निश्चित दर पर ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। इस अनुविधा के कारण रिजर्व बैंक ने इस योजना को रद्दगत्त कर दिया। कृषकों को वित्त-सहायता देने में रिजर्व बैंक का श्रमता कदम सहकारी-रिता-ग्रामिणों में रहा। १४ मई १९२८ को रिजर्व बैंक ने एक नई योजना बनाई जिसके द्वारा सहकारी बैंकों को, जो कृषि-साधन का काम करते थे, रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर कृषकों को बीटने को सुविधा दी गई, परन्तु केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बैंक ने इस योजना के अनुसार लाभ उठाया। २ जनवरी सन १९४२ को रिजर्व बैंक ने दूसरी योजना बनाई जिसमें रिजर्व बैंक के कानून की धारा ११ (२) (ब) और ११ (४) (म) के अनुसार बैंक ने कृषि-उपज के विपणन के लिए कटौती-दर से १% कम पर सहकारी बैंकों को धन देना निश्चित किया जिसमें वे कम व्याज-दर पर रुपया उधार दे सकें। परन्तु बैंकों ने इसमें पूरा-पूरा लाभ न उठाया और केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बैंक ने २% पर रिजर्व बैंक से धन लिया और फिर ५% पर गरीब कृषकों को उधार दिया। सन् १९४४ में रिजर्व बैंक ने कृषि की वित्त-समस्या को भली भाँति समझा और कृषकों को फसल के समय में आवश्यक धन-राशि देने के लिए गत प्रण-पत्रों तथा व्यापार-पत्रों को विशेष अग्रहार (कटौती) देकर स्वीकृत करना निश्चय किया। परन्तु सहकारी बैंकों ने इस योजना से भी कोई लाभ न उठाया और केवल निम्न धन-

राशि ही कुछ प्रान्तीय सहकारी बैंकों ने प्राप्त की और यह धन राशि कृषि-वित्त के लिए बहुत कम रही।

वर्ष

धन-राशि (लाखों में)

१९४१-४२

६६.९

१९४२-४३

२७५.२५

१९४३-४४

३१७.१५

माच १९४६ तक रिजर्व बैंक ने उत्तर-प्रदेशीय सहकारी बैंक को तो ११% की एक विशेष छूट देकर श्रृण देना स्वीकृत किया था।

रिजर्व बैंक कानून की धारा ११ (४) (द) अभी तक कृषि साप के हित में भार्यान्वित ही नहीं हो सके हैं। इस धारा का नियमानुसार उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि देश में रजिस्टर्ड-गोदाम न हो। इस अभ्यास की पूर्ति करने के लिए नवम्बर १९४४ में रिजर्व बैंक ने एक आज्ञा पत्र निम्नलिखित कि देश में रजिस्टर्ड गोदाम स्थापित किए जाएं जहाँ कृषि उपज इकट्ठी की जाय, इसका ग्रेशन (Grading) किया जाय तथा उनका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाय। यह सोचा गया कि रजिस्टर्ड-गोदाम होने से बैंक कृषि को वित्त सहायता देने में अधिक काम कर सकेगा। परन्तु अभी तक हमारे देश में इस प्रकार के गोदाम नहीं बन सके हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कृषि के लिए वित्त-सहायता का कोई उचित और सगाठत प्रबन्ध नहीं है। आवश्यकता के समय कृषक विपन्न होकर महाजन की ओर ही देखता है और वही उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाता है। परन्तु अब तरह तरह के कानून बनने से साहूकारों और महाजनों की शक्ति कम होती जा रही है। सहकारिता आन्दोलन की अभी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसने द्वारा कृषकों की वित्त-सम्बन्धी सभी आवश्यकताएँ अच्छी तरह पूर्ण नहीं हो पाती। व्यापारिक बैंक केवल अल्पमालीन ग्राम ही दे पाते हैं और वह भी बहुत कम।

रिजर्व बैंक भी जैसा कि अभी कहा गया है, कृषि के लिए बहुत सीमित सहायता कर पाता है। अतः कृषि की वित्त समस्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे हल किए बिना कृषि और कृषक की उन्नति सम्भव नहीं। इस विषय में

सरकार को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए। औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की भाँति कृषि-वित्त कॉरपोरेशन स्थापित करने चाहिए जो म्यूर कृषकों को श्रृण दें तथा श्रृण देनेवाली अन्य संस्थाओं को भी समन्वित करें। गाँवों में ग्रामीण बैंक स्थापित करने चाहिए जो लोगों में रुढ़ता जमा लेकर उन्हें संचय करना सिखाएँ तथा उनको श्रृण देकर सहायता भी करें। मन्त्रालय की बात है कि ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिये में जॉन-रिडाल करने के लिए सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग-जॉन-कमेटी नियुक्त की थी। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है परन्तु रीढ़ है कि इस कमेटी ने अपनी मित्ताशियों में बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव तो रखे हैं परन्तु उनका उद्देश्य लोगों को केवल संचय सिखाना ही आँका गया है, ग्रामीणों को श्रृण देना नहीं। यही का अर्थ यह है कि कमेटी ने संचय-योजना पर अधिक ध्यान दिया है परन्तु वित्त-समस्या का मुलभाने के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखे हैं। कमेटी का कहना है कि “कृषि की वित्त समस्या को मुलभाने में काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसमें समय लगेंगा और दार्ढ्यमान योजना बनाने की आवश्यकता होगी।” वास्तव में बात तो ठीक है परन्तु केवल इतना कहने में मन्त्रालय नहीं हो सकता। करने की बात यह है कि कृषि का वित्त सहायता देनेवाली भिन्न-भिन्न संस्थाओं को समन्वित किया जाय तथा उनका कार्य-क्षेत्र भी बढ़ाया जाय। इसके लिए निम्न उपाय अधिक दिनकर मित्र हो सकते हैं :—

१. कृषि-वित्त-कॉरपोरेशन स्थापित किए जाएँ। एक अग्रिम भारतीय कॉरपोरेशन हो तथा गाँवों में भी अलग-अलग कॉरपोरेशन बनाए जाएँ।

२. सहकारी आन्दोलन की स्थिति सुधार कर उन्हें कृषकों के अधिक समीप लाया जाय। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा उनके माधन में भी कुछ बढोत्तरी की जाय।

३. माहूकार और सहायता पर कुछ प्रतिबन्ध लगा कर उन्हें केन्द्रीय बैंक के नियंत्रण में लाया जाय जिसमें वे मनमानो धाज-दख बचू न कर सकें। उनको कार्यप्रणाली भीथी और सरल बनाई जाय।

४. रजिस्टर्ड मोदारम स्थापित किए जाएँ तथा नाव-तील का एकमा

प्रबन्ध हो। यदि ऐसा होगा तो व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में कृषि की सहायता करने लगेंगे।

५. आर्मीय बैंक स्थापित किए जाएँ, जो न केवल लोगों से राशि ही जमा करें वरन् उनकी सहायता भी करें।

६. रिजर्व बैंक ने कृषि विभाग को धन-राशि देकर एक केंप बनाया जाय जिसमें ने वह कृषि की सहायता कर सके।

यदि ये सुझाव काम में लाये जाएँ तो कृषि की अन्तस्था बहुत लुब्ध सुधर सनेगी।

१०—भारत की पशु-समस्या

हमारे कृषि-प्रधान देश में पशुओं की उन्नति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कृषि और कृषक की उन्नति ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश-वासियों का जीवन-स्तर तथा देश भर की भावी उन्नति निर्भर है। भारतीय कृषि आदिकाल में बैलों पर आश्रित रही है—बैलों की रक्षायता में जेतों की जुताई, जुताई तथा पसल काटने का काम होता है। कुओं में पानी निकालकर बिनाई करने के काम में बैल ही काम आते हैं। दूध पी का व्यापार पशुओं के स्वास्थ्य तथा उनके रहन-सहन के स्तर पर निर्भर है। उन के लिए भेड़-बछ्वाँ रातू की सन्पत्ति कही जाती है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं व्यापार तीनों की समृद्धि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में पशुओं की उन्नति पर ही निर्भर है। परन्तु वेद का विषय है कि हमारे देश में इस समस्या की ओर अभी तक आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया है। गिल्ले दन-बारह वर्षों में तो सरकार ने कभी देश में पशुओं की गणना भी नहीं की जिससे यस्तुस्थिति का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। पशु-गणना के अभाव में यह कहना असम्भव है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या क्या है; उनका रहन-सहन कैसा है? सामान्यतः पशु दुर्बल और रोगी क्यों हैं? आदि, आदि। १९४० में एक बार एक छोटे पैमाने पर पशु-गणना करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उस समय भी देश भर की पशु-गणना न की जा सकी। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में उस समय पशु-गणना न हो सकी। अतः किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण देश की पशु-संख्या के विषय में जानना दुर्लभ है। एक विरोध ने अपनी एक पुस्तक में १९४० और १९३५ की पशु-गणना के आधार पर लिखा है कि उस समय देश भर में कुल मिलाकर लगभग १८,६०,००,००० पशु थे। उन्होंने उनका यह थोड़ा दिया है।

भैंस-गाय	४,५०,००,०००	घोड़े-गरज्वर	२२,००,०००
भेड़	४,७०,००,०००	गूँआर	२७,००,०००
बकरी	४,८०,००,०००		

इन आँकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि कृषि के काम में आने वाली भूमि पर प्रति १०० एकर के क्षेत्रफल में पशुओं का घनत्व इस प्रकार था।

बैल	२२.१	भैंस	७
गाय	६७	सूअर	६
मुर्गी	२६.३		

अन्य देशों को देखते हुए पशुओं का घनत्व हमारे देश में बहुत अधिक है और निम्ता का विषय भी है। गत वर्ष में लखनऊ में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की गाय और कृषि कांग्रेस में भाषण देते हुए सरदार दानारसिंह ने स्पष्ट किया था कि देश भर में पशुओं की कुल संख्या लगभग १७,६०,००,००० है। इन आँकड़ों के आधार पर प्रति १०० एकर कृषि भूमि (जो प्रति वर्ष कृषि के लिए बोई जाती है) के हिस्से में लगभग ७५ पशु आते हैं जबकि हालैण्ड में प्रति १०० एकर के क्षेत्रफल में ३८ पशु तथा मिश्र में २५ पशु हैं। हमारे देश में पशु संख्या जन संख्या का साई ५५% है। इस प्रकार भोजन के लिए जन और पशु—दाना पुरी तरह से आधित है। जन, पशु तथा भूमि में एक प्रकार का संघर्ष सा चल रहा है और आज, जबकि हमारे देश में खाद्य मकड़ है, इस समस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जन संख्या तो पेट भर भोजन पाती ही नहीं, पशु भी भूख और प्यास रहते हैं। वर्तमान परिस्थिति में पशुओं को पेटभर चारा नहीं मिलता और देश के अनेक भागों से चारे के अभाव के समाचार प्रति दिन मिलते रहते हैं। गत वर्ष गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में चारे का बहुत अभाव रहा जिससे सैकड़ों पशु मर गए। आज भी राजस्थान में चारे की कमी है। इससे पशुओं को निम्न श्रेणी के आहार पर जीवन बिताना पड़ता है जिससे पशुओं में रोग फैलते हैं और उनकी नस्ल गिरती जाती है। न के कृषि के उपयोग के रहते हैं और न उनसे आहार प्राप्त किया जा सकता है। आज भी हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में पशु तपेदिक, कोढ़ तथा अन्य रोगों में पड़े हुए हैं। कानूर इन्स्टीट्यूट में शोध करके बतलाया गया है कि पशुओं के दुबल और रोगी होने का मुख्य कारण उन्हें भोजन की कमी तथा पौष्टिक आहार का अभाव है। परन्तु जैसे-जैसे पशुओं की

नस्ल बिगड़ती जाती है तेसे हो तेसे कृषकों को अधिक संख्या में पशु रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पशु-समस्या एक कुचक्र में फँसती चली जा रही है। आज से लगभग २० वर्ष पहिले कृषि के शाही कमिशन ने अपने रिपोर्ट में व्यक्त किया था :—

“किसी भी जिले में पशुओं की संख्या बैलों की स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर रही है। कुशल पशुओं के पालन-पोषण की परिस्थितियाँ जितनी खराब होती हैं उतनी ही अधिक संख्या में पशु रखने की आवश्यकता होती जाती है। और जैसे-जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती है तेसे-तेसे उनका स्वास्थ्य, नस्ल तथा कार्यक्षमता कम होती जाती है।”

इस प्रकार यह निश्चित है कि जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती जाती है तेसे-तेसे उनकी कार्यक्षमता कम होती है और उनकी नस्ल बिगड़ती है। कृषि-भूमि पर दबाव पड़ने के कारण अन्न के अभाव में चारे की भी कमी होती है और चारे की कमी के कारण पशु हल्के, छोटे तथा रोगी हो जाते हैं। पशुओं की संख्या बढ़ने से गाय वस्तुआ की कमी होने लगी है क्योंकि जनसंख्या के साथ-साथ पशु-संख्या का दबाव भी भूमि पर बढ़ गया है। सूत्रा के समय में पशुओं की जंगलों में चराया जाता है जिसमें जंगलों की उपज भी कम होती जाती है। जैसे-जैसे पशु निर्बल तथा रोगी होत गए हैं तेसे-तेसे वे कृषि कार्य को कुशलता से नहीं कर पाते और कृषि की उपज कम होती जाती है।

हमारे देश की पशु-संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है। बिहार-उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में प्रति १०० एकड़ भूमि क्षेत्र में अनुमानित ८६, ४२ तथा ७५ पशु हैं जबकि हालैण्ड, मिश्र, चीन तथा जापान में अनुमानित ३८, २५, १५ और ६ हैं। इससे शान होता है कि हमारे यहाँ पशु संख्या का गन्वर कितना अधिक है। हमें ६ एकड़ भूमि पर एक जोड़ी बैल रखने पड़ते हैं जबकि मिश्र में प्रति १०० एकड़ पर ३ बैलों को रखना पड़ता है। १६३८-३६ में पंजाब में अनुमान लगाया गया था कि एक महीने में औसतन १० दिन बैलों को कोई काम नहीं रहता और वे निटल्ले रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देश के उत्पादन-स्तर को कम किए बिना तथा प्राप्य-यातायात के माधनों को भंग किए बिना आवश्यकता से अधिक पशुओं को कम करके

कृषि भूमि के समतुलन में ले आना चाहिए। परन्तु जब तक देश भर में पशु-गणना नहीं हो यह कहना कठिन है। कितने पशु अनावश्यक हैं। देश के विभाजन से पहिले अनुमान लगाया गया था कि ६ पशु अनावश्यक हैं। यह बात पशुगणना करके निश्चित कर लनी चाहिए। पशु समस्या का हल करने के निम्न उपाय हो सकते हैं —

१ देश भर की पशु गणना करके पता लगाया जाय कि भिन्न भिन्न प्रकार के कितने पशु देश में हैं। उनमें से कितने असमर्थ हैं और कितना का विशेष राग आदि है। इस गणना से यह पता लगाया जा सकेगा कि साधना की दृष्टि से कितने पशु देश में आवश्यक हैं।

२ पशुओं का अशक (Gradation) किया जाय जिससे उनकी नस्ल सुधारने का राई याचना बनाई जा सके।

३ पशुओं की नस्ल सुधारी जाय। इस काम में सरकार को योगदान देना चाहिए। जितने भी पुरे, रोगी तथा गराब नस्ल के पशु हों उनका निग हीन कर देना चाहिए। बृजइखाना में भी यह देयना चाहिए कि अच्छे और स्वस्थ पशु न काटे जाएँ परन्तु साथ ही साथ अपने चर्म-व्यापार को दृष्टि में रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि देश का चर्म व्यापार कम हो जाय। सरकार ऐसे पशुशाला बनाए जहाँ असमर्थ तथा रोगी पशु रह सकें। अन्य पशुओं के साथ इन्हें न छोड़ा जाय।

४ भिन्न भिन्न प्रकार के दो नर और मादा पशुओं को पशु संख्या बढ़ाने से रोका जाय। इस प्रकार नस्ल बिगड़ने का भय रहता है। परन्तु इसमें कठिनाई हो सकती है क्योंकि हमारे देश में अच्छे साँड़ नहीं हैं। सरदार दातारसिंह ने लगनऊ फार्म में कहा था कि हमें १०,००,००० साँड़ों की आवश्यकता है जबकि हमारे पास केवल १०,००० साँड़ हैं। ब्रॉस ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि-मंत्री एम० ए० शेरगानी ने लगनऊ में कहा था कि Cross breeding हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। दूसरे, यह व्यर्था भी बहुत है। इससे जानवरों का स्वास्थ्य गिरता है तथा उनमें रोग फैलते हैं। तीसरे, ब्रॉस ब्रीड करने वाले पशुओं को जितना अच्छा

आहार चाहिए वह हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। अतः मांस वीडिंग को, जहाँ तक हो सके, रोकना चाहिए।

५. हमारे देश में पशुओं की एक बड़ी समस्या उनके लिए चारे का अभाव रहता है। हम, अगर वास्तव में देखा जाय तो, आवश्यक चारे का ३ भाग भी अच्छी तरह नहीं पैदा करते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि की कृषिकरण योजना में नई भूमि को तोड़कर चारा पैदा किया जाय। चारागाहों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध हो। चारे को संग्रह करके रखने की सुविधाएँ हो तथा साल में दो बार चारे की फसल की जाय। चारा उगाने का काम गाँवों की पंचायतों को सौंपा जा सकता है। ये पंचायत गाँव के आस-पास की बेकार भूमि पर चारा पैदा करने का प्रबन्ध करें। यदि यह प्रश्न हल हो गया तो पशुओं का स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में आवश्यक वृद्धि होगी।

६. पशु चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो। इसके लिए गाँवों में पशु-चिकित्सालय हो जहाँ पशुपतियों को चिकित्सा का लाभ मिल सके। पशु-रोगों की राधा के लिए विशेषज्ञों का प्रबन्ध करके शोध-केन्द्र खोले जायें।

७. पशु-गन्ना के घनत्व को गंतुलन में लाया जाय। अधिक घनत्व वाले प्रदेशों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में पशुओं को भेजा जाय। इस के लिए सरकार पशुशाला तथा डेरी फार्म खोलने का प्रबन्ध करे।

८. सरकारी सॉइ-यर खोले जायें। इनमें अच्छी-अच्छी नस्ल के सॉइ हो और ये सॉइ आवश्यकता के समय पशुओं की सख्या बढ़ाने में योग दें।

यदि ऐसा किया गया तो देश की पशु-समस्या हल हो जायगी और कृषि, कृषक तथा जनता को भी आवश्यक लाभ होगा। कृषि-प्रधान देश की समृद्धि पशु-सम्पत्ति पर निर्भर होगी है। अतः कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषक को सुग्री करना होगा और कृषक का सुख पशु-सम्पत्ति पर निर्भर है।



११—कृषि-आयोजन की आवश्यकता ?

भारतीय कृषि की नई पुरानी समस्याओं का वर्णन पीछे किया जा चुका है। हमारी कृषि में कुछ ऐसी अनुविधाएँ, अइचनें तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हें दूर करना इतना सरल नहीं है जितना प्रायः समझा जाता है। इन कठिनाइयों के कारण ही देश ने कृषि साधना का पूरा पूरा निदोहन नहीं किया जा सका है जिससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो गई है तथा उत्पादन व्यय बहुत बढ़ गया है। इन दोनों कारणों से हमारे कृषक तथा समूचा ग्रामाण जनता गरीबी में ग्रसित होती जा रही है। अस्तु ! कृषि सम्बन्धी समस्याओं को अलग अलग करने नहीं सुलभाया जा सकता। इसके लिए तो सर्वाङ्ग पूर्ण कृषि योजना की आवश्यकता है जिससे अनुसार काम करते हुए कृषि साधना का पूरा-पूरा निदोहन किया जा सके तथा उत्पादन व्यय कम करके कृषकों की आय बढ़ाई जा सके और इस प्रकार उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सके। राष्ट्रीय आर्थिक आयाजन के किसी भी प्रोग्राम में कृषि-उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग धन्धों के विकास को सबसे पहिला स्थान मिलना चाहिए। आर्थिक आयाजन का अर्थ यह है कि देश की उत्पादक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाय कि जिससे सम्पत्ति का उत्पादन बड़े, पितरण में सुधार हो तथा जिससे सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊँचा बनाया जा सके। यद्यपि नहीं, आयोजन करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक देशवासी को काम करने के समान अगसर मिल सकें और सम्यक् समाज के अन्तर्गत उसकी न्यूनातिन्यून आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। राष्ट्रीय आयाजन-समिति ने अपनी योजना में देश का कृषि और कृषक को मुख्य स्थान दिया था। आयोजन करते समय केवल आर्थिक जीवन-स्तर के विषय में नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय पक्ष की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। योजना के लक्ष्य और उद्देश्य योजना कार्यान्वित करने से पहिले ही निर्धारित कर लेने चाहिए। हमारे देश ने कृषि-आयोजन में निम्नलिखित बातों को अग्रस्थ ध्यान में रखना पड़ेगा :—

१. कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और रहेगा। अतः इसको विशेष स्थान देना चाहिए। आयोजकों को देश की आर्थिक जनता के आर्थिक और सामूहिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि के साथ-साथ तन्मन्मन्धी उद्योग-धन्धों को उन्नत करने का प्रयत्न भी करना चाहिए जिससे कृषक अपने खाली समय में इन उद्योगों में काम करके अपना आय बढ़ा सकें।

२. कृषि व्यवसाय में पूँजी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषकों को बचत करना मिलाने के लिए सहायक बैंक होने चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो विशेष प्रकार की साप-भंस्थाएँ भी स्थापित करनी चाहिए जहाँ लोग अपनी बचत जमा कर सकें तथा जहाँ से वे ऋण भी ले सकें। कृषकों का ऋण जाने-बाले दीर्घकालीन ऋणों पर ४ प्रतिशत से अधिक तथा अन्य ऋणों पर ६-६ प्रतिशत से अधिक व्याज नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक का कृषि और कृषकों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

३. कृषि-योजना में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें देश में आर्थिक विपत्ति दूर होकर सन्तुलन उत्पन्न हो। हमारे देश के वर्तमान आर्थिक-संगठन में अधिराश जनता कृषि पर अवलम्बित है और बहुत कम लोग उद्योगों, यानायात तथा अन्य व्यवसायों पर आश्रित हैं। योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कृषि पर पड़ा हुआ भार कम हो। कृषि-क्रियाओं में ऐसी सुधार होने चाहिए कि जिसमें जन-शक्ति के साथ-साथ कृषि-उत्पादन भी बढ़ता जाय। सहायक उद्योग धन्धे भी स्थापित होने चाहिए जहाँ कृषि पर आश्रित लोग काम कर सकें।

४. नई भूमि को तोड़कर उसे कृषि के काम में लाना चाहिए। बिना भूमि का कृषिकरगु किए साथ तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार यह काम कर रही है परन्तु इसमें भी अधिक काम की आवश्यकता है।

५. सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सिंचाई के नए-नए साधन बनाए जाएँ तथा पुराने साधनों को विकसित किया जाय। सरकार को इस विषय में कृषकों के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने में धन तथा यांत्रिक सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

६. भूमि-व्यवस्था तथा कृषि क्रियाओं में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कृषक स्वतन्त्रता पूर्ण काम कर सकें। उसे किसान बाह्य शक्ति पर आश्रित न रहना पड़े। इसका अर्थ यह है कि जिस वायु मण्डल में आज हमारे कृषक जीवनयापन करते हैं उस वायु मण्डल में ही मुधार कर देना चाहिए।

७. कृषि भूमि का इस प्रकार वितरण होना चाहिए कि जिससे खान-पदार्थ तथा अन्य रूच्चा माल सतृप्तन व साथ आवश्यकतानुसार उत्पन्न किया जा सके। देश व विभाजन से उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने से हमें कच्चे माल की बहुत कमी हो गई है। कृषि योजना में रूच्चे माल के मामले में देश को स्वतन्त्र बनाने का आयाजन होना चाहिए। गहरी खेती करने व साधना का प्रयोग किया जाय। आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग किया जाय। उत्तम प्रकार के बीजा का प्रयोग हो तथा पयाप्त और रासायनिक खाद लगाई जाय। इन उपायों से कृषि की उपज बढ़ने लगेगी। सरकार को कृषक व लिए इन सब वस्तुओं की सुविधाएँ देकर उससे हाथ मजबूत करने चाहिए।

८. कृषि आयोजन में सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के प्रयत्न तथा साध होने चाहिए। जिन स्थानों में सिंचाई आवश्यक है वहाँ जल-साधनों को नियन्त्रित करके उचित रूप से काम में लाने का प्रबन्ध करना आवश्यक है। देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पानी के अभाव के कारण भूमि से बिल्कुल काम ही नहीं लिया गया है। राजस्थान में यदि सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय तो वहाँ की भूमि मनुष्य ही सोना उगल सकती है, परन्तु सरकार ने इस ओर प्रभावशाली ध्यान नहीं उठाया है। यदि योजना बनाकर नल वृष बनाए जाएँ और किसी भी प्रकार एक नहर का प्रबन्ध किया जा सके तो राजस्थान की भूमि देश के अधिकांश भाग को अन्न दे सकती है। बहुमुगल जल-योजनाएँ तो कार्यान्वित हो रही हैं परन्तु छोटी-छोटी योजनाओं को भी कार्यान्वित करना चाहिए। स्थानीय और छोटी छोटी सिंचाई की योजनाएँ गाँव पंचायतों को सौंप दी जानी चाहिए जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रबन्ध कर सकें।

९. भूमि स्तर तथा जगहों को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार को

अपने ऊपर लेना चाहिए । देश भर की भूमि की जाँच पड़ताल करके यह पता लगाना चाहिए कि कितनी भूमि कृषि-योग्य होने लगे भी कृषि के काम में नहीं आती । ऐसी भूमि को कृषि के काम में लाने का काम बहुत आवश्यक है । जंगलों का विदोहन करके उन्हें मरुस्थान बनाना भी आवश्यक है । जितने भी व्यक्तिगत जंगल हो उन सबको सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए । सरकार ऐसी सन-नीति बनाएँ जिसमें जंगलों का अधिकाधिक उपयोग हो सके ।

१०. कृषि-मजदूरों की स्थिति सुधारने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इन मजदूरों का शोषण बन्द करके उन्हें सामाजिक-मरुता-योजना का लाभ देना आज बहुत आवश्यक है । न्यूनातिन्यून मजदूरी का प्रबन्ध करके इनके जीवन-स्तर को उठाने का प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण है ।

११. कृषि अन्य वस्तुओं के यातायात की सुविधाएँ देकर उन्हें मण्डियों में बेचने का प्रबन्ध करने की व्यवस्था कृषि-योजना में आरम्भ होनी चाहिए । आजकल इन बातों की बहुत अमुविधाएँ हैं । इसके लिए योजना में संचालित-बाजार (Regulated Markets) स्थापित करने चाहिए । कृषकों को मण्डियों के भाव समय-समय पर मिलते रहें । इसकी भी व्यवस्था योजना में करनी चाहिए ।

१२. योजना-अधिकारियों को एक निश्चित मूल्य-नीति निर्धारित करनी चाहिए जिसमें कृषक न्यूनातिन्यून तथा अधिकाधिक मूल्यों की सीमाएँ जानता रहे । सरकार को चाहिए कि वह कृषि पदार्थों का मूल्य स्थायी बनाने का प्रयत्न करे । न्यूनातिन्यून तथा अधिकाधिक सीमाएँ निश्चित की जाएँ और फिर सरकार देवे कि इन सीमाओं से नीचे या ऊपर मूल्य का उच्चावचन न हो । कृषि की उन्नति के लिए मूल्यों का संचालन एक नितान्त आवश्यकता है । मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ कि जिससे कृषक व्यापार तथा अन्य बच्चा माल सभी वस्तुएँ उपजाता रहे । कहीं ऐसा न हो कि व्यापार के भाव अपेक्षा-कृत ऊँचे हो या अन्य वस्तुओं के भाव ही ऊँचे हों । यदि ऐसा हुआ तो कृषि-उत्पादन अधूरा रहकर एक-पक्षी बन जायगा । कृषि उत्पादन में संतुलन होना चाहिए ।

१३. योजना में एक ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए कि जिसके अनुसार

ग्रामीण जनता को शिक्षा तथा मस्तिष्क सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त होती रहें। योजना के अंतर्गत शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गाँवों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली आरम्भ हो और आवश्यकतानुसार माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय। ग्रामीण शिक्षा का आयोजन इस प्रकार हो। कि उसमें शारीरिक श्रम का यथेष्ट स्थान मिले और विद्यार्थी प्रत्येक शारीरिक श्रम का योग्य बन सकें। इससे लिए विश्वविद्यालय कमीशन के सुझाव बहुत उपयोगी हैं कि देश में ग्राम्य-विश्वविद्यालय खोले जाएँ। सरकार को इस आरंभ नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा देशवासियों के दृष्टिकोण में मूल परिवर्तन करके ही कृषि को उन्नत बनाना सम्भव है। इससे लिए एक बृहद् योजना बननी चाहिए।

कृषि आयोजन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे कृषि और उद्योग दोनों में समुचित उत्पन्न करके देश के मानवाय और भौतिक साधना का अधिक से अधिक प्रदोहन किया जा सके। कृषि के विकास के साथ साथ छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और एक की उन्नति दूसरे के विकास पर आश्रित है। कभी कभी कहा जाता है कि कृषि और उद्योग दोनों में से किसी एक का ही उन्नत किया जा सकता है और किसी एक के विकास को ही पर्याप्त पूँजी मिल सकती है इसलिए किसी एक का ही विकास होना चाहिए। परन्तु यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। दोनों का ही विकास आवश्यक है परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि कोई समुचित योजना बने। कृषि और उद्योगों में होने वाला प्रतियोगिता का रोग को ऐसा प्रबंध किया जाय कि जिसमें उत्पादन, उपभोग, पूँजी, प्रिनियोग आदि सभी के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने की दार्पकालीन और अल्पकालीन योजनाएँ बनाई जा सकें। लक्ष्य बनाकर निश्चित समय में उन्हें प्राप्त करने के पूरे-पूर प्रयत्न होने चाहिए। इस आरंभ के उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पंच-वर्षीय योजनाएँ बनाकर विकास होता रहा है। योजना सरकार बनाने परन्तु उस योजना के साथ जनता की सहोदरता तथा सहभाग होना चाहिए क्योंकि बिना जन सहभाग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

१२—पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान

योजना कमीशन ने हमारी कृषि का महत्व समझ कर अपनी 'पंचवर्षीय योजना' में इसको विशेष स्थान दिया है। कमीशन ने साधर्म्य से बढ़ने वाली हमारी जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे खाद्यान्न तथा कच्चे माल की माँग और पूर्ति में संतुलन बनाया जा सके। गत कुछ वर्षों से हम अन्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे हैं परन्तु इस प्रकार किसी देश का काम सदैव नहीं चल सकता। अतः योजना के अन्तर्गत देश को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार उपनिर्वाह पर अगले पाँच वर्षों में इस प्रकार राशि व्यय की जायगी :—

(फरोड़ रूपयों में)

दो वर्षों में मिलाकर पाँच वर्षों में मिलाकर
(१९५१-५२) (१९५१-५६)

कृषि	६०'८	१३६'६
पशु व्यवस्था, पशु चिकित्सा तथा डेरी-स्थापन	६'७	२२'५
वन	३'२	१०'१
सहकारिता-विभाग	३	७'२
मछली उद्योग	१'४	४'४
ग्रामीण विकास	४'०	१०'६
योग	७६'१	१६१'७

योजना के अन्तर्गत कमीशन ने अपने लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं कि पाँच वर्ष के पश्चात् योजना पूर्ण होने पर ७२,००,००० टन अधिक अन्न; २१,००,००० अधिक पटसन की गाँटें; १२ लाख अधिक रुई की गाँटें;

३,७५,००० टन तिलहन और ६,६०,००० टन अधिक चीनी उत्पन्न हो सकेगी । इन लक्ष्यों का व्यौरा प्रत्येक राज्य में अलग अलग इस प्रकार दिया गया है—

(हजारों में)

	अन्न	पटसन	रूई	तिलहन	चीनी
	४०० पाँड की टनों में		३६२ पाँड तोल की गाँठों में		टनों में
आसाम	३११	४४०	५०
बिहार	८७६	३६०	...	८५	५०
बम्बई	३६७	.	१६८	६३*०	३४
मध्यप्रदेश	३४७	..	१२८	२७*०	...
मद्रास	८३४	...	२१८	१४२*०	७८
उड़ीसा	२६५	२००
पंजाब	६५०	...	७६	...	५७
उत्तरप्रदेश	८००	३३०	४६	६१*०	४१०
पंजाब गाल	७६७	७००	११
हैदराबाद	६३३	..	८८	४६*०	...
मध्यभारत	३००	...	६१	६*५	...
मैसूर	१५६	..	७५
पूर्वी पंजाब —					
रियासती सघ	२४६	...	५६
राजस्थान	८६	...	७५
सौराष्ट्र	६४	...	१५६	१५*०	...
ट्रान्समोर-					
कोचीन	१४१
अन्य राज्यों में	२६०	...	१७
योग	७२०२	२०६०	१२००	३७५*०	६६०

इसमें शान होता है कि योजना कमीशन ने अपना दृष्टिकोण नितना विस्तृत बनाया है और कितनी व्यापक योजना रीकार की है। देश के प्रत्येक भाग में कृषि के विकास की व्यवस्था की गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने सिंचाई को विकसित करने, खाद तथा अन्य दैर्घानिक साधनों का प्रयोग करने, उत्तम कोटि के बीज प्रयुक्त करने तथा भूमि के शृणीकरण की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का लोरी इस प्रकार है—

अधिक क्षेत्र जो अधिक अन्न-उत्पादन योजना के अनुसार प्रयुक्त होगा।		अधिक अन्न-उत्पादन जो योजनानुसार प्रयुक्त होगा।	
(१०० एकड़)		(१०० टन)	
१. बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा	८,७१२	२,२७०	
२. छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा	७,६२१	१,६३२	
३. भूमि-सुधार तथा शृणीकरण की योजनाओं द्वारा	७,४०५	१,५२४	
४. खाद तथा अन्य रसायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा	...	४८८	
५. उत्तम कोटि के बीज-वितरण की योजना द्वारा	...	३७०	
६. अन्य योजनाओं द्वारा	...	५२०	
योग	२३ ७३८	७,२०२	

कमीशन ने यह भली भाँति समझ लिया है कि देश की शृण-व्यवस्था और समष्टि में कुछ ऐसे मूल दोष हैं जिनके कारण शृषि की उन्नति नहीं हो सकी है। योजना कमीशन ने इन दोषों को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक जिले को कई-कई विकास-प्रदेशों में बाँटा जाय। प्रत्येक विकास-प्रदेश में २५ से ३० हजार की जनसंख्या वाले ५० से ६० तक गाँव ह। इन प्रदेशों का अलग-अलग संगठन किया जाय। प्रत्येक विकास प्रदेश एक विकास-अफसर के प्रबन्ध में रहे। ये अफसर कृषि, सहकारिता तथा पशु विभागों का काम संगठित करें।

इस अपसर के नीचे कुछ ऐसे कार्यकर्त्ता हों जो ५ या ६ गाँवों का दायित्व लें। इनके नाम की देख भाल तथा धन राशि सम्बन्धी व्यवस्था 'सहकारी केन्द्र' में, जो उस प्रदेश में स्थापित किया जाय, सौंप दी जाय। प्रत्येक जिला एक जिला-कमेटी के अधीन हो। इस कमेटी में विकास विभागों के वायव्यता तथा अन्य विशेषज्ञ हों, जिलाधीश इसका अध्यक्ष रहे। जिलाधीश की सहायता को जिला-विकास अपसर रहें। यह जिला कमेटी नीति निर्धारण का काम करे और विकास प्रदेशों का काम देखे भाले। एक एक राज्य में जिला विकास काम करने रहता जाय और यह राज्य के हुए सब धन नाम की देख भाल करे। कमीशन का विचार है कि योग्य कर्मचारियों के अभाव के कारण यह योजना एक साथ ही सारे देश में लागू नहीं की जा सकती। अतः इस योजना की पहिले उन राज्यों में लागू किया जाय जहाँ वर्षा अच्छी होती है और मिचाई के आशयक साधन भी उपलब्ध हों। इस प्रकार यह योजना धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू कर दी जाय। कमीशन की यह योजना वास्तव में सफल है। कमीशन ने भूमि-व्यवस्था का सुधार करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई जमींदारी-जागीरदारी उन्मूलन योजनाओं का स्वागत किया है और कहा है कि इससे भूमि की उन्नति में काफी योग मिलेगा।

योजना में सहकारिता के सिद्धान्त पर गाँवों का प्रबंध करने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी रूप पर अधिक जोर दिया गया है। कमीशन का मत है कि सहकारी रूप के लिए भूतत्ति रूपों की भूमि को मिला लेना चाहिए। अपनी अपनी भूमि पर उनके अधिकार रहें परन्तु वे रूप कामों को सब मिल कर करें। यह योजना उन्हीं गाँवों में लागू की जाय जिनमें कम से कम २/३ भूतत्ति रूप, जिनके पास गाँव की कम से कम १/२ भाग कृषि भूमि हो, राजी हो जाएँ।

कृषि-मजदूरों की स्थिति सुधारने के विषय में योजना कमीशन का विचार है कि सहकारिता के आधार पर कृषि करने तथा सहकारी गोपधन्यायों के बनने से उनकी अवस्था में अग्रगण्य सुधार हो जायगा। जब तक ऐसा संगठन कार्यान्वित किया जाय तब तक के लिए योजना कमीशन ने राज्य सरकारों को निम्न सुझाव दिए हैं :—

१. जिन प्रदेशों में कृषि-मजदूरी की मजदूरी कम है और स्थिति बहुत खराब है वहाँ न्यूनानिम्न मजदूरी कानून (१९४८) को लागू कर दिया जाय।

२. भूमि की कृषीकरण योजना में नई भूमि को तोड़कर कृषि-मजदूरी को बसाया जाय जिस पर वे कृषि करने लगें।

३. उनके रहन-सहन की स्थिति सुधार कर उनका सामाजिक स्तर उठाने के प्रयत्न किए जाएँ।

कृषि के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए वर्मेशन में छोटी बड़ी अनेक जल-योजनाएँ निश्चित की हैं। इनको पूरा करने के लिए योजना में ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। योजनानुसार वर्ष का चोरा इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	अधिक-भिन्नित क्षेत्र (एकड़ों में)	अधिक निम्न- उत्पादन (बिलोवाट में)
१९४०-४१	६६	१५,४६,०००	१,४४,०००
१९४२-४३	११२	२७,१०,०००	३७३,०००
१९४३-४४	१००	४४,२४,०००	८,८६,०००
१९४४-४५	७७	६७,२४,०००	१०००,०००
१९४५-४६	५३	८८,६२,०००	११,२४,०००
अन्त में	...	१,६५,०१,०००	१६,३४,०००

योजना के प्रथम भाग में, जिसमें कुल मिलाकर १४६३ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है, केवल उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनके द्वारा अल्पकाल में ही व्यापक उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। योजना में प्रस्तावित नदी-न्यायी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी अगले १५ वर्षों में पूर्ण होने की आशा है। जनता का भविष्य-योजना में सहयोग तथा समर्थन बढ़ाने के लिए कमीशन ने प्रस्ताव किया है कि नहरें आदि बनाने के लिए जहाँ अनुशुल धन की आवश्यकता पड़े वहाँ पर प्राप्तीय लोगों को काम पर लगाना चाहिए। इससे उन्हें काम भी मिलेगा और इन योजनाओं में उनका समर्थन भी प्राप्त होगा।

योजनानुसार कृषि की उन्नति होने से आशा है कि सामान्य जनता को अधिक भोजन तथा उद्योगों को अधिक बचा माल मिल सकेगा । तब अन्न आयात करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी । अनुमान है कि योजना सफल होने पर प्रति व्यक्ति १४५ ग्राम भोजन मिल सकेगा जबकि आज १० ग्राम भोजन प्रति बालिग के हिसाब से ही प्राप्त है ।

१३—भारत में औद्योगीकरण की समस्या

भारत की अनेक आर्थिक समस्याओं में से एक मूल समस्या यह है कि देश की आर्थिक विपन्नता को दूर करके कौटिल्य-कौटिल्य देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत किया जाय। जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिए देश की राष्ट्र-समृद्धि में न्यूनानिम्न दो गुणों वृद्धि करनी होगी।^१ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि-क्षेत्रों का व्यवस्थित करना होगा, मजदूर-वर्गों का विदोहन करके उनका सदुपयोग करना होगा तथा देश के छोटे बड़े सब प्रकार के उद्योगों का संस्थापन तथा पुनर्संरचना भी करना होगा। पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष है कि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रही और ज्यों-ज्यों जनसंख्या में वृद्धि होती गई कृषि व्यवसाय दीर्घ और अचल होता गया एवं परिणामस्वरूप भारत में दुर्भिक्ष, बेकारी तथा आर्थिक विपन्नता का प्राधान्य हो गया। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश का आर्थिक कलेवर सुदृढ़ हो जिसके अनुसार अन्न-उत्पादन में स्वावलम्बी होने के अनिवार्य देश में भिक्ष-मिश्र प्रकार के छोटे बड़े तथा माध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों का निर्माण किया जाय, जिसमें लगभग आधी जनसंख्या का भार कृषि में उठ जाय और देश स्वावलम्बी होने के साथ-साथ राष्ट्र समृद्धि में भी वृद्धि हो। देश के आर्थिक कलेवर को उन्नत तथा सन्तुलित करने के लिए देश का औद्योगीकरण अनिवार्य है जिसके बिना सामान्य जनता की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देश का औद्योगीकरण आवश्यक है। आज के युग का तो नारा ही यह हो चला है कि "औद्योगीकरण करो अन्यथा नष्ट हो जाओ" (Industrialise or Perish)।

हमारे देश में औद्योगीकरण का क्षेत्र विशाल है। औद्योगिक साधनों की भी कोई कमी नहीं परन्तु अब तक इन साधनों का विदोहन करके उपयोग ही नहीं किया गया। आज औद्योगीकरण की नितांत आवश्यकता हो चला है।

कृषि के, जो हमारे देश का प्रधान व्यवसाय माना जाता है, विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए भी औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। जैसा कि पिछले प्रष्टों में बताया जा चुका है हमारे आर्थिक बलेतर का मुख्य आधार—कृषि बहुत ग़रब और हीन दशा में है। इसका कारण यह है कि इस पर जनसंख्या का भारी दबाव है। देशवासियों का व्यवसाय के अन्य साईं मत न होने के कारण कृषि पर ही आश्रित रहना पड़ता है। यदि देश में उद्योग स्थापित किए जाएं तो कृषि पर आश्रित लोगों का एक अन्य व्यवसाय भी मिल सकता है और कृषि का भार भी कम हो सकता है। इससे अतिरिक्त उद्योगों के द्वारा कृषि मशीनों का अधिक शक्तिशाली उन्नत प्रकार का यन्त्र मिल सकते हैं, यातायात की सुविधाएँ मिल सकती हैं तथा कृषि निगमों का सम्बन्ध करने के लिए वैज्ञानिक साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। आज अनेक उन्नत देशों के अनुभव हमारे सामने हैं कि उद्योग किस प्रकार उद्योगों का उन्नत बनाकर कृषि को उत्थान की। इन सब देशों में पहिले बेकारी की समस्या आई और इसे दूर करने के लिए उन देशों ने उद्योगों का निर्माण तथा पुनर्संरुद्धन किया^१। उद्योगों के बनने से भ्रमिका की माँग बढ़ती है और भ्रमिकों की माँग बढ़ने से उनकी मजदूरी भी बढ़ने लगती जिससे उनकी जीवन स्तर ऊँचा बनेगा। देश का औद्योगिक विकास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आज के युद्ध प्रसिद्धी के समय में उद्योगों के बिना शान्ति शान्ति पुनार रहा है परन्तु फिर भी हम किसी प्राकृतिक दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः ऐसी रणनीति का बनाने के लिए देश में औद्योगिक कारखाने स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। इन बातों से स्पष्ट है कि हमारे देश का औद्योगीकरण आवश्यक है नही परन्तु अनिवार्य भी है। उद्योगों से देश की आर्थिक व्यवस्था में अनुनय आयगा और देशवासियों का उत्थान होगा। किसी भी आर्थिक आर्थिक में औद्योगीकरण का उचित स्थान मिलना चाहिए।

^१ १० मण्डेलनू द्वारा लिखित 'दो इण्डस्ट्रियलाइजेशन ऑफ़ बैकवर्ड एरियाज' : पृष्ठ ३

प्राकृतिक गैस हमारे यहाँ नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ शक्ति अभाव है। हिमालय की गर्म भर बहने वाली नदियों में अपार जल शक्ति छिपी पड़ी है परन्तु दुर्भाग्यवश इसका विदोहन करके उपयोग नहीं किया गया है। यदि प्रयत्न किए जाएँ तो गन्ने के शीरे से छिप्रट तथा बोंयला स गैस तैयार की जा सकती है। पन बिजली बनाने के लिए सरकार ने काम आरम्भ कर दिया है। नादया की बहुमुखी योजनाओं के अन्तर्गत यह काम चालू है। आशा है देश भर का पर्याप्त पन बिजली मिल सकेगा।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे उद्योगों में बनाए गए माल की खपत हमारे यहाँ हो सकेगी? इसने लए हम अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हमारी अपार जनसंख्या है—उसने भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर हैं। तो क्या ऐसी जनसंख्या में हमारे माल की खपत नहीं होगी? यह ठीक है कि अभी हमारे देशवासियों की गरीबी है और इस योग्य नहीं हैं कि ऊँचे स्तर का माल खराद सकें। परन्तु यदि सरकार प्रयत्न करे सगाठत आर्थिक नाति बना कर उस पर चले तो हम लागा का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। पर प्रणाली में कुछ फेर बदल करने लोगों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूसरे, अन्य देशों की भाँति हम भी अपना पक्का मान विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। अतः खपत की समस्या का लकर हम औद्योगीकरण से विमुक्त नहीं होना चाहिए।

औद्योगीकरण की सबसे बड़ी समस्या है—पूँजी। जहाँ है हमारे देश में पूँजी का अभाव है और हमारा देश की पूँजी समुचित है, परन्तु यह बात संधा सत्य नहीं। देश में सम्पत्ति का कोई अभाव नहीं परन्तु काटनाई यह है कि यह सब सम्पत्ति दबी पड़ी है। अगर हमारे देश की मुद्रा मण्डी को संगठित किया जाय और दबी हुई सम्पत्ति का निकालने के लिए सरकार विश्वसनीय उपाय करे और जनता को दिग्गदे कि देश में वास्तविक औद्योगीकरण हो रहा है, तो यह सम्पत्ति पूँजी का रूप लेकर देश के हित में लगाने के लिए निजाली जा सकती है। वास्तव में देखा जाय तो देश की पूँजी समुचित नहीं बरन् पूँजीपति भय राष्ट्रे हुए हैं। उन्हें सरकार के प्रति, सरकारी नीति के प्रति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं है। हाल ही में जिस तेजी से जनता ने सरकारी श्रेणों में पैसा लगाया उससे तो यही जात होता है। क

देश में पैंगे की कमी नहीं है। कमी है पारस्परिक विश्वास की, समझी समझित नीति की, पूँजी लगाने के लिए आवश्यक तथा उपयोग क्षेत्र की। फिर भी यदि पूँजी की कमी हो तो विदेशों में उधार लिया जा सकता है। अनेक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जहाँ से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। सरकार ने विश्व बैंक से तीन ऋण तो ले लिए हैं और चौथा ऋण लेने का बात-चीत चल रही है। इसी प्रकार विदेशी सरकारों से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। इंग्लैण्ड और अमेरिका ने भी अपने अपने देशों में औद्योगीकरण में सचने पहिले विदेशी पूँजी लेकर काम चलाया था। हम भी ऐसा कर सकते हैं।

अब मे प्रश्न है प्रबन्धक और साहसी लोगों का जो उद्योगों का आयोजन करके कामचालाने स्थापित करें, उनका प्रबन्ध करें और संचालन करत हुए उनको उन्नत बनायें। औद्योगीकरण करने तथा उद्योगों को उन्नत बनाने के लिए बुद्धिमानी, दूरदर्शिता प्रबन्ध-शक्ति तथा तत्परदृष्टि की आवश्यकता होती है। परन्तु हमारे देश में तो इन गुणों का भी अभाव नहीं। हमारे यहाँ के प्रबन्धक अधिकारी (मेनेजिंग डायरेक्टर्स) इन कामों में दक्ष रहते हैं। इनके प्रयत्नों से भारत अब तक थोड़ा-बहुत औद्योगिक प्रगत कर रहा है। टाटा, बिड़ला जैसे दूरदर्शी, निपुण, चतुर तथा कार्यशील उद्योगपतियों ने देश का आर्थिक नक्शा ही बदल दिया है। यह ठीक है कि इस पक्ष में अपने कुछ दोष हैं परन्तु कुछ प्रबन्धकों ने तो निश्चय ही अपने उत्तरदायित्व, शायकता, कुशलता तथा देश प्रेम का परिचय दिया है। जहाँ तक साहस का प्रश्न है वह तो औद्योगिक विकास के साथ साथ आयागा। ज्यों-ज्यों औद्योगिक प्रगत होगी कार्यकर्ता कुशल और साहसी बनत चले जायेंगे।

इन सब बातों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में औद्योगीकरण के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ उपलब्ध हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब योरोप के अनेक देशों ने, जो आज औद्योगिक क्षेत्र में अग्रगण्य बने बैठे हैं, सम्यता का प्रकाश भी नहीं देखा था तो भारत अपने देशवासियों की फला और बलाकाओं की निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। हमारे देश का कपड़ा, लोहा, हाथीदाँत की वस्तुएँ, होने जयान्त्रिक के आभूषण तथा क-प ऐसी

ही वस्तुएँ अपनी कला के अतिनीय नमूने समझे जाते थे। कहा जाता है कि बादशाह प्रौरङ्गजेब ने एक बार अपनी लडकी को नगे शरीर दरबार में आने के लिए डाँटा था जबकि वह साडी का सात लट्ठ शरीर पर लपेटे हुए थी। यह थी हमारी करने की रीति। अनेक वस्तुएँ अपनी प्रौद्योगिक कला के लिए समाप्त भएँ प्रसिद्ध थीं। परन्तु औद्योगिक ज्ञान के आने ही भारत की कला लुप्त हो गई। हमारे ऊँचे सारण थे, जैसे (१) दशराज्य का अन्न, जो देशी कला का सम्मान करने थे (२) विदेशी शासन-सत्ता (३) पश्चिमी सभ्यता के सारण जनता में भाग्यवाद और प्रात उदामानता तथा (४) मशीन द्वारा बनाए गए माल की प्राप्ति गता। हमारा प्रौद्योगिक व्यवस्था में दो मरन बड़े देखे जाते हैं—(१) पृथ्वीगत माल का प्रभाव, (२) विदेशी पृथ्वी एवं प्रदूषण शासन-सत्ता का प्रभुत्व। इन दोनों कारणों से हमारा प्रौद्योगिक प्रलेख नितांत निर्यत्न अन्धारा और अनिश्चित रहा है। हमें इन दोनों का दूर करना चाहिए तभी देश का वास्तविक औद्योगिक प्रगम सम्भव हो सकता है। फिर भी औद्योगीकरण कोई बहुत सरल बात नहीं है। इसके लिए संगठित प्रयत्न और आयोजन की आवश्यकता है। यदि आयोजन करने प्रयत्न किए जायें तो निश्चय ही देश औद्योगिक क्षेत्र में अपूर्व उन्नति कर सकता है।

१४—औद्योगिक आयाजन की आवश्यकता ?

भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में आज औद्योगिक अन्धकार का भय समाया हुआ है। युद्धकाल में और उसके पश्चात् भी मद्रास की मयूरशक्ति मजबूत होना लगा। मद्रासकाल की नींव के कारण भी जनसाधारण की चर्चे कम घटित नही गयीं। भूमिगत वर्ग के नेताओं को इस बात का भय है कि निवृत्त भविष्य में भूमिगत वर्गों का भाग्य में बेकार हो जायेगा। हमारा भी यह विचार है कि यदि निवृत्त भविष्य में यह भय सत्य का रूप धारण करले तो औद्योगिक अशान्ति के अतिरिक्त हम सामाजिक जगत् में भी उन प्रतिस्पर्धात्मक तत्त्वों को जागरूक करेंगे, जो भारत की वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए अकल्याणकारी सिद्ध होंगे। यदि भविष्य में हम अपना आर्थिक जीवन सुदृढ़ बनाना है और उसे ऐसे बाह्य प्रभावों से दूर रखना है जिससे कि उसमें अस्थिरता न आने पावे, तो हमें अपना आर्थिक संगठन इस दृष्टिकोण में करना चाहिए कि जिससे उसकी अस्थिरता ही दूर न की जा सके, वरन् जिससे जनसाधारण का आर्थिक-स्तर भी ऊँचा बनाया जा सके।

आज का युग कुछ ऐसा हो चला है कि आर्थिक जगत् में व्यक्तिगत कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता, और न हम व्यावसायिक के सिद्धान्तों पर पूर्णरूपेण निर्वास हो कर सकते हैं। हमारा जीवन इतना जटिल होता जा रहा है तथा अन्य व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन से इतना सम्बद्ध होता जा रहा है कि किसी भी बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या का हल व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सहायता पर निर्भर रहकर करना सम्भव नहीं। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन करना अब व्यक्तिगत याद के सिद्धान्त पर सम्भव नहीं। आज का तो युग ही व्यक्तिगत याद के विपरीत है। जनसंख्या बढ़ने के कारण, उत्पादन में परिवर्तन के कारण और इन दोनों के कारण मनुष्य का जीवन इतना द्रव्य-आलित हो गया है कि जन साधारण की भलाई के लिए आजकाल के युगकी मांग है उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण की मांग की महत्त्व है समाजवाद की

भायना जिसमें कि औद्योगिक उत्पादन का वस्तुआ का जनसाधारण में नवन उचित वितरण होना परन्तु उद्योगों का जनस्वरूप का लाभ कुछ देने मिले लाभा का ही प्राप्त होता है, यह स्पष्ट होता है कि लाभ का ही उत्पादन का वृद्धि में लगाया जा सके अन्यथा जनसाधारण की भलाई के लिए उसका उपयोग किया जा सके। उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक एकाधिकार होने से औद्योगिक एकाधिकार की आशंका बनी रहती है और उसका प्रभाव प्रायः जनसाधारण — हिता के विपरीत होता है। भारत का एक नया उन्नत प्रत्येक देश के औद्योगिक जगत् के इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण देखने का मिलता है और इसीलिए आवश्यकता की विचारधारा इसमें प्रातःकृत है।

इसमें अनिश्चित और भी कई कारण हैं जिनमें यह आवश्यक है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार न रहकर सामूहिक अधिकार रहे और सरकार ही जनहित के लिए इनका संचालन भार अपने ऊपर ले। प्राक्कृत हमारे देश में जापान की सभी आवश्यक वस्तुआ का भारी टाटा है। अन्न और रुपये का तो मुख्यतः प्रभाव है। मणि की अधिकता और पूर्ति की कमी के कारण उनका बाजार भार उनका उत्पादन व्यय से बहुत अधिक है। जनसाधारण का इस अधिक मूल्य के कारण बहुत कठिनाई भोगना पड़ता है। कुछ लोग तो धन के अभाव के कारण इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में खरीद ही नहीं पाते जिससे उनको प्रत्यक्ष अत्यन्त शाचनाय है। इससे न तो उनके व्यक्तित्व का ही विकास होता है और न जीवन में उन्हें वह आर्थिक स्तुति ही हो पाती है जो अपने सामाजिक और राजनैतिक सत्ता के मदस्य होने के नाते उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। इस प्राथमिक शापण का परिणाम होता है मानसिक असन्तोष की वृद्धि, जो देश की उन्नति में सहायक नहीं हो सकती। दूसरी ओर, मणि की अधिकता और प्रदाय की कमी के कारण, बाजार मूल्य में उत्पादन मूल्य के अतिरिक्त का अभिवृद्धि है, यह वृद्धि सिर्फ उत्पादन-संचालक का ही प्राप्त होती है। हमारे समुदाय जो उदाहरण उपस्थित है उसकी सहायता से हम यह निश्चय कह सकते हैं कि इस अतिरिक्त धन का उपयोग अधिकांश जगह में उत्पादन की वृद्धि में नहीं किया जाता जिससे कि उपभोग की वस्तुआ के मूल्य में कमी हो।

यह सब हमीलिण होता है कि वर्तमान आर्थिक संगठन में उत्पादन सिर्फ लाभ-मिद्वान्त को ही लेकर किया जाता है, जनहित की भावना को लेकर नहीं। और यदि अधिक लाभ प्रदाय में कमी कर प्राप्ता किया जा सकता है, तब कोई भी व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न करना चाहेगा और जबतक हमारा आर्थिक संगठन व्यक्तिगत संबल को लेकर विद्यमान है, तबतक इस दशा में विशेष सुधार की आशा नहीं की जा सकती। यद्यपि अर्थशास्त्र के विशिष्ट नियमों के अनुसार यदि बाजार मूल्य उत्पादन व्यय में अधिक है तो कुछ समय बाद ही उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी और उस समय तक होनी रहेगी जबतक कि बाजार-मूल्य और उत्पादन-व्यय एक दूसरे के बराबर न हो जाएँ और भाग तथा प्रदाय में साम्य बिन्दु (I equilibrium Point) न स्थापित हो जाये। लेकिन अर्थशास्त्र का यह नियम यस्तुतः सत्य नहीं होता। इसका कारण है कि आजकल वर्तमान में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में उनके उत्पादन-कर्ताओं ने पूर्ण एकाधिकार (Complete Monopoly) स्थापित कर एकाधिकार मूल्य भी स्थापित करने का प्रयास किया है। शककर ये ही व्यवसाय यो ले लीजिए। उसका काम किसी एक फैक्ट्री के उत्पादन-मूल्य पर नहीं निर्भर रहती भी वरन शुगर सिडीकेट द्वारा निर्धारित की जाती भी। और यदि कोई मिल इस निर्धारित मूल्य पर न विप्रय करे तो शुगर सिडीकेट अपनी अन्य सम्बर-मिलों की सहायता से इतना कम मूल्य बाजार में रग सकता था जोकि उस मिल के उत्पादन व्यय में बड़ी कम होता तथा प्रतियोगिता के कारण उस मिल को इतनी अधिक हानि होती कि उसे सिडीकेट के निर्धारित मूल्य यो अपनाना पड़ता। पल स्पष्ट है। यही कारण है कि मूल्य-मुल्य उपभोग की ये वस्तुएँ जिनका उत्पादन यथाकी सहायता से बड़े पैमाने पर किया जाता है, उनमें के किसी भी एक उत्पादक के लिए स्वयं के उत्पादन-व्ययसे उसका विक्रय करना कठिन हो जाता है। यही हान उस व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले नये व्यक्ति का होता है। वह उसका एक अनसुना अर्थ माय बन जाता है जिसमें उसके स्वयं के अस्तित्व का कोई विशेष मूल्य नहीं। इस दशा के प्रतिकार का सिर्फ एक ही उपाय है और यह यह कि उत्पादन के साधनों के संचालन का भार सरकार के हाथों में रहे जो उत्पादन लाभ-मिद्वान्त

को लेकर नहीं बरन् जन साधारण को अधिकाधिक दृष्टि। तृप्ति की भावना को लेकर करेगी। युद्धकाल न बरों में और उसके बाद के बरों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि यदि सरकार उपादन व्यक्तिगत होने पर उचित मूल्य निर्धारण करने को चेष्टा करनी है तो उसका प्रयास सफल नहीं होता। इसी कारण हम इस बात का जार देकर यह सफ़त है कि आज न युग की माँग है कि उत्पादन के उपकरणों पर अधिकार व्यक्तिगत न हो। उत्पादन का नुन प्ले लाभ ही न हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं। कि इसी कारण आर्थिक व्यक्तिगत प्राजकन अधेशन मा प्रनीत हाता है

एक कारण और है। किसी ना देश का आर्थिक जीवन न्तर उत्पादन पर निर्भर रहता है, यह हम स्वाकार करत हैं लग्न विर भी कई ऐसे स्थत है जहाँ वैयक्तिक पूँजी का लाभ न होने का कारण या वह लग्न समय के बाद लाभ की प्राप्ता का कारण, शायद काइ आवश्यक नहीं। लग्न देश की परिस्थिति शायद ऐसी हा कि उनका उत्पादन देश की राजनैतिक सुरक्षा के ध्यान से आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार को उन कई चीन नाश्ता का लीनिए जिमें कि प्राज वह व्यस्त है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार ना यह जान है कि यह स्थन ऐमें है कि जिनमें व्यक्तिगत पूँजी शायद कभी न लगे या वह अपर्याप्त मात्रा में मिले। इसी कारण उनमें निर्माण की आवश्यकता को समझ कर, सरकार को उनमें संचालन का कार्य प्रारम्भ से ही रम्य करना पड़ा है।

उक्त कारणों से यह स्पष्ट हो जावेगा कि आजकल के आर्थिक जीवन के निर्माण में सरकार का काफी हाथ रहता है। बरन् यह कहना अधिक ठीक होगा कि किसी भी देश के जनसंसियों के आर्थिक स्तर का निर्माण वहाँ की सरकार ही कर सकती है। हितकर की अजेय शक्ति का दम चूर करने का भेय रुस की आर्थिक योजनाओं ही या है। युद्ध के परन्दात् भी इंगलैंड की आर्थिक योजना का ज्वलत उदाहरण हमारे सम्मुख उपस्थित है। युद्ध से क्षतिपूर्ण राष्ट्रों को उनके पुनर्निर्माण में जो सहायता मार्शल योजना द्वारा दी जा रही है, उसे भी हम भुना नहीं सकते। युद्धकालीन बरों में प्रत्यक्ष रूप से मले ही भारत के आर्थिक जीवन को उस तरह की क्षति न हुई हो जो यूरोप के अन्य राष्ट्रों को

हूँ है, पर विदेशी सरकार की उपस्थिति के कारण भारत के आर्थिक विकास में जो हानि हुई है, उसे हम भूल नहीं सकते। युद्ध के वर्षों में भी, जब अमेरिका युद्ध सामग्री के उत्पादनों की अत्यन्त आवश्यकता थी और जबकि आस्ट्रेलिया सरीसृप देशों को नये उद्योग खोलने का प्रोत्साहन दिया गया, भारत को कोई भी औद्योगिक विकास में विशेष सहायता नहीं दी गई। एक बड़ी भारतीय उद्योग युद्ध के बाद अमेरिका के उद्योगों से प्रतिस्पर्धिता न कर सकें। मेरा मिशन का योजनाओं को इसीलिए प्रकाश में कभी न आने दिया गया बल्कि युद्ध समस्या के बसाने भारतीय उद्योगों को क्षति ही पहुँचाई गई। जो भी उद्योग वहाँ विद्यमान थे उनमें मशीनों से लगातार कार्य लिया गया और उनके सुधार की कोई चेष्टा न की गई। फलस्वरूप हमारा उत्पादन-क्षम और भी कम हो गई। यहाँ तक कि राशन समस्या का भी टाक बन न दिया गया और बंगाल के अफ़ाल में सदस्यों का आने जगन की बल बनाना ही, सरकार की शोचनीय उदासीनता के कारण देना पड़ी। उन साधारण की सरकार की दृष्टान्तीति के कारण गण्ड बाटनारियों का सामना करना पड़ा। युद्ध के पश्चात् रक्षणता प्रार्थ के बाद जो युद्ध भी हम करना चाहते थे वह विभाजन के पश्चात् का घटनाओं के कारण न कर सके। गोप के अन्य देशों की तरह हमारे मन्त्र यह समस्या नहीं है कि हम इस तरह युद्ध के कारण हुई क्षति की पूर्ति कर सकें तो प्राथमिक श्रेणियों से ही अपनी आर्थिक नीति का निर्माण करना है। हमें इस विषय पर ध्यान देना है कि किस तरह से शीमाविहीन हम उत्पादन में वृद्ध कर राष्ट्र का आय में भी वृद्धि करें तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर जन साधारण का आर्थिक जीवनस्तर ऊपर उठाएँ। इन भव्य उत्तरदायित्व आज की सरकार पर है और यही कारण है कि आर्थिक गणना की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है। युद्धकालीन वर्षों में 'बम्बे प्लान' (Bombay Plan) तथा और भी कई ऐसी योजनाओं के नाम प्रकाश में आए, पर उसके पश्चात् उनके विचारों के अनुसार कुछ प्रगट किया गया हो, यह हमें मानना नहीं।

यद्यपि हम यह मानते हैं कि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है अन्यथा हमारे आर्थिक जीवन का अंत हो जायेगा, फिर भी भारत के पूर्ण विकास के लिए

आर्थिक योजना का निर्माण करना सरल नहीं है। उत्पादन पूँजी और भ्रम पर निर्भर रहता है। जहाँ तक भूमिक वर्ग में स्थायित्व का प्रश्न उठता है वहाँ उनमें व्याप्त औद्योगिक अशांति के कारण हमें उनमें अस्थिरता ही दृष्टगोचर होती है। भूमिक वर्ग ने यह सोचा कि अपनी सरकार की उपस्थिति के कारण शायद उन्हें वे सब सुविधाएँ प्राप्त हो जावें, जो उनके जन्मसिद्ध अधिकार हैं। यह उनकी भूल थी। लेकिन इसी कारण तो अभी तक उनमें स्थायित्व आ नहीं पाया है। वर्तमान उत्पादन के हास में भूमिक वर्ग का यथष्ट उत्तरदायित्व है। इसी तरह भारत सरकार ने अपनी भारी आर्थिक नीति का जबतक स्पष्टीकरण नहीं किया था, तबतक पूँजी का भी असहयोग रहा और आज भी हम पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि उसका पूर्णतः सहयोग प्राप्त है। इसके सिवाय जिन महत् उद्योगों को भारत सरकार स्वयं प्रारंभ करना चाहती है उनमें लिए शायद उसे उपयुक्त टेक्निकल व्याक्त भारत में प्राप्त नहीं हो सकते इसलिए हम इस दशा में विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा।

औद्योगिक योजना के अंतर्गत हमें कई और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि देश के किस विभाग में कौन से उद्योगों को प्रारंभ किया जावे। हमें देश के सभी उद्योगों का विकास करना है और इस तरह में विकास करना है कि देश का कोई भाग अछूता न रह जावे। इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की योजना प्रान्तों पर निर्भर न रहे बर केन्द्रीय विषय हो और वहाँ से उसका नियंत्रण किया जावे। हमें आशा है कि टी. टी. आर्थिक योजना के प्रयाग के बाद हम अपनी कई उन कुरीतियों को दूर कर सकेँगे जिनसे आज हम ग्रस्त हैं।

१५.—अध्यात्मिक-निर्माण का रूप

जन शक्ति का आवश्यकता का दूर करके खल था। व्याप्तियाँ की अपना दास बनाते हैं और इस प्रकार वकाली की समस्या और भी भीषण हो जाती है। ऐसी अवस्था में ये आवश्यक विनिम्नित कुटीर धंधा पर आधक जोर देते हैं। उनका स्थान है। कृषक व धंधा। नमः प्राधन पुत्र तथा आधन धर्म शास्त्र की आवश्यकता है और। नमः उभावत एवाधकार एता आवश्यक है, नेम नायला का गाने, सवान वाहन (Railways) आदि का यह पमान पर हान का कारण। उनका प्रचार म बड़े पमान के कारणों का नाय प्राकृतिक वस्तुओं का कुटीर धंधा के लिए आनमित मान बनाना मात्र ही है।^१ परन्तु हमारे देश की पारास्थातिका में यह स्थान साथ और उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। गाँव महायुद्ध के पश्चात् भारत का नया सार हमारे का आर्थिक नकशा बदल रहा है। सभी देश युद्ध के द्वारा आर्थिक प्रस्था के निमाण में व्यस्त हैं। इससे साथ साथ राजनैतिक पारास्थात भी अलग भिन्न है और सभी राष्ट्र तृतीय महायुद्ध की तैयारी में मगलन हैं। कोरिया में युद्ध चल रहा है। रक्त में भी नगड़ा पैदा हो गया है तथा इरान में नव के मामल में इंग्लैंड और इरान में रीचान्ताना चल रही है। भारत के सामने भी काश्मीर की प्रकृत समस्या है। इसलिए आवश्यकता है कि देश को समय बनाया जाय ताकि हम दूसरा का मुँह न देखना पड़े। इस कार्य के लिए देश में बचे हुए विशाल उद्योगों का अनमाण करना चाहिए जिससे उत्पादन कार्य शीघ्र बड़े और देश की रक्षा के लिए सामग्री इकट्ठी की जा सके। रौं, धातु का दृष्टि से तथा कृषि का कृषि कार्य से बचे हुए समय का उपयोग करके आवश्यकता की वस्तुएँ बनाने के लिए हम माध्य या कुटीर धंधों का निर्माण भी आवश्यक समझते हैं। परन्तु देश के आधिकाधिक प्राकृतिक साधनों, जनसंख्या, देश की आवश्यकताओं तथा संसार की राजनैतिक परिस्थितियों को सामने रखकर हम बड़े पैमाने के कारखानों की व्यवस्था स्थापित करना होगा। इससे अतिरिक्त अभी तो देश में अधिक नकट ने ही पैर जमा रखेंगे हैं। इस समय तो देश में किसी जादू की भी सहायता से अत्यधिक उत्पादन

बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सरकार की इस नीति की प्रशंसा करने हैं कि उसने पुराने विशाल कारखानों की उन्नति के लिए तथा नए नए विशाल कारखानों स्थापित करने के लिए मुहूर्त नीति में काम लिया है और इस प्रकार की अनकड़ मुद्रापाए स्वीकार की है। सरकार ने नये श्रीयोगिक कारखानों स्थापना का है।

जहाँ तक श्रीयोगिक निर्माण की सीमा का प्रश्न है इसमें सन्देह नहीं कि विशाल कारखानों का विस्तृत रूप ही हमारा आवश्यकताओं की दिक्कर होगा। परन्तु काल विचार मात्र में ही सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं। देश में प्राप्त करने मान, श्रम शक्ति, पूँजी तथा पक्के मान का खर्चाने के लिए मानव्यता के विस्तार आदि माना पर उद्योगों की निर्माण सीमा अनन्तमान होगी। सम्भाव है प्रथम तीन उद्योग विशाल कारखानों की आवश्यकतानुसार आवश्यक रूप में और आवश्यक मात्रा में पूर्ण प्राप्त न हो सके। उन्हीं अर्थशास्त्र में भी हमें श्रीयोगिक निर्माण का करना है। कुशल सम शक्ति पूर्ण और आवश्यक तथा मान हम विद्वानों में भी ला सकते हैं।

विप्लवी शक्ति-दी में अनेक तरह लगभग सभी देश उद्योगों के केन्द्राकरण के पक्ष में हैं। इसका कारण यही था कि जिस स्थान पर उद्योगों में खदानों के लिए कच्चा मान तथा कारखानों को लगाने के लिए शक्ति, जल, कच्चा, विद्युत आदि मिलने गए उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण होता गया और देश के अन्य भाग इसमें अछूते रहे। उदाहरण के लिए लोहे के कारखानों का केन्द्राकरण कोयले तथा लोहे के खानों के आस-पास बंगाल, बिहार में, जूट उद्योग कलकत्ते के आस-पास, सूती वस्त्रों की निर्माणियाँ अहमदाबाद तथा बम्बई में केन्द्रित हो गईं, परन्तु गत महायुद्ध में उत्पन्न हुए परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि केन्द्रीकरण ही नीति सर्वथा उपयुक्त नहीं। विचार कर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ जनसंख्या एक लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है। देशवासियों को रोजगार देने के लिए उद्योगों का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है और अब हमें देश का श्रीयोगिक-निर्माण इस भाँति करना है कि भारत के सभी क्षेत्रों में छोटे-बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो और इस प्रकार सम्पूर्ण देश की बेकारी की समस्या भी मुलभूत जाय।

सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक सभी दृष्टिकोणों से श्राव विवेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ उद्योगों का केन्द्राकरण हुआ है, देश की अधिकांश जनसंख्या रोजगार की नीयत से एकाग्र हो गई है और किसी किसी स्थान पर तो इतनी अधिकता हो गई है। कि इन स्थानों पर स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक और नैतिक वृद्धि में अधिक बाधा हुई और रोगादिक भयंकर दुष्परिणाम हुए हैं। इस हानि भय को दूर करने के लिए विवेन्द्रीकरण ही एक उपाय हो सकता है। जापान की औद्योगिक उन्नति का रहस्य विवेन्द्रीकरण है। प्राथमिक दृष्टिकोण से भी उद्योगों का केन्द्राकरण उपयुक्त नहीं। इस प्रकार देश के कुछ स्थान तो उत्तिशाल हो जाते हैं तथा अन्य अधिकांश भाग, जहाँ उद्योग नहीं हैं, प्राथमिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं जिससे पारलाम स्वरूप आर्थिक विषमता तथा देशराशिया के जीवन-स्तर में भारी अन्तर हो जाता है। कुछ स्थान तो उद्योगशाल हो जाते हैं और देश का अधिक भाग कृषि या अन्य प्रपञ्चित साधनों पर ही अवलम्बित रह जाता है। कुछ भाग धन माना तथा श्रम साधारण कहलाते लगते हैं जिससे दुष्परिणाम पूँजीवाद हमारे सामने है। आज का राजनैतिक परिस्थिति विवेन्द्रीकरण के पक्ष में है। वर्तमान युग रूपरेखा तथा युद्ध का युग है। आधुनिक युद्ध में प्रताप से उड़कर विध्वंसकारी बम्बों मारना एक साधारण बात हो गई है। ऐसी अवस्था में यदि देश की सभी उद्योग शक्ति एक ही स्थान पर केन्द्रित हुई तो किसी भी समय युद्ध काल में थोड़े ही बम्बों गिराकर शत्रु, देश की सम्पूर्ण शक्ति को नष्ट कर सकता है और फिर देश को अपना शक्ति खोकर शत्रु के आसरे रहना पड़ेगा। इससे एक मात्र उपाय विवेन्द्रीकरण है। यह बात हमारे वीर-महायुद्ध के अनुभव से प्रत्यक्ष है। इस अतिरिक्त शान्ति काल में भी केन्द्रीकरण राजनैतिक हानि में नहीं। आश्चर्य होगा कि देश के उन प्रांतों में, जहाँ उद्योगों की अधिक संख्या है तथा उन प्रांतों में जहाँ या तो कोई कारखाने नहीं हैं या जहाँ हैं भाता उतने नहीं हैं पारस्परिक चेमनन्त्य के निम्न दृष्टिकोण रहे हुए हैं जो केन्द्रीकरण का याचना से और अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए देश की आर्थिक विषमता को संतुलित करने के लिए उद्योगों का विवेन्द्रीकरण ही एक रामबाण औपधि है।

नव भारत के औद्योगिक निर्माण में सबसे अधिक सम्पूर्ण प्रश्न यह है कि बड़े-बड़े वर्तमान उद्योगों का तथा नए बनने वाले विशाल उद्योगों का अधिपति कौन हो—सरकार या जनता ? अब तक भारत की सरकार विदेशी-सरकार थी और विशाल उद्योग जनता की पूर्वी से चढ़े थे। दोनों ही में अज्ञान रूप से स्पर्ध था। परन्तु अब भारत का शासन भारतीयता के हाथ में है। इस प्रश्न का मुख्य अब और भी अधिक बढ जाता है। इस विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों का कथन है कि देश के उद्योग-धंधों का स्वामित्व, अधिकार तथा नियन्त्रण सरकार के हाथ में होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार भार-भारी लाभ जो कुछ इने-मिने पूँजीपतियों का जेबों में चले जाते हैं सरकार को जनता का सेवा के लिए प्राप्त हो सकेंगे और सरकार को इन उद्योगों को चलावे के लिए पूँजी भी अधिक मात्रा में थोड़ा ध्यान-दर पर मिल सकेगा। इसके अनिश्चित यह भी कहा गया है कि उद्योगों के सरकार के हाथ में होने से भ्रमजीवी अधिक से अधिक कार्य करेंगे क्योंकि वे समझ लेंगे कि अब पूँजीपति इसके स्वामी नहीं बल्कि सरकार के रूप में सम्पूर्ण जनता ही इसकी मालिक है और इस प्रकार उत्पादन काय में अधिक वृद्धि होगी। दूसरी विचारधारा है कि संयुक्त श्रमिकों की भाँति जनता ही उद्योगों की अधिपति रहे और सरकार का उन पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण रखा जा सकता है। हमारे विचार में देश की आर्थिक विपन्नता को मिटाने के लिए दोनों ही विचार-धाराएँ समायोजित नहीं रहेंगी। कांग्रेस ने १९३१ में ही घोषित किया था कि सरकार के अधिकार में आधार-उद्योग (Key-Industries) (यंत्र बनाने के कारखाने; रसायन-पदार्थ-निर्माणियाँ; जहाज, मोटर, इस्त्रि, आदि बनाने के कारखाने; शक्ति उत्पन्न करने के कारखाने, खनिज तेल, लकड़ी, कोयला आदि) रेल मार्ग, जलमार्ग, समुद्रमार्ग तथा आवागमन के साधन होने चाहिए और उनका नियन्त्रण भी सरकार के हाथ में ही हो। अविन-राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों (Basic Industries) का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है क्योंकि इनका जनता के नियन्त्रण में रहना राष्ट्र के हित में नहीं। हमारे विचार में ऐसे उद्योगों को, जिनमें लाभ की अपेक्षा कर (Tax) का अधिक महत्व हो, सरकार

को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए क्योंकि इससे, नियोजन होने के अतिरिक्त, सरकार की आय में कमी नहीं हो सकती। ऐसा सुझाव राष्ट्रीय-योजना समिति ने भी देश के सामने उपस्थित किया था। (राष्ट्रीय योजना समिति-रिपोर्ट पृ. ३८)। परन्तु सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आज उपयुक्त नहीं। डा० जान मथार्डे ने रेल विभाग में काल करने के पक्ष में भाषण देते हुए एक बार यह चेतावनी दी थी कि देशको भ्रष्ट निज प्रकार का अन्धका राटनाइया को मुक्तताये बिना राष्ट्रियकरण के अस्तित्व पुरोगम पर अभाव पड़ेगा। उठाना चाहिए। भारत सरकार अभी सफल उद्योगपात नहीं करती। डा० मथार्डे ने अपना अगला घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के औद्योगिक निर्माण में अभी जनता का ही व्यक्तिगत हाथ होना देश के हित में हो सकता है परन्तु इन सभी पर धाड़ी बहुत दृढ़ रूप से सरकार की अवश्य होनी चाहिए। जन लाभ के उद्योग जैसे विद्युत-वितरण, जल वितरण, आवागमन आदि सरकार के अधिकार में होना चाहते हैं, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे प्रांतीय सरकार हो अथवा स्थानीय। आधार्य उद्योग (Key Industries) तथा रक्षा उद्योगों का सत्था सार्वजनिक होना ही अनिवार्य है। इससे अतिरिक्त अन्य उद्योगों को थोड़ी थोड़ी सहायता देकर जनता को उनका व्यक्तिगत-स्वामी बनाया जा सकता है। इनमें भी जिन उद्योगों को सरकार कुछ वित्त सहायता दे उन पर वह अपना कुछ नियन्त्रण रखे जिससे जात होता रहे कि सरकार की नीति का सत्था पालन किया जा रहा है या नहीं। इन प्रकार 'सरकार' तथा 'जनता' दोनों के द्वारा नियंत्रित और संचालित उद्योग-वधों की सम्मिलित योजना भारत की व्यावहारिक औद्योगिक योजना होनी चाहिए। सरकार या जनता दोनों में से कोई भी अकेले ही इस योजना को सफल बनाने में योग्य नहीं। सम्मिलित समाज अर्थात् सरकार और जनता ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा सभी भारतीयों के देश को कृषि, भोज, अज्ञान, रोग तथा अस्वास्थ्य के दुर्दान्त चक्र से उबारने में पुण्यकार्य में सहायक हो सकते हैं। डॉक्टर होल्डरने, ने इसे 'मेनेजरियल इकनॉमी' के नाम से पुकारा है।

जैसा कि पहिले उल्लेख किया गया है, भारत के औद्योगिक निर्माण के लिए उच्च मान का देश में कोई अभाव नहीं। भारत ने तो विदेशी राष्ट्रों से

श्रौद्योगिक निर्माण में तीसरी समस्या श्रम शक्ति की है। श्रौद्योगिक उन्नति के लिए कुशल (Skilled) श्रम की जितनी आवश्यकता है उतनी अकुशल (Unskilled) श्रमिका की नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए श्रमिका की उचित शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और यह भा देवना चाहिए कि इस प्रकार शिक्षित श्रमिका का उचित भूमि पर कार्य भी मिल जाना है या नहीं। परन्तु निम्न भावप्य में कुशल श्रम कैसे प्राप्त हो ' इस प्रारम्भिक अवस्था में कुशल श्रमिक बाह्य देशों से लाकर उद्योग निर्माण में लगाए जा सकते हैं। श्रमिका का इतनी अधिक भूमि देनी होगी कि वे अपना कार्य कुशलता से जाँचित रखकर उसमें वृद्धि कर सकें। जैसा कि पहले सुझाया गया है कुछ उद्योग जनता के अधिकार तथा नियंत्रण में आ रहने चाहिये हैं। ऐसा अवस्था में उत्पादन की वृद्धि के लिए उद्योगपातया तथा श्रम बगल संपर्कों का सम्बन्ध होगा। उद्योगपातया का श्रम भूत उचित मात्रा में देना होगा। सरकार को इस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होगा।

कहा गया है कि भारत में पूँजी समुचित है। देश में पूँजी का अभाव तो है ही परन्तु जो कुछ पूँजी विद्यमान है वह भी देश के उद्योगों के लिए नहीं प्राप्त होती। इस पूँजी के प्राप्त न होने का कारण पूँजी प्राप्त करने की मुख्यस्थिति का अभाव तथा ऐसी पूँजी के स्वामियों की मनोवृत्ति है। दूसरी बात यह तो है कि पूँजी प्राप्त करने के उद्योगों में लगाने के साधन भी देश में उपलब्ध नहीं। इससे लिए सरकार का मद्रा-मार्गद्वयों का विकास करना होगा, अधिनियम प्रणाली को भी विस्तृत करना होगा तथा पूँजी वाल व्याक्तियों के हृदय में उद्योग के प्रति विश्वास जमाकर पूँजी प्राप्त करना होगा। यह बात तो हमारे देश की पूँजी की हुई। निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी पूँजी लेने में कोई दोष नहीं। कुछ लाग विदेशी पूँजी भारत में लगाने के विचार से सहमत नहीं। परन्तु लगभग सभी राजनातिक, सभी अर्थशास्त्रा विदेशी पूँजी को कुछ नियंत्रण के साथ भारत के उद्योगों में लगाने के पक्ष में हैं। समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी श्रौद्योगिक उत्पादन के विकास के विषय में भाषण देते हुए कहा था कि नए नए उद्योग स्थापित करने तथा पूर्वस्थित विशाल उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक विदेशी पूँजी ले लेनी चाहिए।

विदेशी पूँजी का निर्यन्त्रण भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। उसमें राष्ट्र मध्य के उद्योगों में तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में नर्त लगाना चाहिए जिससे उन पर किसी भी प्रकार से विदेशियों का आधिपत्य हो जाय। ऐसे उद्योगों में जिनकी निर्माण बला भारतवासियों का ज्ञान न हो और न भारत भावार्थ में शक्त होने की सम्भावना हो। विदेशी पूँजी, कार्म दाने के साथ स्वाभिव्यक्ति अधिकार को देकर भा ललाई जा सकता है। यह विदेशी पूँजी विदेशों से सरकार या जनता द्वारा शुल्क लेकर ही लगाना चाहिए। जिससे विदेशी पूँजीपतियों का आधिपत्य न रह सके। विदेशी पूँजी को बिना सरकार की आज्ञा के देश के किसी उद्योग धर्म में नहीं लगाना चाहिए।

नर भारत का श्रीयोगिक निर्माण केवल विशाल उद्योगों से स्थापित करने से ही सर्वज्ञ पूर्ण नहीं कहा जा सकता। जब तक विशाल उद्योगों के साथ-साथ ग्राम या कुटीर-धर्मों का निर्माण नाशका जाय तब तक बेकारों की समस्या शत प्रतिशत हल नहीं हो सकती। ग्राम में छोटे छोटे कुटीर-धर्म जैसे, कपड़ा बुनना, गूँथ बनाना, लकड़ी और चमड़े का काम, बर्तन बनाना, कामज तथा बीड़ी बनाना, मेल घानी, टोकरा बनाना आदि आदि याद स्थापित हो जायें तो कुपड़ों को उनसे कृपकार्य में बचें हुए समय में कुटीर धर्मों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अवसर मिलेगा। नर भारत में इस योजना का सफल बनाने के लिए कुछ शर्तुर्निर्माण हामी। इन धर्मों के लिए आनर्मित द्रव्य, राजस्व, यन्त्रुविनय की सुवधाएँ देना तथा इनकी विशाल उद्योगों की प्रतियोगिता से भी सरकार को रक्षा करनी होगी।

भारत का उत्थान बिना श्रीयोगिकरण और यह भी शर्त लिए बिना नहीं हो सकता। हमें आशा है कि नरभारत का राष्ट्रीय-सरकार इस योजना पर विचार कर देश के श्रीयोगिक निर्माण में अधिक प्रलम्ब न करेगी।

१६—उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

प्रागुनिज काज में सभा दशा में प्रोग्रामिज ज्ञात हो गयी है। जन-साधारण में जागरण-स्तर में परिवर्तन हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति वापिस आय पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न किए जा रहे हैं। मनदूर तथा सामान्य जनता की दैनिक आवश्यकताओं को पर्याप्त प्रति का प्रारम्भ ध्यान दिया जा रहा है। पाश्चात्य देशों में हर एक व्यक्ति को लिए भूख, बीमारी, बर्बादी इत्यादि कठिनाइयों से बचाने में पूरा प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सब कुछ उत्पादन बढ़ाने द्वारा ही सम्भव हो सकता है प्रारम्भ उत्पादन बढ़ाने लिए उत्पादन में साधना का ठीक प्रकार से संगठन करना आवश्यक है, तथा पाश्चात्य देशों में ऐसा हो भी रहा है। उत्पादन-क्षेत्र में दो प्रकार में प्रगति हो सकता है। एक तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना उत्पादन कार्य, जैसे जल चाने, जल चालाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय। सरकार की ओर से उस कार्य में कोई हस्तक्षेप न हो। इसका व्यवसाय या स्वैच्छावाद कहते हैं। दूसरा मार्ग यह है कि उत्पादन में साधना का स्वामित्व सरकार को हाथ में हो तथा पूरी उत्पादन क्रियाओं का नियंत्रण करे। प्रागुनिज प्रोग्रामिज ज्ञानि के प्रारम्भ में प्रथमान्वी पहिले मार्ग को पक्ष में था। उसी नीति का बहुत समय तक प्रयोग किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि अन्त में पूर्ण उत्पादन कम गया तथा मनदूर तथा पूर्णजागरितों में संघर्ष होना लगा। इसलिए तथा अन्य पश्चिमी देशों में आर्थिक इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि व्यक्तिवाद की नीति में समाज का क्षति अध्ययन पहुँची। फलतः ऐन कानून बने जिनमें उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यों में सरकार को पर्याप्त अधिकार मिलने लगे।

प्रश्न यह है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में साथ सरकार का क्या सम्बन्ध हो। इस सम्बन्ध में राष्ट्रियकरण के कई रूप होते हैं जिनमें से मुख्य तीन हैं। एक तो यह कि सरकार को उद्योग धर्मों का प्रबन्ध तथा संचालन करे

तथा वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित हो। यह तो निश्चित ही है कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी वृष्ट घरेलू धंधों तथा बड़े पैमाने के विशाल उद्योगों द्वारा ही हो सकती है। इन सभी साधनों को उद्यत करना आवश्यक है। पर न देखना यह है कि धंधा का राष्ट्रीयकरण हो अथवा इनकी व्यवस्था का भार तथा उत्तरदायित्व व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर ही छोड़ दिया जाय। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में हमारे देश में दो विचारधाराएँ हो चली हैं। कुछ लोगो का कहना है कि देश में उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण होना चाहिए जिससे पुँजीवाद का अन्त हो और वर्ग संघर्ष की समस्या समाप्त हो जाय। दूसरा मत है कि हमारी सरकार अभी उद्योगों का प्रबन्ध एवं संचालन करने में योग्य नहीं हुई है इसलिए इनका प्रबन्ध व्याक्त के अधिनाम में ही रहना चाहिए। व्यक्तिवाद विचारधारा के पक्ष वालों ने कुछ ऐसे तर्क दिए हैं जो राष्ट्रीयकरण का विरोध करने हैं। उनका कहना है कि—

(१) इतने उद्योग धंधे में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा बहुत हानि भय रहता है। सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके इस हानि-भय को अपने अंदर मोल लेना न ठीक है और न वांछनीय ही।

(२) उद्योग धंधों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यता और साहस की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारियों में यह योग्यता और साहस नहीं होता और न उनमें इनका कुछ अनुभव ही होता है। अतः सरकार उद्योगों का ठाक-ठीक संचालन नहीं कर सकती।

(३) सरकार उद्योग चलाने के लिए आवश्यक माना में पूँजी इकट्ठी नहीं कर सकती।

(४) सरकार को उद्योगों में काम करने के लिए कुशल मिस्त्रियों तथा इंजीनियरों की जो आवश्यकता होगी उसे वह अपनी सरलता से पूरा नहीं कर सकती। जनता सरलता में व्यक्तिगत उद्योगपति बन लेने है। ऐसी अवस्था में यह भय होता है कि राष्ट्रीयकरण से उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढ़ने की जगह उल्टी गिरने लगेंगी जिससे समाज और देश को और भी अधिक हानि होने की सम्भावना है।

परन्तु इन कारणों से ही राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। प्रो० के० टी० शाह ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं—

(१) उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंध सरकार के अधिकार के अन्तर्गत से उद्योगों में संगठन आणना तथा बचत भी होगी।

(२) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में जो लाभ हासिल हो जनता के हित में व्यय किया जा सकेगा। इससे सरकार के हाथ संचयित होंगे और इस जनता पर भारी-भारो टैक्स लगाकर अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(३) राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अर्थ जनता की सेवा करना होगा न कि जनता का शोषण करके भारी-भारी लाभ कमाना। इससे देश के आर्थिक संस्कार में हड़ताल आणगी तथा जन माधुर्य की उत्पत्ति होगी। तब पूँजीवाद और वर्ग-संघर्ष के दोष नहीं रहेंगे।

(४) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में श्रमिकों की अपनी-अपनी हानि के अनुसार पुरा पुरा रोजगार मिल सकेगा। श्रमिकों का शिक्षा तथा उनका वक्तव्य का संपादन प्रबन्ध होगा और भ्रम शोषण की समस्याएँ न रहेंगी।

(५) उद्योगों का राष्ट्र-करण होने से देश भर में स्थान-स्थान पर उद्योग स्थापित होंगे। सरकार को व्यापारों की भाँति विदेश प्रदेश में हित न रहेगा। इससे उद्योगों का विदेशीकरण घटने लगेगा तथा देश के हर एक भाग में लोगों को रोजगार की सुगन्ध मिले जायेगी।

इसी प्रकार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में युक्तियों दी जा चुकी हैं। परन्तु उचित बात तो यह है कि ये सभी बातें परिस्थित के अनुसार बदलती रहती हैं। आर्थिक मामलों में देश, काल और परिस्थित के अनुसार परिवर्तन हुआ करते हैं और होने भी चाहिए। प्रारम्भ में हम न समझें कि प्रणाली न बदलकर स्थितिगत कुछ होता ही बचती थी परन्तु समाजवादी उनमें उचित परिवर्तन होने होने आवश्यक वह समझें कि कुछ प्रणाली ही सही है। हमारी वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयकरण का देश भीता ही है। कुछ उद्योग-धन्धे तो ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होना बहुत आवश्यक है। रत्न, मरुह

१ A Minute of Dissent by Prof. K. T. Shah in the Report of the Advisory Planning Board, 1947.

तथा अथ नु व्ययानायात न साधना का ता राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। बहुत से आधार भूत धातु ऐसे हैं जिनका ठीक ठीक प्रबंध पार मंचालन सरकार अच्छी तरह से कर सकता है। भाग रसायान पदार्थ तथा मशीन बनाने के कारखाना चलाने बनाने के कारखाना का भा राष्ट्रीयकरण करना प्रायः श्रम है क्योंकि उनसे लिए प्यात मात्रा में पूँजी का प्रबंध करना तथा देश हित के लिए उनका संचालन करने का प्रबंध सरकार अच्छी तरह कर सकता है। इस उद्योगों का, जिनमें उद्योग्य उद्योग बनता है, व्यापारिक या आधार पर हा छोट दना उचित है, परन्तु सरकार का इन पर नियंत्रण प्रत्यक्ष होना चाहिए। छोट पमान के उद्योगों तथा कृषि तथा का सरकार के प्राधिकार में देने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर भी इनके संचालन मानव साधना का आवश्यकता होना है उनसे सम्बंध में सरकार का सहानुभाव प्रदर्श करना चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हा या नहीं सरकार का यह प्रश्न्य दग्ना चाहिए। इस देश के सभी भागों में औद्योगिक उन्नति हो रही है या नहीं। उद्योग सम्बंध नई नई चीज करने में, मानव बचत में तथा इस सम्बंध में व्यापक गति गंचालन का आवश्यक जानकारी देने का काम सरकार का करना चाहिए। लाभों प्राप्त का आवश्यकताओं के अनुसार धन का स्थानोचरण सरकार का उत्तरदायित्व है।

हमारे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विवादग्रस्त विषय को सरकार की प्रौद्योगिक नीति ने अगले दस वर्षों तक लगभग समाप्त हो कर दिया है। सरकार का मत है कि देश के अधिक उत्पन्न के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए सब सम्भव साधनों से देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सरकार यह भी समझती है कि यदि उत्पादन बढ़ाना है तो देश के वर्तमान औद्योगिक क्लेयर को नष्ट करना चाहिए। सरकारी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नहरू ने एक बार कहा था कि “दस विषय में (उद्योगों के राष्ट्रीयकरण) कोई भी कदम उठाने समय यह देखने की आवश्यकता है कि देश में वर्तमान आर्थिक स्तर को नष्ट होने न दें। दस और सत्तर का वर्तमान परिस्थिति का देखते हुए वर्तमान क्लेयर का बिल्कुल भंग कर देने से आर्थिक विनाश की गहरी चोट लगने की आशंका हो सकती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्लेयर को शनैः शनैः बदल जाय" हमारा सरकार के पास उद्योगों के स्वामित्व और संचालन का उत्तरदायित्व लेने का शक्ति अभी नहीं है। स्वर्गाय सरदार पटेल ने इस विषय में एक बार कहा था कि सरकार में उद्योगों को चलाने की न योग्यता है और न शक्ति। अतः एक व्यक्तिगत प्रबन्ध में ही छेड़ना होगा। राष्ट्रीयकरण के विषय में वाक्स आर्थिक प्रोग्राम कमेटी का मत है कि देश-व्याप्त तथा जनता के लिए आवश्यक बनता बनाने वाले उद्योग-धंधे तथा आधार-भूत उद्योग सरकार के आधीन होने चाहिये। जो उद्योग समस्त देश के हित में आवश्यक हैं वे भी सरकार के आधीन कर दिए जाए। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में स्पष्ट कर दिया है कि पुराने उद्योगों का हम मात्र ग़रम समय में राष्ट्रीयकरण करने का सोच प्रश्न नहीं है। परन्तु हमारा ध्यान इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का समय निर्धारित करना नहीं है क्योंकि उद्योगपरिचय इस बात से भय था कि उनमें अपनी पूर्ण लगाना बन्द कर देंगे। यदि हम यहाँ में हमारी आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो जाये और सरकार इस भार ही सँभालने के योग्य बन सके तो राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है। यदि जल्दबाजी में याकर अभी अभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो उत्पादन व्यवस्था बिल्कुल भंग हो जायगी और समूचा आर्थिक क्लेयर झुकावपूर्ण हो जायगा। राष्ट्रीयकरण करने में पहले इस बात की आवश्यकता है कि योजना बनाई जाय कि किस प्रकार राष्ट्रीयकरण हितकर होगा? कौनसे उद्योगों का पहले राष्ट्रीयकरण होना चाहिये? इस प्रकार उद्योगों की व्यक्तिगत स्वामित्वों में प्राप्त किया जाय। उनसे बदले में क्या दिया जाय? तथा फिर उद्योगों का प्रबन्ध तथा संचालन कैसे किया जाय? इन सब बातों को निश्चित करने के बाद ही राष्ट्रीयकरण के विषय में सोचना चाहिये।

१७—औद्योगिक-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार

देश का वर्तमान स्थिति में उद्योग व राष्ट्रीयकरण का राजनीति का व्यापक-हारिक न जानकर केन्द्रीय सरकार अपने नियन्त्रण और स्थापित में नए नए उद्योग स्थापित करने लगी है। सरकार ने अपनी पूँजी लगाकर कारखाने खोले हैं, विदेशी उद्योगों के सामे भी खोलें हैं तथा कुछ पंम कारखाने भी स्थापित किए हैं। जनस सरकार तथा जनता दोनों का साभा है। यहाँ हर औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का मुख्य मुख निरात्र का अध्ययन करेंगे।

१ रेल के इञ्जनों का कारखाना

रेल के इञ्जनों में देश का आमानभर बनाने उद्देश्य से सरकार ने प्रास्त-साल से साइ २५ मील का दूरा पर पश्चिम बंगाल में चतराइन नामक स्थान पर रेल के इञ्जन बनाने का एक विशाल कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने का काम १९४८ में प्रारम्भ किया था और लगभग समान ही चुका है। इस कारखाने में कुल मिलाकर १४६३ फरड रुपये ०४४ पैसे का अनुमान है परन्तु अभी तक १२५० फरड रुपये व्यय हो चुका है। १९५६ तक इसमें २० इञ्जन तथा ५० पावर टर्बिन्स प्रतिदरप बनने लगेंगी। इतना काम करने में साइ २०,००० रू. इस्पात का आवश्यकता हुआ करेगी जिस दश मह मिलाते हुए लाटे में पूरा करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। १९५० और ५१ में आवश्यक मात्रा में मिलने के कारण इस कारखाने का काम आशानुवृत्त उत्पत्ति नहीं कर सका है परन्तु फिर भी अब तक २० मालगाड़ी के रेलवे इञ्जन बनाए जा चुके हैं जो वे फिर काम देंगे हैं। अनुमान है कि इस वर्ष इसमें ३८ इञ्जन तथा अगले वर्ष ५२ इञ्जन बनाए जा सकेंगे। यह कारखाना एशिया में अपनी सीमा का प्रमुख कारखाना बन जायगा। इसमें १३००० क्यूब रक्ति के १५८६ माटर इञ्जन लगाए गए हैं। प्रायतन इस कारखाने में २८५० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं जो कुल अन्तः प्रचलित ५२०० में अर्धसे अधिक, इसमें काम करने लगेंगे। भविष्य का यह सम्बन्ध सिद्धा देने के लिए यहाँ एक यात्रि-स्टून भी गिरा गया है। सरकार ने इस कारखाने में काम करने वाले लागा के कल्याण की सभी आवश्यक सुविधाएँ दे रखी हैं।

२. कल-पुर्जे का कारखाना

कल-पुर्जे ऐसी आधार भूत वस्तुएँ हैं जिन पर किसी देश का औद्योगिक विकास निर्भर होता है। युद्ध के पहले हमारे देश में कल पुर्जे बनाने का कोई संगठित उद्योग नहीं था। उस समय लगभग १०० प्रकार के कल पुर्जे देश में बनते थे। परन्तु यद्वाकाल में इनकी आवश्यकता बढ़ी और ६००० प्रकार के कल-पुर्जे प्रति वर्ष हमारे उद्योगों में बनाए जाने लगे। १९४७ में देश भर में २४ अष्ट्री तथा १०० निम्न कोटि की ऐसी फर्म थीं जो कल-पुर्जे बनाया करती थीं। देश के विभाजन से इस उद्योग को काफी चोट लगी और कल-पुर्जों के कारखाने तथा उनमें काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या कम हो गई। विभाजन के पश्चात् हमारे देश में १६ उत्तम कोटि की तथा ५० निम्न कोटि की फर्म थीं जो कल पुर्जे बनाती थीं। इनमें लगभग ४० लाख रुपये के कल-पुर्जे प्रति वर्ष बनाए जाते थे। आतंक हमारा कुल आवश्यकताओं का ३ प्रतिशत भाग भी हमारे देश में बने हुए कल-पुर्जों में पूरा नहीं हो पाता। इस समय हमारे कारखानों को १० करोड़ रुपये के मूल्य के कल-पुर्जों की प्रति वर्ष आवश्यकता होती है जो हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। सरकार ने कल-पुर्जों में देश को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से बंगलोर के पास जानाशली नामक स्थान पर कल-पुर्जों का एक कारखाना स्थापित किया है। मैथूर राज्य ने इस कारखाने को बनाने के लिए भूमि दे दी है और कारखाने का अधिकांश काम पूरा भी हो चुका है। केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल १९४८ में म्विटजर-लैण्ड की एक कम्पनी के साथ समझौता करने वहाँ से मशीन, यन्त्रागार, विरोध तथा इन्जिनियर बुलाने का निश्चय किया है। १९५५-५६ तक यह कारखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा जब इसमें कोई ४ करोड़ रुपये के मूल्य के कल-पुर्जे बनने लगेंगे।

३. टेलीफोन बनाने का कारखाना

अब तक हम टेलीफोन तथा उसके लिए आवश्यक कल पुर्जे विदेशों से आयात करते थे परन्तु अब इनका आयात बन्द करने के उद्देश्य से बंगलोर में टेलीफोन बनाने का एक कारखाना खोला गया है। डायल तथा कण्डेन्सर

को छोड़ अन्य सभी वस्तुएँ इस कारखाने में बनाई जाया करेंगी। इस समय इस कारखाने में २५,००० टेलीफोन प्रति वर्ष बनाए जाते हैं परन्तु आशा है कि जब यह कारखाना अपनी पूर्ण शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमें ५०,००० टेलीफोन प्रति वर्ष बनने लगेंगे। आज तक रुबिआ माल पद्याल मात्रा में न मिलने के कारण उत्पादन सीमित है। यह कारखाना दारुइयन टेलीफोन इन्डस्ट्री लि० के नियंत्रण में रखा गया है। यह कम्पनी २३ कराइ रुपये की अधिकृत पूँजी से १ फरवरी १९५० को बनाई गई थी। इसकी पूँजी में ६५% भाग भारत सरकार तथा मध्य राज्य का है तथा शेष पूँजी इंग्लैंड की एक कम्पनी ने लगाई है। इसका नजालन और प्रबन्ध न लिए आठ संचालक की एक बाँड है जिसमें सात भारत सरकार द्वारा नियुक्त हैं। १९५१ के अन्त तक इस कारखाने में ४०,००० टेलीफोन तैयार किए गए थे और अब यहाँ लगभग २००० टेलीफोन प्रति मास तैयार होते हैं। अब टेलीफोन के बहुत से नए पुनः इस कारखाने में बनाए जाने लगे हैं।

टेलीफोन के लिए हमें एक प्रकार का तार की आवश्यकता होती है जो अब तक विदेशों से मंगाया जाता था। इस आयात को बन्द करने के लिए सरकार ने देश में ही एक कारखाना खोल दिया है। इसके लिए ३० नवम्बर १९४६ को सरकार ने इंग्लैंड की एक कम्पनी के साथ समझौता किया जिसके अनुसार वह कम्पनी पश्चिमी बंगाल में मिडलान नामक स्थान पर एक कारखाना बना रही है। इस कारखाने में १ कराइ रुपये व्यय होने का अनुमान है और आशा है कि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो इसमें १०० लाख रुपये के मूल्य के तार प्रति वर्ष बनाए जा सकेंगे। इस कारखाने के लिए भूमि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दी है और कारखाना बनाने का काम आरम्भ हो चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस कारखाने में प्रति वर्ष ६५ लाख रुपये की लागत लगाकर २७ लाख रुपये के मूल्य का तार बनाया जा सकेगा और इस प्रकार २२ लाख रुपये प्रति वर्ष का लाभ होगा।

४. वायुयान का कारखाना

देश में हवाई जहाज बनाने का कारखाना बनाने की आवश्यकता द्वितीय युद्ध के आरम्भ से ही होने लगी थी। दिसम्बर १९४० में बाबूचन्द हीराचन्द

नामक एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने ४ करोड़ रुपये की अविश्व पुँजी से बंगलौर में जहाज बनाने की लिमिटेड कम्पनी में अग्रणी पद १९०० वर्ष की स्थापित की। १९८२ में केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकृत कर अपने नियंत्रण में ले लिया। (सितम्बर १९८३ से युद्ध समाप्त होने तक इस कारखाने में जहाजों की तेज़ संख्या होती थी। युद्ध के पश्चात् इस कम्पनी का पुनर्गठन किया गया जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा मेसूर राज्य सरकार हिस्सेदार बनें। अब यह रक्षा विभाग के अन्तर्गत काम कर रहा है और इसमें जहाज बनाए जाने लगे हैं। छोटे छोटे जहाज बनाने में इस कारखाने ने अब तक बड़ी प्रगति की है। इटलैण्ड की एक जहाज बनाने की कम्पनी की सहायता से इस कारखाने में बड़े बड़े जहाजों का निर्माण भी होने लगा है। उत्पादन के मामले में अभी यह कारखाना भारतवर्षीय होने के कारण इसमें जहाजों की मरम्मत भी की जाती है जिससे भविष्य को काम मिलता रहे। इस कारखाने ने युद्धकाल में बहुत से टूटे-फूटे जहाजों की मरम्मत करके चालू कर दिया है जो अब अच्छा काम कर रहे हैं। जहाज बनाने के अतिरिक्त इस कारखाने में रेल के इंजनों भी बनाए जाने हैं। रेलवे विभाग में इंजनों बनाने का काम इस कारखाने को मिला हुआ है। अब तक इसने तीसरे दर्जे के लगभग २०० इंजनों तैयार किए हैं जो काम में आने लगे हैं।

५. पैनिम्लिन उद्योग

देशवासियों के जन-स्वास्थ्य के लिए देश में ही पैनिम्लिन बनाने की बहुत आवश्यकता थी। इस काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 'गैसुर स्टाभ्य नव' तथा 'गैसुर राष्ट्रीय बाल, सहायता कोष' में सम्मेलन करके पैनिम्लिन बनाने का एक कारखाना खोलने का निर्णय किया है। यह सम्मेलन जुलाई १९५१ में किया गया था जिसके अनुसार उक्त दोनों संस्थाओं ने, गैसुर तथा बाल सहायता देने का वचन दिया है। सम्मेलन के अनुसार भारत सरकार कारखाने के लिए भूमि देगी, कारखाना बनाएगी, प्रयोग-शालाएँ बनाएगी तथा बिजली आदि का प्रबंध करेगी। 'बाल सहायता कोष' ८,५०,००० डॉलर के मूल्य की अन्य सामग्री देगा कर कारखाने को देगा:

तथा 'विश्व स्वास्थ्य सत्र' तांत्रिक सहायता पर ३,५०,००० डॉलर व्यय करेगा। अनुमान है कि प्रारम्भ में इस कारखाने में प्रति वर्ष ३६०० यूनिट पैनिस्लिन बनेगी परन्तु धीरे-धीरे ६००० यूनिट बनने लगेगी। यह कारखाना पूना के पास देहू सड़क पर बनाया जा रहा है और आशा है कि १९५३ तक अन्ततः काम करने लगेगा। जब तक यह कारखाना बनकर तैयार हो तब तक पैनिस्लिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बम्बई के हैम्पटन इन्स्ट्रिक्ट में पैनिस्लिन का बोतला मभरन का प्रबन्ध कर दिया गया है। यहाँ प्रति दिन १५००० मायल्स बोतला म भरी जा रही है। यह काम २८ मई १९५१ से प्रारम्भ किया गया था जो अब तक सरफार तथा जनता की पैनिस्लिन की माँग को पूरा करता रहा है।

६ औजारों का कारखाना

सरकार ने गणित सम्बन्धी तथा अन्य औजार बनाने का भी एक कारखाना स्थापित किया है। कलकत्ता में अब तक गणित सम्बन्धी औजारों का जो कार्यालय था उसमें 'राष्ट्रीय औजार निर्माण' कारखाना का रूप दे दिया गया है। योजना कमिशन ने अपना पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की है कि इस कारखाने पर १९५१-५३ में ५० लाख रुपये तथा १९५१-५६ में कुल १५४ लाख रुपये व्यय किए जाएँ। कारखाने का मगठित करने की योजनाएँ बन रही हैं और आशा है कि शीघ्र ही इसमें इतना उत्पादन होगा कि फिर देश का विदेशों से इस प्रकार के औजार आयात करने की आवश्यकता न रहेगी। यहाँ इतना बहना भी उचित होगा कि इस कार्यालय की स्थापना सबसे पहले १८२० में हुई थी। तब से यहाँ बराबर प्रकार-प्रकार के गणित ज्योमिति सम्बन्धी औजार बनते रहे थे। आज इसकी संपत्ति सरकार ने देशहित के लिए अपने नियंत्रण में ले ली है और बड़े पैमाने पर औजार बनाए जाने लगे हैं।

७. वैज्ञानिक खाद का कारखाना

औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने एशिया भर में बहुत बड़ा काम जा किया है वह है वैज्ञानिक खाद बनाने का सिधरा का कारखाना। हमारे देश में वैज्ञा-

निक ग्लाड की बहुत आवश्यकता थी। इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने लगभग आठ वर्ष पहिले इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की थी। उस योजना के अनुसार १९४५ में बिहार में मिथली नामक स्थान पर भूमि खरीदने, उसे समतल बनाने तथा वास्तुमान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का काम आरम्भ कर दिया गया था। १९४६ में कारखाना बनाना भी आरम्भ कर दिया गया। पाँच वर्ष तक लगातार काम होता गया और अन्त में राष्ट्रीय सरकार ने कोई ३० करोड़ की लागत में यह कारखाना तैयार ही कर दिया। कारखाने का काम २० दिसम्बर १९५१ की आधी रात से आरम्भ हो गया है और १५ जनवरी १९५२ को सिवरी पेट्रिलाइज्ड एण्ड केमिकल्स लि०, कम्पनी बनाकर इस उसके अधीन कर दिया गया। इस कम्पनी की अधिकृत पूँजी ३० करोड़ रुपये है। यहाँ अमोनियम सल्फेट तैयार होता है। यह सल्फेट भूमि का उर्वरता बढ़ाने के काम आता है। हमारे देश में इसको बहुत आवश्यकता था। आता है कि इस वर्ष के मध्य तक इस कारखाने में १००० टन अमोनियम सल्फेट बनाने लगेंगे। आज तक भारत सरकार ४,००,००० टन अमोनियम सल्फेट उदेगा में आयात करती रही थी और यह भी देश का आवश्यकताओं के लिए पूर्ण नहीं था। जब हमारा यह कारखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमें ३,६५,००० टन अमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष बनने लगेंगे जिससे हमें १० करोड़ रुपये के मूल्य के विदेशी निनिमय की बचत होगी। सरकार का प्रयत्न है कि इस कारखाने में विभिन्न-प्रकार के वैज्ञानिक ग्लाड इतनी सस्ता लागत पर तैयार का जाय कि भारत के ग्रामों से ग्राम तक भी उसे खरीदकर अपने खेतों में प्रयोग कर सकें। यह निश्चय में तनिक भी सन्देह नहीं कि मिथली का यह कारखाना बना कर भारत सरकार ने रासायनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है।

८. निवास गृह बनाने का कारखाना

नई दिल्ली के पास स्थित एक ऐसा कारखाना बनाया गया है जो निवास गृह बनाने का काम करता है। सरकार का योचना है कि यह कारखाना उपयोगी और सस्ते पर बनाए जो जनता को बेचे जा सकें। इस उद्देश्य

की प्राप्ति के लिए सरकार स्वीडन की एक कम्पनी से बातचीत कर रही है। आशा है यह काम शीघ्र पूरा हो सकेगा और बड़े-बड़े नगरों में मरानों की समस्या समाप्त हो जायगी।

६. जलपोत बनाने का कारखाना

सरकार पानी के जहाज बनाने के उद्योग को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। सिंधिया स्टीमशिप नेरीगेशन कम्पनी ने पास रिजगापट्टम पर एक ऐसा कारखाना है जहाँ पानी के जहाज बनाए जाते हैं। सिंधिया कम्पनी इस कारखाने को बन्द करना चाहती थी परन्तु सरकार का विचार था कि इसके बन्द होने से देश का जहाज निर्माण उद्योग अस्त व्यस्त हो जायगा और उसमें काम करनेवाले पुराने कारीगर भी देश के हाथ से निकल जाएंगे। अतः सरकार ने इस कम्पनी को २५ फरवरी १९५० को ८००० टन वजन के तीन माल ढोने के जहाज बनाने के आर्डर दे दिये जिससे यह कारखाना चालू बना रहे और कुशल विगेषज्ञ काम में लगे रहें। सरकार यह भली भाँति जानती थी कि इस कम्पनी से जहाज बनाने में उसे एक जहाज का मूल्य ६८ लाख रुपये देना पड़ेगा जबकि इंग्लैण्ड में वैसा ही जहाज ४२ लाख रुपये में बन सकता था। फिर भी सरकार ने भारतीय कम्पनी से ही जहाज बनवाए और २२ लाख रुपये प्रति जहाज की दर कम्पनी को अधिक मूल्य देकर इस उद्योग का एक प्रकार से परास्त सहायता कर दी। अभी तक तीन जहाज बन चुके हैं और काम कर रहे हैं। तीन और जहाज बनाने का आर्डर अगस्त ५१ में दिया गया है। इस प्रकार सरकार इस उद्योग में सहायता दे रही है। परन्तु उद्योग का उन्नत करने का यह एक अस्थायी उपाय है। सरकार की योजना है कि सिंधिया कम्पनी से कारखाने को खरीद ही लिया जाय और किसी विदेशी कम्पनी के साथ साझा करके इसमें बड़े पैमाने पर जहाज बनने लगे। विश्वास है यह काम शीघ्र पूरा हो जायगा।

इन प्रयत्नों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में और भी अनेक छूटे-मोटे काम किए हैं। हाल ही में औषाधियाँ तथा रंग बनाने के एक कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है जहाँ शुद्ध औषाध तथा

सच्चे रंग बना करेंगे। निदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर सांस्कृतिक बनाने के कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। नदियों के बहुमुखी बांझनालों में सरकार ने जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं उनका वर्णन तो पीछे किया जा चुका है। परेलू-उद्योग-धरो में भी सरकार ने जो सहायता दी है वह भी कम नहीं है, उनका उल्लेख भी पीछे किया जा चुका है। अब तो यह आशा है कि सरकार इस और और भी अधिक काम करे। राज्य सरकारों को भी इस कार्य में भाग लेना चाहिए। प्रादेशिक उद्योगों का स्थापना तथा उनका संवर्धन तो राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने कागज की एक मिल बनाई है तथा मद्रास, मैसूर और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने भी उद्योगों में हिस्सा बढ़ाया है। अन्य राज्यों को भी इस क्षेत्र में आना चाहिए।

१८—कुटीर-धंधों की समस्याएँ

प्राचीन काल से ही भारत के आर्थिक उलार में छोटे तथा कुटीर धंधों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। अंगरेजी शासन से पहिले ये धंधे देशवासियों के आर्थिक जीवन के मूल आधार थे। ढाका का मलमल, बनारस की साड़ियाँ, काश्मीर के शाल, धातु का मूनियाँ, लकड़ी के गिलौने आदि ससार-प्रसिद्ध वस्तुएँ इन्हीं कुटीर-धंधों में बनती थीं। विदेशी राजनैतिक सत्ता के कारण इंग्लैण्ड में मशीना से बनी हुई वस्तुएँ हमारे देश में आने लगीं। उन वस्तुओं की प्रतियोगिता में हमारे ये छोटे धंधे न टिक सके। गाँवों की स्वावलम्बी आर्थिक इकाइयाँ भग होने लगीं तथा मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बने हुए सस्ते माल की प्रतियोगिता से, सरकार की हमारे उद्योगों के प्रति उदासीनता से एवं लोगों के रहन-सहन, रीति रिवाजों तथा सामाजिक सम्यता में परिवर्तन होने से हमारे छोटे तथा कुटीर धंधों को गहरी चोट लगी, परन्तु फिर भी ये मैदान में जमे रहे। स्वदेशी आन्दोलन के द्वारा इन्हें कुछ सहारा मिला तथा १९२१ और १९३१ के राजनैतिक आन्दोलनों में सादी तथा अन्य देशी वस्तुओं के उपभोग पर जो जार दिया गया उससे ये धंधे कुछ उभरने लगे। इनमें काम करनेवाले श्रमिकों की बुशलता, योग्यता तथा कार्यक्षमता में भी वृद्धि होने लगी। १९३६-३७ में जब प्रान्तीय शासन व्यवस्था कांग्रेस के हाथ में आई तो इन धंधों को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। द्वितीय युद्धकाल में नागरिक उपभाग के लिए कारखानों में बने हुए माल की कमी होने के कारण इन धंधों में बनाए गए माल का उपयोग बढ़ने लगा। फलतः इन धंधों की संख्या बढ़ी और इनमें काम करनेवाले कलाकारों को प्रोत्साहन मिला। आज भी ये छोटे और कुटीर धंधे हमारे आर्थिक जीवन के प्रमुख अङ्ग हैं। औद्योगीकरण का किसी भी देश व्यापी योजना में इनका सम्मिलित करना अनिवार्य होगया है। परन्तु इस विषय पर अधिक विचार करने से पहिले छोटे तथा कुटीर-धंधों का अभिप्राय समझना भी आवश्यक है। पृ० १०

औद्योगिक विरासत समिति (१९३५) के अनुसार "कुटीर-धंधे वे होते हैं जिनमें प्रांतीय अपने-ही-होते पर अपने-प्रांतीय में लगाकर चलाने हैं" सामान्यतः एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर इनमें काम करते हैं—परन्तु कभी-कभी आवश्यकतानुसार भ्रमदूरी देकर मजदूर भी लगा लेते हैं। इन धंधों में पञ्जाली की सहायता भी ली जा सकती है। कुटीर-धंधे नगर और गाँवों दोनों स्थानों में चलाए जा सकते हैं। गाँवों में जो कुटीर धंधे स्थित होते हैं उन्हें पन्द्रह ईंफिंग जॉन कमेंटीज प्रामीण या परलू उद्योग कहकर पुकारा है। इन उद्योगों में करीब से बगइचा बनाना, रेशम बनाना, सोने-चंदी का तार बनाना, धातु के बर्तन बनाना, बीड़ा सिगरेट बनाना, चटाईयाँ बनाना, गुड़ बनाना, धान से द्रायन निकालना, भी दूध का काम करना, तेल करना, आदि सम्मिलित हैं। योजना विभाग में इनका अन्तर्-स्फुट करने को विचार है कि जो छोटे छोटे धंधे गाँवों में स्थित होंगे उन्हें 'कुटीर-धंधे' कहेंगे तथा जो नगरों में स्थित होंगे उन्हें केवल छोटे उद्योग धंधे कहा जा सकता है।

हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ के निवासी मरीच हैं तथा अधिकांश जनता का जीवन स्तर नीचा है। हमारे कृषकों को पूरे वर्ष भर कृष में काम नहीं करना पड़ता। कृषि के शाही कमीशन ने लिखा है कि "भारतीय कृषकों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष काम करने वाले कृषकों को इसमें वर्ष भर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष में काम में काम नार महीने वह बिलगुल गाली रहता है। ऐसे गाली समय में उनको तथा उनके परिवार को कोई काम देने के लिए छोड़ने-छोड़ने कुटीर-धंधों की आवश्यकता है। भारतीय ईंफिंग जॉन कमेंटीज का भी मत है कि 'कृषकों को तथा उनके परिवार को उनके गाली समय में काम देने के लिए कुटीर-धंधे स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह अपनी आय भी बढ़ा सकता है।' डॉ० राधाकमल मुखर्जी ने गीज करके बता लगाया है कि उत्तर भारत के बहुत-से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के कृषक वर्ष भर में लगभग २०० दिन बेकार रहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ-वहाँ तो, जहाँ मिचार्ड ने कृषि और उत्तम साधन प्राप्त हैं, इन्होंने भी आधुनिक समय तक वे बेकार रहते हैं। जिस कृषक के पास कम भूमि है उससे तो सोचे परिवार को भी उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः उन लोगों

का ऐसा काम देना ही आवश्यकता है जहाँ व काम करने अपनी आवश्यकता की वस्तु भी बना सक तथा अपनी आय में वृद्धि भी कर सकें।^१ इस प्रकार आवश्यकता यह है कि किसी भी प्रकार ऐसा कुटीर धंधे स्थापित करण जाए जो कृषक को राजगार न सक तथा उनकी आय भी बढ़ा सकें। राष्ट्रीय योजना समिति (१९३६) का मत था कि “ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता अपने भौतिक कल्याण के लिए अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ पैदा करना नहीं प्राप्त कर पाती। अब उनके लिए कुटीर धंधों का स्थापना करना बहुत आवश्यक है।” और जब हम अपनी कृषि का वैधानिक करना चाहते हैं और उसमें यंत्रों का प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के लाग राजगार हाथ, उनका काम देने के लिए छूटे धरेलू धंधों को प्रोत्साहित किया जाय। ऐसा स्थान में तो देश के आर्थिक आयातन में कुटीर धंधों का स्थान और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण योजना कमिशन ने अपनी पंच वर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन धंधों के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। जमनी नागान, स्टाटजरलैंड तथा योरप के अन्य देशों में वहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग छूटे तथा कुटीर धंधों पर आश्रित रहता है। जमनी का कुल जनसंख्या का २/५ भाग ऐसा ही छूटे उद्योग धंधों में काम करता रहा है। वहाँ बहुत से छूटे छूटे उद्योग सरकारी सहायता से चाले गए थे। योरप के अन्य देशों में कृषक अपनी भूमि पर काम करते ही हैं, उद्योगों में भी काम करते हैं। इससे उन्हें उपभोग का काम मिलता रहता है और वे निरल्ले नहीं रहते। यही कारण है कि वहाँ जनसंख्या का धनत्व कम है और एक वर्ग मील में २०० से ३०० तक लाग रहते हैं जबकि हमारे देश में जनसंख्या का धनत्व अधिक है और एक वर्ग मील में ५०० से ६०० व्याप्त रहते हैं। जनसंख्या के इस घनत्व को कम करने के लिए कृषकों का कृषि के अनिवार्य फाइ सहायक काम धंधे देने की आवश्यकता है।

प्रश्न यह है कि यदि हम अपने देश में छूटे और कुटीर धंधे स्थापित कर ता क्या वे विशाल आय उद्योगों की प्रतिस्पर्धिता में टिक सकेंगे? यह ठीक है कि विद्युत् यंत्रों में ये धंधे विशाल और बड़े पैमाने के कारखानों के सामने न टिक सकें और इन्हें गहरी खाँच लगी परन्तु आज की स्थिति पुरानी स्थिति

ने विनमूल भिन्न है। आज कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण वे धर्म सफलता-पूर्वक बड़े उद्योगों का सामना कर सकेंगे। ये बातें हैं—एक, आज कुल विजली का प्रयोग बढ़ने से इन धर्मों में विजली के द्वारा मशीन चलाने में सहायता होगा तथा इन धर्मों को बाह्य तथा आन्तरिक व्ययों का लाभ मिल सकेगा। दूसरे, आज प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है जो वस्तुएँ सरलतापूर्वक अपने मूल्य पर इन धर्मों में बनाई जा सकती हैं। ऐसा वस्तु विशेषतः विनाम री है जिसे जनता इन धर्मों से खरीदने में आपत्ति भी नहीं करेगी। आज छोटे और कुटीर-धर्मों का क्षेत्र पहिले का अपेक्षा अब अधिक है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने के विशाल उद्योग स्थापित करने में उत्पादन अधिक होता है इसलिए छोटे धर्मों को छोड़ बड़े उद्योग ही स्थापित होने चाहिए। ऐसा लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा ध्यान बड़े उद्योगों को भिटाकर छोटे धर्मों स्थापित करने का नहीं है। समस्या यह है कि श्रमिकों तथा अन्य लोगों का जो कोई मुख्य काम करना हो परन्तु फिर भी उनके पास गान्धी समय हो, छोटे उद्योगों में सहायक काम दिया जाय। आज हमारे देश की समस्या कल उत्पादन बढ़ाने की ही नहीं है बल्कि देश के विशाल जन-समुद्र का राजगार देने का भी है। बड़े पैमाने के उद्योग इतनी बड़ी जन-संख्या का एक साथ काम का व्यवस्था नहीं कर सकते। काम की व्यवस्था तो केवल छोटे छोटे घरेलू धर्मों में ही सकती है जहाँ लोग अपने मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त यह काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार इन धर्मों से हमारे देश में दो समस्याएँ सुलभ होती हैं। एक, लोगों का खाली समय में काम मिलता है तथा दूसरे देश का उत्पादन भी बढ़ता है। एक बात और है। इस समय बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए देश के पास न तो आवश्यक मूल्य है और न संसाधन ही हैं। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने के उद्योगों का ध्यान लगाकर बैठ रहने से यह वास्तविक है कि छोटे उद्योगों को बनाकर दो समस्याएँ एक साथ हल की जायें। अतएव देश के आर्थिक संवृद्धि के लिए पुराने कुटीर-धर्मों को पुनर्जीवित करना तथा नए धर्म स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार देश की अतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा स्वयं और बाहरों को भी उनकी शक्ति और योगदानानुसार काम मिलने लगेगा। कामोन्मुख

लोगों को अपनी आय बढ़ाने के साधन मिलेंगे तबमें वे अपना जीवन स्तर ऊँचा बना सकेंगे। हमारे गाँवों का पुनरुद्धार एक प्रकार से कुटीर धन्धा पर निर्भर है। इनमें बहुत से पड़े लख लागे का भी राजगार मिलता तथा देश का श्राविक स्लेज सतुलित शहर सुदृढ बन जायगा।

हमारे यहाँ कुछ ऐसी काटनाइयाँ हैं जिनका कारण कुटीर धन्धे आश्रयक उत्पत्ति नहीं कर पाए हैं। धरा की उत्पत्ति बनाने के लिए पहिले इन कठिनाइयाँ को दूर करना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनमें काम करनेवाले लोग अज्ञान, अशिक्षित और गरब हैं। उनका दृष्टिकोण समुचित है और वे परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने उद्योगों का संगठन नहीं कर पाते। इसलिये यह आश्रयक है कि उन्हें उद्योग सम्बन्धी जानकारी कराई जाय। इससे लिए गाँवों में स्थान स्थान पर ऐम् जेन्ट्र हॉल का रूप में दहातियों का उद्योगों का महत्त्व समझाया तथा तत्सम्बन्धी शिक्षा भी दें। अधिक जानकारी के लिए श्रौंगों गिरु स्टूल होने चाहिए जहाँ ऊँची शिक्षा देने की व्यवस्था हो। औद्योगिक कर्मों शान ने सिफारिश की थी कि 'जिन क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित करने चाहें उन्हें उद्योगों के प्रदर्शन केन्द्र सरकार स्थापित करके लागे का उस उद्योग सम्बन्धी पूरा पूरा जानकारी कराये।' दूसरी, काटनाई अबतक यह रहा है कि इन उद्योगों में काम करने वाले स्टाफ करने के लिए माल नहीं बनाते हैं बल्कि उसी समय माल बनाते हैं जब उनका पास माल के गार्डर आ जाते हैं। माल बनाने से पहिले वे लोग आडर देनगनों से या अन्य मध्यस्था से कच्चा माल उधार लेते हैं और उन्हीं का पक्का माल बेचने का बचन दे देते हैं। इससे तब उन्हीं कच्चा माल मरत दामा पर मिलता है और न पक्के मानव ही अच्छे दाम मिल पाते हैं। ये तो एक प्रकार से थोड़ी मात्रा पर हा काम करते रहते हैं। सच बात तो यह है कि ये लोग ऐसा काम परिस्थितियों से प्रेरित होकर करते रहते हैं। उनकी कुछ ऐसी काटनाइयाँ हैं जिनमें बाध्य होकर वे ऐसा करते हैं। ये कठिनाइयाँ निम्न हैं :—

१. पूँजा का अभाव,

२. पर्याप्त कारखाना में बने हुए माल की प्रतियोगिता, जिससे उन्हें अपना माल बेचने में सदा भय रहता है कि कहीं उनका माल बिना बिके न रहे

जाय। यदि ऐसा हुआ तो उनकी पूँजी उस माल में बँध जाती है और वे कहीं के नहीं रहने।

३. माल का स्मरूपता तथा उत्तमता के विषय में वे निश्चित नहीं होने और इसलिए माल सप्लाई करने के लिए वे किसी प्रकार का काई बचन नहीं देते। इसलिए वे माल का स्टॉक भी नहीं रक्ते।

४. कच्चे माल का अभाव।

इनने अतिरिक्त कुटरी-धंधों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किए बिना इन धंधों का उन्नति सम्भव नहीं हो सकती। यू० पी० औद्योगिक मंत्रालय (१९३५) ने इन धंधों की निम्न समस्याएँ लिखा है : -

१. लाभ के साथ पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल प्राप्त करने की कठिनाई,
२. आवश्यक मात्रा में पूँजी का अभाव,
३. बना हुआ माल बेचने की कठिनाई,
४. उत्पादन व्यय सम्बन्धी अंकित लगाने में उद्योगियों की अनभिज्ञता,
५. स्मरूप तथा उच्चकॉटि का माल तैयार करने का कठिनाई,
६. उद्योगियों की अज्ञाता तथा रुढ़ता,
७. आधुनिक उत्तम प्रकार के औजारों का अभाव।

ग्रेजु धंधों की सबसे बड़ी समस्या समय पर आवश्यक मात्रा में उत्तम कॉटि का कच्चा माल प्राप्त करने की है। अधिकतर उद्योगी कच्चा माल उपार लाते हैं जिससे न तो उन्हें अच्छा माल मिलता है और न माल मिलता है। कभी-कभी तो उन्हें कच्चा माल मिलता भी नहीं जिसमें वे अपने धन्धे का बन्द किए बैठे रहते हैं। यहाँ यह आवश्यक है कि उद्योगियों की अपनी सहकारी समितियाँ हो जो उन्हें कच्चा माल लाकर दें। ये ही समितियाँ उनके माल को अच्छे भावों पर बेचने का प्रबन्ध कर। उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई में काफी धुनेवाले उद्योगियों का सहकारी समितियाँ हैं जो सदस्यों को कच्चा माल देती तथा उनके बपट्टे को ऊँचे से ऊँचे भावों पर बेचने का प्रबन्ध करती हैं। ऐसी समितियाँ प्रत्येक औद्योगिक-क्षेत्र में होनी चाहिये। समितियों के होने से मध्यस्थ लोग उद्योगियों का शोषण नहीं कर सकेंगे।

दूसरी समस्या है, वैज्ञानिक यंत्रों की। अब तक हमारे उद्योगी यही पुराने

और टूटे-पूटे औजारों और मशीनों का प्रयोग करते आते हैं। इससे न तो उत्पादन बढ़ता है और न उनका आय में ग्राह्य होती है। उनका माल भी उत्तम गुण का नहीं बन पाता। इन कारखानों में बन हुए माल का प्रातयागतता में बिक्री नहीं पाती। इस समस्या का सुलभान के लिए उद्योगों का नए नए आधुनिक यंत्र दिए जाने चाहिए। स्थान स्थान पर ऐसे मन्द माल जाए जहाँ इन यंत्रों का प्रदर्शन हो तथा उनका प्रयोग बनलाया जाय। सरकार इन आधुनिक यंत्र उद्यागियों को करता पर द और देना कि वे उनका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। सरकारी मिन्त्रा नियुक्त किए जाए जो इन यंत्रों का प्रयोग उद्योगों को करावे तथा यंत्रों का टूट-पूट का मरम्मत भी करें। यह काम सहकारी सामितिया द्वारा भी अच्छी तरह किया जा सकता है। बिहार में इस काम के लिए सामितियाँ हैं जो रेशमी पड़ों बनानेवाले कुलाहार मशीनों का प्रयोग दिखाने और सिखाने का प्रबन्ध करती हैं।

पूँजा का अभाव उद्यागियों की तासंग बड़ी समस्या है। न तो इन लोगों के पास अच्छा माल खरादने का पैसा होता है, न य मशीन खरीद पाते हैं और न इनकी इतनी सामर्थ्य होती है कि माल बनाने के बाद अच्छे भाग का इन्तजार कर सकें। इन्हें माल तैयार करते ही बेचना पड़ता है चाहे भाव अनुपलब्ध हो या न हो। यलाग महाजन से या अच्छा माल बनने वाले व्यापारी से रुपया उधार लाते हैं। यह रुपया इन्हें उच्च व्याज दर पर मिलता है और यभा नभा तो इन्हें अपना माल हा खर्च देनवाले महाजन या व्यापारी के हाथ बेचना पड़ता है। न तो इन्हें बेका से उधार मिलता है और न सरकार का हा कोई प्रबन्ध है। कन्द्रीय बैंकिंग जॉच कमिटी का सिफारिश है कि इस काम के लिए इन्हें लिए सहकारी सामितियाँ हाना चाहिए, जो सदस्यों का मामूली व्याज दर पर रुपया दें। औद्योगिक कमाशन का सुझाव है कि राज्य में उद्यागों के हायरेक्टर का थोड़ा थोड़ा राश उद्यागियों को उधार देनी चाहिए। हमारा विचार है कि बड़े-बड़े उद्यागों का भाँति इन उद्यागों को भी राज्य से सहायता मिलनी चाहिए।

छाटे उद्यागियों के पास अच्छे दाम पर अपनी माल बनाने की भी सुविधाएँ नहीं हैं। जब तक इनमें काम करनेवालों को उनका माल के अच्छे दाम नहीं

मिलेंगे तब तक उनकी यह काम करने में रुचि नहीं होगी। सरकार को इनका माल विक्रयाने का प्रयत्न करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक अभ्यासिक योजना बनाई गई जो कुटीर-धंधों में बनी हुई माल का विज्ञापन करना है तथा माल बेचने का भी प्रयत्न करता है। ऐसा सस्थाएँ प्रांत-प्रान्त में होना चाहिए। हमारे देश की ये वस्तुएँ विदेशों में बेचने का अब तक वह प्रयत्न नहीं था परन्तु अब विदेशों में स्थिति हमारे दुतावासों में हमारी इन कलामें वस्तुओं के प्रदर्शन होने लगे हैं जिससे हमारी वस्तुओं का विज्ञापन होता है और विक्रय में सहायता मिलती है। सबसे में उपयोग विभाग में एक स्थान पर उप-विभाग बनाया गया है जो कुटीर-धंधों में बनी हुई वस्तुओं का विज्ञापन करता है। इस राज्य में मार्केटिंग आफीस नियुक्त किए हुए हैं जो माल के बेचने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा संगठन राज्य राज्य में होना चाहिए। इस विषय में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सरकार इन वस्तुओं का लोक-प्रिय बनाने में सहायता करे। सरकारी विभाग इन उत्पादों में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करे तब जनता भी उनका उपयोग करने लगेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्रयोग की अभिलाषा वस्तुएँ इन्हीं उपयोगों में लगी देने लगी है। इस नाति की अन्य राज्यों में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार भी इन उत्पादों की प्रगति में विशेष ध्यान लेने लगी है। १९४८ में शामिल भारतीय कुटीर-धंधों का बोर्ड बनाया गया था जिसका उद्देश्य देश विदेशों में कुटीर-निर्मित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना है। इसी बोर्ड की सिफारिश है कि विदेशों में हमारे दुतावास और व्यापार कमिश्नर हमारी इन वस्तुओं को प्रदर्शन करके विज्ञापन करें। आवश्यकता यह है कि देश में एक केन्द्रीय ट्रेनिंग मस्था भी खोला जाय जहाँ कुटीर-उद्योगों की तालमेलभी शिक्षा दी जाय। इसी प्रकार राज्य राज्य में ऐसे बोर्ड होने चाहिए जो इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा इनके माल को बेचने का प्रयत्न करें। यदि इस प्रकार संगठन से काम होगा तो हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक परेलु-धंधों एक बार फिर उन्नत हो सकेंगे। १९५०-५१ में केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को कुटीर-धंधों को उन्नत बनाने के लिए ६३ लाख रुपये दिये हैं। इसके आतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने

प्ररोपशो को जारान, डेन्मार्क, इंग्लैण्ड आदि देशों में भी भेजा था जिससे वे वहाँ की स्थिति का अध्ययन करके देखें कि क्या वहाँ जो कार्य पद्धति हमारे कुटीर-धन्धों में लागू हो सकती है? अखिल भारतीय बर्ड का गव जनरल में पुनर्वैगठन किया गया है और उसमें निम्न कार्य दे दिये गए हैं—

- (१) सरकार का छोटे तथा कुटीर-धन्धों के सौजन्य एवं विकास सम्बन्धी योजनाओं पर परामर्श देना,
- (२) सरकार को सुझाव देना कि छोटे तथा कुटीर-धन्धों और विशाल उद्योगों में किस प्रकार सहयोग बनाया जा सकता है,
- (३) कुटीर-धन्धों सम्बन्धी सरकारी योजनाओं का देखना तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता देना,
- (४) कुटीर धन्धों में बने हुए माल को भारत तथा विदेशों में बिकवाने का प्रबन्ध करना ।

आशा है भारत के नवीन औद्योगिक क्लेयर में इन उद्योगों को यथा स्थान प्राप्त होगा ।

१६—औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ

हमारे देश में औद्योगीकरण के साथ-साथ उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या तथा उनके रहन-सहन, पान-पान, रोजगार, जीवन-मरण सम्बन्धी समस्याएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी इन समस्याओं का महत्त्व सरकार ने भी भली प्रकार पहिचान लिया है। हमका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि सन् १९३० में लेकर अब तक इन समस्याओं को जॉब-पड़ताल करने के लिए दो कमीशन नियुक्त हो चुके हैं। एक कमीशन १९३० में 'ग्राहो कमीशन' के नाम से नियुक्त किया गया था और दूसरा कमीशन युद्ध काल में 'रेम कमेटी' के नाम से नियुक्त हुआ था। इतना ही नहीं, अग्रेज १९४८ में प्रकाशित अपनी औद्योगिक नीति में सरकार ने भूमि-उत्पादन की ओर विशेष रूप से संकेत करते हुए कहा था कि देश में ऐसी व्यवस्था का जाना चाहिए जिसमें श्रमिकों का भरा-पूरा रोजगार मिल सके, उनका अच्छा तथा पर्याप्त मजदूरी मिल सके तथा उनका रहन-सहन का स्तर सुधर सके। केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों श्रमिकों के उत्थान के लिए अब कुछ संतोषजनक कार्य करने लगी हैं, फिर भी इन श्रमिकों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें जानना आवश्यक है।

पहिले कारखानों में जब श्रमिकों की कमी होती भी तो गाँव में श्रमिक लाने के लिए ठेकेदार भेजे जाते थे। अब यहाँ अभिकार उद्योगों में यह बात नहीं है और उन्हें श्रमिक लाने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु फिर भी अनेक उद्योगों में यह प्रथा अब तक प्रचलित है। ऐसे उद्योगों में मजदूर लाकर भरपूर कराने का काम ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है और यही ठेकेदार उनके काम की देख-भाल पर भी लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक इन ठेकेदारों पर ही आश्रित बन जाते हैं। ये ठेकेदार श्रमिकों से उन्हें काम दिवाने के बदले में रिश्वत लेते हैं और उन्हें अनुचित में अनुचित बातों के लिए भी दबाते रहते हैं। ग्राहो कमीशन ने सिफारिश की थी कि श्रमिकों

को भरती का काम ठेकेदारा पर न छाड़ कर श्रम अफसरों का दे देना चाहिए। श्रम अफसर ही उन्हें भरती करें तथा वही उन्हें भुगतान करें। इन श्रम अफसरों का राज्य की आर स इस राज्य में श्रमिकों को प्रबन्ध होना चाहिए। इसी मिशनरों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल तथा अन्य राज्यों की सरकारें श्रम अफसरों का शक्ति देना मुविधाएँ देना लगी हैं। इससे आता है कि श्रमिकों का भरती करना के लिए 'काम दिनाग्रा दफ्तर' खोल गए हैं जो वहाँ लागा जा शोचनीय दिलाएँ का प्रबन्ध करते हैं। १९४७-४८ में कुल मिला कर ५३ 'काम दिनाग्रा दफ्तर' थे जिनमें ७ प्रादेशिक तथा ४६ उप-प्रादेशिक दफ्तर थे। अब इनकी संख्या बढ़ता जा रही है। परन्तु इस योजना को विस्तृत बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में एक 'काम दिनाग्रा दफ्तर' स्थापित होना चाहिए जिससे उस जिले के निवासी सरलता से वहाँ तक पहुँच सकें और उन्हें काम पाने में आसानी रहे।

श्रमिकों के सम्बन्ध में हमारे यहाँ एक समस्या यह है कि ये श्रमिक उद्योगों में स्थायी रूप से रह कर काम नहीं करते। ये लोग थोड़े दिन काम करते हैं और जब कुछ रुपया इनके पास इकट्ठा हो जाता है तो काम पर आना बन्द कर देते हैं और जब पैसा पास नहीं रहता तो फिर काम पर आने लगते हैं। शाही कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 'भारतीय श्रमिकों के विषय में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे स्थायी रूप से काम नहीं करते। इसका कारण यह है कि वे लाग गाँवाँ से अपने खाली समय में उद्योगों में काम करने के लिए शहरों में चले आते हैं और जब इनकी इच्छा होता है तभी फिर गाँवाँ में लौट जाते हैं। इस प्रकार भारतीय श्रम स्थायी नहीं होता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उद्योग में कभी कभी श्रमिकों की कमी हो जाती है जिससे उत्पादन कम होना लगता है। श्रमिकों के स्थायी न रहने के अनेक कारण हैं। ये लाग अधिकांश में कृषक होते हैं अतः जैसे ही कृषि का समय आता है वे उद्योगों को छोड़कर गाँवाँ में लौट जाते हैं। दूसरे, इन्हें अपने गाँवों तथा अपने परिवारों का इतना माह होता है कि थोड़े दिन उद्योगों में काम करने के पश्चात् ही इन्हें उनकी याद आती है और वे वहीं चले जाते हैं। श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उद्योगों में आस पास रहने देने की प्रवृत्ति

सामाजी सुविकास की ओर जिसमें वे अपने बाव-बच्चा के साथ रहें और उनके। इसमें उनकी अनुपस्थिति बहुत बुरा भीमा में कम हो जायगी। परन्तु इस भी यह समस्या पुनः रूप में हल नहीं हो सकती। इसमें बुरा नहीं मगर समाधान में समाधान के कारण तथा कृत्रिम आधार के कारण होने के कारण सामाजिक जनता समाज रूप में यहसे में आकर समझे लगा है और उपायों में काम करनी है। बुरा समा देवने में भी आया है। कम कामकाजी अनुपस्थिति और अनुपस्थिति के और भी कारण हैं जैसे बीमारी, उपायों में आकर समय तक काम करने का बकाया, औद्योगिक मशीनों का भय, सामाजिक तथा धार्मिक शोषण, जोरों के आधारों के कारण में उनका सन्देह, आदि, आदि। यदि उपायों में इन बातोंमें से या दूर करें तो आमक समाज बन सकने दें और उपायों का यह समस्या सुलभ सहाई है।

आमकों के विषय में एक समस्या यह चलनाई जानी है कि वे अपने काम में कुशल नहीं होते। भारतीय आन्दोलन अन्य देशों के आन्दोलनों की अपेक्षा बहुत अनुपस्थित होता है। इसका आधिकारिक उत्तरदायक उनका मानना है। उनके मानिक ने तो उन्हें उनके काम की शक्ति देना है और न इस बात की देना मान करन है कि जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं वे उनके अनुपस्थित देना नहीं। कारणों का सहाई, सहायता तथा सामाजिक सम्बन्धों का आधारों में आकर वे कुशलता पर कार्य प्रभाव पड़ता है। हमारे देश के उद्योगपति इन बातों का विशेष ध्यान नहीं करते। जहाँ आम्हारा का बीमारी में उनकी आवश्यक देखभाल की जा है और न उनके दिव्य-कल्याण का। ध्यान रखना जाता है। इसमें उनकी कार्यक्षमता कम होता है। फिर उनका मानिक उनमें आवश्यकता में अधिक काम कराना है। यदि इन बातों में सुधार करा दिया जाय तो धर्म की कुशलता के स्तर में तो पाठनाई के यह दूर हो सकती है और आमक कुशल बन सकती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार उद्योगपति तथा आमकों के दिव्य-कल्याण का आवश्यक सामाजी सुदाना पड़ना है। काम करने के घण्टों में नियमानुसार निर्धारित किए जाने लगे हैं। परन्तु इतना होना पर भी आमक तथा एक कुशल नहीं बन सकती जब तक कि उन आवश्यक सुदानों को दूर न कर दें। इससे निम्न दिव्य-कल्याण होना चाहता है।

जहाँ श्रमिक श्रम-श्रम करने कामों की प्रारम्भिक शिक्षा ले सकें। इससे अतिरिक्त उन्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, मकान, आनन्द-प्रमोद की सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए।

औद्योगिक श्रमिकों का एक श्रम की समस्या यह है कि शहरों में उनमें रहने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता। उनमें मकान छोटे, गन्दे और सड़े हुए होते हैं। उनमें संडास और स्नानगृहों का कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता। कहाँ कहाँ तो वे इतने पास-पास रहते हैं कि उनमें रोशनी और हवा का समुचित व्यवस्था भी नहीं होता। बड़े-बड़े शहरों में तो मकानों का और ना-काटन समस्या है। यहाँ जर्मनी की कमाँ हान के कारण बड़े-बड़े चॉल बना दिए जाते हैं जिनमें एक-एक में २०-२० परिवार रहते जाते हैं। एक-एक परिवार के हिस्से में एक-एक कमरा आता है। श्रमिकों की इस समस्या का दूर करने तथा उनकी आय कुशलता बढ़ाने के लिए मैं यह आवश्यक है कि उनके रहने का समुचित प्रबन्ध हो। उद्योगपतियों तथा सरकार का भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। अप्रैल १९४८ में अपनी औद्योगिक नीति घोषित करते समय सरकार ने १० लाख मजदूर गृह बनाने तथा इस सम्बन्ध में देश-व्यापक करने के लिए एक स्थायी बोर्ड बनाने का निश्चय किया था। अभी तक इस विषय में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। बम्बई राज्य में १९४६ में एक कानून बनाया गया था जिससे आधीन जनवरी १९४६ में एक हाउसिंग बोर्ड बनाया गया था। बम्बई राज्य की सरकार ने ५१ करोड़ रुपये की लागत से ६५०० मजदूर-गृह बनाने का निश्चय किया है। भारत सरकार ने खाना में काम करनेवाले मजदूरों की गृह समस्या सुलझाने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया है। श्रमिकों तथा उद्योगों के हित में इस समस्या को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों तथा श्रम-संस्थाओं—सभी को काम करना चाहिए।

श्रमिकों की श्रम की दूसरी समस्या सामाजिक सुरक्षा की है। श्रमिकों को दुर्घटनाओं, बेकारी, बीमारी तथा अन्य आकस्मिक जीवन-घटनों से सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। उसकी आय तो इतनी अधिक होती नहीं कि वह भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उस पर निर्भर रह सके। अतः उसके भविष्य

के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके सहारे वह आगे आगे बढ़ती कठिनाइयों को पार कर सके। पश्चिमी देशों में श्रमिकों के लिए इस प्रकार की अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं। हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की उतनी अधिक व्यवस्था तो अभी नहीं हो सकी है जिनकी इंग्लैण्ड में या अन्य देशों में है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस ओर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। श्रमिक-हर्जाना कानून बनाए गए हैं जिनके अनुसार श्रमिकों के साथ काम करते-करते कोई दुर्घटना होने पर उन्हें हर्जाना दिया जाता है। इसमें श्रमिकों की एक समस्या हल हो गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर भी सरकार ने कुछ काम किया है। अप्रैल १९४८ में एक एम्प्लॉयज इन्श्योरेंस एक्ट बना दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना एक कारपोरेशन को सौंप दी गई है। इस कारपोरेशन में केन्द्रीय सरकार के धर्म मन्त्री, केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य मन्त्री, उद्योगपतियों के प्रतिनिधि तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कोष बना हुआ है जिसमें श्रमिकों तथा श्रमिका द्वारा राशि जमा होती है, सरकारी सहायता भी जमा होती है तथा अन्य किन्हीं साधनों से जो राशि प्राप्त हो सके, वह भी जमा होती रहती है। केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंच सालों में कारपोरेशन के संचालन व्यय का २ भाग देना स्वीकार किया है तथा प्रांतीय सरकारें, श्रमिकों की चिकित्सा में जो व्यय होगा है उसकी राशि जमा करती है। उद्योगपति और श्रमिक जो राशि जमा करते हैं वह कानून द्वारा निर्धारित कर दी गई है। श्रमिकों की राशि उनकी तनख्वाह से काट ली जाती है। राशि प्राप्त होता-होता जमा करली जाती है। इस प्रकार जो कोष बना हुआ है उसमें से श्रमिकों को उनकी बीमारी के समय में, स्थितियों को उनके अपने-अपने दिनों में तथा श्रमिकों को उनके साथ दुर्घटना होने पर सहायता दी जाती है। श्रमिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के लोगों को भी सहायता दी जाती है। इस प्रकार इस योजना से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ मिल गई हैं। स्थितियों के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में जाने के दिनों में सहायता देने के लिए कोष बने हुए हैं। हाल ही में सरकार ने मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फण्ड योजना बनाई है। यह योजना अभी कुछ उद्योगों में ही लागू हुई है परन्तु शनैः शनैः

इसे बढ़ाकर अन्य उद्योगों में भी लागू किया जाएगा ।

श्रमिका की श्रम की तमगा समस्या मजदूरी की दरों के बारे में है । एक ही प्रकार के काम के लिए एक ही उद्ग या कारखाने में या भिन्न भिन्न कारखानों में भिन्न भिन्न वतन की दरें जाती हैं । श्रमिका का वतन न तो उनका रतन मरन के हिसाब से दिया जाता है और न वह उनके पारिवारिक व्यय के लिए पर्याप्त होता है । यह वही ता वतन नियमत रूप से भी नहीं दिया जाता और उनके हिसाब से काम करना गड़बड़ी कर दी जाती है । इससे लिए उनको मजदूरी की अनग्न र दर व ध देने का अ पश्यकता है । इस समस्या को सरकार ने सानन बनाकर भला प्रकार सुलभान की च्छा व है । मजदूरी सुगतान कानून बना ाया गया है जो २०० रु० मासिक से कम मजदूरी पानेवाले श्रमिका पर लागू होता है । पहिल यह कानून वरल कारखानों में काम करने वाल मजदूरों में ही लागू होता था परन्तु उनवरी १९४८ से यह खाना में काम करनेवाले श्रमिका के लिए भी लागू कर दिया है । इस कानून में वतन समय पर दिए जाने तथा वतन में स काटे जानेवाले जुमाने आदि बातों की व्यस्त्या की गई है । इसी प्रकार १९४८ में निम्नतम मजदूरी कानून पास किया गया है । इससे अनुसार श्रमिका को मिलनवाला निम्न-म मजदूरी को दरे ान र्चन कर दा गई है । इससे श्रमिका की वतन सम्बन्धी समस्याएँ अधि र सीमा तक हल हो गई हैं ।

श्रमिका में पर्याप्त और सुचारु संगठन होने के कारण उह अपने माजिसा से अपने अधिरारों की माग करने में बड़ी अइचनें रह है और काम-कमाता वग-सधप इतना बड़ जाता है कि श्रमिका को अनुचित बात के लिए भी दबा कर उनमें काम लिया जाता है । परन्तु अब यह समस्या इतना भीषण नहीं रही है जितना दस वर्ष पहिल था । औद्योगिकरण के साथ साथ श्रमिका में चेतना आती रहा है और उनका संगठन भी होता जा रहा है । उनका श्रमों श्रम-मरस्थाएँ हैं जो सदस्या के हितों की रक्षा करती हैं । सरकार ने इन मरस्थाओं को मान्यता देने के लिए ट्रेड-यूनियन कानून पास कर रक्का हैं जिनका अनुसार इन मरस्थाओं का सरकार और उद्योगपतिया के साथ सम्पक बना रहता है । श्रमिका तथा उनका मालका के बीच में होनेवाला नगड़ा का

निराग करने के लिए भी सरकार ने ट्रेड डिस्पुट एक्ट पास किया हुआ है जिसमें इन भगदड़ों की मुनासब खरग निरटारने का व्यवस्था का गई है। इस प्रकार औद्योगिक धमिकों की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार न प्रयत्न कर रह्ये है। यदि इन उपायों को सकल बनाया जा सका तो धमिकों की स्थिति निश्चित ही सुधर जायगी परन्तु इस कार्य में सरकार, उद्योगपति तथा धमिक—तीनों का ही काम करना चाहिए।

२०—भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास

‘पर्यटन उद्योग’ विदेशी मुद्रा कमाने का एक ऐसा सरल साधन है जिससे द्वारा राष्ट्रीय आय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना—दोनों ही बढ़ाए जा सकते हैं। सुदूर पूर्व तथा पश्चिम के अनेक राष्ट्र नई-नई योजनाएँ बनाकर अपने अपने पर्यटन उद्योग को उन्नत बनाते रहे हैं। एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक कमोशन ने सुझाया है कि भारत में भी इस उद्योग को उन्नत बनाकर डॉलर कमाए जा सकते हैं। कमोशन का विचार है कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दर्शनाय स्थान डॉलर कमाने में अधिक योग दे सकते हैं। वैसे तो हमारा देश विदेशी यात्रियों व दर्शकों का पन्द्र रहा है परन्तु उनका क्षेत्र और उद्देश्य केवल धार्मिक था। अब भारत के प्राकृतिक स्थानों को विदेशी दर्शकों का मनोरञ्जन-क्षेत्र बनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। हिमाच्छादित हिमालय की चोटियाँ, काश्मीर की मनोहर घाटी, विभिन्न जलस्रोत व राजपूताना का सौंदर्य प्रकृति की देन है। इसी भाँति ताजमहल, विशाल दुर्ग, अजन्ता एलोरा की चित्रकारी तथा हिन्दू कालीन अन्य ऐतिहासिक स्थान विदेशियों के लिए अद्भुत चमत्कार हैं। इन्हीं सब स्थानों का भ्रमण करने के लिए यदि अमेरिका से दर्शक आने लगे तो देश के ‘पर्यटन-उद्योग’ से डॉलर कमाए जा सकेंगे। अमेरिका के दर्शक देशाटन-पर्यटन में ही ११,००,००,००,००० डॉलर प्रति वर्ष व्यय करते हैं। योरोप के देश इसी उद्योग से विपुल डॉलर-राशि कमाते रहे हैं। १९४८ से १९५१ तक योरोप को ‘पर्यटन-उद्योग’ द्वारा लगभग ३,००,००,००,००० डालर मिले। इंग्लैंड ने इन्हीं तीन वर्षों में इस उद्योग द्वारा १४,००,००,००० डॉलर कमाने की योजना बनाई थी। १९४८ में इंग्लैंड ने ‘पर्यटन उद्योग’ द्वारा निर्माण-उद्योग की अपेक्षा अधिक डॉलर कमाए। उस वर्ष ५,००,००० से भी अधिक विदेशी दर्शकों ने अपना अवकाश समय इंग्लैंड में व्यतीत किया। इन ‘पर्यटकों’ ने लगभग ४,७०,००,००० पौण्ड इंग्लैंड में व्यय किए जिनमें से २,१०,००,०००

पौण्ड के डॉलर तथा बासी के अन्य दुर्लभ मुद्रा कमाए गए। १९४६ के प्रथम ६ महीनों में २,५०,००० से भी अधिक दर्शक इंग्लैण्ड में आए तथा उस वर्ष कुल मिलाकर उन्होंने ४५,००,००० पौण्ड वर्षा खर्च किए। स्ट्रैट्समैण्ड का तो यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कमाया जाता है। वर्षा की सरकार विज्ञापन पर विपुल धन राशि व्यय करके विदेशी दर्शकों को अपने देश के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए आकर्षित करती रहती है जिसमें प्रतिवर्ष असंख्य दर्शक वहाँ आकर अपने समय व्यतीत करने हैं और सरकार उनसे विदेशी मुद्रा कमाती है। वेनेडा, ब्रिजियम, स्पेन, लक्जमबर्ग तथा जापान आदि देशों ने अपने-अपने 'पर्यटन उद्योग' का बढ़ाने के लिए रिस्रुत योजनाएँ बनाई हैं। वेनेडा की सरकार विदेशों में अपने देश के विज्ञापन पर अतुल राशि व्यय करती रही है। मॉन्टर्नैण्ड, ब्रिजियम तथा लक्जमबर्ग ने मिलकर संयुक्त योजना के अनुसार अपने अपने उद्योगों का बढ़ाने का काम आरम्भ कर दिया है। स्पेन में विदेशियों को ठहरने के लिए होटलों का प्रबन्ध किया गया है तथा ऐसे होटलों को धन की सहायता देने के लिए एक विशेष बैंक स्थापित किया गया है। १९४६ में स्पेन में लगभग ३,००,००० विदेशी आए जिनमें वहाँ की सरकार ने विदेशी मुद्राएँ कमाईं। जापान में भी विदेशी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं। 'दक्षिणी अफ्रीका पर्यटन कारपोरेशन' ने विदेशों दर्शकों को नई नई सुविधाएँ देकर अपना यह उद्योग बढ़ा लिया है। हमारा पड़ोसी देश लका भी 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा ही ६०,००,००० रुपये के आस-पास प्रति वर्ष कमाता रहा है। १९४८ में लका की सरकार ने २,६०,००० रुपये पर्यटन-उद्योग के विकास पर व्यय किए थे। भारत यद्यपि इस दृष्टि से एक धनी देश है परन्तु फिर भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। विदेशी दर्शकों को भारत आने में आकर्षित करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें भारत के उन आकर्षक स्थानों का बोध कराया जाय तथा दर्शनीय स्थानों के जल-विद्युत विदेशों में प्रदर्शित किए जाए। देश देश में 'पर्यटन-सूचना समिति' व भ्रमण-सूचना-केन्द्र स्थापित होने चाहिए जो इस प्रकार का विज्ञान करें, प्रचार करें और भारत आनेवाले दर्शकों को देश के विभिन्न दर्शनीय स्थानों का पूरा पूरा

जान रहा सके। आयरलैंड का 'आयर दर्शक मध' तथा अमराता का 'दक्षिण अमराता दर्शक कारपागशन' विदेशी दर्शकों का विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएँ देते हैं जिससे भ्रमण करने में सुविधा हो व दर्शकों का यातायात-साधन, निवास एवं तथा भोजन आदि का उपयुक्त सुविधाएँ प्राप्त हों। हमारे देश में भी ऐसा संचालन होना चाहिए।

भारत सरकार ने भी अब देश के 'पर्यटन उद्योग' का विकास करने की वित्तीय योजना बनाई है। काश्मीर की मनोरम घाटी व रमान चलचित्र तैयार कराए हैं जो विदेशों में दिखाए जाते हैं। मनोरम सरकार ने 'काश्मीर आग्री' 'काश्मीर का गैर' आन्दोलन उठा रखा है। इनमें विदेशी दर्शकों का आकर्षित करने में काफी सहायता मिली। पर्यटन मूल्यना पुस्तक तथा अन्य ऐसी ही तरह तरह के रमान उद्घोषित विदेशों में वितरित किए गए हैं जिनसे आकर्षित होकर विदेशी हमारे यहाँ आकर प्रकाश वितरित लगें हैं। कन्द्रीय सरकार के यातायात विभाग ने इस उद्योग का दायित्व अपने ऊपर लेकर एक समिति बनाई है जो इस विकास की योजनाओं पर विचार करके कार्यान्वित करती है। विदेशी दर्शकों का यातायात का विशेष सुविधाएँ दी जाने लगी हैं। पर्यटकों के लिए आयात निर्यात सम्बन्धी नियम ढीले कर दिए गए हैं। अब कोई भी विदेशी दर्शक अपने प्रयाण के लिए खुला शराब बाजार में ला सकता है। पहिले एक दर्शक बिना चुगी चुकाए अपने निजी प्रयोग के लिए केवल एक घड़ी, एक पाउएन्टैन तथा ५० केमरा ला सकता था परन्तु अब प्रत्येक दर्शक दो पाउएन्ट ला सकता है। पहिले पाचम हवाई अड्डे पर आए हुए दर्शकों का रजिस्ट्रेशन सर्वोपिक्टे लेने के लिए १५ मील चल कर दिल्ली जना पड़ता था परन्तु अब सुविधा देने की दृष्टि से यह रजिस्ट्रेशन सर्वोपिक्टे हवाई अड्डे पर मिलने का प्रबन्ध कर दिया गया है। विदेशों में हमारे राजदूतों के पास 'पर्यटन-पत्र' रख दिए गए हैं जो विदेशों में भारत आने वाले पर्यटकों को दिए जाते हैं। इस प्रकार उन्हें भारत सरकार के पास लिखा पदो करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार की योजना है कि देश में आए हुए दर्शकों का एक विशेष प्रकार के परिचयपत्र दे दिये जाएँ जिनको दिगा कर दर्शकों को चुगी की सुविधा मिले तथा उनका ठहरने के लिए आरामगृह एवं डाकघरों

की सुविधाएँ भी मिल सकें। अज्ञातवश तथा अन्य दर्शनीय स्थानों के प्रबन्धक इन पत्रों को देखकर दर्शकों को सब प्रकार की सुविधाएँ दे। रेल में यात्रा करने समय विदेशी पर्यटक अपनी पसन्द का भोजन कर सकें। इसका प्रबन्ध भी कर दिया गया है। दिल्ली, आगरा, बंबई, कलकत्ता, शिमला, दार्जीलिंग, हैदराबाद, जयपुर आदि आदि प्रमुख स्थानों पर 'पर्यटन कन्ट्र' गोलों गण हैं जहाँ से पर्यटकों को आवश्यक सूचना और सुविधाएँ मिलती हैं। सरकार दर्शकों को 'मार्गवाहक' साथ देने का भी प्रबन्ध करने लगी है। रेलवे रेलगाइयों तथा मस्टों का भी दर्शकों को सुमाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। पर्यटन-उद्योग के विकास का योजना में सरकार ने होटलों की सुविधाओं को बढ़ाने का काम भी सम्पादित कर लिया गया है। होटलों में रेस्तराँन आदि वस्तुओं की सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। होटलों का स्तर ऊँचा किया जा रहा है जिससे विदेशी दर्शकों को ठहरने में अनुपयोग न हो। सरकार 'दर्शकवाहक' (Guides) तैयार किये जा रहे हैं जिससे वे नियम के साथ दर्शकों को सभी स्थानों दिखा सकें और दर्शनीय वस्तुओं का महत्व समझा सकें। १९५०-५१ में सरकार ने विचारने पर ५ लाख रुपये तथा प्रादेशिक संगठन पर २ लाख रुपये व्यय किये थे। इससे ज्ञात होता है कि सरकार 'पर्यटन उद्योग' का महत्व भली भाँति समझने लगी है। यह निश्चित है कि इस उद्योग के विकास से केवल विदेशी पर्यटकों की कमाई नहीं होगी बल्कि भारत और अन्य देशों की सामर्थ्य में वृद्धि होगी और दर्शकों द्वारा हजार बेरोजगारों, बालक-कर्मियों तथा कुटीर-धर्मियों को भी प्रगति मिलेगी।

२१—उद्योगों की वित्त समस्या

सभी मानते हैं कि देश के जनसाधारण का जीवनस्तर ऊँचा करने के लिए देश में औद्योगीकरण होना चाहिए। औद्योगीकरण के बिना देश के आर्थिक स्तर में सुधार नहीं आसकता। परन्तु औद्योगीकरण के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण कठिनाई उद्योगों के लिए पूँजी प्राप्त करना की है। नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए पुराने उद्योगों का पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए तथा युद्ध एवं मंदी जैसे आर्थिक संकटों से उद्योगों को निष्काश कर उन्नत बनाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। बिना पूँजी के कोई भी उद्योग, छोटा हो या बड़ा, स्थापित किया ही नहीं जा सकता। उद्योगों में प्रायः दो कामों के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है—एक, उद्योग स्थापित करते समय भूमि, कारखाने, मशीनें, आदि स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए, दूसरा, कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों की मजदूरी चुकाने के लिए तथा दिन रात होनेवाले व्यय निश्चित और आकस्मिक खर्चों का भुगतान करने के लिए। स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए जो पूँजी लगाई जाती है वह स्थायी रूप से उद्योगों में फँस जाती है इसलिए उस ऐसे साधनों से प्राप्त किया जाता है जो स्थायी रूप से उसे उद्योगों में लगाए रहें और वापिस निकालने पर व्यर्थ न करें। ऐसे पूँजी सामान्यतः बचत बैंक, बीमा कंपनियों, बैंकों, वित्त संस्थानों, आदि से प्राप्त की जाती है। कच्चा माल खरीदने तथा अन्य खर्चों के लिए पूँजी स्थायी रूप से उद्योगों में नहीं फँसती बल्कि जैसे ही पक्का माल बिकता जाता है इस पूँजी का भुगतान कर दिया जाता है। फिर भी उद्योगों में कच्चा माल की तो सदैव ही आवश्यकता रहती है। इसलिए थोड़ी सी पूँजी इस माल में सदैव ही घिरी रहती है। इसे भी स्थायी पूँजी ही कहना चाहिए। ऐसे पूँजी सामान्यतः श्रमिकों, व्यापारियों, बैंकों, वित्त संस्थानों, आदि से प्राप्त की जाती है। ये श्रमिक प्रायः अल्पकालीन हाते हैं और जैसे ही कच्चे माल का पक्का माल में बदल कर बचा जाता है वैसे ही इस श्रम का भुगतान भी कर दिया जाता है।

हमारे देश में अब तक जो कुछ भी औद्योगीकरण हुआ है और जितने भी थोड़े घने उद्योग स्थापित हुए हैं उन सबके लिये पूँजी का प्रबन्ध दो साधनों से होता रहा है—(१) मनेजिग एजेंट्स द्वारा, (२) विदेशी पूँजीपतियों या विदेशी श्रमों द्वारा। न हमारे देश में अन्य औद्योगिक देशों का भविष्य औद्योगिक बैंक रहे हैं और न वित्त कारपोरेशन रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश की बैंक ने उद्योगों की वित्त सहायता करने में कुछ भी उल्लेखनीय योग नहीं दिया है। हमारे देशवासियों भी पूँजी लगाने में सदैव भय प्राने रहे हैं और न उन्हें पूँजी लगाने के काम में किसी से समझाया ही है। जॉ. मनेजिग एजेंट्स के बल पर और उनकी की साम्य पर थोड़े बहुत श्राव्य भिन्न रहे हैं। परन्तु वे भी ब्याज और उद्योगशाला उद्योगों के लिए न कि अवनत उद्योगों को। पूँजी के अभाव में गिरे हुए उद्योगों को तो किसी से सहारा दिया ही नहीं है। अभावका का भविष्य हमारे यहाँ विनियोगियों की मुक्ति के लिए विनियोगी-दृष्ट या विनियोग बैंक भी नहीं है। कल्पने का अर्थ यह है कि भारत में उद्योगों के लिए पूँजी की एक बड़ी समस्या रही है और आज भी है। इस समस्या के कारण ही हमारे यहाँ उद्योगों की आशानुत्पल प्रगति नहीं हो सकी है।

पूँजी का कोई विशेष प्रबन्ध न होने के कारण हमारे उद्योग प्रगतिशील या जनता में जमा राशि लेकर अथवा मनेजिग एजेंट्स से श्राव्य ले लियकर काम चलाने रहे हैं। स्थाया सम्पत्ति परीक्षण का काम तो श्रम बैंक पर ही होता है। प्रसार-प्रसार के श्रम बैंक जानते हैं जिसमें सभी प्रकार के विनियोगी अवनत अपनी मुक्ति और मुक्ति के अनुसार श्रम परीक्षण कर पूँजी का विनियोग कर सकें। परन्तु इसमें भी कुछ दोष हैं। हमारे उद्योगपति जनता के सभी वर्गों की मुक्ति-धात्रों का ठीक ठीक अध्ययन न करके श्रम बैंक ले लगते हैं जिसमें कभी कभी वे विनियोगियों के अनुदान नहीं होने और पूँजी प्राप्त नहीं हो पाता। कभी-कभी आवश्यक पूँजी का ठीक-ठीक अनुमान लगाए बिना ही श्रम बैंक दिए जाते हैं जिसमें आगे चलकर पूँजी का अभाव होने लगता है। दीर्घकाल न तथा अल्प-कालीन पूँजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाए बिना ही काम आरम्भ कर दिया जाता है जिसमें आगे पूँजी इकट्ठा करने की फिर आवश्यकता होने लगती है और पूँजी न मिलने के कारण उद्योग बन्द करने पड़ते हैं। श्रम-

पत्र वचनर पूजा प्राप्त करने का तो हमारे यहाँ आधुनिक प्रचार ही नहीं है। अहमदाबाद का ५६ मिला म मूल पूजा का लगभग १० प्रतिशत भाग अष्टम पत्र वचनर प्राप्त किया गया है जबकि इङ्ग्लैण्ड के उद्योगी इन पूजा की आवश्यकताओं का २० प्रतिशत से भी अधिक भाग अष्टम पत्रों का वचनर प्राप्त करते हैं। अष्टम पत्रों का प्रचार न होने का अनेक कारण हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं। जहाँ तक लागू से जमा राशि लेकर पूजा प्राप्त करने का प्रश्न है सो यह प्रथा देश भर में प्रचलित नहीं है। कबल बम्बई और अहमदाबाद का आर हा जमा लेकर पूजा का काम चलाया जाता रहा है। परन्तु इस प्रथा में एक बड़ा भारी दोष रहा है। जब तक उद्योग लाभ कमाते रहते हैं तब तक जमा करनेवाले लोग अपना अपना रकम उसमें जमा करने हैं और आ हा जमा होने ही जाता है या अथवा कोई अस्वाभाविक घटना या जाना है तभी वह लोग अपना अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं जिससे उद्योगों में पूजा का जमा ही जाता है और वे कभी जमा बंद भी हो जाते हैं। व्यापारिक वर्ग की कुछ अपनी ऐसी फाटनाइयाँ हैं जिनका कारण वे उद्योगों की सहायता नहीं कर सकते हैं। उद्योगों में प्रायः दायकाल के लिए पूजा की आवश्यकता पड़ती है परन्तु व्यापारिक बैंक अपना रकम दायकाल के लिए उधार नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें सदैव यह भय रहता है कि न मालूम कब उनका ग्राहक अपनी जमा राशि निकालने आ जाए। उस पारस्थिति में बैंक का सन्तुष्टि का भय रहता है। हाँ, ये बैंक अल्पकाल के लिए अगुवाई करते हैं परन्तु वह भी बहुत कम। इसका अर्थ यह है कि हमारे व्यापारिक वर्ग उद्योगों की आरम्भ में सहायता नहीं कर पाते बल्कि उद्योगों को चालू हो जाने पर ही थोड़ा बहुत सहायता करते हैं जो उद्योगों का पर्याप्त नहीं होती।

इन बातों पर विचारितवा में हमारे मार्निंग एन्वैस्टमेंट्स हा उद्योगों का नाम देते रहते हैं और वे ही इनका लाञ्छित पालन भी करते रहते हैं। अपना नाम पर वे अगुवाई लेकर उद्योगों का देते हैं अपनी सामग्री और रियायत पर कम्पानियों का अगुवाई करते हैं, अष्टम पत्र वचनर तथा आवश्यकता पड़ने पर वे अपने पास से अगुवाई देकर उद्योगों की सहायता करते रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा देश आज जो भी औद्योगिक प्रगति कर रहा है सब मनीजिंग एन्वैस्टमेंट्स

के परिभ्रम का फल है। परन्तु अब यह साधन भी देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं पड़ता। भूतकाल में इन लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की महान कठिनाई को परन्तु आज के युग में इनका भी कुछ भीमान ही चला है। वर्तमान योजनाओं के अनुसार जिस गति में देश का औद्योगिकरण होगा वह उभर लगे हुए जुटाने का काम करना अब मेनेजिंग एजेंट्स के काम का नहीं है। अब यह प्रणाली प्राचीन, जुटाने तथा अयोग्य मिश्रणों का नहीं है। नए-नए उद्योगों को जमान और पुराने उद्योगों का संसादन करने का काम इनके पास का काम नहीं है। दूसरी बात और है। वे लोग जनसाधारण से अपने प्रति विश्वास नहीं जमा कर रहे। विद्युत् निर्माताओं में इन्होंने उद्योगों का अपने हाथ की कठपुतली बनाकर जिस प्रकार नकल है और कमनियों के असाधारणों पर जो शासन किया है वह काम की मान नहीं है। निश्चय ही, इन्होंने अनेक मरना हुआ उद्योगों का जीवन दिया परन्तु अनेक जीवित उद्योगों का पतले भूटा मूल बना कर अधिकांश में ले लिया और यह स्वयं उसके अधिकांश अनेक अनेक दिया परन्तु असाधारणों को मूल बना दिया। यह ठीक है कि इनके पास उद्योगों का निर्माण पूँजी का सारा भाग परन्तु पूँजी के चल पर इन्होंने उद्योगों की सारा भाग का भाग उन्हीं गुणों बनाया। देश के वर्तमान और भविष्य औद्योगिक संसादन में मेनेजिंग एजेंट्स अब अधिक काम के नहीं रहे हैं। कुछ दिनों बाद अभी इनसे और काम निगल लिया जाय परन्तु अन्त में चल कर तो उद्योगों की वित्त समस्या का स्थायी और स्थायी रूप निकालना ही है।

विदेशी पूँजी का मान यह है कि जब तक हमारी सहायता में भी देश के औद्योगिकरण में कभी योगदान है। परन्तु इसके विषय में भी अब लोगों में तरह-तरह के संदेह होने लगे हैं। विदेशी पूँजी में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जिनसे हमारे राजनीतिक हितों को नोट लगाया रहा है। परन्तु फिर भी जिस मात्रा में और किस भीमा तक इसके द्वारा उद्योगों की वित्त समस्या हल हो सकती है इसका विश्लेषण अगले पृष्ठों में किया गया है।

विद्युत् कुछ वर्षों में वर्तमान उद्योगों की वित्त-समस्या कुछ मुलभूत-सी होकर पड़ी है। नई नई बैंकों तथा इन्डियन कम्पनियों के स्थापन में उद्योगों को

कुछ सहायता मिली है। ये समस्याएँ उद्योगों का वित्त समस्या में कुछ दिल चस्पी लेन रहे हैं और उन्होंने औद्योगिक कम्पनियाँ व ग्राम तथा श्रम पत्र खरीद कर और श्रमज्ञान भण्डारण भी देखकर उनकी सहायता की है। किसी किसी मामले में तो इन बातों ने उद्योगों का बहुत प्रशंसनीय सहायता दी है। औद्योगिक कम्पनियों तथा व्यापारिक बैंकों के सलाहकारों ने व्यक्तिगत रूप से कारण उन्होंने उद्योगों का वित्त सहायता देने में सहायता दिया है। १९५८ में 'औद्योगिक वित्त कारपोरेशन' गठित कर सरकार ने भी उद्योगों का वित्त समस्या कुछ सामान्य सहूलियत करने का प्रयत्न किया है। इस कारपोरेशन का पूँजी १०० करोड़ रुपये है और अपने तीन वर्ष के जीवन में इसने अनेक उद्योगों का वित्त सहायता दी है। इसने अधिकतर दायित्वपूर्ण तथा मध्यकालीन श्रम दिए हैं तथा यह औद्योगिक कम्पनियों के ग्राम तथा श्रम पत्र बचन में भी उनकी सहायता करता है। कई राज्यों में भी 'प्रांतीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन' बनाए जा चुके हैं जो राज्यों के उद्योगों का वित्त सहायता देते हैं। परन्तु इन सबसे भी उद्योगों की वित्त समस्या मुक्त नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन अपने मासिक मात्रा में ही उद्योगों की सहायता कर सकता है। इससे श्रम देने की शक्ति कुछ कम सरल नहीं है। अब तो इससे कुछ मिला कर साइ १२ करोड़ रुपये श्रम दिया है। आज जब कि हमारे देश में औद्योगिक विकास का इतना भारी काम बाँटी है और अनेक योजनाएँ पूँजी व अभियान में डूब पड़ी है—इस बात की आवश्यकता है कि उद्योगों की वित्त समस्या का हल करने के और भी उपाय किए जाएँ। हमारा मतलब यह नहीं कि वित्त कारपोरेशन ने कुछ काम नहीं किया हो या ये काम नहीं कर सकते हैं, परन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि इनसे अनिश्चित और भी उपाय होने चाहिए जिससे औद्योगिकीकरण के काम का प्रगति मिले।

- हमारे देश में उद्योगों की वर्तमान वित्त समस्या के दो मुख्य पहलू हैं—
- (१) वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों का वित्त पूँजी की आवश्यकता है ?
 - (२) यह आवश्यक पूँजी स्थायी रूप से किस प्रकार प्राप्त की जाय ?

उद्योगों की आवश्यक पूँजी की मात्रा के विषय में भिन्न भिन्न अनुमान हैं। बम्बई योजना के प्रणेतृओं ने आर्थिक विकास को समुचित योजना के लिए १०,०००

करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था जिसमें उद्योगों के लिए अनुमानित: ३०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आवश्यकता आती है। राष्ट्रीय योजना समिति ने भी अपनी भूमिका में लगभग इतनी ही पूँजी का अनुमान लगाया था। हो सकता है यह अनुमान मूलतः हो परन्तु यह सब औद्योगीकरण के क्षेत्र और मति पर निर्भर करता है। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने अनुमान लगाया है कि देशवासियों की वास्तविक आय में २% की वृद्धि करने के लिए करीब १५०० करोड़ रुपये का निनियोग करना होगा। परन्तु इन अनुमानों में उद्योगों के लिए आवश्यक पूँजी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उद्योगों की आवश्यकताएँ तो उनके उद्देश्य, क्षेत्र, साधन तथा मति पर निर्भर करने हैं। जैसा कि योजना कमिशन का विचार है कि "हमारे वर्तमान उद्योगों के लिए पूँजी की जो वर्तमान आवश्यकता है वह अधिकतम पुराने उद्योगों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने के लिए है न कि नए-नए उद्योगों को एक साथ ही बढ़ाने के लिए।" कमिशन का अनुमान है कि पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनसे प्राप्त करने के लिए उद्योगों के विकास में लगभग १२५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें में सरकार २५ करोड़ रुपये देगी, ६० करोड़ रुपये उद्योग स्वयं जुटाएँगे तथा शेष राशि औद्योगिक वित्त कारपोरेशन से लेकर पूरी की जायगी। यह तो दृष्टा कमिशन का अस्थायी विचार केवल पाँच वर्ष तक के लिए। स्थायी रूप से यह समस्या किसे हल हो ? इसके लिए दो साधन सम्भर हैं—(१) विदेशी पूँजी लेकर, (२) देश में ही पूँजी निर्माण करके।

विदेशी पूँजी लेकर उद्योगों की वित्त समस्या मुलभूतना कोई बुरी बात नहीं है। विल्हुली शताब्दी में जर्मनी, फ्रांस, जापान तथा अन्य उद्योग प्रधान देशों ने विदेशों से ऋण लेकर काम चलाया था। हमारे यहाँ भी अब तक विदेशी पूँजी का काफी ध्यान रहा है। रेल मार्ग, नदी-गाड़ी-योजनाएँ, गाने, बैंक, इन्श्योरेंस कम्पनियाँ तथा बड़े बड़े प्रमुख उद्योग विदेशी पूँजी के कारण ही इतनी प्रगति कर सके हैं अब आगे भी हमें द्वारा समस्या हल की जा सकती है। योजना कमिशन का मन है कि देश का औद्योगीकरण में हमें विदेशी पूँजी का स्वागत करने में कोई हानि नहीं क्योंकि इसके द्वारा हमें अपने

उद्योगों को पूँजीगत माल तथा विशेषज्ञ मिल सकेँगे जिनकी हमें इतनी आवश्यकता है। परन्तु क्या हम अब विदेशी पूँजी प्राप्त कर सकते हैं? विदेशी पूँजी लेने से पहिले हमें यह देख लेना चाहिए कि उसका साथ 'विदेशी पूँजीपति' या 'विदेशी राजनैतिक सत्ता' हमारे देश में न आने पावे। हम 'विदेशी पूँजी' लायें न कि 'विदेशी पूँजीवाद'। जैसा कि डॉक्टर राय ने कहा है हमें विदेशी पूँजी का "राजनैतिक डारी" संबंध कर नहीं लेना चाहिए। विदेशी पूँजीपतियों को यहाँ पूँजी लगाने का सुविधाएँ दी जाएँ परन्तु कोई राजनैतिक सत्ता उनका न सीसी जाय। सरकार ने अप्रैल १९४६ में विदेशी पूँजी सम्बन्धी अगनी नीति में जो शर्तें रखी हैं उन पर विदेशी पूँजी का लाया जाय। ये शर्तें निम्न हैं—

१. सरकार को सामान्य औद्योगिक नीति व अन्तर्गत भारतीय और विदेशी पूँजी में कोई अन्तर नहीं सम्झा जायगा।
२. विदेशी पूँजी पर जो लाभ होगा उस तथा पूँजी का वापिस ले जाने के लिए विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएँ दी जाएँगी। विदेशी पूँजी का लौटा कर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
३. यदि राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो पूँजीपतियों का आवश्यक हाना दिया जायगा।

इन शर्तों पर यदि विदेशी पूँजी आवे तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। विदेशी पूँजी प्राप्त करने के निम्न साधन हैं—

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्व।
२. विश्व बैंक।
३. अमेरीका तथा इंग्लैण्ड व अन्य देशों के पूँजीपति।
४. विदेशी सरकारें।

इन साधनों से हमारे देश में पूँजी आइ है और आती रही है, परन्तु क्या इन साधनों से स्थायी रूप से हमारा उद्योगों की वित्त समस्या हल हो सकती है? यह ठीक है कि इनसे हमारी वर्तमान आवश्यकताएँ विशेषतः पूँजीगत माल की तथा विशेषज्ञों की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएँगी। परन्तु जैसा कि डॉ० राय ने कहा है "स्थायी रूप से ये साधन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते।"

हमें अपने देश में भी पूँजी निर्माण का काम करना चाहिए। जनता के दिल में से भय निराल कर उन्हें उद्योगों में सक्रिय निनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उद्योगों की आन्तरिक वित्त आवश्यकताओं के लिए हमारे देश में काफी पूँजी उपलब्ध है, बस उसे उचित रूप से काम में लाने के लिए निरालवाने की है। औद्योगिक कमीशन ने टीक कहा था "कि भारत में उद्योगों का वित्त समस्या देश में धन के अभाव के कारण नहीं है और न भय के कारण है बल्कि औद्योगिक अदृशत्व तथा पूँजी निर्माण के साधनों की कमी के कारण है। इसके लिए देश में औद्योगिक बैंक बनाए जाएँ व निनियोग ट्रस्ट तथा निनियोग-बैंक स्थापित किए जाएँ। वित्त वारपोरेशन प्रत्येक राज्य में होने चाहिए। सरकार छोटी बचत योजना बनाकर लोगों को बचत करना सिखाये [पूँजी निर्माण की योजना पर विस्तृत लेख आगे पढ़िए।] तब उद्योगों की वित्त समस्या अपने ही देश की पूँजी से हल हो सकेगी। वही समस्या का मधा हल होगा।

२२—पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान

गत तास वर्षों में भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में काफी उन्नति की है। आवश्यकता की अनेक उपभाग्य वस्तुएँ अब हमारे देश में ही बनाई जान लगी हैं। तिनमें कपड़ा, चीनी, नमक, मातुन, शक्कर तथा चमक का सामान मुख्य हैं। इस्पात, सामर्य तथा रासायनिक वस्तुएँ बनान में भी हमारे उद्योग ने सन्तोषजनक प्रगत आग्राइ है। युद्ध काल में तथा युद्ध न पश्चात् अनेक नए नए उद्योग स्थापित हुए और अब हमारे देश में रोडिया, साइकिल, बिजली व पखे, माटर, रेल व इंजन आदि, आदि, सामान बनने लगा है परन्तु फिर भी बात यह है कि उपभाग्य वस्तुआ व कारखाना में तो चार हम काफी आगे हों किन्तु पूँजी गत माल बनान में अभी हमारे यहाँ काफी क्षेत्र है। पिछले कुछ दिना स ता औद्योगिक उत्पादन में काफी कमी हाती जा रहा है। कुछ उद्योगों में पहिल का अप्रत्ता २० से ३० प्रातशत तक उत्पादन गिर गया है। यदि सच पृछा जाय तो इसका कारण है—युद्धकाल में मशाना की घिसावट तथा नई मशाना का जान का कठिनाइयाँ श्रमिकों तथा उद्योगपात्यों व बीच पारस्परिक सघष तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ। याजना कमशन ने औद्योगिक उन्नति कदधिकरण स इन दापा का दूर करन का मुक्ताय दिया है। याजना व अन्तर्गत कृषि और बिचाइ का प्रमुख स्थान मिलन व कारण यापना कमशन का उद्देश्य यह रहा है कि ऐम ज्योग पहिल स्थापित किए जाए जा सिचाइ योजनाओं तथा कृषि का सफल बनाने में सहायक ह। इसका बाद याजना कमशन ने उन उद्योगों का उन्नत बनान का मुक्ताय दिया है जो उपभाग्य वस्तुएँ बनाते हैं। याजना में औद्योगिक विकास का जन्म कम निधारित किया गया है —

१. मजदूरी वृद्धि, कृषि-विकास तथा मिचाने और पन बिजली की यात्राओं को सकल बनाने के लिए जो उद्योग आवश्यक हैं, उन्हीं का विकास किया जाय।
२. इससे बाद उपभोग्य वस्तुओं बनानेवाले उद्योगों की वर्तमान कार्यक्षमता के अनुसार उपभोग्य वस्तुओं के लक्ष्य निर्धारण करके उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जाय।
३. इसके पश्चात् इस्पात, लोहा, भारी सामायनिक यन्त्रों आदि वस्तुओं को बनानेवाले उद्योगों का विकास किया जाय।
४. अन्त में, देश के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में जो दोष हैं उन्हें दूर किया जाय।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना समिति ने उद्योगों को तीन भागों में बाँट दिया है, जो इस प्रकार हैं :—

१. मुख्य उद्योग जिन में युद्ध सम्बन्धी वस्तुओं जैसे हथियार, बास्केट आदि अन्य सैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ बनाई जाएँ।
२. 'उत्पादक-वस्तुओं के उद्योग' जिनमें इस्पात, सीमेंट, पटसन का सामान, भारी सामायनिक वस्तुएँ आदि पूर्वोक्त माल बनाया जाय।
३. उपभोग्य-वस्तुओं के उद्योग, जिनमें जनसाधारण को उपभोग्य वस्तुएँ बनाई जाएँ।

चूँकि योजना में कृषि और मिचाने की उन्नति के लिए अधिक महत्त्व दिया गया है इसलिए सरकार के अधिकारि माधन इन्हीं बातों की पूर्ति में लगाने जाएंगे। इसीलिए उद्योगों के लिए भा अधिक धन राशि का निनियोग सम्भव नहीं हो सकेगा। कमोशन के प्रसारण के अनुसार केवल ये ही योजनाएँ पूरी की जाएंगी जो सरकार ने आरम्भ कर रखी हैं। नए क्षेत्र में केवल ये ही

उद्योग बनाए जाएंगे जो वर्तमान में देश की आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य हो। याचना के अनुसार निम्न राशि औद्योगिक विकास पर व्यय की जायेगी।

(करोड़ रुपये में)

दो वर्षों में मिलाकर पाँच वर्षों में मिलाकर
(१९५१-५२) (१९५१-५६)

बड़े पैमाने के उद्योगों में	३८.१	७६.५
छोटे तथा कुटीर-उद्योगों में	४.८	१५.८
औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध में	२.४	४.६
खनिज विकास पर	०.३	१.१
योग	४५.६	१०१.०

पंचवर्षीय योजना में न तो केवल व्यक्तिवाद पर ही जोर दिया गया है और न केवल राष्ट्रीयकरण पर ही। परन्तु दोनों प्रणालियों के प्राधान्य पर औद्योगिक विकास करने का मुद्दा दिया गया है। कमीशन का मत है कि "राष्ट्रीय आयाजन की किसी भी याचना में औद्योगिक विकास के लिए व्यक्तिवाद के आधार पर चलाये गए उद्योगों की नितान्त आवश्यकता है। परन्तु इस प्रकार जो उद्योग चलाए जाएं उनसे मालिकों को उपभोक्ता, विनियोगी तथा भूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए।" इससे लिए योजना कमीशन का मुद्दा है कि उद्योगपतियों, भूमिदाता तथा साहसी औद्योगिकों का अपने अपने दृष्टि कोणों में आवश्यक परिवर्तन कर लेना चाहिए। कमीशन ने व्यक्तिवाद उद्योगों में उद्योगपतियों से मिल कर निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं जिनके अनुसार याचना पूर्ण होने पर उत्पादन बढ़ाने का अनुमान है—यह निश्चित नहीं है कि इन लक्ष्यों को पूरा किया ही जा सकेगा परन्तु फिर भी अनुमान लगा कर ध्येय बना लिया गया है जिसके अनुसार व्यक्तिवाद उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सके।

या नहीं और व्यक्तिगदी उद्योग ठीक प्रकार में काम कर रहे हैं या नहीं, कमीशन ने औद्योगिक विकास-नियंत्रण-एक्ट बनाने का मुझार दिया था जो अब पास हो चुका है। इस कानून में निम्न बातों को विशेष रूप से व्यवस्था की गई है —

- १ सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी नया उद्योग स्थापित न किया जा सकेगा और न पुराने उद्योग का विकास हा किया जा सकेगा। इस प्रकार की स्वीकृति देने समय सरकार उस उद्योग की स्थिति आदि के बारे में कुछ शर्तें रख सकती है।
- २ यदि किसी उद्योग में उत्पादन गिर रहा हो या मान नीची कोटि का बनाया जाने लगा हो, अथवा कोई उद्योग अशुभारिथा के हित में निरुद्ध काम करने लगा हो तो सरकार उस उद्योग की जाँच पड़ताल कर सकती है।
- ३ यदि कोई उद्योग सरकार की दी हुई हिदायतों का पूरा न करे तो उसे सरकार अपने प्रबन्ध में ले सकती है।

औद्योगिक विकास की जाँच-पड़ताल करने तथा उद्योगों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कमीशन ने एक केन्द्रीय औद्योगिक बोर्ड बनाने का मुझार दिया था। यह बोर्ड १९४६ के औद्योगिक विकास नियंत्रण कानून के अन्तर्गत बना दिया गया है। इसने अतिरिक्त प्रत्येक उद्योग के लिए 'विकास कौंसिल' बनाने की योजना है। 'विकास कौंसिलों' में सरकार, उद्योगों तथा भूमिकों के प्रतिनिधि रहेंगे। ये कौंसिलें उद्योगों की प्रगति में सहायता देंगी तथा केन्द्रीय बोर्ड तथा उद्योगों में ताल मेल बनाये रखेंगी।

योजना में छोटे तथा कुटीर धंधों को भी आवश्यक स्थान दिया गया है। कमीशन ने मुझार दिया है कि केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य तथा उद्योग विभाग कुटीर धंधों की जाँच-पड़ताल करके एक निरुद्ध योजना बनावे। योजना में ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सहकारी समितियों पर ज़ार दिया गया है। कमीशन का मत है कि ये समितियाँ छोटे-उद्योगियों को अच्छे माल का प्रबन्ध करें, उन्हें आवश्यक राशि दिलाने का प्रबन्ध करें तथा उनके माल को बिकवाने में भी सहायता करें। कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि "सरकारों को इन उद्योगों के विकास में उतना ही काम करना चाहिए जितना वे क्षम

२३—देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन

मेन्य, सुरक्षा एवं उद्योग और यातायात को दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में खनिज पदार्थों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक पद्धति पर सेनाया को सुसज्जित करने, सुरक्षा एवं युद्ध-संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि सच पृष्टा जाय तो सुरक्षा-संगठन की सफलता बहुत सीमा तक खनिज सम्पत्ति पर ही निर्भर होता है। लाहा, कायला और तैल सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों के प्राण मात्र हैं—यह बात गत महायुद्ध ने पूर्ण रूप में सिद्ध कर दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी खनिज पदार्थों का मुख्य स्थान है। लाह, कोयले एवं भारी भारी रसायनिक पदार्थों पर देश का समूचा औद्योगिक स्तर निर्भर करता है। विदेशों पर देश के आधारभूत धंधे तो इन वस्तुओं के बिना प्रसम्भर ही हैं। पूँजागत माल बनानेवाले उद्योगों का प्रारम्भ लाहे और कोयले के बिना हो ही नहीं सकता। हमारे देश में उद्योग एवं सुरक्षा के भविष्य के दृष्टिकोण से खनिज सम्पत्ति का सुव्यवस्थित उपयोग एवं नवीन साधना की जाँच पड़ताल तथा विकास बहुत आवश्यक है। देश के औद्योगीकरण के लिए पूँजागत माल के लिए हमें विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। यदि हमारे देश के खनिज पदार्थ एवं धातुओं का विकास हो जाय तो हम विदेशियों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा।

भारत सरकार के निर्माण, खान तथा विद्युत विभाग ने जनवरी १९४७ में खनिज-जोति सम्मेलन के समय देश की खनिज सम्पत्ति का एक अनुमान पत्र सैशार किया था। इस अनुमान पत्र में बताया गया था कि भारत के विस्तार तथा उसकी जनसंख्या को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि देश के खनिज साधन बहुत अधि हैं, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। परन्तु तो भी जो कुछ खनिज सम्पत्ति हमारे देश में है उसका संगठित रूप में पूरा

होती रही है। खनिज-सम्पत्ति का विदोहन कभी संगठित रूप से किया ही नहीं गया। सरकार की हस्तक्षेप न करने की नीति के बड़े भयंकर परिणाम हुए हैं। खनिज निर्यातने का काम मुख्यतः विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में रहा, जो देश के पेट्रोल, साना और ताँबे की खानों के स्वामी बने रहे और कोयला, क्रोमियम एवं मैंगनीज की खानों भी उन्हीं के नियंत्रण में रही। केवल लाभ कमाने के लिए खानों का शोषण होता रहा। उनकी खुदाई के ढंग ऐसे श्रवैज्ञानिक हैं कि उनके कारण बहुत सी खनिज सम्पत्ति नष्ट होती है। इतना ही नहीं, देश की सम्पत्ति बढ़ाने की दृष्टि से खानों का विदोहन नहीं किया गया। खान मालिकों की भरपूर स्वतंत्रता मिलने के कारण अब तक उनका ध्यान खानों के निर्यात की ओर ही रहा। जो पदार्थ विदेशों में गए, वे अपरिष्कृत रूप में बड़ी नीची दरों पर भेजे गए। इन वस्तुओं का विदोहन यदि देश के हित में होता और देश में ही इनसे पक्का माल तैयार किया गया होता तो देश में न केवल रोजगार ही बढ़ता परन्तु राष्ट्रीय आय में भी बहुत वृद्धि होती। खानों पर सरकार का जो कुछ भी नियंत्रण रहा वह प्रधानतः प्रांतीय सरकारों का रहा केन्द्रीय सरकार का नहीं। प्रांतीय सरकारों ने कोई दीर्घकालीन दृष्टिकोण से काम नहीं लिया और खानों के लाइसेंस देने का काम अधिकतर लगान-वसूल करने वाले महकमों को दे दिया जाता रहा। खनिज पदार्थों एवं धातुओं की न वैज्ञानिक रीति से जांच-पड़ताल हुई न शोध हुई और न सदुपयोग ही हुआ। अब तक अशुद्ध खनिज-पदार्थों का निर्यात ही होता रहा। फलतः करोड़ों रुपयों की वार्षिक हानि के अतिरिक्त देश में खनिज-सम्पत्ति का विकास नहीं हो पाया और न निर्यात के बदले में सैन्य एवं औद्योगिक दृष्टि से आवश्यक खनिज-पदार्थ एवं धातु विदेशों से मँगाए जा सके। खान अधिकार सम्बन्धी कानूनों में भी समता नहीं रही।

पिछले दो-तीन वर्षों से सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और खनिज-सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए निम्न कार्य किये हैं :—

- (१) सरकारी खनिज नीति बनाई है।
- (२) खनिज-सम्पत्ति की खोज एवं विकास के लिए 'ज्यॉलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' नामक संस्था का विकास किया है।

(३) देश के रानिज-पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखने तथा उनका संगठित रूप से विकास करने के लिए 'यूरोपियन ऑफ माइन्स' नामक समिति बनाई है।

अब तक कुछ लोगों की यह धारणा रही है कि औद्योगिकरण के लिए हमारे देश में सभी रानिज-पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हैं परन्तु यह बात विनाशालोक नहीं है। उद्योगों की दृष्टि से हमारे देश की रानिज-सम्पत्ति में कुछ ऐसी कमी है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए रानिजों का पता लगाना होगा, उनकी मात्रा का ठीक ठीक अनुमान लगाना होगा तथा उनकी शोध, जीने पड़ताल और संगठन करना होगा। इन कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक हमारे यहाँ निम्न सम्पूर्ण काम कर रही हैं —

१. ज्योमेट्रिकल सर्वे ऑफ इण्डिया।

२. इण्डियन यूरोपियन माइन्स।

३. मैशानल पयुअल रिमर्न्स इन्डोस्ट्रिट।

४. मैशानल मैटनआक्ल रंजोरेटरी।

५. सेक्टरल ग्लाना एण्ड मिनिमल रिमर्न्स इन्डोस्ट्रिट।

देश की रानिज सम्पत्ति का संगठित रूप से विदीहन करने के उद्देश्य से योजना समीक्षण ने नीचे लिखे कुछ सुझाव दिए हैं—

देश की रानिज सम्पत्ति का पूरा पूरा सचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संगठित रूप से रानिज पदार्थों का जीवन-चक्रावली करके रिक्रान नक्षत्रों से तैयार किए जाएं। आवश्यक तथा महत्वपूर्ण रानिजों की वारे से सुरक्षा के लिए उपयोगी हों वारे नियमित विवे जानें हों और वारे अपने देश में प्रयोग किए जाने हों, सबसे पहिल ज्ञान पड़ताप कराई जाय।

रानिजों में से परसुए नियानने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जाय तथा इस काम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएं। सरकार भी इस काम में योग देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करे जो रानिजों में जा-जाकर देखे कि उनमें वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग हो रहा है या नहीं। ये विशेषज्ञ रानिजों में काम करनेवाले लोगों का नए तरीक़ों से परिचित करे और देखे कि रानिज सम्पत्ति नष्ट हो नहीं हो रही है। समीक्षण का मत है कि यदि ऐसा किया गया तो

खनिज सम्पत्ति की रक्षा होगी, विदोहन होगा तथा सदुपयोग भी होगा। किसी भी प्रकार की खानों के अधिकार देने के लिए लाइसेंस देने से पहिले 'माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट १९४८' के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होना चाहिए। दूसरे, किसी एक व्यक्ति को खाना का पट्टा नहीं देना चाहिए परन्तु देने से पहिल यह देख लेना चाहिए कि पट्टा लेने-गाना खाना का विदोहन करने के साधन और शक्ति सन्तुष्ट है या नहीं। पट्टा अधिकतर बड़ी बड़ा कम्पनियाँ ही देना चाहिए।

खनिज उद्योगों के वास्तविक और सच्चे अर्थों में इच्छे होने चाहिए। खनिज पदार्थों के निर्यात सम्बन्धी अर्थ भी प्राप्त करने चाहिए। यह काम 'यूरो ऑफ माइन्स' का सौंप देना चाहिए। कमाशन का मत है कि इस प्रकार के अर्थों होने से खनिज सम्पत्ति के विदोहन सम्बन्धी आयाजन में सरलता रहेगी।

अभरक, मैंगनीज तथा क्रोमाइट आदि वस्तुएँ, जो मुख्यतः अशुद्ध रूप में निर्यात होती रही हैं—शुद्ध करने निर्यात की जाएँ और यदि सम्भव हो सके तो उनका पक्का माल या अर्द्ध पक्का माल बनाकर निर्यात किया जाय।

खानों की सुरक्षा तथा खनिज पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी अन्वेषण और शोध की जाएँ। अशुद्ध तथा निम्न कौटि के खनिज-पदार्थों को शुद्ध बनाने में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाय। याचना कमीशन ने अपनी पञ्चसत्रीय योजना में खनिज-सम्पत्ति के विकास के लिए लगभग १ करोड़ रुपये व्यय करना निश्चित किया है।

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है खानों का अधिकार अब तक विदेशी पूँजीपतियों या व्यक्तिगदी भारतीय कम्पनियों के हाथ में रहा है। इससे अनेक दुष्परिणाम हुए हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए एक उपाय यह हो सकता है कि देश के खनिज और धातु-साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। देश की आर्थिक उन्नति के लिए तैयार की गई विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं में खानों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति की खानज एवं धातु-शोधन उपसमिति ने अपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट किया था कि "देश का खनिज-सम्पत्ति सामूहिक रूप से राष्ट्र की

सम्पत्ति है। स्थानों की खुदाई और गनिज सम्बन्धी उद्योग सरकार के हाथ में रहने चाहिए।" जनवरी १९६७ में आयोजित गनिज नीति सम्मेलन ने, जिसमें गनिज-उद्योगों, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय काम करनेवाले मजदूरों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, स्थानों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। परन्तु इन कामों में अभी-अभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं है ही कारण स्थानों के राष्ट्रीयकरण में बाधक है। तभी तो उक्त सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भाभा ने अपने भाषण में कहा था कि "सरकार की गनिजोन्नति में बढ़ती हुई दिलचस्पी का यह अर्थ नहीं है कि सरकार गनिजोत्पादन और भानु शोधन उद्योगों पर तुल्य हाथ सरकार स्थापित करले। गनिजोत्पादन के उद्योगों में हमें मजदूर होकर बहुत बड़े क्षेत्र में व्यक्तिगत पूँजी की आवश्यक देना होगा, यद्यपि उस पर कुछ सरकारी नियंत्रण अवश्य रहेगा।" श्री भाभा ने आगे चलकर यह भी कहा कि "आगामी कई वर्षों तक सरकार को मुख्यरहित गनिजोन्नति के लिए आवश्यक कानूनी एवं व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएँ देने में ही मन्तव्य करना चाहिए।" राष्ट्रियकरण में कई आर्थिक, वैज्ञानिक एवं व्यवस्था सम्बन्धी ऐसी बाधनाएँ हैं जिनसे सरकार वर्तमान परिस्थितियाँ में हल नहीं कर सकेगी। रॉ. दस साल के पश्चात्, जैसाकि सरकार का विचार है, इस परलू पर विचार किया जा सकता है। इस समय तो हम अपनी गनिज-सम्पत्ति का विदोहन करके रंगडित बनाना है। यह काम सरकारी नियंत्रण में व्यक्तिगत के सिद्धान्त पर हो सकता है। यदि हमारी गनिज-सम्पत्ति का यथोचित विदोहन हुआ तो देश के औद्योगिकरण में काफी सहायता मिलेगी।

२४—हमारी बैंकिंग-व्यवस्था—कुछ दोष

पाश्चात्य देशों की भाँति हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था सगठित, पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। लम्बे चौड़े देश, विशाल जन-समूह तथा असीम व्यापार का देखत हुए हमारे देश में बैंकों की संख्या बहुत कम है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ बैंक का विकास बहुत कम हुआ है। स्थिति इस प्रकार है—

देश	वर्गमील क्षेत्रफल	जनसंख्या	बैंक कार्यालयों की संख्या	व्यक्तियों में बैंकों की संख्या
	(हजारों में)	(१००,०००)		
इंग्लैण्ड	८६	५०	११४६१	२०६
अमरीका	३६७४	१४७	१८६७५	१२६
कनेडा	३६६०	१३	३३२३	२५६
ऑस्ट्रेलिया	२६७५	८	३५६०	४५०
भारत	१२२०	२३७	५५५८	१६

इन आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों में १६ बैंक कार्यालय हैं अर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक बैंक कार्यालय है।

बैंकिंग सम्बन्धा लेन देन अनेक संस्थाएँ करती हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- (१) सरकारी ऋणालय तथा उप-ऋणालय,
- (२) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया,
- (३) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया,
- (४) व्यापारिक बैंक,
- (५) सहकारी बैंक तथा साज्य समितियाँ,
- (६) डाकघरों की वचत बैंक,
- (७) महाजन तथा स्वदेशी बैंकर।

भारती कोषालयों में सरकारी लेन-देन होता है तथा सरकारी खस जमा रहती है। हमारे सिवाय ये कोषालय जनता में राशि जमा करने या उ-हें गारु उधार देने का कोई काम नहीं करने। ये कोषालय प्रायः जितना नगर। म हा स्थित हैं तिमने सरकारी लेन-देन में जनता को आने-जाने में अनुयायता रहता है। रिजर्व बैंक सरकारी केन्द्रीय बैंक है जो देश में मुद्रा और साख व्यवस्था की देय भाग्य करता है। अन्य बैंकों से राशि जमा करना तथा उन्हें उधार देने का काम भी इसके हाथ में है। यह बैंक एक प्रकार में देश की बैंकिंग व्यवस्था की चौकसी करता है। परन्तु अभी तक यह बैंक देश की मुद्रामण्डी की मगाटिक करके बिलमण्डी की उद्यत नहीं बना सफा है। यथा केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रहता है परन्तु महाजनो तथा स्वदेशी बैंकों पर इसका कोई प्रबन्ध-नियन्त्रण या चौकसी नहीं है। इर्रियल बैंक एक आधुनिक व्यापारिक बैंक है। रिजर्व बैंक का उद्घाट होने के कारण यह अध सरकारी बैंक माना जाना है। यथाय इस बैंक ने देश में अनेक शाखाएँ खोलकर बैंकिंग-व्यवस्था की रिक्किन बनाया है परन्तु उस व्यवस्था का यह देश की अन्य व्यापारिक बैंकों का बहुत प्रतियोगी बन बैठा है। व्यापारिक बैंक का प्रसार के है (१) नाविक बङ्ग बैंक, (२) अनाजिक बङ्ग बैंक। देश में इन बैंकों का काम बड़ा आवश्यक है। करी-करी तो बहुत सी बैंक स्थापन हो गई है और किसी किसी स्थान पर बैंकों का नाम भी नहीं है। मुद्रा तथा पश्चिमा बंगाल में बैंकों का सबसे अधिक संख्या है—मुद्रा में ११२६ तथा बंगाल में ७२० बैंक-कार्यालय है। बिर्मा-बर्क राज्य में तो बैंकों के बहुत हा कम कार्यालय हैं। कुल देश में बैंकों की संख्या बहुत कम है। १९६७ के अन्त में इर्रियल बैंक तथा विानमय-बैंको को मिलाकर देश में कुल ५४८० बैंक-कार्यालय थे। विनाजन के पश्चात् तो संख्या और भी कम हो गई है और सामान्य बैंकिंग जिन कमेट्री के अनुमानों से ज्ञात होता है कि आजकन कुल बैंक कार्यालय ५१०० के आसपास है। व्यापारिक बैंक अधिनियम बने बने नगरा तक ही सीमित है। स्ट्राट स्ट्रुडे आगो तथा कम्पों में इनका शाखाएँ बहुत कम हैं और गाँवों में तो व्यापारिक बैंक ही ही नहीं।

देश की पश्चिम व्यवस्था में सरकारी बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है

श्रीर बचई तथा मदरास में इनका व्यव प्रचार हुआ है। सहकारी बैंक मुख्यतः तीन प्रकार की हैं—(१) प्रान्तीय सहकारी बैंक, (२) केन्द्राय सहकारी बैंक, तथा (३) नागरिक सहकारी बैंक। प्रान्तिय सहकारी बैंक प्रान्त भर की एक श्रोटी की सहकारी बैंक होता है जो अन्य प्रकार की सहकारी बैंक स राशि जमा करती है तथा उस समय पड़ने पर रुपया उधार देती है। १९३६ में इनकी संख्या १० थी जो १९४६ में बढ़कर १३ हो गई परन्तु १९४८ में ११ ही रह गई। केन्द्राय सहकारी बैंक जिले भर की एक बैंक होती है जो सहकारी समितियों से राशि जमा करती तथा उन्हें सहायता करती है। १९२६ में इनकी संख्या ५६४ थी जो १९४६ में बढ़कर ६०१ हो गई और १९४८ में घटकर ४४८ ही रह गई। नागरिक सहकारी बैंक नगर में होती हैं और नगर निवासी मला-मारा, व्यवसायिया तथा यतनभागिया स राशि जमा करती तथा उन्हें श्रम देती है। गाँवों में बैंकिंग सुविधा देन की काम सहकारी साख सामाजिक करती हैं। ये समितियाँ गाँव में कहीं रुका ता काफी संख्या में फैली हुई हैं और किसानों से राशि जमा करती तथा उन्हें श्रम देती है। १९४७-४८ में साख-समितियों की संख्या ८५,२६० थी जिनमें ३४,८२,८५२ सदस्य थे।

लोगों को अपना अपनी बचत जमा करने में प्रोत्साहित करने का सबसे प्रबुद्ध काम डाकघरों की बचत बैंक करती हैं। सरकारी विभाग होने के कारण जनता का इनमें विश्वास रहता है। मार्च १९४६ में कुल मिलाकर २६,७६० डाकघरों थे जिनमें से कोई ६८६५ डाकघरों में बचत बैंक की व्यवस्था थी। गाँवों में रुपया उधार देने तथा आभूषण जमा रखन का काम महाजन और स्वदेशी बन कर रहे हैं। महाजन प्राय गाँव का बनिया होता है जो गाँववालों के सम्पर्क में आता है और उन्हें य साथ रहता-सहता है। इस कारण गाँववाले इन महाजनो में विश्वास भी अधिक करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे इन्हीं लोगों से रुपया उधार लेते हैं और फसल आने पर माल देकर या नरुदी दान क्रम चुकाते रहते हैं। यद्यपि ये महाजन किसानों की सहायता करत रहे हैं परन्तु इनका कार्यप्रणाली में ऐसे दोष रहे हैं जिनसे इनके किसानों का व्यवसाय किया है। न इनके पास संगठित और नियमित हिसाब किताब होते हैं और न और कोई लेखा जाता होता है। अनपढ़ किसानों में ये मनमानी व्याज-दर रखने

करते हैं तथा उनके लेन-देन में प्रकार-प्रकार की और घेरेमानी भी कर लेते हैं। इन महाजनों पर सरकार का नियन्त्रण न होने के कारण ये मनमानी गतों पर कपया उधार देते हैं।

इनके अनिरीक हमारे यहाँ विदेशी विनिमय बैंक हैं जो विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करते हैं। इन बैंकों की शाखाएँ देश के आन्तरिक भाग में भी फैली हुई हैं जो व्यापारिक बैंकों की प्रतियोगिता में बैंकिंग सम्बन्धी अन्य काम करती हैं। १९२६ के पश्चात् में आज तक यद्यपि हमारे यहाँ बैंकों की संख्या बढ़ती रही है परन्तु उनमें से अधिकांश कुंआ की अवस्था बहुत गिरी हुई रही है। १९८१ से १९४६ तक २५८ मिश्रित पत्रवाले बैंक बन्द करने पड़े। इनका या तो प्रबन्ध ठाक नहीं था और या इनका पास पैसों की कमी थी। देश के विभाजन के पश्चात् १९८७ १९४८ तथा १९४९ में ११८ बैंक और बन्द किए गए। इस स्थिति से पता लगता है कि हमारी बैंक-व्यवस्था आज भी कितनी गिरी हुई है। इस स्थिति को सुधारने तथा देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता का अनुभव करते १९४६ में बैंकिंग कम्पनी एक्ट पास कर दिया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को देश भर की बैंकों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे दिया गया है। परन्तु अब भी देश का बैंकिंग-व्यवस्था के दो भाग हैं। एक भाग वह जिसमें इम्पेरियल बैंक, व्यापारिक बैंक, सरकारी बैंक तथा अन्य संगठित बैंकिंग-संस्थाएँ सम्मिलित हैं; दूसरा भाग वह जिसमें महाजन तथा स्वदेशी पैसर सम्मिलित हैं। मद्रास-मण्डा का यह भाग बहुत अव्यवस्थित तथा अव्यगटन है। न तो इन पर किसी कानून का दबाव है और न इन पर किसी केन्द्रीय संस्था का नियंत्रण है। इनकी व्याज-दर सबसे अधिक होती है। गतियों में कपया उधार देनेवाली बैंकों के अभाव में महाजन ही ग्रामीण जनता के विश्वासपात्र बने हुए हैं। परन्तु इनके नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कौटुम्हिया कानून बनाना चाहिए कि जिससे अन्तर्गत रिजर्व बैंक का इन पर भी नियंत्रण होने लगे। विलुके गतों में कई बार रिजर्व बैंक ने इनको कानून के शासन में लाने के प्रयत्न किए परन्तु अभी तक सफलता नहीं मिली है। अब इनको कानून में बाँधने की बहुत आवश्यकता है। जब तक इनके कानून में नहीं बाँधा जाएगा तब तक हमारे यहाँ देश भर

की व्याज-दरों में समता और सन्तुलन नहीं आसकता। रिजर्व बैंक की अनेक योजनाएँ अभी अभी तो इन अव्यवस्थित महाजनो के कारण पूर्ण रूप से सफल नही हो पाती।

हमारे यहाँ काम करने वाले विदेशी बैंक देश के आन्तरिक नगरों में पहुँच कर देशी व्यापारिक बैंक का प्रतियोगिता करने हैं। इससे हमारा बचका आशातीत प्रगति नहीं हो पाती। आवश्यकता यह है कि विदेशी बैंकों पर नियंत्रण रखकर उन्हें विदेशी मुद्रा के लेन देन तक ही सामित कर दिया जाय। दूसरे, हमारे बैंक का विदेशी मालागाना होने का कारण हमारे बैंक अन्तर्देशीय व्यापार में विशेष योग नहीं दे पाते। आवश्यकता यह है कि हमारी बचक विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलें। इस काम में सरकार का इनका सहायता करनी चाहिए। विदेशों में स्थान प्राप्त करने में तथा विदेशों सरकार से अन्य सुविधाएँ दिलाने में सरकार का भी योग दे सकती है। हाल ही में यूनाइटेड इम्पिरियल बैंक ने हांगकॉंग में अपना एक शाखा खोली है। देश के बँकिंग इतिहास में यह एक नया और प्रशंसनीय प्रयास है। यह बैंक इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में भी अपनी शाखाएँ खोलने के विषय में विचार कर रही है। इसी प्रकार अन्य व्यापारिक बैंकों का आग बढ़ कर विदेशी क्षेत्र अपने हाथ में लाना चाहिए।

हमारी बैंकिंग-व्यवस्था कई दृष्टियों से अपूर्ण भी है। न तो हमारा यहाँ औद्योगिक बैंक है और न विनियोगी बैंक ही है। उद्योगों के लिए वित्त सहायता देने का कोई मुख्य स्थान नहीं है। व्यापारिक बैंक इस विषय में सदैव से उदासान रहे हैं क्योंकि उनका परिस्थितियाँ उन्हें दीर्घकालीन आग न देने पर बाध्य करती रही हैं। जनता का पूँजा विनियोग की सुविधाएँ देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रयत्न नहीं है। इसका लिए आवश्यक है कि औद्योगिक बैंक स्थापित किए जाएँ तथा विनियोगियों की सुविधा के लिए विनियोगी बैंक तथा विनियोगी ट्रस्ट खोल जायें। इस काम में सरकार को पहिल आग बढ़ाना चाहिए। सरकार इस प्रकार की बैंकों के अग्र गरीद तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार उन्हें अपने सम्बन्धी सहायता करे। यद्यपि इस क्षेत्र में सरकार ने अगिन भारतीय औद्योगिक वित्त निरपेक्षन स्थापित कर एक नया कदम उठाया है परन्तु तो भी

उद्योग विदेशों के लिए औद्योगिक वैकों की आवश्यकता है जो उद्योगों को दीर्घकालीन तथा माध्यमकालीन अणु देकर सहायता करें। कृषि तथा कृषिकों को वित्त सहायता देने के लिए भी हमारे यहाँ वैकों का आभाव है। गति में तो वैकों का समन्वित व्यवस्था है ही नहीं। केवल यहाँ यहाँ कुछ डाकघराने की बचत-बैंक तथा सहायरी सागर-समितियाँ हैं जो आवश्यकताओं के लिए बिलकुल अपूर्ण हैं। कृषि को दीर्घकालीन सहायता देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके लिए भूमि बन्धक-बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है। कुछ प्रान्तों में भूमि-बन्धक बैंक स्थापित किए गए हैं परन्तु कृषि-प्रधान देश में सभी जगह ऐसे वैकों की आवश्यकता है।

इस भाँति हम देखते हैं कि हमारी वैकिंग व्यवस्था पार्श्वस्थ देशों की वैकिंग-व्यवस्था की तरह बहुमुखी नहीं है। यह अपूर्ण, असंगठित, अभावरूप, अनुभवाहीन तथा अध्यासित है। हमें देश के लिए सर्वोत्तमरूपेण उपयोग बनाने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता अनुभवा तथा योग्य वैकिंग-विशेषज्ञों की है। वैकों की सफलता अभिकाश में उनके कम-बाधित तथा प्रबन्धों पर निर्भर होती है। देशवासियों को इस ओर गिरा देने की आवश्यकता है। दूसरे, जनता को वैकों से लेन-देन करने के लिए प्रारम्भित करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाय तो हमारे देश की मुद्रा मण्डी के दोष दूर किए जा सकेंगे।

२५—भारतीय गाँवों में बैंकों की व्यवस्था

बैंकों की आवश्यकता प्रायः राशि जमा करने तथा समय पड़ने पर उनसे राशि उधार लेने के लिए होता है। हमारे देश में यह काम मुख्यतः व्यापारिक बंसा, सहकारी बैंकों, राज्य समितियों, डाकघरों की बचत बैंक तथा महाजना और देशी बैंकों द्वारा किया जाता है। परन्तु हमारे देश के जनफल, जनसंख्या तथा व्ययसाय का दायित्व हुए हमारे यहाँ बैंक का पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ भी व्यापारिक बैंक अथवा डाकघरों की बचत-बैंक हैं वे प्रधानतः बड़े-बड़े शहरों में हैं—एक या दो देशों में तो इस सम्बन्ध में कोई सुविधाएँ ही नहीं हैं। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में बैंकों की संख्या इस प्रकार है—

देश	वर्ग मील में जनसंख्या (हजारों में)	जनसंख्या (१०००,०००)	बैंक कार्यालयों की संख्या	प्रति दस लाख व्यक्तियों में बैंकों की संख्या
इंग्लैण्ड	८८	५०	११,४६१	२२८
अमेरिका	३६७४	१४७	१८,६७५	१२८
फ्रेड	३६८०	१३	२,३२३	२५६
ऑस्ट्रेलिया	२८७५	८	३,५६६	४५०
भारत	१२२०	३३७	५,५५८	१६

इसमें ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों के बीच में १६ बैंक कार्यालय हैं अर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक बैंक-कार्यालय है। इस पर अधिकांश कार्यालय या तो बड़े-बड़े शहरों में हैं और या बड़े-बड़े कस्बों में, गाँवों में तो इनका नाम भी नहीं है। १८४८ में सब राज्यों में मिलाकर व्यापारिक बैंकों के कुल ३६६१ कार्यालय थे जिनमें से २०८८ या तो बड़े-बड़े शहरों में थे या जिलों की राजधानी में। अन्य स्थानों पर

अर्थात् ग्रामों और गाँवों में मिलाकर केवल १६०२ बैंक कार्यालय थे। इससे बिजकुल स्पष्ट है कि हमारे गाँवों में बैंक हैं ही नहीं। गाँवों में राशि जमा करने का काम डाकघरानों की बचत बैंक करता रही है। सरकारी प्रभाग होने के कारण इन डाकघरानों में प्रामाण्य जनता का विश्वास बना हुआ है और ये अपनी अपनी बचत इन्हीं में जमा करके रखते हैं। परन्तु देश में गाँवों की संख्या तथा उन गाँवों में बसनेवाली जन-संख्या की दृष्टत दृष्ट डाकघरानों की बचत बैंक की संख्या भी थोड़ा है। यह संख्या इस प्रकार है —

प्रामाण्य डाकघरानों की बचत-बैंक

	१९४३	१९४६	
डाकघरानों का संख्या जिनमें बचत बैंकों की व्यवस्था है	५,५१२	६४०१	+ ८८९
इन बैंकों में लगभग लेखा की संख्या	७,२१,४६२	११,६६,४३४	+ ४,७४,९७२
बचत बैंकों में जमा— राशि	१७,७१,११,५५०	६३,१४,३८,७७८	+ ४५,४३,२७,२२८
प्रति लेखे पर औसत जमा	२४५	५२८	+ २८३

यद्यपि १९४३ की अपेक्षा १९४६ में गाँवों में काम करने वाली डाकघरानों की बचत-बैंकों में बड़ातरी हुई है परन्तु फिर भी हमारे विशाल देश के लिए यह संख्या सन्तोषजनक नहीं है। फिर, इनके द्वारा गाँवों की बैंक समस्या पूर्णरूपेण सुलभगी नहीं है क्योंकि ये बैंक उनमें राशि जमा तो करती हैं परन्तु उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार श्रृंखला नहीं देती। प्रामाण्य को श्रृंखला देने का काम तो विद्यमान गाँवों में रहनेवाले महाजन तथा देशी बैंकर करने आए हैं परन्तु इनमें एक बड़ा भारी दोष है। इनकी व्याज देर बहुत ऊँची तथा इनके लेखे-जोखे बहुत गड़-गड़ होते हैं। इनके लेन-देन के विषय में टीक टीक अटकें प्राप्त करना पड़ित है क्योंकि ये ठीक तरह में अपने कोई हिसाब-किताब नहीं रखते। इन महाजनों पर सरकार या केन्द्रीय बैंक का

कोई नियन्त्रण न होने के कारण ये मनमानी करने हैं। अब कानून बनाकर इनकी मनमानी रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुतों ने अपना लेन देन अब बहुत सीमित कर दिया है और ये लोग अब अपना अपना अलग अलग ध्यानार करने लगे हैं। अतः गाँवों में बैंकों की सबसे अधिक सुविधाएँ देने का काम अब सहकारी साख्त समितियाँ ही करती हैं। जैसे तो गाँव के प्रत्येक क्षेत्र में अब सहकारी समितियों द्वारा काम होने लगा है अर्थात् माल गरीदना, बचना, आदि, आदि, सभी काम इन समितियों से हात हैं परन्तु बैंकों की सुविधाएँ देने का काम साख्त समितियाँ ही करती हैं। ये समितियाँ आर्मिंगा से राशि जमा करती हैं तथा उन्हें उधार भी देती हैं। १९४७-४८ में साख्त समितियों की स्थिति इस प्रकार थी —

१	समितियों की संख्या	८५,२६०
२	सदस्यों की संख्या	३४,८२,८५२
३	जमा राशि (करोड़ रुपये में)	३.०४
४	स्वीकृत ऋण (,,)	१६.०२

इस प्रकार सहकारी आन्दोलन ने गाँवों की बैंक समस्या काफ़ी मात्रा में हल कर दी है परन्तु तो भी इसमें अभी काफ़ी विकास की गुञ्जाइश है। जैसा कि आँकड़ों में स्पष्ट है इन समितियों में केवल ३.०४ करोड़ रुपये की जमा राशि थी। देश के क्षेत्रफल तथा कृषि-जनता की संख्या को देखते हुए यह रकम आशा से बहुत कम है। इस विषय में हमारे यहाँ अभी काफ़ी क्षेत्र है।

अब युद्ध के पश्चात् जब कि हमारे देश में पूँजी निर्माण का काम आरम्भ होना है इस बात का नितान्त आवश्यकता है कि गाँवों में बैंकों की सुविधायें व्यवस्था करके गाँववालों का बचत करने का सुविधाएँ दी जाए जिससे वे बचत करना सीखें और अपना बचत को उन बैंकों में जमा करके देश के हित में प्रयोग करें। अपने देश में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए अब पूँजी का बहुत आवश्यकता है परन्तु पूँजी निर्माण का काम ढीला है। अब तब तो कठिनाई यह रहा कि गाँववालों की आय ही इतनी न थी कि वे बेचारे बचत करके बैंकों में जमा करते। परन्तु युद्धकाल तथा युद्ध के पश्चात् अब परिस्थिति

विलकुल भिन्न है। युद्धकाल में तथा उसके पश्चात् व्याप-वस्तुओं के भाव बहुत ऊँचे रहे जिससे ग्रामीणों ने काफी पैसा कमाया। शहर के वन-भोगियों तथा मध्यमवर्ग में पैसा निकल निकल कर अब किसानों के पास जमा हो गया। ऐसी परिस्थिति में उनके यहाँ बैकों की आवश्यकता है जो उनकी इस आतंरिक आय को जमा करें। कुछ लोग हम मत के विरुद्ध हैं कि किसानों की आय बढ़ गई है और वे बचत कर सकते हैं। परन्तु हम यहाँ मित्र करेंगे कि किसानों की आय निश्चित ही बढ़ गई है और उन्हें बचत राशि जमा करने के लिए साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता है। युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल में किसानों की आय में जो बढोत्तरी हुई है उसका शान्तिन तीन बाँटों में लगाया जा सकता है—(१) राष्ट्रीय आय के आँकड़ों द्वारा, (२) कृषि ऋण का अध्ययन करके, तथा (३) कृषि-जन्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य-स्तरों का तुलना करके।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में यद्यपि अधिकृत आँकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु विश्व-सनीय तथा जानकारीयों द्वारा जो अनुमान लगाए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

वर्ष	कुल राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपयों में)	कृषि-आय	कृषि-आय का कुल आय के साथ प्रतिशत	सूत्र
१९३१-३२	१६८६	८८२	५२.८	डा० गा
१९३६-४०	१९३४	९५३	४९.२	इंग्लैंड
१९४३-४४	४२३३	२१२८	५०.३	एवनिमिस्ट
१९४४-४५	४२७१	२२९४	५३.७	११-१२-४८
१९४५-४६	४२४०	२२२५	५२.५	"
१९४६-४७	४४८७	२५६६	५७.३	"
१९४७-४८	३९६२	२१२६	५४.०	"
१९४७-४८	४९३२	२६६०	५६.२	पाममें
				दिसम्बर ४८

इन अनुमानों से पता लगता है कि किसानों की आय १९३१-३२ की अपेक्षा १९४७-४८ में तीन गुनी अधिक हो गई और कुल राष्ट्रीय आय में

कृषि आय का प्रतिशत ५२ से बढ़ कर ५७ ३ तक हो गया। इसमें मार स्पष्ट है कि युद्धकाल में किसान की आय बढ़ गई और इसलिए उनका खर्च बँका का प्रबंध करके उनमें बहुत राश लेबर पूना का निमाण किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों की आय तो अत्यंत बढ़ी परन्तु उनका खर्च नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकता का वस्तुएं गरीबों में सारी मूल्य चुनाना पड़ा था। अतः नैसर्गिक रूप से उनकी आय बढ़ती गई तब तब उनका खर्च भी बढ़ता गया। परन्तु यह बात भी नितान्त सत्य नहीं है। इस कारण हम कृषिजन्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य लेते हैं—

कृषि जन्य वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सामान्य
व्यक्तिगत मूल्यों के निर्देशाङ्क (१९२० = १००)

माह	कृषि जन्य वस्तुओं के औसत निर्देशाङ्क			अन्य वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्यों के निर्देशाङ्क		
	१९४७	१९४८	१९४९	१९४७	१९४८	१९४९
जनवरी	३५६ ७	४२३ १	५०६ २	२९० ५	३२९	३७६
फरवरी	३५८ २	४४२ ०	५०५ १	२९२ २	३४०	३७२
मार्च	३५७ ०	४४५ ८	४९६ ०	२९३ २	३४०	३७०
अप्रैल	३४९ ८	४५५ ४	४८७ ४	२८९ ६	३४७	३७६
मई	३४९ ०	४७३ ०	४८५ ३	२८८ ५	३६७	३७७
जून	३५८ ६	५०३ ८	४९३ ६	२९१ ०	३८०	३७८
जुलाई	३५९ ४	५०८ ४	४८० ४	२९७ ७	३८९	३८०
अगस्त	३५८ १	५०६ १	४९० ७	३१४	३८५	३८९
सितम्बर	३५६ ३	५०६ २	४८५ ७	३०२ ४	३८२	३८९
अक्टूबर	३५६ ४	५०० ९	४९२ ५	३०३ ०	३८१	३९३
नवम्बर	३५५ ३	५१३ ७	४९५ २	३०० ०	३८२	३९०
दिसम्बर	३९२ ०	५३९ ०		३१४ २	३८३	

इन मूल्यों से यह बात अत्यंत स्पष्ट होती है कि १९४२ के पश्चात् से ही कृषिजन्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में नियमिता रही और किसानों को दाहरा लाभ मिला—अन्य माल के दाम अधिक मिले तथा अल्प माल खरीदने पर कम दाम देना पड़ा। इस प्रकार किसानों का धन आय तथा वास्तविक आय

दोनों बँदी । अतः किसानों की बचत करने की समता बँदी है इसमें कोई संदेह नहीं । इसी बचत की योजना के लिए गाँवों में बँक का आवश्यकता है । कृषि-श्रम के दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो जाय होगा है । कृषि-श्रम के काल में कृषक का जो आय है उसमें उसने अपने-अपने खर्च बचा । अतः के अभाव में यह कहना तो सही है कि जिस भाँसा वह कृषि-श्रम चुका । अतः वह बचत जो भी बचता प्राप्त है उसमें निश्चय ही यह जानना है कि कृषि-श्रम करने की अवस्था कम अवश्य हो गयी । इस प्रकार यह निर्धारित है कि कृषकों को आय और बचत करने की समता में वृद्धि हुई है, बचत निम्नो वृद्धि हुई है, यह कहना सही है । भिन्न-भिन्न आवृत्ति । जानना है कि अवसर-अवसर अनुमान लगाए हैं । इसी प्रकार यह कहना भी सही है कि क्या यह स्थिति सर्वत्र में भी बनी रहेगी । जहाँ अधिक स्थिति में भी गाँवों में बँकों की व्यवस्था तो करनी ही है वरन्तु कोई भी नई योजना बनाने में पहले ही कुछ काम हो रहा है उसे समझित बनाना चाहिये । जिन गाँवों की आर्थिक-स्थिति अच्छी हो और जहाँ के किसान, जमींदार आदि जनता आवक पैसों वाली हो उन गाँवों के आम-पाम केन्द्र बनाकर व्यापारिक-बँकों के कार्यालय स्थापित करने चाहिये । व्यापारिक बँकों का प्रोत्साहन किया जाय कि वे अपने-अपने कार्यालय गाँवों के आम-पाम नगरों में या कम्पों में गाँवों । जिन गाँवों में छोटे-छोटे व्यवसाय हैं और जिनका आय अपेक्षाकृत कम हो वहाँ व्यापारिक बँकों के कार्यालय स्थापित करके बचत में कोई लाभ नहीं होगा । ऐसे स्थानों पर तो आवश्यकता है बचत बैंक तथा माध्यम-संविधानों की स्थापना । इनके द्वारा ही वहाँ की बचत निश्चय कर पूँजी का काम दे सकती है । इसके साथ-साथ सरकारी बचत करने में किसानों का प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन तथा प्रारम्भिक करना चाहिये । गाँवों में जनता की बचत सिखाने में तथा उनका राज्य जमा करने में इन्हीं साधनों में काफी लाभ मिल सकता है ।

अब रहा प्रश्न इसका कि गाँवों में कृषकों को माध्यम-सुविधाएँ देने का क्या प्रबन्ध किया जाय ? गाँवों में किसानों की बचत करने की सुविधाएँ देने के साथ-साथ उन्हें माध्यम पर रकम देने का सुविधाएँ भी देना आवश्यक है । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो संस्थाएँ उनमें रहस्य जमा करें वे ही उनको माध्यम

पर रुपया उधार भा दे । किसान को यदि यह विश्वास हो जाय कि जो राशि वह जमा कर रहा है वह आवश्यकता पड़ने पर उसको उधार मिल सकती है तो वह बैंकों में राशि प्रशस्त नमा करेगा अन्यथा नहीं । अतः वचन सिक्का के साथ साथ उर्ह साग्न सु रक्षा भी देना आवश्यक है । हो सकता है कि बहुत से ग्रामीण पाहले ऋण लने के लिए ही बैंक के सम्पर्क में आये और बाद में जब उनकी आय बढ़ने लगती है राशि जमा भी करने लग । एक बात और है । हमारी कृषि और ग्रामीण धंधा का उन्नत करने के लिए बहुत मात्रा में और श्रम ही पड़ती है । आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में गाँवों में ऐसी बैंक का प्रबन्ध होना चाहिए जो लोग स अधिक स अधिक राशि नमा लेकर पूँजी निर्माण करें और फिर इस पूँजी का इन उद्देश्यों में लगावे । अभी तक निम्नता को रुपया उधार देने का काम मुख्यतः महाजन तथा सहकारी समितियाँ करती हैं । परन्तु जैसा कि पहिले बताया जा चुका है महाजन अनेक कारणों से अब लुप्त होत जा रहे हैं और अब इनका कार्यक्षमता भी क्षीय हो गई है । व्यापारिक बैंक तो इस क्षेत्र में कोई काम करने ही नहीं । सहकारी समितियों का काम भी आज लगभग ५० वर्ष के पश्चात् अधूरा ही है । इस विषय में जॉन्-पडताल करने के लिए सरकार ने पिट्टले वर्षों में काफी दिलचस्पी ली है । १९४५ में गेडगिन कमेटी ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दी, १९४६ में सरैया कमेटी ने इस विषय की जॉन् पडताल की तथा राज्या में भी अनेक बार विशेषज्ञों द्वारा इस समस्या का समाधान सोचा गया । गेडगिन कमेटी ने कृषकों को अन्तर-मालीन तथा मध्यकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए कृषि साख कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश की तथा दीर्घकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए भूमि बन्धक बैंक गठाने पर जोर दिया । सरैया कमेटी ने सहकारीता आन्दोलन का समर्थन करने तथा साख समितियों की मर्यादा बढ़ाने पर जोर दिया तथा देश भर के लिए एक कृषि-साख कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश की । ग्रामीण बैंकिंग जॉन् कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि बैंकों को भी कृषकों को साख-सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए । कमेटी ने सुझाव दिया है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक-

घरों तथा सहकारी-बैंकों को मिलाकर संगठित करना चाहिए जिससे दोनों मिलकर यह काम अच्छी तरह से कर सकें।

अब यह भी देखना चाहिए कि गाँवों में बैंक स्थापित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि हमारा कृषि-धंधा अपूर्ण तथा अध्याप-पूर्ण रहा। जब तक एक विशेष योजना बनाकर भूमि सुधार न किया जाय, पैतों की नकबन्दी न हो, सिचार्ज के साधन न बढ़ें, कृषिजन्य वस्तुओं की बाजार में बेचने का समुचित प्रबंध न हो, कृषि कार्यों में वैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग न किया जाय, छोटे-मोटे उद्योग-धंधे न बनाए जाएं तब तक कृषि कार्य में लाभ नहीं हो सकता और इसलिए तब तक बैंक अपने कार्यालय भी नहीं खोल सकते। अतः कृषि सुधार करने की योजना बनाकर कृषि-धंधे का उन्नत करना चाहिए तभी बैंकों की समुचित व्यवस्था लाभप्रद हो सकती है।

गाँवों में बैंकों की स्थापना न बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि वहाँ आने-जाने तथा मन्देश-न्यायन के साधनों का उपयुक्त प्रबंध नहीं है। बहुतसे गाँवों में शहरों से बहुत दूर तथा बिलगुल अलग हैं - न वहाँ सड़कें हैं और न आने-जाने का कोई अन्य साधन है। इसमें बैंकों के विकास में बड़ी असुविधा रहती है। इससे लाभ सरकार को चाहिए कि वह गाँवों में आर्थिक विकास की योजनाओं में सड़कों तथा जलसंचालन की प्रथम स्थान दे। याद रहे कि सुविधाएँ मिल जाएँ तो बैंक अपने कार्यालय भी स्थापित करने लगेगे।

ग्रामीण जनता अशिक्षित और अनरक्षित होने के कारण बैंकों से लेन-देन नहीं कर सकती। न तो वे पास पड़ें ता लेन-देन और लेखा-जोखा समझ सकते हैं और न बैंकों के चेक द्वारा अपना लेन-देन बढ़ा सकते हैं। इससे निम्न दो उपाय करने चाहिए। एक, गाँवों में शराब से प्रोत्साहित की सुविधा दी जाएँ तथा दूसरा, बैंक अपने लेन-देन के काम अमेरिकी से न करके प्रादेशिक भाषाओं में करें। इससे यह कठिनाई आधक भीना तक दूर हो सकती है। ग्रामीण कर्तव्यहीन होने के कारण बैंकों के साथ अपने लेन-देन करना नहीं चाहते। वे न तो बैंकों में राशि जमा करना पसन्द करते हैं और न उनके साथ पर राशि लेना ही चाहते हैं। वे तो सरकारों से ही लेन-देन करने हैं जो इन

लोगों के अधिक समीप रहता सहता है। एक बान और भी है। बैंकों के फेन होने के कारण गाँववालों का इनमें विश्वास भी नहीं रहता। इन कठिनाइयों को अधिकांशतः शिक्षा न द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरे, रियल बैंक या सरकार ग्रामीणों को गाँवों में काम करनेवाली बैंकों की मनवृत्ति की गारंटी करने लागा तो उनसे साथ लगे इन बंटान में प्राप्ति के करे। गाँवों में काम करनेवाले बैंक ग्रामीण जनता में से ही पड़े लगे लागा के साथ अपने सम्पर्क बढ़ाएँ—उन्हें अपने मंचालक मण्डल में रखें तथा कार्यालयों में काम दें। इससे ग्रामीणों में इन बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ने में सहायता मिलेगी।

प्रायः देखा गया है कि गाँवों में धन की मांग लोग अपनी रुपया ग्रामीण जनता को ही उधार देने के, बैंकों में नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन्हें बैंकों की अपेक्षा इन लागा में अधिक व्याज मिलता है। यदि बैंक अपनी व्याज दर बढ़ा दें तो लागा उनके पास अपनी बचत जमा करने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि बैंकों द्वारा दी जानेवाली व्याज-दर कम होने के कारण गाँवों में बैंकों का अधिक सफलता नहीं मिली है। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों शहरों की अपेक्षा ऊँची व्याज-दर रखें और इस काम के लिए सरकार उनको अर्थ सहायता दे। यद्यपि यह मुझसे बैंकों की दृष्टिकोण से उचित नहीं रहेगा परन्तु तो भी प्रयोग के तौर पर ऐसा करने देना चाहिए कि क्या यह योजना सफल हो सकती है।

बहुतसे बैंकों ने अपने कार्यालय गाँवों में इसलिए स्थापित नहीं किए हैं कि उन जायजों में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है और इस प्रकार बैंकों का हानि रहती है। इससे लिए यह उपाय है कि सरकार कुछ समय तक इस हानि की पूर्ति करे और जब कार्यालय आत्मनिर्भर बन जाएँ तो सहायता देना बन्द कर दे। दूसरे, बैंक अपने ग्रामीण कार्यालयों पर शाही-गोड़ी तनख्वाह के कर्मचारी रखें और ये कर्मचारी सम्भवतः गाँवों में से लिए जाएँ। इससे कार्यालयों का व्यय भार कम होगा। सरकार का भाव चाहिए कि इन क्षेत्रों में स्थित बैंकों का शाखाओं पर जो कर्मचारी काम करें उनके साथ शहरों जैसी वेतन भत्ता आदि का सम्बन्ध न लगाए।

इन उपायों के अतिरिक्त ग्रामीण बैंकिंग जांच कमेटी ने गाँवों में स्थित

बैंक की शाखाओं को वृद्धि पंजे काम करने के मुझाव दिष्ट है जिनमें गाँववालों में बैंक के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उनका प्रचार होगा। ये मुझाव निम्न हैं—

१. एक स्थान में दूसरे स्थान पर राशि भेजने भगाने की सुविधा देना।
२. नोट तथा मिर्झों के बदल-बदल की सुविधाएँ तथा खराब नाना और मिर्झों को अच्छे नानों और मिर्झों में बदलने की सुविधा देना।
३. कपड़ा तथा आभूषण सुरक्षित रखने की आर्थिक सुविधाएँ देना।
४. गोदाम बनाकर कृषक को िराये पर देने का सुविधा देना।

यदि इतनी और सुविधाएँ कृषक को बैंकों में मिलनी रहें तो कृषकों से बैंकों के साथ लेन-देन में रुचि बढ़ेगी और विश्वास भी उत्पन्न होगा।

गाँवों में बैंकों की व्यवस्था करने में सामान्य बैंकिंग जॉब कमेंटी ने संक्षेप में निम्न सुझाव दिए हैं—(१) विज्ञापन प्रत्येक राज्य में अपनी शाखा खोलने, (२) इम्पारियल बैंक तथा अन्य आधिकारिक बैंक सहमति में, जिला-नगरों में तथा बड़े बड़े ताल्लुकों में अपनी-अपनी शाखाएँ खोलें, (३) सहकारी-साव सप्लियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा साव-प्रदानन का पुनर्गठन किया जाय, (४) राज्य की ओर से ज्वि साव कारपोरेशन स्थापित किए जायें, (५) दारुकाजान साव-सुविधाएँ देने के लिए भूमि-बंकर बैंक स्थापित किए जायें, (६) डाकघरों की बचत-बैंक गाँव-गाँव में, जहाँ यातायात की सुविधा हो, स्थापित की जायें, (७) गाँवों में खुलने वाली दफ्तों की शाखाओं में प्रादेशिक भाषाओं में काम किया जाय, (८) ये बैंक कपड़ा जमा करने तथा निकालने में अरजा राशि थोड़ी भरल बनायें, (९) सामानों का साक्षर बनाने के प्रयत्न किए जाय, (१०) बैंक में राशि जमा करने तथा बैंक का आर्थिक में आर्थिक प्रयोग करने में सामान्य की प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

२६—रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता आया था। १९२६-२७ में हिल्टन यंग कमिशन की सिफारिशों पर जब भारतीय धारा-सभा में विचार हुआ तो स्पष्टी दत्त राष्ट्रीयकरण का समर्थक था। परन्तु उस समय रिजर्व बैंक स्थापित ही न हो सका और यह बात आगे के लिए टाल दी गई थी। १९३४ में रिजर्व बैंक प्रायः हाएटवा एक्ट पास हुआ और एप्रैल १ अप्रैल सन् १९३५ में रिजर्व बैंक प्रशोधनालय के बैंक के रूप में काम करने लगा। १९४६-४७ में केन्द्रीय विधान सभा में जब बजट पर बहस हो रही थी तो श्री शरतचन्द्र बोस ने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को उठाया। प्रश्न का उत्तर देने हुए वित्त मंत्री सर आर्नाल्ड रोल्ड्स ने कहा कि "मुझे इस विषय में सशय नहीं है कि नेस्ट भविष्य में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। इसका राष्ट्रीयकरण अब तो कबो नहीं हुआ, इसका कारण मेरे विचार से यह था कि विधान सभा रिजर्व बैंक जैसी संस्था को एक अनुत्तरदायी दायर्यभारिणी के हाथ में देने को तैयार न थी।" उस समय भी यह बात टाल दी गई। केन्द्रीय धारा-सभा में राष्ट्र-पकरण का प्रस्ताव परचरी १९४७ में फिर लाया गया परन्तु वित्त-मन्त्री के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इस पर विचार करेगी और समय आने पर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा प्रस्ताव वापस ले लिया गया। १९४८-४९ के बजट पर बहस करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि अब राष्ट्रीय सरकार है और देश एकता है, इसलिए केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न दलालें दी गईं जिनको मानकर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

१. अन्य देशों के केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका था और तभी उन देशों के सरकार की प्रार्थना तथा मौद्रिक नीति का ठीक ठीक मचापन केन्द्रीय बैंक करते थे। भारत में भी यह तभी किया जा सकता था जब कि रिजर्व

बैंक का राष्ट्रीयकरण हो। अतः मौद्रिक तथा माध्य नीति के मरुतल संचालन के कारण राष्ट्रीयकरण पर अधिक जोर दिया गया।

२ भारत में जन साधारण के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक था कि देश का आर्थिक संकट दूर किया जाय तथा लोगों की आय बढ़ाई जाय। ऐसा करने के लिए युद्ध के पश्चात् आर्थिक आयोजन की आवश्यकता थी और आर्थिक आयोजन का काम तभी मरुतल हो सकता था जब रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बैंक भी सरकार का एक विभाग बनकर सरकारी नीति के साथ सहयोग देता। अतः रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग की जाने लगी जिसमें यह राष्ट्रीय संस्था बनकर सरकार का अधिक से अधिक सहयोग दे सके।

३ विलुले वर्षों में, विशेषतः युद्धकाल में, रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति मनोपजनक नहीं रही थी। नोट बहुत छपाए गए थे जिससे मुद्रा-स्फीति हुई और वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गए। बैंक ने इसे रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। इसलिये सोचा गया कि रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण करने से यह दोष दूर हो जायगा और भविष्य में बैंक अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

४. बहुत सी बातों पर रिजर्व बैंक को देश की अन्य बैंकों में आवश्यक गृहना प्राप्त करनी पड़ती थी। असाधारणों का बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक को गृहना प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती थी। इसलिये सोचा गया कि राष्ट्रीयकरण करने से रिजर्व बैंक को एक ऐसा अधिकार और बल मिलेगा कि तब यह इच्छानुसार गृहना प्राप्त कर लिया करेगा।

५. राष्ट्रीयकरण के पक्ष में एक युक्ति यह थी कि इस प्रकार रिजर्व बैंक एक प्रकार से सरकारी विभाग बन जायगा जिसके द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपनी आर्थिक और वित्त नीतियों को इस बैंक की सहायता में मरुतल बना सकेंगी।

इन कारणों को लेकर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और १ जनवरी १९४६ में रिजर्व बैंक राष्ट्रीय संस्था बन गया। रिजर्व बैंक के हिस्से सरकार ने ले लिए और १०० करोड़ के एक हिस्से के बदले में ११८८०१० आने देना स्वीकृत हुआ। ११८८०१० का भुगतान इस प्रकार किया

गया। प्रत्येक १०० रुपये के बदले में तो तीन प्रतिशत वार्षिक व्याज दर के सरकारी बौण्ड दे दिए गए तथा गण गणित के बदले में नगद रुपया चुका दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए। इस प्रकार पेदा रान के २४ वर्ष पश्चात् रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया।

रिजर्व बैंक का प्रबंध अब केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर की सलाह से इसका प्रबंध करता है। केन्द्रीय सरकार बैंक के गवर्नर की सलाह से समय समय पर जन हित का दृष्टि में रखते हुए बैंक को आदेश देती है और इन आदेशों की पूर्ति के उद्देश्य का सामने रखकर एक के द्वाय बांड बैंक का संचालन करता है। केन्द्रीय बांड में निम्न व्यक्ति हात हैं —

(अ) एक गवर्नर तथा डेप्युटी गवर्नर—इनका केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त करती है परन्तु अधिमान्त रान पर इनका फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। इनका बतन केन्द्रीय सरकार का सलाह से तद्वय बांड निश्चित करता है। डेप्युटी गवर्नर से केन्द्रीय बांड की प्रेरण में भाग लेने का अधिकार तो होता है परन्तु मत देने का अधिकार नहीं है। परन्तु यदि गवर्नर की अनुपस्थिति में डेप्युटी गवर्नर कार्य संचालन करे तो उस समय उसका मत देने का अधिकार होता है।

(ब) चार सचिव—य सचिव केन्द्रीय सरकार द्वारा चारों स्थानीय बांड में से मनानीत किए हुए हात हैं। [स्थानीय बांड प्रागे देखिए।]

(स) छ सचिव और होते हैं। इनको भी केन्द्रीय सरकार मनानीत करती है। इनमें से प्रत्येक दो बारी बारी से एक, दो और तीन वर्ष के बाद अनग होते जाते हैं।

(द) एक सरकारी अपसर हाता है। यह भी सरकार द्वारा मनानीत किया हुआ होता है। यह अपसर सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय तक काम कर सकता है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद नए विधान के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड में कुल १४ व्यक्ति होते हैं।

केन्द्रीय बैंक के अनिश्चित बैंक के प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं। स्थानीय-बोर्ड कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में हैं। सीमा की दृष्टि से भारी देश का चार प्रदेशों में बाँट लिया गया है। (१) उत्तर प्रदेश, (२) दक्षिण-प्रदेश, (३) पूर्वी-प्रदेश, (४) पश्चिमी प्रदेश। इन चार प्रदेशों के लिए एक-एक स्थानीय बोर्ड है। प्रत्येक स्थानीय-बोर्ड में पाँच सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति सरकार करती है। ये सदस्य अपने-अपने में सी.पी. बोर्ड का अध्यक्ष चुन लेते हैं। प्रत्येक सदस्य चार वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु अवधि समाप्त होने के बाद इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। चारों स्थानीय-बोर्ड आवश्यक मामलों पर केन्द्रीय-बोर्ड को सलाह देते हैं तथा केन्द्रीय-बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में होता है, परन्तु कोई भी तीन सचिवक मिलकर भी गवर्नर से केन्द्रीय-बोर्ड की बैठक बुलाने की प्रार्थना कर सकते हैं। वर्ष भर में दस बैठकें बुलाना अनिवार्य है परन्तु तीन महीने में एक बैठक जरूर ही हानी चाहिए। बैंक के कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा फाजिरा में हैं। इसका एक शाखा लन्दन में भी है जो अप्रैल १९०६ में खोला गई थी। केन्द्रिय-सरकार की आज्ञा से रिजर्व बैंक अन्य किसी स्थान पर भी शाखा खोल सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनने में रिजर्व बैंक और इण्डिया एक्ट में भी भूमिका निभाने की दिशा में दिख रहा है। पहिले रिजर्व बैंक और इण्डिया एक्ट की धारा ६० और ६१ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक रुपये के बदले में निश्चित रिनिमिय दर पर स्टैंडिंग प्रसेदा और बेना करता था। परन्तु अब एक्ट की इन धाराओं में संशोधन कर दिया गया है। अब रिजर्व बैंक सरकार के आदेशानुसार केवल स्टैंडिंग ही नहीं बल्कि उन सब देशों की मुद्राएँ प्रसारित-बेचना है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। इसी प्रकार रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ६३ में भी संशोधन कर दिया गया है। पहिले इस धारा के अनुसार बैंक को स्टैंडिंग मिन्सूटियों के आधार पर नोट चलाने का अधिकार था। परन्तु अब बैंक केवल स्टैंडिंग के ही आधार पर नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मिन्सूटियों के आधार पर नोट जारी कर चलाने का अधिकार है।

एक्ट की धारा १७ (३) में भी संशोधन कर दिया गया है। धारा १७ (३) (अ) में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी विनिमय' लिख दिया गया है और १७ (३) (ब) में वर्णित 'यूनाइटेड किंगडम' के स्थान पर 'कोई देश जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो' लगा दिया गया है। धारा १८ में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी विनिमय' लिख दिया गया है। इन संशोधनों के फलस्वरूप अब हमारा कया कितने विदेशी मुद्रा पर आधारित नहीं है। इसका वर्णन आगे 'हमारा कया' शीर्षक लेख में मिलेगा।

२७—बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। प्रो० रत्ना जैम कुछ लोगों का मत है कि व्यापारिक बैंकों के लिए ऐवेल कानून बनाने में कुछ नहीं हो सकता, उन्हें तो सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में ले आना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि युद्धोत्तर काल में किसी भी आर्थिक योजना का सफल बनाने के लिए व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में प्रायः निम्न तर्क दिए जाते हैं—

(१) बैंक, जो मुद्रा-निर्माण तथा साव्य-वृजन का काम करती हैं, ये काम तो सरकार के अधिकार की वस्तुएँ हैं। अतः बैंकों को ही सरकारी अधिकार में ले आना चाहिए।

(२) स्वयं और व्यक्तिवादी बैंकों पर केन्द्रीय बैंक सफलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर पाता। अतः आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

(३) यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है तो बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए अन्यथा सम्भव है राष्ट्रीयकृत उद्योगों में व्यक्तिवादी बैंक आवश्यक सहयोग न दें और सरकारी औद्योगिक नीति सफल न हो सके।

(४) यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो वे सफलता के साथ साव्य का वितरण कर सकेंगी।

कुछ लोग व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से बैंकों की लेगा-पुस्तकों का गुप्त भेद सरकारी कर्मचारियों तथा आय-कर गणन करने वाले लोगों को ज्ञात होता रहेगा जिससे वे राशि जमा करने वाले लोगों को अधिक तंग करने लगेंगे। परिणाम यह होगा कि लोग फिर बैंकों में राशि जमा करना बन्द करने लगेंगे और यदि ऐसा हुआ तो देश की पूँजी-निर्माण व्यवस्था पर बड़ी गहरी चोट

लगेगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बड़ा पर राजनैतिक दलबन्धिया का अधिकार हो जायगा और फिर सरकारी दल जैसे चाहेगा बैंकिंग प्रणाली को उसी भाँति नचाना रहेगा। अतः देश के हित में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष की युक्तियाँ पर दोनों ओर से काफी कहा जा सकता है परन्तु देवना यह है कि आगमर वास्तविकता क्या है। विदेशों में प्रायः देवने में आता है कि यहाँ मन्त्रोय बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया है परन्तु व्यापारिक बैंक अभी व्यक्तिवाद के आधार पर ही चल रहे हैं। इंग्लैण्ड में 'बैंक ऑफ इंग्लैण्ड' का राष्ट्रीयकरण हो चुका है परन्तु अन्य बैंकों का नहीं। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखने का पूरा पूरा अधिकार दे दिया गया है। हमारे यहाँ भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करने बैंकिंग कम्पनी कानून पास कर के रिजर्व बैंक को देश के अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखने के असीम अधिकार दे दिए गए हैं। इन अधिकारों के द्वारा रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के नए कार्यालयों पर, उनकी ऋण नीति पर, जमा राशि की नीति पर तथा हिसाब-किताब पर पूरा पूर्ण नियन्त्रण रखता है। व्यापारिक बैंक पूर्ण रूप से अब रिजर्व बैंक के अधिकार में हैं और रिजर्व बैंक सरकारी सत्ता है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि बैंकों पर एक प्रकार से सरकार का ही नियन्त्रण है तो अत्युक्त नहीं होगी। राष्ट्रीयकरण के प्रायः दो पहलू होते हैं—(१) जिसमें सरकार का स्वामित्व और नियन्त्रण दोनों हों, (२) जिसमें सरकार का केवल नियन्त्रण ही रहे। अतः आज भी हमारे यहाँ दूसरे प्रकार का बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सबसे जोरदार बात यह कही जाती है कि इससे सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक आगमन में सहायता मिलती है तथा बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार का अधिकार हाता है जिससे बैंक जनता के विरुद्ध कोई काम न कर सकें। ये सब बातें आज भी हमारे बैंकिंग प्रणाली में मौजूद हैं। रिजर्व बैंक का कड़ा पहरा हाने के कारण हमारे देश की बैंक रिजर्व बैंक की आशा के बिना उस से मस भी नहीं हो सकती। हाँ, बैंकिंग कम्पनी कानून बनने से पहिले इन बैंकों पर किसी का नियन्त्रण न था—न सरकार का था और न रिजर्व बैंक

का। उस समय इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न मुनिमगत बना जा सकता था। परन्तु १९४६ में बैंकिंग कम्पनी कानून पास होने से अब यह बात नहीं है।

। फिर भी कम से कम इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत जोरों से उठाया जाता रहा है। इस प्रश्न को विजय बेंक के राष्ट्रीयकरण के समय उठाया गया था। उस समय के वित्त-मंत्री श्री मथाई ने कहा था “एक देश की आर्थिक परिस्थिति पर राष्ट्रीयकरण के जो दुरुपरिणाम होंगे उनको देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में सरकार इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं समझती”। किन्तु सरकार इम्पीरियल बैंक के देशों को दूर करने का प्रयत्न करेगी—यह आश्वासन उस समय वित्त-मंत्री ने दिया था। हमारे प्रधान १९५०-५१ का बजट पेश करते समय भी इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न लाया गया परन्तु उस समय भी यह कह कर टाल दिया गया कि देश की साव्य व्यवस्था एवं बैंकिंग-उद्योग का दृष्टि से इम्पीरियल बैंक का वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीयकरण करना हितकर न होगा। नवम्बर १९५० में राष्ट्रीयकरण का प्रश्न फिर दोहराया गया। उस समय वित्त-मंत्री भी देशमुख ने कहा “कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न देश के आर्थिक हितों में नहीं होगा”। वित्त-मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि “इम्पीरियल बैंक की बहुत सी चीजें भारतीयों के अधिकार में हैं तथा उनके कर्मचारियों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है तथा कुछ वर्षों में ही इम्पीरियल बैंक हमारे नियंत्रण में आ जायगा। अतः हमारे अपने हितों की दृष्टि से ऐसा कोई भी काम जो शीघ्रतापूर्वक किया जायगा वह अहितकर होगा”। इस प्रकार १९४८ में जो दृष्टिकोण हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने रक्खा था यह आज भी है। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित सा ही हो गया है। इससे ज्ञात होता है कि हमारी सरकार भी बैंकों का स्वामित्व अपने पास लेने को तैयार नहीं है। जहाँ तक सरकारी नियंत्रण का प्रश्न है वह तो सरकार का है ही। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अब हमारी सरकार के सामने बड़ी अनुविधाएं हैं जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैं। इस समय हमें चाहिए कि बैंकों की राष्ट्रीयकरण की मंति न करके उनको मुश्किल और अनहित के योग्य बनाने की मंति करें।

इस समय देश का हित इसमें है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करके एकीकरण किया जाय। यदि बक बनिष्ठ बनानी हैं और उनको सकट से बचा कर उनसे देश के आर्थिक आयाजन में काम लेना है तो आवश्यकता है कि निर्बल तथा बिगरे साधनों को एक साथ मिला कर मजबूत बना दिया जाय और तब उन्हें सुयोग्य, अनुभवी और ईमानदार संचालक के प्रबन्ध में रख दिया जाय। राष्ट्रीयकरण के स्थान पर बैंकों का एकीकरण किया जाय। राष्ट्रीयकरण में चाहे सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण हो जावे परन्तु निर्बल और अयोग्य बैङ्क दूर न हो सकेगी और इनसे रहते सदैव खतरा ही बना रहेगा। अतः कई-कई छोटो-छोटो और साधनहीन बैंकों को मिलाकर एक कर देना चाहिए। इसमें नई बैङ्क के साधन दृढ़ होंगे और प्रबन्धक भी सुयोग्य ही मिल सकेंगे। देश में बैंकिंग विशेषज्ञ की कमी भी दूर हो जायगी और निर्बल बैंक भी मिल कर दृढ़ बन जाएँगी। बैंकों के एकीकरण में कोई विशेष अमुग्धता का सामना नहीं है। प्रायः कई-कई बैंक एक ही संचालक-मण्डल के प्रबन्ध में हैं। ये संचालक-मण्डल मिल कर कई-कई बैंकों का एकीकरण कर सकते हैं। मार्च १९५० में बंगाल में कौमिला यूनियन, कौमिला बैङ्क तथा अन्य बैंकों को मिलाकर बंगाल कमर्शियल बैंक बनाया गया था। सरकार ने इस ओर और ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान परिस्थितियों में जब कि सरकार पूँजी के अभाव में बैंकों का स्वामित्व नहीं ले सकती, योग्य विशेषज्ञों के अभाव में उनका संचालन नहीं कर सकती, और जब रिजर्व बैंक का पहिल ही इन पर काफ़ी नियंत्रण है, राष्ट्रीयकरण का योजना हिनकर नहीं है। अब तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग कानून बनाकर पूरा हो रहा है और एकीकरण के द्वारा और अधिक पूरा हो जायगा। प्राज्ञ की परिस्थितियों में कन्द्रीय बैंक का ही राष्ट्रीयकरण पर्याप्त है।

२८—स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था

डॉलर के प्रश्न को लेकर स्टर्लिंग को डॉलरों में परिवर्तित कराने की जो समस्या उठी हुई है उसमें अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में स्टर्लिंग के प्रांत आलोचना और विश्वास बढ़ना जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था को ही समाप्त करने की दलीलें दी जाती हैं और स्टर्लिंग-क्षेत्र से मध्य-राष्ट्र स्तर पर इस बात को सोचने लगे हैं कि उन्हें इस क्षेत्र से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है जिसे समझने के लिए स्टर्लिंग-क्षेत्र की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

स्टर्लिंग-क्षेत्र में इंग्लैण्ड के साथ-साथ एशिया के भी कई राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, लका, मलादेश मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा रोडेशिया भी इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य-देश अपनी-अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई को केन्द्रित करके एक कोष बनाकर इंग्लैण्ड में जमा रखते हैं। आवश्यकता के समय सदस्य-देश इस कोष में से राशि लेकर उसमें काम चलाने हैं। किन्तु कोई भी सदस्य-देश केन्द्रीय कोष में से असीमित मात्रा में राशि नहीं निकाल सकता। सभी सदस्यों ने मिलकर कुछ नियम बना रखे हैं जिनके अनुसार ही केन्द्रीय कोष में से राशि निकाली जा सकती है। यदि प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी इच्छानुसार इस कोष में से राशि निकालने लगे तो यह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं रह सकती। अतः सदस्य-देशों को अपना अपनी विदेशी मुद्रा की माँग को, विशेषकर डॉलर की माँग को, नियंत्रित करके संयम रखने की आवश्यकता होती है। पिछले कई वर्षों से डॉलर का विश्व-व्यापी अभाव चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप स्टर्लिंग-क्षेत्र के स्तर पर डॉलर की कमी कम होते रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सितम्बर १९४६ में स्टर्लिंग के डॉलर-मूल्य में कमी की गई परन्तु अब समस्या फिर ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले चार वर्षों में स्टर्लिंग-क्षेत्र के स्तर पर डॉलर की स्थिति इस प्रकार रही :—

वर्ष	अभाव (-) अथवा आधिक्य (+) (१००,००० डॉलर)	वर्ष के अन्त में शेष की स्थिति (१००,००० डॉलर)
१९४७	- ४१३१	२०७८
१९४८		
द्वितीय तिमाही	- ६३०	१६५१
तृतीय तिमाही	- १०६	१४०५
१९५०	+ ८०५	३३००
१९५१		
प्रथम तिमाही	+ ३६०	३७५८
द्वितीय तिमाही	+ ५४	३८६७
तृतीय तिमाही	- ६३८	३२६९
अन्तिम तिमाही	- ६३४	२६०५

इन आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण बात यह मालूम होती है कि १९४९ में स्टर्लिंग क्षेत्र अनुल्यून में पड़िले और पीछे शेष में जितना अभाव रहा उससे अधिक अभाव १९५१ की तासरी और अन्तिम तिमाही में रहा। परन्तु तो भी १९५१ में शेष की स्थिति अच्छी रही। इसका कारण यह है कि १९५० में शेष में अधिक राशि जमा होती रही। इसका कारण यह था कि अमरीका उच्च मान को इकट्ठा करने में लगा हुआ था और स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य देश उसका मान बेच बेचकर डॉलर कमा रहे थे। परन्तु १९५१ में अमरीका ने उच्च मान सम्रह करना बन्द कर दिया और तभी पूरा साथ डॉलर की कमी हो गई। दूसरी बात यह थी कि १९५१ की तृतीय तिमाही में अमरीका से तम्बाकू और कपास अधिक सरीदे जा रहे थे जिनसे बदले में डॉलर चुकाए जा रहे थे। इससे विपरीत स्टर्लिंग क्षेत्र से उन और कोसोआ का निर्यात कम हो रहा था जिसमें डॉलर की आय कम हो रही थी। इस प्रकार डॉलर का भुगतान बढ़ने से तथा डॉलर की आय कम होने से दुसरी मार थी। अब परिस्थिति यह है कि सदस्य देशों को अपने अपने डॉलर व्यय में कमी कर देनी चाहिए। यदि अब भी सदस्य देश अपनी मनमानी व्यापार-नीति बरतते रहे तो स्टर्लिंग क्षेत्र के डॉलर

कोय प्रीति ही (१९५२ के अग तक) सामान हो जायें और सब संसार में स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी सदस्यों को एक भारी गकट का सामना करना पड़ेगा ।

इस समय में एक नई बात यह है कि केन्द्रीय कोय में से इंग्लैण्ड अपनी कमार्ड में अधिक व्यय करता रहा है तथा अन्य सदस्य-देश व्यय में अधिक कमार्ड रहे हैं । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य देश इस व्यवस्था को गकट कर अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लें । संसार का अधिकांश व्यापार आज स्टर्लिंग के द्वारा होता है । अतः स्टर्लिंग की सहाय बनाए रखना केवल स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य-देशों का ही काम नहीं परन्तु संसार के उन सब देशों का गर्त्य है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्पन्न करना चाहते हैं । कुछ लोगों का खयाल है कि यदि किसी सदस्य देश को इंग्लैण्ड स्थित कोय में से आवश्यकता मात्रा में डॉलर न मिल सकें तो उसे स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य रहने से कोई लाभ नहीं—उसे कोय में अपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए । परन्तु यह बात व्यावहारिक नहीं है । स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था में केवल यही एक लाभ नहीं कि सदस्य-देशों का आवश्यकतामनुसार डॉलर मिलन रहे परन्तु और भी बड़े लाभ हैं जिनके लिए स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था का अनुगमन रहना अनिवार्य है । इन लाभों का निम्न भाग में बौटा जा सकता है—

(अ) व्यापार-सहाय्य की सुविधाएँ ।

(ब) पूँजी के आदान प्रदान की सुविधाएँ ।

केन्द्रीय कोय के होने से स्टर्लिंग क्षेत्र भर का, विशेषतः क्षेत्र के सदस्यों का व्यापार डॉलर-क्षेत्र वाले देशों के साथ सरलता पूर्वक हो सकता है । सदस्य देश इस कोय पर निर्भर रहने हुए अपनी विदेशी व्यापार सम्बन्धी रूढ़िकामीन नीतियाँ बनाकर अपने व्यापार को उत्पन्न बना सकते हैं । केन्द्रीय कोय के होने से सदस्य-देश इन साधनों का प्रयोग करने में सक्षम और आसक्त रहते हैं । यदि कोय केन्द्रित करने न सक्ता जाय तो प्रत्येक देश को अपना अपनी आर्थिक व्यवस्था और विदेशी व्यापार नीति के अनुगमन करने अर्थात् व्यक्तिगत रीतियों को घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होगी । परन्तु इस प्रकार की सुविधा से सब प्रत्येक सदस्य-देश राहत है । यह ठीक है कि मुद्रकाल में सभी हमारे पहचान भी समय-समय पर कई सदस्य-देशों को डॉलरों का आभार रहा

है, परन्तु इस प्रकार इन देशों का डॉलर-क्षेत्र के साथ किए जाने वाले अपने व्यापार पर अधिक चौकसी का आवश्यकता नहीं रही। यदि प्रत्येक देश अपने अलग अलग डॉलर कोष बनाकर गगता तो उन्हें डॉलर क्षेत्र से होने वाले अपने व्यापार पर इससे भी अधिक चौकसी और नियंत्रण की आवश्यकता होगी और सम्भव है तब उनका व्यापार इतना विकसित न हो पाता। यह भी सम्भव है कि तब उनका वैदेशिक, विशेषतः डॉलर क्षेत्र वाले व्यापार में अनिश्चित घटा बढी होने के कारण उन्हें डॉलर क्षेत्र में हानि वाले अपने आयातों पर अधिक काट छूट करने पड़ना जिससे उनकी परराष्ट्र योजनाओं को भारी धक्का लगने की आशंका हो सकती थी।

केन्द्रीय रूप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि इससे द्वारा क्षेत्र के सदस्य देशों में पार-परिष्कार व्यापार एवं भुगतान सरलता और स्वतन्त्रतापूर्वक चलते रहें हैं। स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के सदस्यों में पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी राशियाँ इतनी अधिक नहीं हैं जितनी अन्य देशों में, और जो कुछ हैं भी यह नहीं बराबर है। इंग्लैण्ड ने तो स्टर्लिङ्ग क्षेत्र से होने वाले आयातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। हाँ अन्य सदस्य देशों ने कुछ नियंत्रण और प्रतिबन्ध लगाए हैं परन्तु फिर भी संसार के अन्य क्षेत्रों का अपेक्षा इस क्षेत्र में व्यापार और भुगतान सम्बन्धी सुविधाएँ सबने अधिक हैं। अन्य देशों के साथ इंग्लैण्ड ने व्यापारिक सम्झौते किए उनके साथ स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के सभी देशों का लेन देन इस क्षेत्र में होने के कारण सरलतापूर्वक चलता रहा। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड ने गारंटीय भुगतान सब के देशों के साथ व्यापारिक लेन देन का कार्य आरम्भ करने की योजना की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के सदस्य देशों में इन देशों के साथ सरलतापूर्वक अपने व्यापारिक लेन देन करत रहे। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लैण्ड ने स्टर्लिङ्ग क्षेत्र और यारोपीय भुगतान संघ के देशों में होने वाले व्यापार में समाशासन यह का काम किया है।

स्टर्लिङ्ग क्षेत्र व्यवस्था होने के कारण इंग्लैण्ड से अन्य देशों में पूँजी का अवरोध आवागमन होता रहा है। स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के किसी भी सदस्य देश की इंग्लैण्ड में पूँजी प्राप्त करने की उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी इंग्लैण्ड स्थित

किसी व्यापारिक कम्पनी को हो सकती है। अन्तर केवल यह है कि इंग्लैण्ड में पूँजी एकत्रित करने वाली बाह्य कम्पनियों को इंग्लैण्ड में यह विश्वास दिलाना होता है कि उन्हें पूँजा का वास्तविक आवश्यकता है और यह उनसे अपने देश में पूर्ण नहीं हो सकती। आकड़ा में जान होता है कि १९४७ में १९५१ तक इंग्लैण्ड में कोई ६०,००,०० ००० पौण्ड की पूँजी स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्य देशों में भेजी गई।

स्टर्लिंग-क्षेत्र की सदस्यता का एक विशेष लाभ यह है कि सदस्य-देशों की इंग्लैण्ड के बाजारों में लेन-देन की सुविधा बनी रही है। यह कोई कम लाभ की बात नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात का है कि इस क्षेत्र का तोड़ने के बजाय सुदृढ़ बनाया जाय और सब सदस्य मिलकर केन्द्रीय कोष का भरपूर कर दें।



२६—पोंड-पावने तथा उनका भुगतान

द्वितीय विश्व युद्ध की भारत की एक देन यह रही कि इंग्लैण्ड की सरकार पर भारत का बड़ा ऋण का बर्ज़ा हो गया। युद्ध से पहिले भारत इंग्लैण्ड ने साम्राज्यवादी ऋण से दबा हुआ था। युद्धकाल में यह सब ऋण चुका दिया गया। इतना ही नहीं, भारत ने भूखे पेट और नंगे शरीर रह कर इंग्लैण्ड को करोड़ों रुपये का माल भेजा। इस माल के बदले में जो राशि हमें मिलना चाहिए थी वह हम उस समय न मिली वरन् हमारे हिसाब में जमा हाता रहा। इस प्रकार देनदार से हम लेनदार (Creditor) बन गए और इंग्लैण्ड पर हमारा लगभग १७०० करोड़ रुपये का बर्ज़ा हो गया। इसी ऋण को 'पोंड पावना' कहते हैं। इस ऋण को 'पोंड पावना' क्या कहा जाता है तथा यह किस प्रकार दफ्ता हाता गया? यह सब कुछ जानना बहुत आवश्यक है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा ३३ के अनुसार रिजर्व बैंक का यह अधिकार था कि वह साने चाँदी के अतिरिक्त कुछ सिक्यूरिटीज रख कर भी नोट चला सकता है। इन सिक्यूरिटीज में कुछ तो भारत सरकार के बिल होते थे तथा कुछ इंग्लैण्ड की सरकार के बिल होते थे। इंग्लैण्ड की सरकार के बिलों का भुगतान स्टर्लिंग में होता था इसलिए इन्हें 'स्टर्लिंग-सिक्यूरिटीज' कहते हैं। युद्धकाल में भारत सरकार इंग्लैण्ड की सरकार को माल वगैरह वगैरह कर भेजती रही और इंग्लैण्ड की सरकार स्टर्लिंग-सिक्यूरिटीज देकर इस माल का भुगतान चुकाती रही। ये स्टर्लिंग सिक्यूरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में जमा हाती रही और रिजर्व बैंक इनके आधार पर नोट छाप-छाप कर चलाता रहा। स्टर्लिंग की यह राशि जो इंग्लैण्ड में हमारे हिस्से में जमा हाती रही और जिसके बदले में रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग सिक्यूरिटीज मिलता रहा 'पोंड पावना' कहा जाता है। इस प्रकार हमारे देश में नियन्त्रित मूल्यों (Controlled Prices) पर माल खरीदा गया और पोंड-पावने दफ्ते होते रहे। वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक न बढ़ सका।

इसलिए नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल मिलना बहुत कठिन हो गया और उन्हें चीगुने वनगुने मूल्यों पर खोर-बानाग से माल परीक्षण पड़ना था।

यदि हमें इन पीण्ड-पावनों के स्थान पर सोना चांदी या पृथ्वीगत माल, जैसे मंगाने आदि, मिलती तो पीण्ड-पावनों की इतनी कठिनाई नहीं होती और भारत में जनता को इतनी कठिनाईयाँ नहीं उठानी पड़ती। प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ना गया। एक समय ऐसा आया जबकि रुपये की दर २ शि० १० पैसे हो गई। इसका यह परिणाम निकला कि रजतियों के मूल्य इतने बढ़े जितने द्वितीय युद्धकाल में बढ़े या उससे बाढ़ और बाढ़ रहे हैं। द्वितीय युद्धकाल में रुपये की विनिमय-दर को स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया। दर को स्थिर रखा परन्तु वस्तुओं के मूल्य धीरे धीरे बढ़ते गए। मन्ते का मूल्यदेगनाह १६३६ में १०० के बराबर था जो कि अगस्त १६४८ में ४३४७ हो गया। यह बात सभी वस्तुओं के मूल्यों के साथ हुई। आतः इन पीण्ड-पावनों के एकत्रित होने से जनता के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हमारी धारणा यह है कि यदि वस्तुओं के मूल्यों की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता और रुपये का दर को स्थिर रख दिया जाता तो न तो ये पीण्ड-पावने इकट्ठे होते और न हमें इतनी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों रुपये की दर ऊँची होती जाती इंग्लैण्ड की सरकार को भी हमारे यहाँ का माल ऊँचे मूल्यों पर मिलता। फलस्वरूप या तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से माल न खरीदकर अन्य देशों में परीक्षती और या हमारे देश में माल की उपलब्धि बढ़ाने के प्रयत्न किए जाने। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने भी सरकार को कोई सलाह नहीं दी जिससे दर की स्थिरता पर ध्यान न देकर मूल्यों की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता। इन पावनों का एक बुरा परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में मुद्रास्फीति अविहारिक बढ़ती गई। सन् १६३६ में हमारे देश में कुल १८० करोड़ रुपये के नोट चलने थे लेकिन १६४३-४८ में कुल नोट १२०१ करोड़ रुपये के हो गए। इस मुद्रास्फीति का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते ही गए और देशवासियों को अभूतपूर्व संकट का

सामना करना पड़ा। हाँ, इनने इकट्ठे होने से देश लेनदार अवश्य हो गया परन्तु इसके साथ-साथ देश का आर्थिक ढाँचा भी तितर-बितर हो गया। बंगाल का अकाल और आकाश का छूते हुए मूल्यस्तर इसी के परिणाम थे। पाण्ड-पावना हमारे त्याग और बलिदानों का समूह है। पौण्ड-पावने इंग्लैण्ड में हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति थी। उसका समुचित उपयोग हमारे कई आर्थिक प्रश्नों का सरलता से हल कर सकता था। आज भारत के आर्थिक उत्थान को अनेक याजनाएँ मशानों और दूसरे पूँजीगत माल के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। देश के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूँजीगत माल हमें मिले। इसका खरीदने के लिए हमारे पास एक मात्र साधन पौण्ड पावने ही थे। परन्तु इंग्लैण्ड उस समय इस परिस्थिति में नहीं था कि वह हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता। उसे तो खुद हाथमरीका का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था। परन्तु अमेरिका से माल खरीदने के लिए हमें पौण्ड पावनों का डॉलरों में बदलवाने की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता का पूरा करने के लिए हमारे सामने एक समस्या थी जिसको मुलभान के लिए भारत सरकार ने इंग्लैण्ड के साथ कई समझौते किए।

१९४७ का समझौता

जनवरी १९४७ में भारत और इंग्लैण्ड के एक समझौते के अनुसार भारत को इन पौण्ड पावना के बदले में स्टर्लिंग-क्षेत्र से माल खरीदने का अधिकार था। परन्तु यह समझौता अधिक दिन न टिक सका। इसी बीच इंग्लैण्ड और अमेरिका में एक आर्थिक समझौता हुआ। इससे परिस्थिति बदल गई और इंग्लैण्ड को फिर भारत के साथ एक नए सिरे से समझौता करना पड़ा। १४ अगस्त १९४७ का भारत और इंग्लैण्ड के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में इन पावनों के दो खाते खोल दिए गए। खाता न० १ में ६३ करोड़ पौण्ड जमा किया गया जिनको खर्च करके किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता था। बचा हुआ कोष जो लगभग ११६ करोड़ पौण्ड था खाता न० २ में जमा किया गया। खाता न० २ की राशि केवल पूँजीगत माल खरीदने के काम आ सकती थी। यह भी तय हुआ कि खाता न० २ की राशि पर साधारण व्याज दर से अधिक व्याज दर पर व्याज

मिलेगी। यह समझीना पत्र-व्यवहार द्वारा आगामी ६ महीने के लिए बढ़ा दिया गया। भारत को १ करोड़ पौंड और मिले। इस विषय में यह बात समझने योग्य है कि एक वर्ष के अन्दर भारत को जो स्टर्लिंग धन बरने के लिए मिला वह धन नहीं हो सका। उसका कारण यह था कि न तो सरकार के पास माल आयात करने की कोई योजना थी और न वृत्तिधियों को इतना समय मिला कि वे बाहर से माल मंगा सकें।

जुलाई मन् १९४८ का समझौता

इस समझौते की शर्तें १५ जुलाई को एक साथ भारत और ब्रिटेन में प्रकाशित कर दी गई थी। समझौते की मुख्य शर्तें ये थी —

(अ) १ अप्रैल १९४७ को अविभाजित भारत की सरकार ने इंग्लैण्ड द्वारा भारत में स्थापित हुए सभी कीजी सामान को अपने अधिकार में ले लिया था। इसका मूल्य उस समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था यद्यपि यह बात बाद में निर्दिष्ट करने के लिए स्वीकृत की गई थी। इसका मूल्य ३७ करोड़ पौंड या ४०० करोड़ रुपये आँका गया किन्तु १० करोड़ पौंड या १२२ करोड़ रुपये में यह मूल्य तय हो गया। यह राजा हमारे पौंड पावनों में से कम कर दी गई।

(ब) समझौते का दूसरा भाग पेंशनों के विषय में है। भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत से अंग्रेज अकसर रिटायर (Retire) हो गए। इनकी पेंशन देने का भार भारत सरकार पर था। समझौते के अनुसार पेंशनों का मूल्य १४ करोड़ ६५ लाख पौण्ड या १६७ करोड़ रुपये निर्दिष्ट किया गया। पेंशन चुकाने के लिए भारत सरकार ने इंग्लैण्ड की सरकार से एक गारिंटी (Guarantee) पत्रीद ली जिसके लिए १६७ करोड़ रुपये की राशि पौण्ड-पावनों में से कम कर दी गई। यह राजा केन्द्रीय अकसों, जो रिटायर्ड हो गए थे, की पेंशनों के चुकाने के लिए निर्दिष्ट की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत ने प्रांतीय सरकारों के अंग्रेज अकसों की पेंशन चुकाने के लिए भी २७ करोड़ रुपये की एक गारिंटी पत्रीद ली और यह राशि भी पौण्ड पावनों में से कम कर दी गई। इस प्रकार गारिंटी के माने पर कुल २२४ करोड़ रुपये कम किए गए। यह भी निर्दिष्ट किया गया

कि वार्षिकी के बदले इंग्लैण्ड की सरकार भारत सरकार को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि दिया करेगी। यह राशि ६० वर्ष तक हमें मिलती रहेगी। परन्तु यह ध्यान रखने की बात है कि यह एक आर्थिक समझौता ही था— जहाँ तक पेंशन देने की जिम्मेदारी का प्रश्न है वह तो भारत सरकार ही की है।

(स) इससे पिछले समझौते के अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपये के पौण्ड पावने लेने का अधिकार मिला था परन्तु इसमें से केवल ४ करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग किया जा सका। अतः इसमें से १०७ करोड़ भारत और ले सकता था। इसका अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के लिए इंग्लैण्ड ने इस समझौते के अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पौण्ड पावने देना और स्वीकार किया। अतः कुल मिला कर जून १९५१ तक हमें २१४ करोड़ रुपये के पौण्ड पावनों का उपयोग करने का अधिकार मिला। यह भी निश्चय किया गया कि व्यापार-संतुलन से भारत का जो आधिक्य होगा उसकी राशि का प्रयोग भी माल मँगाने में किया जा सकेगा।

इस समझौते के समय पौण्ड पावनों की राशि १५५० करोड़ रुपये थी गई थी। इसमें में फौजी सामान के १३३ करोड़ रुपये, पेंशना के २२४ करोड़ रुपये तथा पाकिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ करोड़ रुपये निकाल कर शेष १०६७ करोड़ रुपये के पौण्ड-पावने शेष रहते थे। इस राशि में से २१४ करोड़ रुपये जून १९५१ तक निकालना तय किया गया। इस प्रकार ८५३ करोड़ रुपये का पौण्ड-पावने शेष समझे गए। निम्न तालिका से यह हिसाब सरलता से समझा जा सकेगा—

इस समझौते के समय पौण्ड पावनों का मूल्य	१५५० करोड़ रु.
व्यय— (१) फौजी सामान परीदने में १३३ करोड़ रु.	
(२) पेंशना के लिए वार्षिकी २२४	”
(३) पाकिस्तान का हिस्सा १२६	” ४८३ ”
शेष	१०६७ करोड़ रु.

जून १९५१ तक मिलने की निश्चित की गई राशि

(१) पिछले समझौते का शेष १०७ करोड़ रु.

(२) इस समझौते की नई राशि १०७ करोड़ रु० २५४ ॥

जन १८५१ को बचनेवाली अनुमानित राशि ८५३ करोड़ रु०

इस समझौते के अनुसार तय किया गया कि जून १८५१ तक मिलने वाली १०७ करोड़ रुपये की नई राशि में से अगले वर्ष में केवल २० करोड़ रुपये के पीएड-पावने ही डॉलर या अन्य किसी दुर्लभ-मुद्रा में बदले जा सकते हैं। यद्यपि एक वर्ष में २० करोड़ रुपये के मूल्य के ६ करोड़ डॉलर आवश्यकता से बहुत कम थे परन्तु एक वर्ष में इससे अधिक राशि इंग्लैण्ड दे भी नहीं सकता था।

इस समझौते का भारत में मिश्रित स्वागत हुआ। एक ओर तो कई ध्याशक्ति संस्थाओं, उद्योगपतियों एवं अर्थशास्त्रियों ने इसे भारत के हित में बताया और दूसरी ओर कई अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतियों ने इसे भारत के अहित में कहा। भारत की विधान सभा में भी इस समझौते पर काफीवाद-विवाद हुआ। आलोचकों में भी मनु सूत्रदार तथा धी के० टी० शाह मुख्य थे। कुछ भी हो, भारत को उस समय राशि की आवश्यकता थी और इस समझौते में माल आयात करने के लिए राशि मिल गई।

१८५६ का स्टर्लिंग समझौता

जुलाई १८५६ में स्टर्लिंग प्राप्त करने के सम्बन्ध में लन्दन में फिर बातचीत हुई और एक नया समझौता हुआ। यह समझौता उस समय हुआ जबकि ब्रिटेन के आकाश में भीषण आर्गिक मॉकट के वाले बादल छाये हुए थे। इंग्लैण्ड में डॉलर-सम्राट की विशेष कमो थी। इस समझौते के अनुसार भारत को १८५८-५९ में ८ करोड़ १० लाख पौंड मिलने का निश्चय हुआ। इसके साथ दोनों अगले वर्षों में अर्थात् जून १८५० के अन्त तक और जून १८५१ के अन्त तक ५ करोड़ पौंड प्रति वर्ष मिलना तय हुआ। इसके अतिरिक्त इसे लगभग ५ करोड़ पौंड की राशि मिलनी और तब हुई जो 'ग्रोवन जनरल लाइसेंस' (११) के अन्तर्गत जुलाई १८५६ में पहिले मेंगाए हुए माल के बदले में मुग़तान वुसने के लिए दो गई थी। अब रहा स्टर्लिंग को डॉलर या दुर्लभ-मुद्रा में बदलने का प्रश्न। भारत को केन्द्रीय बॉय

(Central Reserve) में १४ या १५ करोड़ डॉलर देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ हमारे ऊपर एक निम्नदारी भी दी गई। जिम्मेदारी यह है कि भारत ने जितने मूल्य का माल डॉलर दोनों से १९४८ में मँगाया था, उसका ७५% ही अगले वर्षों में मँगाया जा सके अर्थात् अमराता में हानि वाले १९४८ व आगत में २५% उमा परत ही आयात किया जा सके है। लेकिन इस बात का छूट दे दी गई कि अन्तराष्ट्रीय बैंक में उधार लेकर कितना ही माल आयात किया जा सकता था।

इस नए समझौते के अनुसार १९४८-४९ में हमें ८ करोड़ १० लाख पौंड मिले जहाँ हमने जुलाई १९४९ में पहिले ही खर्च कर दिए थे और निर्यात लिए जुलाई १९४८ वाले समझौते में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस समझौते के अनुसार १९५० और १९५१ में प्रतिवर्ष चूंकि अतः तक ५ करोड़ पौंड मिलने लगे हुए, जबकि पिछले समझौते के अनुसार केवल ४ करोड़ पौंड प्रतिवर्ष मिलने की ही व्यवस्था की गई थी। १९४८ के समझौते के अनुसार केवल ६ करोड़ डॉलर १९४८-४९ तक मिलने की व्यवस्था की गई थी परन्तु नए समझौते के अनुसार १४ या १५ करोड़ डॉलर मिलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार नया समझौता पुराने समझौते को अपेक्षा अधिक हितकर था। इंग्लैण्ड के अर्थबारे ने तो इस समझौते के सम्पन्न होने पर इंग्लैण्ड का सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया था कि भारत सरकार का आशा से अधिक स्टर्लिंग-राशि दे दी गई। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी परिस्थिति में इसमें अन्धा और हितकर समझौता और दूसरा नहीं हो सकता था। परन्तु जो स्टर्लिंग हमें डॉलरों में बदलने के लिए मिले थे उनका मूल्य स्टर्लिंग का अमूल्यन होने के कारण ३०-५% प्रति शत कम हो गया है। इसी प्रकार यदि बचे हुए पौंड पावनों को डॉलरों में बदलवाया जाय तो उनका मूल्य ३०-५% कम हो जायगा।

१९५२ का समझौता

८ फरवरी १९५० के अन्तिम ऑर्डरों के अनुसार भारत की कुल स्टर्लिंग-पूंजी ५७ करोड़ पौण्ड अर्थात् ७६१ करोड़ रुपये है। भारत सरकार के विरु

मंत्री ने अपने पिछले इंग्लैण्ड के दौरे पर, जहाँ यह कॉमनवेल्थ वित्त-मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने गए थे, इंग्लैण्ड की सरकार से एक और समझौता किया है जिसकी अवधि ३० जून १९५७ तक है। इस समझौते के अनुसार भारत अपने पीण्ड-पायनों में से ३० जून १९५७ तक ३½ करोड़ पीण्ड प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल सकेगा। ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष ३½ करोड़ पीण्ड स्थिर खाने नं० २ में से खाना नं० १ में जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नं० २ खाने में से ११ करोड़ पीण्ड की एक और राशि नं० १ खान में जमा की जायगी। यह राशि मुरझित राशि के नीचे पर होम्स तथा इसमें से केवल गकटकार्बन स्थिति में ही इंग्लैण्ड की सरकार की पूरा मजान के साथ राशि निकाला जा सकेगी। १९५७ में इस समझौते की अवधि समाप्त होने पर पुनः चर्चा की जायगी, जिसमें इस समझौते की अवधि बढ़ाने या इसके स्थान पर दूसरा समझौता करने पर विचार होगा।

इस समझौते की घोषणा में ये समस्त सन्देश तथा भय दूर हो गए हैं जो इंग्लैण्ड में चर्चित सरकार के बन जाने के कारण उत्पन्न हो गए थे। अब इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि हमारे पीण्ड-पायन हमें सम्मानपूर्वक वापिस मिल जाएंगे। पहिले यह भय होता था कि कहीं इंग्लैण्ड की सरकार इनको चुकाने से मना न कर बैठे परन्तु अब इस प्रकार का कोई भय नहीं है।

युद्ध भी हो, हमने अपनी स्टर्निंग-सम्पत्ति को आशा से कम समय में लगभग समाप्त कर दिया। सारी सम्पत्ति अन्न तथा उपभोग की दमरीवस्तुओं को गरीबों में ही समाप्त हो गई। युद्ध के बाद इन पीण्ड-पायनों पर भारत की आशा लगी हुई थी कि इनसे पूँजीगत माल, जैसे मशीन आदि, गरीब-गरीब कर देश की आर्थिक योजनाओं को सकल बनाया जायगा। परन्तु सारी सम्पत्ति पेट भरने में ही समाप्त हो चली और देश के औद्योगिक विकास की योजनाएँ केवल अधूरी सतूरी हो रह गई। जिन पीण्ड-पायनों के कारण देश में मुद्रा-स्फीति हुई, अन्न पड़े, भुखमरी फैली, लोग भूखे रहे और नंगे चले—यही पूँजी अन्न मगाने में समाप्त हो गई और देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाने में काम न आई। अब भाँ जो कुछ राशि शेष है उसका सदुपयोग पर लेना चाहिए।



३०—मुद्रा-स्फीति

युद्धकालीन व युद्धोत्तरकालीन रूपान्तर

भारतीय मुद्रा के इतिहास में द्वितीय विश्वयुद्ध की सबसे बड़ी देन 'मुद्रा स्फीति' है जिसके अन्तर्गत देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा। परिणाम यह हुआ कि मुद्रा की कय-शक्ति कम हो गई और वस्तुओं के भाव आनाश हो छूने लगे। युद्धकाल में मुद्रा और साख का इतना अवल्पनीय विस्तार हुआ कि वस्तुओं की मात्रा की तुलना में लोगों की मान खरीदने की शक्ति बट गई। इस दृष्टिकोण से भारत में मुद्रास्फीति युद्धकाल में भी थी और युद्धोत्तर काल में भी, परन्तु युद्धकालीन एवं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति में कुछ ऐसा रूपान्तर है जिसे समझना आवश्यक है।

युद्धकाल में सरकार की मुद्रानीति अधिक से अधिक मात्रा में नए मुद्रा चक्रान्नर युद्धव्यय को पूरा करने की थी। अगस्त १९३६ में कुल निचाकर १७६ करोड़ रुपए के नोट चलते थे, परन्तु १९४७ में नाटो की कुल संख्या १२४२ ८६ करोड़ रुपये हो गई। नोट-वृद्धि के साथ साथ देश में मूल्य-स्तर भी बढ़ता गया। अगस्त १९३६ के मूल्य-स्तर की अपेक्षा जनररी १९४५ के मूल्य-स्तर में लगभग २५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। मूल्यों की बढ़ोत्तरी निम्न तानिका से स्पष्ट होती है :—

वर्ष	नोटों की संख्या (करोड़ों में)	अर्थ-सलाहकार के मूल्यांक (१९३६ = १००)
१९३६	१७६	१००
१९४०	२३८	१३३
१९४१	२४५	११४
१९४२	२५६	१४५
१९४३	५६३	१६५
१९४४	८८२	२३२
१९४५	१०३४	२५०

इस तालिका के मूल्यांकन उन वस्तुओं के हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण था और जिनके मूल्य भी सरकार ने नियंत्रित कर रखे थे। अगर उन वस्तुओं के मूल्यों को लिया जाय जो नौर-मात्रा में बिकती थी तो मूल्यों की बढ़ोतरी का प्रतिशत ८०० से भी आगे बढ़ जायगा।

इस प्रकार नोटों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही माथ वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते गए। इन दोनों ही समस्याओं ने देश में मुद्रास्फीति का भान कराया। सबसे पहिले १९४३ में भारतीय अर्थशास्त्रियों ने यह आवाज उठाई कि देश में मुद्रास्फीति के चिह्न आ चुके हैं। उन्होंने समझाया कि देश में मुद्रा के कारण मुद्रा की मांग बढ़ती जा रही है और उत्पादन उसकी अपेक्षा कम है। अर्थशास्त्रियों ने संकेत किया कि यह मुद्रास्फीति नोटों के बढ़ने के कारण पैदा हो रही है और बड़ी गंभीर है। शांतिवन चम्बर आक कामस एण्ड इण्डस्ट्री के अधिकारियों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १९४६ में फिर अर्थशास्त्रियों ने सरकार को इस ओर सचेत किया और कहा कि मुद्रास्फीति के दोष बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए जनता को इन दोषों से बचाने के लिए सरकार को शीघ्र प्रयत्न करने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भी इस बात को मान लिया कि देश में मुद्रास्फीति है परन्तु उसने इसको दूर करने के कोई उपाय नहीं बताये। रिजर्व बैंक के हिस्सेदारों की ८ वीं वार्षिक मीटिंग की रिपोर्ट में कहा गया था कि "देश में मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति पैदा हो गई है। परन्तु इसको दूर करने के उपाय सोचने से पहिले हमें यह सोचना होगा कि मुद्रा की संख्या क्यों बढ़ रही है। और यदि मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारणों पर विचार करें तो पता लगता है कि उन कारणों को दूर करने में अकेला रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता।" इसमें अगली रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया कि "मुद्रास्फीति को जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे गाना, कपड़ा आदि के उत्पादन में कमी होने के कारण और भी बल मिलता जा रहा है जिससे वस्तुओं के भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।" १९४४ में रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि "मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए सरकार ने जनता से अणु लेना आरम्भ कर दिया है तथा नए-नए टैक्स भी लगाए गए हैं। अगर इन दोनों बातों में सरकार का सफलता न

मिनी तो देश में मूल्य-स्तर गिराना तथा जनता का जीवन व्यय कम करना असम्भव हो जायेगा ।”

मुद्रा प्रसार का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र राष्ट्रों को युद्ध में आर्थिक सहायता देना था । भारत सरकार ने इंग्लैण्ड और मित्र-राष्ट्रों के लिए भारत के बाजारों से अन्न, कपड़ा आदि आवश्यक माल खरीदा । यह मान युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था । इस माल के बदले में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारत सरकार को नफ़द रुपया नहीं दिया वरन् यह रुपया इंग्लैण्ड भारत के हिसाब में जमा कर लिया जाता था और बदले में रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग-सिक्यूरिटियाँ दे दी जाती थी । इन्हीं सिक्यूरिटियों के बल पर नोट छापकर चलाए जाते और व्यापारियों का भुगतान किया जाता था । इस प्रकार नोटों की सख्या दिन प्रति दिन बढ़ती रही । पहिले पहिले इंग्लैण्ड की सरकार ने ४२६ करोड़ रुपये का माल खरीदने के लिए भारत सरकार को आर्डर दिए । परन्तु जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया सैते-सैते अधिक माल खरीदा जाता रहा और नोटों की सख्या बढ़ती रही ।

भारत जितना माल आयात करता था उससे कहीं अधिक माल निर्यात करता था । यह बात निम्नतालिका से स्पष्ट होती है :—

व्यापाराधिक्य (भारत के पक्ष में)

वर्ष	करोड़ रुपयों में
१९३८-३९	+ १७.५९
१९३९-४०	+ ४८.८१
१९४०-४१	+ ४१.९९
१९४१-४२	+ ७६.६०
१९४२-४३	+ ८४.२५
१९४३-४४	+ ९१.३२
१९४४-४५	+ २६.०८

इस अनुसृत व्यापाराधिक्य के बदले में बाहर से न तो माल आ सका और न सोना ही मिला । इसके बदले में तो स्टर्लिंग मिले जिनके आधार पर

सरकार ने नोट छुाकर व्यापारियों के भुगतान चुराए । मुद्रा-काल में मोना-चादी भी देश में बाहर भेजे गए । फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की १४वीं वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि १९४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का मोना बाहर भेजा गया जिसमें बदले में स्टर्लिंग मिले जिनके आधार पर हमारे यहाँ मुद्रा प्रसार हुआ ।

कन्द्रीय सरकार ने मुद्रा काल में पचा भी गृह किया जिससे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ता गया । सरकार ने रक्षा-विभाग पर काफी खर्च किया जो इस प्रकार है :—

वर्ष	रक्षा-व्यय (करोड़ रुपये में)
१९३९-४०	४४.६४
१९४०-४१	७३.६१
१९४१-४२	१०३.९३
१९४२-४३	२१७.१३
१९४३-४४	३४५.८६
१९४४-४५	४५६.६४
२४४५-४६	३९१.३५
१९४६-४७	७४४.३४
योग—	
१८८३.४०	

इस प्रकार १९३९-४० से १९४६-४७ तक १८८३.४० करोड़ रुपये व्यय किए गए । इसका यह परिणाम हुआ कि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई । इस खर्च के लिए सरकार ने जनता में अणु लिए और भारी-भारी टैक्स भी लगाए । नोट भी छुा-छुा कर चलाये गए । सरकार ने स्टर्लिंग-सिक्युरिटीज के आधार पर तो नोट चलाए ही—ट्रेजरी बिलों (Treasury Bill) के आधार पर भी नोट छुाये । १९३९-४० में ट्रेजरी बिलों की संख्या, जिनके आधार पर नोट छुाये गए थे, ३७ करोड़ रुपये थी परन्तु १९४१-४२ में इनकी संख्या ७५ करोड़ रुपये हो गई तथा १९४२-४३ में इनकी संख्या १३६ करोड़ रुपये तक जा पहुँची ।

समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों से सलाह ली। सब वर्गों ने समर्थन दिया कि वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हैं और अब उनको रोकना चाहिए। पूँजीवादियों ने उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया और सुझाव दिए कि मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय, आगमन के साधन सुव्यवस्थित किए जाएं तथा आय-कर में छूट दी जाय और बैंक-दर न बढ़ाई जाय। मजदूर-दल व नेताओं ने मनाफामंदी तथा रिश्वतखोरी को घटोतापूर्वक हटाने की सलाह दी। बैंक व प्रतिनिधियों ने बैंक-दर बढ़ाने पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गों ने इस बात का समर्थन किया कि सरकार अपना व्यय कम करने बजट के घाटे का पूरा करे। सरकार ने इन सब सुझावों को सामने रख कर अनेक प्रयत्न किए। जीवन की आवश्यक वस्तुओं, विशेषतः अन्न और कपड़े पर नियन्त्रण लगा दिए—इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए तथा सरकार ही इन वस्तुओं के बेचने का प्रबन्ध करने लगी। मुद्रा की बढ़ी हुई सख्या को कम करने के लिए नए-नए कर लगाए गए। सरकार ने जनता से श्रृणु लिए। बचत-बैंकों में राशि जमा करने की सीमा बढ़ा दी गई। कम्पनियों के द्वारा बाँटे जाने वाले लाभांश सीमित कर दिए। सरकार ने सोना भी बेचा जिससे लोग सोना खरीदकर भय शक्ति सरकार को लौटा दें। विदेशों से माल आयात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग माल आयात करें और देश में माल का अभाव दूर हो। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपने अपने खर्चे कम करने के प्रयत्न किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को दी जाने वाली सहायता कम कर दी। राज्य सरकारों ने कृषि आय-कर तथा बिक्री-कर लगा दिए। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नई-नई सुविधाएँ दी गईं। घोषणा की गई कि नए उद्योगों से कुछ निश्चित समय तक आय कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मँगाने पर उन पर आयात-कर की छूट दे दी गई। इससे नए उद्योग खुलने में सहायता मिली। परन्तु मुद्रास्फीति की मूल समस्या हल न हो सकी।

युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भी देश में मुद्रा-स्फीति बनी रही और वस्तुओं के भाव ऊँचे चढ़ते रहे। अगस्त १९४५ में अर्थ-सलाहकार का

मूल्यांक २४४ १ था जो नवम्बर १९४६ में बढ़कर २८६.६ हो गया। नवम्बर १९४६ के पश्चात् यन्त्रों के भाव और नोटों और इनके मूल्य में मार्च १९४७ तक मूल्यांक ३४४ हो गया और अगस्त १९४८ तक ३८३ हो गया। अतः य भाव सबसे अधिक ऊँचे हो गए। सितम्बर १९४५ में अन्न का मूल्यांक २६४.२ था जो मार्च १९४८ में बढ़ कर ४०२ हो गया। अन्न के अतिरिक्त कच्चे माल के भाव भी बहुत ऊँचे रहे।

मुद्रा के पश्चात् भी नोटों की संख्या बढ़ती ही रही। ३१ दिसम्बर १९४५ को कुल ११५४ करोड़ रुपये के नोट थे परन्तु जनवरी १९४६ में इनकी संख्या १२४८ करोड़ रुपये हो गई और जून १९४६ में यही संख्या आगे बढ़ कर १२५४ करोड़ रुपये हो गई। परिचलन (Circulation) में भी नोटों की संख्या बढ़ती ही गई। सितम्बर १९४५ में ११४१.८४ करोड़ रुपये के नोट चालते थे परन्तु जून १९४६ में यह संख्या बढ़ कर १२४१.६७ करोड़ रुपये हो गई। नीचे लिखी तालिका में यह बात स्पष्ट होती है।

(करोड़ रुपये में)

रिजर्व बैंक के पास

	कुल नोटों की संख्या	चालू नोटों की संख्या	जमा स्टर्लिंग मिक्स्चरिटीज
सितम्बर १९४५	११६२.७४	११४१.८४	१०४२.३२
अप्रैल १९४६	१२४५.६५	१२३५.१२	११२४.७
जून १९४६	१२५४.३३	१२४१.६७	११३२.३२
नवम्बर १९४६	१२५८.८६	१२०१.२६	११३५.३२
दिसम्बर १९४६	१२५८.५६	१२१८.७८	११३५.३२
मार्च १९४७	१२५७.४७	१२४३.०३	११३५.३२

इसमें एक बात यह स्पष्ट होती है कि रिजर्व बैंक के कोष में स्टर्लिंग मिक्स्चरिटीजों की संख्या, जिनके चल पर मुद्राकाल में नोट छापे गए थे, लगभग स्थिर रही परन्तु नोटों की संख्या बढ़ती गई। इसका अर्थ यह निकलता है कि मुद्रांतरकाल में मुद्राकाल की भांति स्टर्लिंग के आधार पर नोट नहीं छापे गए परन्तु देश में रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए य मजदूर के माते को

पूरा करने के लिए नोट छापकर चलाए गए। सरकार को काश्मीर की लड़ाई के लिए, हैदराबाद की चढ़ाई के लिए तथा बे-घर लोगों को बसाने के लिए रुपये की आवश्यकता थी और इसलिए नोटों की संख्या बढ़ाई गई। सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन में वृद्धि होने के कारण भी सम्भवतः कुछ अधिक मुद्रा की आवश्यकता हुई, पर मुद्रा में यह वृद्धि उस समय हुई जबकि उत्पादन में एक तिहाई कमी हो गई थी। युद्धकाल में विदेशी सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा प्रसार हुआ तथा युद्धोत्तरकाल में भारत सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने के लिए नोट चलाए गए इसलिए मुद्राप्रसार हुआ।

युद्ध के पश्चात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने के लिए पहिले तो नोट छापे गए तथा बाद में विजय बैंक की रोक्ड़ राशि में से खर्च किया गया। इससे मुद्रा की संख्या बढ़ती गई। बजट में घाटा होने के कारण थे—अन्न पर असाधारण खर्चा, बे-घर लोगों को बसाने का खर्चा तथा सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी आदि। केन्द्रीय सरकार के बजटों का घाटा इस प्रकार रहा:—

(करोड़ रुपयों में)

१९४५-४६	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९
	संशोधित	संशोधित	संशोधित

आय	२६०.६७	३३६.१९	१७८.७७	३३८.३२
व्यय	४८४.५७	३८१.४८	१८५.८९	३३९.८७
घाटा	-१२३.९०	-४५.२९	-६.५२	-१.५५

इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के बजट भी घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने के लिए मुद्रा शक्ति बढ़ाई गई परन्तु उत्पादन न बढ़ाया जा सका।

युद्ध के बाद मान का उत्पादन भी कम होता गया। 'इंस्टीट्यूट एकौनोमिस्ट' द्वारा तैयार किए गए उत्पादन के अङ्कों से पता चलता है कि १९४३-४४ में औद्योगिक उत्पादन के अंक १२६.८ थे जो १९४६-४७ में १०५ हो गए। अन्न उत्पादन का तो और भी बुरा हाल रहा। १९३६-३७ व १९३७-३८ में अन्न उत्पादन के औसत अंक १०० थे जो १९४५-४६ में घटकर ९४ में आ गए

तथा १९४६-४७ में ६६ और १९४७-४८ में ६७ हो गए । इस प्रकार उत्पादन की कमी होने से बाजार में माल की कमी रही और भाव चढ़ने लगे । औद्योगिक उत्पादन गिरने के कारण ये थे — सरकार द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विचार, कच्चे माल की कमी मजदूरी की हड़ताल, मशीनों की खराबी, भारी-भारी ट्रेक्स तथा ऊँची-ऊँची मजदूरी का भुगतान, आदि, आदि । १९४६ में उद्योगों ने भ्रम-विवादों के कारण १,००,००,००० पुरुष-दिन गंवाये और १९४७ में १,७०,००,००० पुरुष-दिन गंवाये । इस प्रकार उत्पादन लगभग वही परन्तु वितरण की दुर्यवस्था के कारण भी महगी बन गई । लोगों ने मान खिया खिया कर इकट्ठा किया । सरकार ने संग्रह-विरोधी कानून भी बनाए परन्तु कोई फल न निकला । युद्ध के पश्चात् मण्डपा गाँधी ने कण्ट्रोल हटाने का आन्दोलन उठाया । अन्न-नानि निर्धारण-समिति ने भी कण्ट्रोल हटा लेने की सिफारिश की । तदनुसार सरकार ने दिसम्बर १९४७ में कण्ट्रोल तोड़ दिए । कण्ट्रोल हटाने ही पशुओं के भाव आकाश में चढ़ने लगे और जनता को और भी अधिक परेशान हो गई । अक्टूबर १९४८ में कण्ट्रोल फिर लगा दिए गए परन्तु मूल्य ज्यों की त्यों रहे । यदि सच पृष्ठ जाय तो अन्न की रिफ्ट समस्या ने मूल्यों के बढ़ने में काफी सहायता की । देश के विभाजन से तो स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गई ।

व्यापार-नरक के सिद्धान्तों के अनुसार १९४६ के पश्चात् मूल्य स्तर गिरने का अनुमान लगाया जाता था और आशा की जाती थी कि इस वर्ष के पश्चात् तो अवश्य ही मंदी होगी परन्तु इसी बीच में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई रचना पैदा हो गई जिसने मूल्यों के बढ़ने में काफी योग दिया । पूर्व में जोरिया का युद्ध आरम्भ होने ही मान के भाव और अधिक चढ़ने लगे । देश भर में एक प्रकार का आतंक छा गया । अमरीका तथा इंग्लैण्ड युद्ध के लिए पुनःस्थाकरण के काम में जुटने लगे । अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों में माल समक करने की योजनाएँ बन गई । ये देश लड़ाई का अनुमान लगाकर कच्चा माल इकट्ठा करने लगे जिससे हमारे देश में इनका भाव बढ़ गई और मान के भाव अधिक ऊँचे होने लगे । रुपये के अग्रमूल्यन का भी मूल्य-वृद्धि पर कुछ अनुपल प्रभाव ही पड़ा ।

सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को देखकर मूल्य स्तर कम करने की ठानी। एक विस्तृत योजना बनाकर मूल्यों को कम करने का प्रयत्न किया गया। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें थीं—अन्न के उत्पादन में वृद्धि करके वितरण पर नियन्त्रण रखना, बजट के घाटे पूरा करके संतुलित बजट बनाने का प्रयत्न करना, सरकारी व्यय कम करना, सरकारी आय बढ़ाना, जनता को बचत करने की सुविधाएँ देना तथा कम्पनियों के लाभांश सीमित करना। १९५१-५२ के बजट में बजट बनाते समय ५ करोड़ रुपये का घाटा था जो ३१ करोड़ रुपये के नए प्रस्तावों के बाद बराबर करके बजट में २६ करोड़ रुपये का आधिश्य रक्का गया। चालू वर्ष का बजट पेश करते समय शांत हुआ कि गत वर्ष के बजट में ६२ करोड़ रुपये की बचत हुई। इससे मध्य शक्ति अवश्य कम हुई। गत १२ वर्षों में इतनी बचत का यह पहिला बजट है। नवम्बर १९५१ में मास-सुविधाएँ कम करके मूल्य गिराने की नायत से सरकार ने एक नया कदम और उठाया। बैंक दर ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३½ प्रतिशत कर दी गई तथा रिजर्व बैंक ने खुली बाजार क्रियाएँ बन्द कर दी। इससे मुद्रा प्रसार पर बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा। ये सरकार के अन्तिम उपाय थे जो उसने मूल्य स्तर को गिराने के लिए किए।

इन उपायों का कुछ चमत्कारी परिणाम निकला। मार्च सन् १९५२ के आरम्भ से ही मूल्यों में सन्ध का वाटमण्डल छा गया है। वस्तुओं के भावों में गिरावट छा गई है। लगभग सभी वस्तुओं, जैसे अन्न, तेल, गन्ना, रुई, पटसन, सोना, चाँदी के भाव नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि मद्रास्फीति का अन्त होकर व्यापार चक्र नीचे की ओर जा रहा है। वैसे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं नियमानुसार मन्दी आज से दो वर्ष पूर्व ही आनी थी, परन्तु राजनैतिक हलचलों ने इसे रोका। अब मन्दी की ओर रुख बदला है। थोड़ा भाव बराबर गिरते जा रहे हैं और फुटकर भावों में भी गिरावट है, व्यापारी वर्ग इससे कारण चिन्तित है परन्तु सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है। देखना है कि क्या यह मन्दी स्थायी रह सकेगी?

३१—डॉलर की समस्या

गत महायुद्ध ने लगभग सभी यूरोपीय देशों के आर्थिक ऋणेश्वर को पैगु बना दिया। युद्ध की भीषण समस्याओं ने यूरोप देशों के उद्योगों को नष्ट भ्रष्ट किया और यूरोप देश युद्ध में धन कमाने की स्थिति में युद्ध सामग्री ही बनाने में लगे रहे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द रहा स्थानीय वस्तुओं आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न की जा सकी तथा नागरिक आवश्यकताओं के लिए उद्योगों में मानव बलान्ता बन्द हो गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् सभी देशों ने आर्थिक पुनर्निर्माण का काम आरम्भ किया। नष्ट-नष्ट उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाना लगे। परन्तु डॉलर के प्रभु ने एक समस्या खड़ी कर दी। मितम्बर १९४६ में पोलैण्ड युद्ध में तो इस समस्या ने बहुत ही भीषण रूप धारण कर लिया था। आज भी डॉलर का प्रभु कोई कम देवी समस्या नहीं है। संसार के चट्टे-चट्टे राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, अर्थशास्त्री इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हैं। मितम्बर १९४६ में रटर्निक तथा उसके साथ-साथ संसार की अनेक मुद्राओं के डॉलर-मूल्य में सभी करने में इस समस्या की भीषणता कुछ कम हो गई थी और आज भी यह समस्या सुलझ ही जायगी परन्तु १९५० के पश्चात् इस समस्या ने फिर भीषण रूप धारण कर लिया। देखना यह है कि यह समस्या है क्या ?

डॉलर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रतीक मुद्रा है। गत महायुद्ध में योरोप के लगभग सभी देशों ने युद्ध में प्रयत्न अथवा परोक्ष रूप में भाग लिया। अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया परन्तु इसका कार्य युद्ध में प्रयत्न रूप में लगे हुए देशों को युद्ध सामग्री बेचना ही रहा। सभी देशों ने अमेरिका से बहुत माल खरीदा। इसके बदले में अमेरिका की मुद्रा 'डॉलर' या सोना चुकाया गया। अमेरिका अपने उद्योग-धंधों को उन्नत करता गया और अन्य देशों में युद्ध के कारण यह उन्नति बन्द रही। युद्ध के पश्चात् आज भी अमेरिका में अन्य देशों की आवश्यकता की सामग्री है—पूँजी प्रधान सामान है, गान-पदार्थ है, संसाधन है तथा कुशल कारीगर भी हैं। इन सभी वस्तुओं

की युद्ध से बिगड़े हुए देशों की आवश्यकता है। ये वस्तुएँ दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुसार अन्य देश अपने देश का सामान अमेरिका को निर्यात करें और उससे बदले में अमेरिका से सामग्री खरीदें या अमेरिका को उससे माल का भुगतान डॉलर चुका कर किया जाय। यह भी हाँ सक्ता है कि अमेरिका इन देशों का उधार माल बेच दे। अन्य देशों में अमेरिका का निर्यात की जाने वाली कोई वस्तुएँ न तो थीं और न आवश्यक माना में आज ही उपलब्ध हैं क्योंकि अमेरिका स्वयं समर्थ देश रहा है, आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वहाँ के लोगों का प्राप्त हैं। यदि अन्य देशों में अमेरिका की आवश्यकता की वस्तुएँ हैं भी तो उनके भाव बहुत ऊँचे रहे हैं। अन्य देशों के पास अमेरिका का भुगतान करने के लिए सोना या डॉलर भी नहीं रहे जिनके बदले में वहाँ से माल खरीद कर आर्थिक विकास की योजनाओं को पूर्ण किया जाता। अमेरिका ने करोड़ों डॉलर कुछ देशों को उधार और भेंट में दिए हैं जिससे किसी प्रकार डॉलर का अभाव टल जाय। मार्शल योजना व ट्रूमन का चतुर्भुज योजना इस बात के प्रमाण हैं। परन्तु अमेरिका भी निरन्तर अनिश्चित अधि के लिए माल उधार नहीं बेच सकता और न असंमित माना में भट ही स्वीकृत कर सकता है। और यह भी निश्चित है कि यूरोप के अन्य देश तथा भारत भी अमेरिका से यत्रादि, कुशल कारीगर तथा साधन पदार्थ के बिना आयात नहीं रह सकते। तो समस्या यह है कि अमेरिका से उक्त वस्तुएँ लाकर उससे बदले में भुगतान करने के लिए डॉलर कैसे प्राप्त किए जाएँ? डॉलर का उपाजन व्यय से कम होने के कारण बाहर के देश अमेरिका के माल की गत में कमी करने के लिए विवश होते रहे हैं। प्रति वर्ष डॉलर-क्षेत्र से होने वाले आयातों में कमी करने के सुझाव दिए जाते हैं और कमी होती भी रही है। इस विवशता के कारण अमेरिका के निर्यात में कमी आती है जिससे वहाँ का उत्पादन कम करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि अमेरिका के वे उद्योग धंधे, जो विदेशी माँग पर निर्भर हैं, धीमे पड़ जाते हैं और अन्त में वहाँ बेकारी की समस्या आने लगती है। फिर वह बाह्य-देशों से और भी कम वस्तुएँ ले सकता है। इसका परिणाम यह हुआ

है कि वाय-देशों की डॉलर-आय और भी अधिक गिर जाने से समाज में डॉलर की कमी अधिराधिक होने लगी है। इस प्रकार डॉलर की समस्या केवल योरोप या एशिया के देशों की ही समस्या नहीं है बल्कि अमेरिका का भी प्रश्न है कि यहाँ बहती हुई बेकारी और मन्दी को कैसे रोका जाय। मन्दों और बेकारी को टालने के लिए ही तो अमेरिका विद्युत् यंत्रों से विप्लव डॉलर राशि वाय-देशों को प्राण के रूप में या गैट स्वल्प देता रहा है। परन्तु यह कब तक चल सकता है। आगिर समस्या दोनों ओर की है, अमेरिका की भी और योरोप तथा अन्य देशों की भी। अन्य देशों की समस्या डॉलर प्राप्त करके अमेरिका में माल मंगाने की है तथा अमेरिका की समस्या अपने निर्यात बढ़ाकर उत्पादों की उत्पादन-शक्ति बनाए रखने की है।

यह समझना भूल होगी कि डॉलर की समस्या केवल गत महायुद्ध की ही देन है। युद्ध से पहले भी १९३० के आसपास स्टर्लिंग और डॉलर के बीच विपत्ति थी। अफ्रीका से जात होता है कि १९३० में इंग्लैण्ड का वर्तमान स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ १२ करोड़ पौण्ड का आधिक्य था और पश्चिमी सोलाह के देशों के साथ ११ करोड़ पौण्ड का अभाव था। अन्य स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों का पश्चिमी सोलाह के साथ २ करोड़ पौण्ड का अभाव था। इस प्रकार इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों का पश्चिमी सोलाह के देशों के साथ १३ करोड़ पौण्ड की कमी थी। स्टर्लिंग क्षेत्र में प्राप्त मोना केवल ११ करोड़ ५० लाख पौण्ड का ही था। इस प्रकार १ करोड़ ५० लाख पौण्ड की डॉलर की कमी थी। लेकिन उस समय इंग्लैण्ड के पास एक गुविधा थी। इंग्लैण्ड के अमेरिका स्थित डॉलर कोष और डॉलर-विनियोग (Dollar Investments) इतने अधिक थे कि वह स्टर्लिंग-क्षेत्र अपनी डॉलर की कमी को इस विनियोगित पूँजी के लाभ से पूरा करता रहा। दूसरे, कुछ देशों की डॉलर की कमी अमेरिका की ओर से दिए गए ऋणों से कुछ वर्षों तक पूरी होती रही। अक्समात्, १९३० के बाद अमेरिका की सरकार ने और बर्ह के पूँजावियों ने श्राण देना बन्द कर दिया। वह समय एक प्रकार से वाय-देशों के लिए डॉलर के अकाल का था। इस अकाल में अधिकांश देशों ने अपने स्वयं को अमेरिका की चेन

ढाले और अत में संसार के सभी देशों को स्वर्ण-प्रमाण पद्धति का परित्याग करना पड़ा। द्वितीय युद्ध काल में इंग्लैण्ड और दूसरे देशों ने अपनी डॉलर की कमी अपनी डॉलर सम्पत्ति तथा स्वर्ण काय बेचकर पूरी की और जब वह सम्पत्ति समाप्त हो गई तो अमेरिका ने डॉलर की कमी पट्टे और उधार सम्बन्धी श्रृंखला देकर पूरी की। सितम्बर १९४६ तक बाह्य देशों को दा सौ अरब रुपये से भी अधिक के डॉलर इस योजना के अन्तर्गत मिले। युद्ध समाप्त होते ही यह सहायता भी बन्द कर दी गई और संसार में डॉलर की कमी फिर सामने आ गई। युद्ध के पश्चात् अमेरिका में अन्य देशों से आयात कम होता गया। मयुक्त राज्य के वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त किए आँकड़ों से ज्ञात होता है कि मार्च १९४६ में अमेरिका का आयात ६३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराबर था जो अगले माह हा घटकर ५३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराबर हो गया। इसी प्रकार अगले महीना में भी अमेरिका का आयात और कम होता गया। युद्ध के पश्चात् स्टर्लिङ क्षेत्र में डॉलर का अभाव इस प्रकार था —

वर्ष	डॉलर की कमी (०००,०००)
१९४६	२२६ पौण्ड
१९४७	१००४ ”
१९४८	४२३ ”
३० जून १९४६ तक	२३६ ”

इस प्रकार साढ़े तीन वर्षों में कुल डॉलर की कमी १,६१,२०,००,००० पौण्ड के बराबर थी जिसमें से केवल इंग्लैण्ड के लेखे पर १,४६,८०,००,००० पौण्ड की डॉलर की कमी थी। उस समय इंग्लैण्ड ने इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। ६३० लाख पौण्ड १९४८ तक अमेरिका से उधार खाते पर लेकर पूरे किए गए। कनेडा के उधार खाते पर इंग्लैण्ड ने २६१ लाख पौण्ड के डॉलर लिए। मार्शल योजना के अनुसार ३६५ लाख पौण्ड से इंग्लैण्ड ने डॉलर की कमी पूरी की। इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्रमशः ७,५०,००,००० तथा २,५०,००,००० पौण्ड के बराबर डॉलरों का आहरण किया। दक्षिणी अफ्रीका ने इंग्लैण्ड को ८,००,००,००० पौण्ड सोने में उधार दिया। २०,६०,००,००० पौण्ड की डॉलर की कमी को इंग

लैण्ड ने अपने सोने तथा डॉलर-कोषों में से पूर्ण किया^१।

इंग्लैण्ड के ये स्वर्ण कोष ३० जून १९४६ तक ४०,६०,००,००० पौण्ड के बराबर थे। उस समय इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्य देशों का डलर-अभाव ६०,००,००,००० पौण्ड प्रतिवर्ग की दर से था। उस समय इस समस्या के कारण संसार दो भागों में बँटा हुआ था—(१) अमेरिका और डॉलर-प्रदेश, जैसे वेनेडा, मेक्सिको, ब्राजील, क्यूबा, कोलम्बिया आदि जिनका आयात योरोपीय-देशों से गिरता जा रहा था और जहाँ का आन्तरिक मूल्यस्तर अन्य देशों की अपेक्षा नीचा था। (२) इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-प्रदेश के अन्य प्रदेश जैसे भारत, ब्रमा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, मलाया, न्यूजी-लैण्ड आदि जहाँ मूल्य-स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा था, जहाँ का आर्थिक बलेश्वर द्विज-भिन्न था और जहाँ से अमेरिका तथा डॉलर प्रदेशीय अन्य देशों का माल निर्यात करने की अनिवार्य आवश्यकता थी। तो इस प्रकार डॉलर की समस्या ने संसार को दो ऐसे भागों में बाँट दिया जिनमें से एक भाग दूसरे पर आभित था परन्तु उस आभय को प्राप्त करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं थे।

इस समस्या को मुक्तमाने के लिए १९४६ के अन्त तक अनेक देशों के वित्त मन्त्री अनेक बार लन्दन तथा अन्य स्थानों पर मिले। विचार-विनिमय हुआ और फिर इसके निम्न उपाय सोचे गए—

१. इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्य देश अमेरिका और डॉलर-प्रदेशों को निर्यात करके बदले में आयात करें। परन्तु, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, स्टर्लिंग-क्षेत्र में मूल्यस्तर ऊँचे थे और अमेरिका के मूल्यस्तर नीचे थे अतः स्टर्लिंग-क्षेत्र से डॉलर-क्षेत्रीय देशों में निर्यात बढ़ाना सम्भव नहीं था।

२. अमेरिका इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-प्रदेशों के अन्य देशों को डॉलर उधार दे अथवा माल और विशेषज्ञ भेजे। ऐसा किया भी गया। अमेरिका ने मार्गल योजना बना कर विपुल डॉलर तथा योरोपीय देशों को दी। इसके

^१ कॉमर्स—जुलाई ३०, १९४६ पृ. ४, १६०

अतिरिक्त अमरीका ने इंग्लैण्ड को एक विदेश समझौते के अनुसार १७५ करोड़ डॉलर उधार दिए। अमरीका ने स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देशों में पूँजी विनियोग भी का। भेंट भी दी गई तथा धुग भा दिए गए। परन्तु ये उपाय दीर्घकालीन और स्थायी नहीं हो सके थे।

३ तीसरा मुझाय रक्खा गया कि इंग्लैण्ड और स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देश, जहाँ मूल्यस्तर ऊँच है, अरना उत्पादन कम करके मूल्यस्तर नीचे करें जिससे इन देशों का माल अमरीका तथा डॉलर प्रदेशीय देशों में प्रतियोगिता के साथ बेचा जा सके।

४ अन्तिम मुझाय यह रक्खा गया कि स्टर्लिङ्ग का अमूल्यन कर दिया जाय अर्थात् स्टर्लिङ्ग का डॉलर मूल्य कम कर दिया जाय जिससे अमूल्यन करने वाले देशों का डॉलर प्रदेशीय देशों में निर्यात बढे और इस प्रकार वे डॉलर कमा कर डॉलर का कमा को दूर कर सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के अधिकारियों ने तथा मयुक्त राष्ट्र अमरीका के वित्त-मंत्री श्री जॉन साइएडर ने इस बात पर जार दिया कि स्टर्लिङ्ग का अमूल्यन कर दिया जाय। भा साइएडर ने बतलाया "कि यदि योरप देश अमरीका तथा पश्चिमी गोलाार्द के अन्य देशों के साथ अपना मुगतान स्तुन करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अपनी मुद्राओं की विनिमय दरों में आवश्यक समायोजन कर लेना चाहिए"। उनका मत था कि यूरोप की मुद्राओं के भविष्य अनिश्चित होने के कारण अमरीका की पूँजी उन देशों में नहीं जा रही थी। अतः उन देशों की विनिमय-दरों में समायोजन करने से समस्या हल हो सकती थी। श्री साइएडर या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के अधिकारियों में से किसी ने भी किसी विशेष मुद्रा के अमूल्यन की ओर स्केत नहीं किया था परन्तु उनका अर्थ विशेषतः स्टर्लिङ्ग स था। और वही हुआ। इंग्लैण्ड, अमरीका और केनेडा के वित्त मंत्रियों की वाशिंगटन में एक कांफ्रेंस हुई। इंग्लैण्ड के वित्त मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इस कांफ्रेंस से लौटते लौटते अमूल्यन की योजना स्वीकार कर ली और सितम्बर १९४६ में स्टर्लिङ्ग का डॉलर मूल्य २०.५% कम कर दिया गया। स्टर्लिङ्ग के साथ साथ अन्य अनेक देशों व भारत ने भा अपनी अपनी मुद्राओं की विनिमय-दरों में आवश्यक

फेर-बदल कर ली। [अवमूल्यन का वर्ग्यन आगे किया गया है]। अवमूल्यन करने के बाद इंग्लैण्ड तथा भारत सहित अन्य स्टर्लिङ्ग क्षेत्रीय देशों के निर्यात बने और अगले ही वर्ष इन्होंने डॉलर और मोना कमा-कमा कर अपने केन्द्रीय कोष भर पूर कर लिए। उधर कोरिया की लड़ाई छिड़ गई जिससे अनेक देश कच्चे माल की माँग करने लगे और अमरीका कच्चा माल समग्र करके जुटाने में लग गया। अन्य देश भी अपनी पुनः शस्त्रीकरण योजनाओं में जुट गए। इसमें स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के निर्याता की और भी अधिक बढ़ावा मिला। डॉलर की समस्या कुछ हल होती ही जान पड़ी। परन्तु १९५० के पश्चात् में स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ और डॉलर का बमो फ्रि अनुभव होने लगा। १९५१ के अन्त तक तो समस्या फिर गम्भीर होती गई। स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के केन्द्रीय कोष में से डॉलर और माना घटता गया। इस समय भारत तथा अन्य देशों के साथ डॉलर की समस्या इतनी जटिल नहीं थी जितनी इंग्लैण्ड के साथ थी। परन्तु तो भी स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी सदस्य-देशों को एक बड़ा भारी खतरा सामने था। समस्या पर सोच-विचार करने के लिए जनवरी १९५२ में कॉमनवेल्थ वित्त-मंत्रियों का एक सम्मेलन इंग्लैण्ड में बुलाया गया। इस सम्मेलन में डॉलर की समस्या पर सब ओर से विचार करके निर्णय लिया कि स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के वे देश, जिनमें डॉलर की समस्या बहुत जटिल बन चुकी है, डॉलर प्रदेशीय देशों में अपने अपने आयात कम करें, अपने घरेलू-पचने कम करें तथा अपने आन्तरिक-मूल्यस्तरों को नीचा गिराने के प्रयत्न करें। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सब सदस्य-देश सहमत हो गए। इंग्लैण्ड की सरकार ने तो अपने नए बजट में आयात कम करने की विशेष व्यवस्था की है तथा अपने आन्तरिक मूल्यों भी कम किए हैं। यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकी तो डॉलर की समस्या सुलभ होगी। इस समय डॉलर का खरट इंग्लैण्ड के सामने सबसे भारी है। इसलिए इंग्लैण्ड को इसे दूर करने के लिए अपनी भुगतान-क्षमता को दूर करना चाहिए।

३२—रुपये का अवमूल्यन

१८ सितम्बर १९४६ को इंग्लैण्ड के वित्त मंत्री सर स्टेफर्ड रिप्स ने स्टर्लिंग के डॉलर मूल्य में ३० ५ प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार इंग्लैण्ड का स्टर्लिंग, जो पहिले ४०३ डॉलर के बराबर था, अब २८० डॉलर के बराबर रह गया। इंग्लैण्ड की सरकार को स्टर्लिंग का यह अवमूल्यन अपनी परिस्थिति से बाध्य होकर करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण था 'डॉलर की कमी'। इंग्लैण्ड जितना माल डॉलर-प्रदेश को निर्यात करता था उससे कहा अधिक माल आयात करता था जिससे उसे भुगतान करने में डॉलरों की आवश्यकता होती थी। धीरे-धीरे उसका डॉलर काप कम होता गया। सन् १९३८ में इंग्लैण्ड के आयात उसके निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक थे। इस कमी का भुगतान इंग्लैण्ड ने अपनी विदेशों में लगी हुई पूँजी के लाभ और जहाजों, बैंकों तथा इन्शारेन्स कम्पनियों से होने वाली विदेशी आय से की। युद्धकाल में उसे अपनी बहुत सी विदेशी सम्पत्ति बेच देनी पड़ी। इस प्रकार विदेशी सम्पत्ति से होने वाली आय कम हो गई और अब आयात निर्यात के अन्तर का भुगतान पहिले की तरह नहीं चुकाया जा सकता था। सितम्बर १९३६ से जून १९४५ के अन्त तक इंग्लैण्ड ने लगभग ४१ अरब डॉलर की अपनी विदेशी सम्पत्ति बेची और उसके विदेशों से लिए हुए ऋण में ११'६ अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इस काल में इंग्लैण्ड के स्वर्ण और डॉलर काप में लगभग ६१ करोड़ डॉलर की कमी हुई। सब मिलाकर युद्ध काल में इंग्लैण्ड का लगभग १७ अरब डॉलर या तो विदेशों से ऋण लेने पड़े या अपनी उन देशों में लगी हुई सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा। कुछ समय तक इंग्लैण्ड योरोपीय पुनरुत्थान योजना के अन्तर्गत दी हुई अमरीका का सहायता से अपने आयात निर्यात के अन्तर का भुगतान करता रहा परन्तु यह सहायता स्थायी नहीं थी। विदेशों के भुगतान में मनुलन प्राप्त करने के लिए उसे या तो अपने आयात कम करने थे या अपने मान का निर्यात बढ़ाना

चाहिए था। आयात का अधिकांश भाग खाने-पीने की वस्तुओं और कच्चे माल का था जिनमें कमी करने से अकाल और बेकारी फैलने की आशंका हो सकती थी। फिर भी इंग्लैण्ड की सरकार ने अमरीका व अन्य दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से १९४८ के आयात की अपेक्षा अगले वर्षों में २५ प्रतिशत कमी करने का निर्णय किया। परन्तु इसमें भी डॉलर की समस्या हल नहीं हो सकती थी। सन् १९४८ में इंग्लैण्ड के आयात उसके निर्यात से ५५० करोड़ रुपये या ४० करोड़ पौण्ड से भी अधिक के थे। मुद्रा के बाद इंग्लैण्ड ने निरन्तर अपने निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया। परन्तु जैसे-जैसे इंग्लैण्ड का उत्पादन बढ़ता गया विदेशों में उसके माल की माँग कम होनी गई। इसका कारण यह था कि वहाँ का माल विदेशों में अधिक महंगा पड़ता था। डॉलर क्षेत्र में तो यह बात और भी अधिक लागू होती थी। अतः मूल्य कम करने के दो उपाय हो सकते थे। या तो लागत-व्यय और मजदूरी घटा दी जाती जिसमें माल के भाव नीचे हो जाते और या डॉलर-क्षेत्र में इंग्लैण्ड के माल को रुक्ता करने के लिए स्टर्लिंग की डॉलर दर में कमी कर दी जाती। पहला उपाय स्थायी रूप से अधिक उपयुक्त था पर इसका कार्यान्वित करना बड़ा ही कठिन था। मजदूर अपनी मजदूरी कम करने के लिए तैयार न थे तथा लागत-व्यय में किसी भी प्रकार कमी करना सम्भव नहीं था। दूसरा उपाय ही उपयुक्त समझा गया। इंग्लैण्ड, अमरीका और वेनेज़ा की एक कांफ्रेंस वाशिंगटन में बुलाई गई। इंग्लैण्ड ने यह मान लिया कि स्टर्लिंग का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे दोनों मुद्राएँ अपने स्वर-मूल्य पर आ जायें। साथ ही साथ अमरीका ने भी अपने आयात-वस्तुओं में कमी करने का निर्णय किया जिसमें विदेशों का माल अमरीका में सस्ते मूल्यों पर आकर बिकने लगे। इस निर्णय के अनुसार इंग्लैण्ड ने स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य ३०.५% कम कर दिया। एक पौण्ड जो पहले ४ डॉलर ६ सेण्ट के बराबर था अब केवल २ डॉलर ८० सेण्ट के बराबर ही रह गया। स्टर्लिंग का अमूल्यन इंग्लैण्ड के अपने स्वार्थ में था पर इसका सम्बन्ध गसर को डॉलर-समस्या से भी उतना ही निकट है जिसके बिना मुन-गावे सप्तर भित्त-भित्त क्षेत्रों में विभाजित होता जा रहा था।

स्टर्लिंग का अमूल्यन होते ही भारत सरकार ने भी रुपये के डॉलर-मूल्य

में ३० ५% की कमी कर दी। पहिले एक रुपया लगभग ३० सेण्ट के बराबर था परन्तु अवमूल्यन के बाद लगभग २१ सेण्ट के बराबर रह गया। एक डॉलर का मूल्य ३ रुपये ५ आने से बढ़कर लगभग ४ रुपये १२ आने हो गया। प्रत्यक्ष रूप से इस परिवर्तन के यह अर्थ हैं कि हमारे देश में डॉलर क्षेत्र से आने वाली यदि कोई वस्तु पहिले ३३२ रुपये में मिलती थी तो अब उसका मूल्य ४७६ रुपये हो गया और इसी अनुपात में हमारी वस्तुएँ अमरीका में सस्ती हो गईं। इस प्रकार हमारे आयात में हानि हो गई तथा हमारे निर्यात बढ़ने लगे। जनता के कुछ वर्गों ने सरकार की अवमूल्यन नीति का विरोध किया और कहा कि रुपये की दर गिराने से हमारे निर्यात अवश्य बढ़ेंगे परन्तु डॉलर क्षेत्र से हानि वाले आयात में हानि हो जायेगी। इससे देश को हानि रहेगी। अवमूल्यन के आलोचकों ने यह भी बताया कि देश को पूँजीगत माल की कठिन आवश्यकता है और यह माल अमरीका से मिल सकता है। अतः इस माल पर रुपये का अवमूल्यन करने से अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसके अनिश्चित यह भी अनुमान लगाया कि इंग्लैण्ड में जमा हमारी स्टर्लिंग राशि को डॉलरों में बदलवाने में भी हमें हानि रहेगी। परन्तु उस समय परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। भारत सरकार के सामने उस समय तीन उपाय थे—

(१) रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जाता और स्टर्लिंग का अवमूल्यन होने पर भी रुपये का डालर मूल्य उतना ही रहता जितना पहिले था। ऐसा करने से देश के सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाती। भारत का निर्यात इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों में बढ़ता हो जाता और तब बिल्कुल बन्द हो जाता। भारत का ६० प्रतिशत निर्यात स्टर्लिंग क्षेत्र में होता है। यदि रुपये का अवमूल्यन न किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते। अमरीका में तो हमारे माल की खपत पहिले ही कम थी स्टर्लिंग क्षेत्र में भी उन्चे माल की खपत कम हो जाती। सन् १९४८-४९ में अमरीका ने केवल ७० करोड़ रुपये का माल हमसे खरीदा जब कि इससे पहिले वर्ष में ८० करोड़ रुपये की वस्तुएँ खरीदा थी। रुपये का अवमूल्यन न करने का परिणाम यह होता कि हमारे निर्यात और भी कम हो जाते या हमें विदेशों में अपने देश की वस्तुएँ लागत से कम मूल्य पर नुकसान के साथ बेचनी पड़तीं। इससे हमारे व्यापार

को बड़ा धक्का लगता ।

(२) दूसरा उपाय यह हो सकता था कि सरकार रुपये का स्टर्लिंग-मूल्य कम करके रुपये की विनिमय-दर १ शि० ४ पैसे बना देती । इसका यह परिणाम होता कि देश में वस्तुओं के भाव और भी अधिक बढ़ जाते । स्टर्लिंग क्षेत्र से आने वाले माल के भाव भी बढ़ जाते और मूल्य-स्तर आगे बढ़ जाता । इससे जनता को बड़ी कठिनाई होती ।

(३) तीसरा उपाय यही था कि रुपये की स्टर्लिंग-दर उतनी ही रखी जाती और स्टर्लिंग के साथ-साथ रुपये का भी अवमूल्यन कर दिया जाना । सरकार ने ऐसा ही किया । रुपये का डालर-मूल्य ३०.५ प्रति शत कम कर दिया गया । संसार के कुछ अन्य देशों ने भी अपनी-अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया । वेनेडा ने भी अपने डॉलर का मूल्य अमरीका के डॉलर में १० प्रतिशत कम कर दिया ।

भारत सरकार को रुपये के अवमूल्यन की चाह न थी और न इंग्लैण्ड या अमरीका ने ही सरकार को इसके लिए बाध्य किया था । यह तो भारत की अपनी ही आवश्यकता थी । परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को ऐसा करना पड़ा । युद्ध से पहले भारत अमरीका से इतना माल आयात नहीं करता था जितना यह उसको निर्यात करता था । युद्ध-काल में भी भारत ने अमरीका से व्यापार में इतना माल नहीं मंगाया था जितना माल यहाँ भेजा गया था । स्टर्लिंग क्षेत्र के डॉलर क्षेत्र में हमने लगभग इन छ. सात वर्षों में ६२ करोड़ रुपये के डॉलर जमा किये थे । परन्तु युद्ध के बाद हम अमरीका में बहुत अधिक मूल्य की वस्तुएँ मँगाने लगे और हमारा निर्यात कम हो गया । १९४६ में इस प्रकार हमें ५ करोड़ रुपये के डॉलरों की कमी पड़ी और सन् १९४७ में यह कमी ८६ करोड़ रुपये की थी । जून १९४८ को समाप्त होने वाले वर्ष में हमें ६३ करोड़ रुपये के डॉलर का कमी थी । इस कमी को पूरा करने के लिए हम ने कुछ नो अपनी स्टर्लिंग पुँजी को डॉलरों में परिवर्तित किया और जब इस प्रकार भी आवश्यक माप्रा में डॉलर प्राप्त न हो सके तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र से डॉलर खरीद कर कमी पूरी की गई । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से भी ३४ करोड़ डॉलर, १ करोड़ डॉलर तथा १ करोड़ ८५ लाख डॉलर के तीन ऋण लिए । इस प्रकार

डॉलर की कमी पूर्ण होती रही। परन्तु इससे डॉलर की समस्या हल नहीं हो सकती थी। डॉलर की समस्या हल करने के लिये तो डॉलर कमाने की आवश्यकता थी। डॉलर तभी कमाये जा सकते थे जब कि डॉलर क्षेत्र में मान का निर्यात किया जाता। मान का निर्यात तभी हो सकता था जब कि उसने भाव कम किए जाते। भाव कम करने के लिये लागत व्यय कम करने की आवश्यकता थी। परन्तु लागत-व्यय कम करना बहुत कठिन था। इसलिए डॉलर-क्षेत्र के देशों के लिए माल का भाव कम करने का रुपये का डॉलर मूल्य कम करना पड़ा जिससे हमारा माल डॉलर क्षेत्र में भी बिक सके और स्टर्लिंग क्षेत्र में भी खप सके। सरकार ने योजना बनाई कि रुपये के अवमूल्यन से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अवमूल्यन करने के पश्चात् एक आठ-सूत्री योजना बनाई। इसमें निम्न सुझाव दिए गए—

१. देश की वैदेशिक व्यापार नीति ऐसे हो जिसमें विदेशी मुद्राओं की कम से कम आवश्यकता पड़े।

२. अमरीका तथा डॉलर क्षेत्रीय अन्य देशों से कम से कम माल आयात किया जाय।

३. देश में साख-नियंत्रण करके वस्तुओं के भावों को नीचा रखने का प्रयत्न किया जाय। आवश्यकतानुसार इसके लिए सरकारी कानून भी बनाए जायें।

४. जो माल दुर्लभ-मुद्रा-क्षेत्रों में निर्यात किया जाय उस पर निर्यात कर लगाकर आय बढ़ाई जाय।

५. उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाय; लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा देशांतरों में बैंकिंग सुविधाएँ देकर लोगों को बचत करना सिखाया जाय।

६. जिन लोगों ने मुद्राकाल में बड़े-बड़े लाभ कमाए थे परन्तु सरकारी टैक्स की चोरी की थी उनसे पैसला करके रुपया निकलवाया जाय जिससे उस रुपये को काम में लाकर उत्पादन बढ़ाया जाय।

७. सरकारी खर्चें कम कर दिए जाएँ— १९४६ ५० में कम से कम ४०

करोड़ रुपये की बचत करने का मुभावा दिया गया और १९५०-५१ में कम से कम ८० करोड़ की बचत की सिकारिश की गई। यह भी मुभावा दिया गया कि यदि आवश्यकता समझी जाय तो विकास की योजनाओं पर अधिक राशि व्यय करके उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय जिससे देश का उत्पादन बढ़ाने में योग मिले।

८. देश में गन्तुओं के भाव नीचे लाए जायें। अन्न, पत्रागाल तथा अन्य आवश्यक गन्तुओं के भाव कम से कम १० प्रतिशत कम कर दिए जायें।

इस प्रकार सरकार ने अयमूल्यन से लाभ उठाने के लिए सब प्रकार की रोक-थाम की। परन्तु अयमूल्यन से हमारे डॉलर-आयात मेंहमें अवश्य ही गए और बढ़ते में हमें अधिक खर्चा चुकाना पड़ा। हमारी स्टर्लिंग-पूंजी का भी दलियों में बदलवाने में हमें हानि रही। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में लिए ऋणों को चुकाने में भी हमें अधिक राशि चुकानी पड़ेगी और आयात मेंहमेंहोने के कारण हो सकता है कि हमारे मूल्य-स्तरों पर भी उसका प्रभाव पड़े। परन्तु अयमूल्यन न करने से हमारी समस्याएँ और भी जटिल बन जाती। हमारे निर्यात वस्तुएँ टप हो जायें। हमारा माल न अमरीका को जाता, न डॉलर-क्षेत्र में बिकता और न स्टर्लिंग-क्षेत्र में खपता। इस प्रकार माल आयात करने के लिए न हमारे पास मोना होता और न डॉलर होने। हमारा वैदेशिक व्यापार एक प्रकार से समाप्त हो ही हो जाता, हमारे उद्योग बन्द हो जाते, बेकारों फैल जाती और व्यवसाय टप हो जाते। इन कारणों से रुपये का अयमूल्यन करना अपने हित में माना गया।

भारत सरकार ने अपने रुपये का अयमूल्यन किया परन्तु पड़ोसी पाकिस्तान ने अपने रुपये का अयमूल्यन नहीं किया। पाकिस्तान के इस निश्चय के अनुसार वहाँ के रुपये की विनिमय-दर २१.६ पैसे प्रति रुपया हो गई। एक पीढ़ी के पहिले १३.८० पैसे आ. ४ पाई के बराबर था अब घटकर ६.२६ पाकिस्तानी दरयों के बराबर हो गया। भारत के रुपये और पाक-रुपये में भी समता आ गई। भारत के १०० रुपये पाकिस्तान के ६६.५० रुपयों के बराबर हो गए या पाकिस्तान के १०० रुपये भारत के १४४ रुपयों के बराबर हो गए। पाकिस्तान को समझाया गया कि यह भी अपने रुपये का अयमूल्यन कर दे वरन्तु पाकिस्तान ने अपने हित में यही उचित समझा कि पाक-रुपये का अयमूल्यन

न किया जाय । भारत सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की नई विनिमय दर (१०० पाक रुपये = १४४ भारत के रुपये) को न माना । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान का व्यापार बलपूर्वक बन्द हो गया । पाकिस्तान से भारत आने वाला माल जैसे रुई, जूट, चमड़ा, चावल आना बन्द हो गया तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाला माल भी जैसे चीनी, कोयला, मक्का आदि जाना बन्द हो गया । पाकिस्तान की ६० लाख जूट (पटसन) की गाँठों में से ५० लाख गाँठ भारत का मिला में काम आता था । इन सबका आना बन्द हो गया निम्न फल करने की जूट मिला का उत्पादन भी बहुत कम हो गया । भारत से पाकिस्तान का कायला जाना भी बन्द हो गया । विनिमय दर की विपमना के कारण व्यापार बन्द हो जाने से दाना ही पड़ोसियों का मुम्बित उठानी पड़ी । भारत का जूट उद्योग तो एक प्रकार से टप ही हो गया था । पाकिस्तान से गहुँ व चावल न आने के कारण अन्न समस्या भी विकट होती गई । प्रयत्न किए गए कि किसी भी प्रकार दाना देश सम्भोता करके व्यापार की विनिमय दर की समस्या को मुलभारों परन्तु यह सम्भोता न हो सके । अतः इस मामले का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ल जाया गया । अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के अधिकारियों ने इस प्रश्न पर विचार न किया । मुद्रा कोष के वार्षिक सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार होना था परन्तु किसी भी प्रकार इस प्रश्न का तब टाल दिया गया । आश्चर्य की बात है कि वार्षिक सम्मेलन के प्रगट भारत के सर नितामणि द्वारकादास दशमुख थे परन्तु फिर भी इस प्रश्न को सम्मेलन के कार्यक्रम में सम्मिलित न किया जा सके और आनाफानी करके बात टाल दी गई । सितम्बर १९४६ से लेकर फरवरी १९५१ तक इसी प्रकार बात टलती रही । भारत सरकार ने अब इस स्थिति का बहाना ठीक न समझा । भारत का अन्न, जूट व रुई का रुटिन आवश्यकता थी । अतः १६ फरवरी १९५१ को भारत सरकार ने कराचा में पाकिस्तान से एक व्यापार सम्भोता किया जिससे अन्नगत भारत ने कायला, लाहा, सोमेट आदि भेजना तथा किया तथा पाकिस्तान ने भारत को चावल, गेहूँ, पटसन, रुई तथा चमड़ा आदि भेजना स्वीकार कर लिया । भारत सरकार ने पाकिस्तान की विनिमय-दर (१०० पाक रुपये = १४४ भारतीय रुपये) माननी पड़ा । सम्भोता ३०

जून १९५२ तक के लिए किया गया। २६ फरवरी १९५१ को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक विज्ञप्ति निकाल कर पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान लिया।

२६ फरवरी १९५१ से रिजर्व बैंक ने अपने सम्पर्क, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयों पर भारतीय रुपये के बदले में पाकिस्तानी रुपये का खरीदना-बेचना आरम्भ कर दिया। अब रिजर्व बैंक अधिकृत लोगों (Authorized Persons) को १०० भारतीय रुपये के बदले पाकिस्तान के ६६ रु० ६ आ० ६ पाई बेचने लगा तथा उन लोगों से १०० भारतीय रुपये के बदले में पाकिस्तान के ६६ रु० ८ आ० ३ पाई खरीदने लगा। इसी प्रकार २७ फरवरी १९५१ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने कराची, लाहौर, दाका और मिंटगाँव के कार्यालयों पर १०० पाकिस्तानी रुपये के बदले में भारत के १४४ रु० ६ पाई खरीदने लगा तथा १४३ रु० १३ आ० ३ पाई बेचने लगा। दोनों पक्षीसिद्धा ने एक दूसरे की विनिमय-दर मान ली और आपस का व्यापारिक लेन-देन फिर आरम्भ हो गया। भारत की क़ितम्बर १९४६ से फरवरी १९५१ तक पाकिस्तान से व्यापार बन्द होने के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी। अन्न आना बन्द हो गया, रुई न मिलने के कारण कपड़े की कट्टी मिलें बन्द करनी पड़ीं तथा पटसन न मिलने के कारण पटसन का पया माल न बनाया जा सका जिससे उसे निर्यात करके डॉलर उमाए जाते। भारत सरकार को आगिर अग्रमूल्यन की तिथि से टीक १७ महीने के पश्चात् पाकिस्तानी रुपये की दर को मानना ही पड़ा। जैने ही भारत ने पाकिस्तान की दर को स्वीकार किया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भी तुरन्त ही पाकिस्तान के रुपये की दर को मान लिया और मान्यता दे दी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि १७ महीने तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान रुपये की विनिमय दर के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया यहाँ तक कि कोष के वार्षिक सम्मेलन में भारत के बार-बार कहने पर भी इस विषय को सम्मेलन के कार्य क्रम में सम्मिलित तक नहीं किया। परन्तु जैने ही भारत ने पाक रुपये की दर मानी, कोष ने भी उसका। नतुय उसके उभी दर को मान्यता दे दी।

कुछ भी हो, भारत सरकार ने अपने देश के व्यापारिक लोगों को सामने रखकर ही रुपये का अग्रमूल्यन किया था—उम पर न किसी का दबाव था और

न किसी की जबगदस्ती थी। अपने ही हितों की रक्षा में हमने पाकिस्तान की दूर स्वीकार की। परन्तु अब हम पाकिस्तान की रुई, अन्न या पटसन पर ही निर्भर नहीं रहे। अवमूल्यन के पश्चात् तो हमने काफी प्रगति की है जिसका वर्णन अगले निबन्ध में किया गया है।

३३—अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ

अवमूल्यन के द्वारा, निम्नदेह अमरीका, इंग्लैण्ड और भारत को भी अभीष्ट फल मिला। अमरीका के व्यापार एवं उद्योगों की गति मिली जिससे योरोप और एशिया के अन्य देशों को भी अमरीका में कच्चा माल निर्यात करने का अवसर मिला। अवमूल्यन के पश्चात् ६ महीनों में ही इंग्लैण्ड के स्वर्ण एवं डॉलर-कोष में लगभग ४५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। १९४६ के अन्त में इंग्लैण्ड का यह कोष १,६८,८०,००,००० डॉलर के समान था जो १९५० के मध्य तक २,४२,२०,००,००० डॉलर हो गया तथा १९५० के अन्त में ३० करोड़ डॉलर से भी अधिक हो गया। इस प्रकार एक तरह से स्टर्लिङ्ग का अवमूल्यन मकल रहा। इंग्लैण्ड की डॉलर की भूमि खाना होने लगी तथा भुगतान-संतुलन का असामंजस्य भी मिट गया। रुपये का अवमूल्यन करने से भारत की आशा भी पूर्ण हुई। भारत के निर्यात बढ़ने लगे। अवमूल्यन से पहिले १९४६ में भारत में डॉलर-प्रदेश को ५६२ करोड़ रुपये का माल भेजा था जबकि वहाँ में १३८६ करोड़ रुपये का माल मँगाया था। परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात बढ़े और आयात कम हो गए जिनसे मार्च १९५१ तक कुल २५ करोड़ रुपये के मूल्य के डॉलर भारत ने कमाए। यह ठीक है कि अवमूल्यन के कारण भारत के आयात मेंहमे हो गए और यह भी ठीक है कि पाकिस्तान की हठभर्मी के कारण हमें काफी अनुविधाएँ रही परन्तु तो भी हमारे निर्यात व्यापार में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

एली कपड़ा, मसाले, तमाकू, माइका (Mica), मैंगनीज, ऊन तथा चमड़े का निर्यात बहुत बढ़ा। अवमूल्यन से पहिले अक्टूबर १९४८ से अगस्त १९४९ तक लगभग ४ करोड़ रुपये का एली कपड़ा निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के बाद अगस्त १९५० तक लगभग १८ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात किया गया। जितने मसाले अगस्त १९४६ को समाप्त होने वाले वर्ष में निर्यात किए गए थे उसके ठीक दुगुनी राशि के मसाले अवमूल्यन के बाद अगस्त

१९५० तक निर्यात किए गए। यही बात माइका (Mica) के साथ रही। अगस्त १९४६ को समाप्त होने वाले वर्ष में लगभग ४½ करोड़ रुपये का माइका निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के बाद अगस्त १९५० तक लगभग ६ करोड़ रुपये का माइका (मुड़मुड़) निर्यात किया गया। मैंगनीज, जून तथा चमड़े का निर्यात भी अवमूल्यन के पश्चात् बहुत हुआ। १९५० में तो भारत ने वैदेशिक व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रही। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट होती है —

[करोड़ रुपये में]

	१९४६	१९५०	
निर्यात	४४१'३१	५४१'४४	+ २००
आयात	६२८'८०	४६४'४४	— १६४
शेष	-१८७'४९	+ ४६'८४	

१९४६ में भारत के वैदेशिक व्यापार में १८७'५१ करोड़ रुपये की कमी थी अर्थात् जितना माल निर्यात किया गया था उससे १८७'५१ करोड़ रुपये का माल अधिक आयात किया गया। यह कमी १९५० में दूर हो गई। १९४६ के निर्यात की अपेक्षा १९५० में १०० करोड़ रुपये के निर्यात अधिक हुए। १९५० में भारत का व्यापार-अंतुलन (Balance of Trade) लगभग ४७ करोड़ रुपये में भारत के पक्ष में रहा। इसके अर्थ यह है कि अवमूल्यन के बाद १९५० में १८७ करोड़ की व्यापार की कमी पूरी हो गई और ४७ करोड़ रुपये का आधिक्य (Surplus) और कमा लिया गया। इस आधिक्य के बसाने में एक बात अग्रस्त हुई और यह यह कि १९५० में १९४६ की अपेक्षा १६४ करोड़ रुपये ने आयात कम हो गए। यह तो होना ही था क्योंकि अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना था। इस बात में अवमूल्यन सफल रहा। इतना ही नहीं, भारत का निर्यात सुनभ और दुर्लभ दोनों

ही मुद्रा क्षेत्रों में बढ़ा—

[करोड़ रुपये में]

	दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र		मुलभ मुद्रा क्षेत्र	
	१९४६	१९६०	१९४६	१९६०
निर्यात	१२० ६४	१८० ०६	३८८ १७	३६० ०६
आयात	१७१ ००	१३४ १०	४४६ ७८	३६८ ६६
शेष	-४० ३६	+ ९६ ९६	-१२७ ६१	+ ३१ १३

ऊपर दिए गए आँकड़ों में ज्ञात होता है कि अवमूल्यन के पश्चात् १९५० में भारत के निर्यात मुलभ मुद्रा-क्षेत्र वाले देशों में बहुत बढ़े। १९४६ में इन देशों के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार में लगभग १२८ करोड़ रुपये की कमी थी। अवमूल्यन के बाद १९५० में यह कमी पूरी हो गई और लगभग ३१ करोड़ रुपये का आधिरस्य रहा। इसी प्रकार दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र वाले देशों में भी भारत का निर्यात १९४६ की अपेक्षा १९५० में लगभग ६० करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा और कुल मिला कर इन देशों के साथ भारत के व्यापार में लगभग १७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। १९५० में अमरीका की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक माल निर्यात किया—

[करोड़ रुपये में]

	अमरीका		इंग्लैण्ड	
	१९४६	१९५०	१९४६	१९६०
निर्यात	७१ २८	१०१ ४२	११६ २४	१२२ ०१
आयात	१०२ ८१	११३ ३०	१७३ ७५	११७ २५
शेष	-३१ ५३	+ ७ १२	-५७ ५१	+ ४ ७६

इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत का निर्यात अमरीका की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक हुआ। परन्तु अमरीका में भी भारत का निर्यात १९४६ की अपेक्षा १९५० में लगभग ३० करोड़ रुपये अधिक हुआ। १९५० में गन् वर्यों की उमा पूरी हो गई और २ करोड़ रुपये का बचत रही।

इस प्रकार अवमूल्यन के पश्चात् भारत का निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई। पौण्ड भी मूल और डॉलर का समस्या तब उत्पन्न मायल न रहा जितनी मितम्बर १९४६ से पहिल थी। परन्तु एक बात ऐसी हुई जिसके लिए भारत सरकार को और भारतीय जनता का विचार करना आवश्यक है। बात यह हुई कि हमारे आयात में वृद्धि हो गई और कम भी हुए। अन्न का समस्या को हल करने के लिए अमरीका तथा इन्डियन प्रदेस के अन्य देशों से और पाकिस्तान से आयात किया हुआ अन्न हम मरगा पड़ने लगा। दूसरे, हमारे औद्योगिक विकास के लिए तथा विकास योजनाओं के लिए पूँजीगत माल के आयात में भी हमें नुकसान रहने लगा। अवमूल्यन के कारण ही भारत और पाकिस्तान के रुपये में विषमता पैदा हो गई जिससे भारत और पाकिस्तान का आरम में लेन-देन बन्द हो गया। भारत और पाकिस्तान का स्वतन्त्र व्यापार बन्द होने से भारत को नानि उठानी पड़ी। पाकिस्तान में आने वाला अन्न, कपास, पटसन तथा दूसरा माल आना बन्द हो गया। अन्न का आयात बन्द होने से देश में अन्न की समस्या बिगड़ जाती गई। कपास तथा पटसन न आने से कपड़े और चूट की मिनोँ का भारो नुकसान रहा। कहीं कहीं तो कपड़े और चूट की मिनोँ बन्द करनी पड़ी।

यद्यपि अवमूल्यन के पश्चात् हमारे निर्यात बढे और इस प्रकार हमारे भुगतान संतुलन (Balance of Payments) की विषमता दूर हो गई परन्तु देश के मूल्य स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। निम्नन्देह, अवमूल्यन करते ही सरकार ने अन्न, मूल, कपड़े तथा दूसरान के मूल्य गिराने की भरमक काशिश की और इसमें कुछ सफलता भी मिली। सामान्य मूल्यांक में ३% की कमी हो गई और मूल्यांक ३८१.०० हो गए। परन्तु मूल्य-स्तर फिर बढ़ने लगे और जून १९५० तक मूल्यांक ३९५.६ हो गए। तब से बराबर मूल्य-स्तर बढ़ने ही रहे। नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण कहीं कहीं न होने के

कारण तथा भूचाल के कारण अन्न की समस्या और विकट हो गई जिसमें अन्न के मूल्य बहुत ऊँचे चढ़ गए। जहाँ तक कपास और गूट (पटमन) का प्रश्न है वे दोनों वस्तुएँ पाक-रूपों का अवमूल्यन न होने के कारण दुर्लभ हो गई। आयात बढ़ते हो गए और पहिले की अपेक्षा कम भी हुए। आयात कम होने के कारण वस्तुओं की कमी हो गई जिसमें उनका मूल्य-स्तर और भी बढ़ गया। कोरिया के युद्ध में, यापन में पुनः सम्प्रोकरण की योजना ने तथा अमरीका की कच्चे माल को समझ करके रखन की नीति ने परिस्थिति और भी गंभीर बना दी। इन सब कारणों से मूल्यों में और भी बढ़ोतरी होने लगी। अक्टूबर १९५० में तो मूल्य एक ४१३ ५ हो गया। इस प्रकार अवमूल्यन के पश्चात् वस्तुओं के भाव बढ़ने ही गए और सरकार प्रयत्न करने पर भी इनकी घटा में न कर सकी। परन्तु हममें सन्देह नहीं कि इससे द्वारा भारत के निर्यात व्यापार में आघातित वृद्धि हुई। परन्तु विद्युत् युद्ध महीनों में निर्यात में फिर कमी दिखालाई दे रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि भारत के निर्यात घटने का कारण रुपये का अवमूल्यन नहीं यवन कोरिया का युद्ध था, अमरीका तथा योपन की पुनः शस्त्रीकरण की नीति भी और अमरीका का कच्चा माल समझ करने की योजना भी। यह ठीक है कि इन कारणों से भी भारत के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिला परन्तु निर्यात घटने के केवल ये ही कारण नहीं रहे। किसी भी एक कारण-निर्णय को उठाकर यह कहना कि इसकी वजह से निर्यात घटे, ठीक नहीं जान पड़ता। हम किसी भी एक कारण को निर्यात-वृद्धि का श्रेय नहीं दे सकते (We cannot isolate the cause of Exports)। वास्तव में निर्यात तो अवमूल्यन के कारण तथा अन्य उक्त कारणों के योग में बढ़े। अवमूल्यन की वास्तविकता को पहचानने के लिए तो हमें पश्चात् रहित बनना पड़ेगा। भुगतान-संतुलन की विषमता दूर करने में, निर्यात बढ़ाने में तथा रक्षण और दलित कोष बढ़ाने में अवमूल्यन का जो हाथ रहा वह दिखाता नहीं जा सकता। यदि देखा जाय तो अवमूल्यन एक ऐसा कृत्रिम साधन मात्र है। इसके द्वारा देरा का माल विदेशों में मंगा देना जा सकता है। आर्थिक संकट का वास्तविक उपाय तो उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन भी ऐसा जिसमें लागत-रुद्ध कम हो। उत्पादन

बढावर ही अनमूल्यन से सच्चे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आज दैंगलैण्ड और स्टर्लिंग क्षेत्र में डॉलर का अभार जो फिर उठ खड़ा हुआ है उसका कारण यही है कि इन देशों में उत्पादन वृद्धि में आश्चर्यातीत प्रगति न हुई। अब कुछ लोग स्पष्ट व पुनर्मूल्यन के विषय में जानाफूसी करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हम आगे देखेंगे कि क्या यह उपाय सार्थक हो सकता है ?

३४—रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न

भारतीय रुपये के अवमूल्यन करने की घोषणा के लगभग एक वर्ष पश्चात् में ही देश के अर्थशास्त्रियों की जिज्ञा पर 'पुनर्मूल्यन' शब्द भी प्रयोग में आने लगा। देश के शिथिल आर्थिक जीवन में विभिन्न मतों की पुष्टि करने के लिए 'पुनर्मूल्यन' शब्द इतना पनपा कि आज सरकार व जनता, उत्पादक व उपभोक्ता, व्यवसायी व उद्योगपति, अर्थशास्त्र के प्रगतिशील व रूढ़िवादी विद्वानों आदि के लिए यह एक विवादप्रस्त व जटिल प्रश्न बन कर खड़ा है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी करघट लेने लगी हैं कि इस विषय से सम्बन्धित कुछ चोटों के विचारकों का ऐसा मत हो चला है कि 'भारतीय रुपये का अविलम्ब पुनर्मूल्यन होना चाहिए'। आज करे दो रुपये के अत्यन्त महंगे अन्न, रुई व पटमन के आयात गूँज-गूँज कर यह कर रहे हैं कि रुपये का पुनर्मूल्यन देश को करोड़ों रुपये की सम्भव हानि से बचा देगा। पाक रुपये की विनिमय दर को देश विदेशों से दी गई मान्यता भी आज उपरोक्त मत का समर्थन कर रही है। किन्तु यह सब तथ्योक्त का एक पृष्ठ है। पुनर्मूल्यन का विरोधी दल भी आज अपनी दर्जाला से यह मित्र कर रहा है कि आये दिन देश की मुद्रा के साथ मनचाही विनिमय-दर बंध कर हम अपनी मुद्रा के साथ 'बन्दर नाति' बरत कर संसार के सामने अपनी अक्षमशक्ति का परिचय नहीं देना चाहते। देश का राजनीतिक दृष्टि आर्थिक जीवन की स्थिरता एवं स्थायित्व पर आज भूतकाल से भी अधिक जोर दे रहा है। पुनर्मूल्यन के विरोधियों का मत है कि पुनर्मूल्यन से सम्भव है हमें अपने आयात मिलने लगे पर यह सब कतिपय वस्तुओं पर केवल अल्पकाल के लिए हो लागू होगा। इसलिए वैदेशिक व्यापार के कुछ दहलुआ के लिए अस्थायी लाभ पाने की भावना में प्रेरित होकर रुपये का पुनर्मूल्यन करना देश के हित में नहीं बना जा सकता।

इस विवादप्रस्त प्रश्न की निर्विवाद बनाने के लिए कुछ सम्बन्धित व आधारभूत दहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।

पुनर्मूल्यन की विभिन्न सीढ़ियों— पुनर्मूल्यन के परिणामों को तटस्थतापूर्वक तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यह न जाना जाय कि आखिर पुनर्मूल्यन किस दिशा में, किस मात्रा तक व किसके साथ रहकर करना है। इस ओर ये सम्भावनाएँ हो सकती हैं —

१. स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों, विशेषकर इंग्लैण्ड के पौण्ड के साथ रुय ही भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन।

२. स्टर्लिंग क्षेत्र ने देश अपनी अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन चाहें वरें या न करें परन्तु भारतीय रुपये का अविलम्ब पुनर्मूल्यन।

३. क्या भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन उस मात्रा तक किया जाय (३० ५%) कि भारतीय रुपये की विनिमय दर अवमूल्यन से पूर्ववत्-सी हो जाय ?

४. क्या भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन अवमूल्यन की हुई दर से अधिक या समदर पर किया जाय अर्थात् ३० ५% से कम या अधिक किया जाय ?

यदि पुनर्मूल्यन के पक्ष की दलीलों के अनुसार आज भारतीय रुपये के डॉलर मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाय तो उसका प्रभाव देश के समस्त आर्थिक शरीर पर पड़ेगा। देश का वैदेशिक व्यापार, भारत-पाक सम्बन्ध, राष्ट्रीय सम्मान आदि विषय भी अपनी गम्भीरता लिये खड़े हैं।

(क) देश का वैदेशिक व्यापार

आयात—सन् १९५० में भारतवर्ष के कुल आयात ५४२ करोड़ रुपये के थे। इस वर्ष अन्न आयात की विशेष योजना के कारण सन् १९५२ में आयात की मात्रा लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये की होगी, ऐसी सम्भावना है। यदि भारतीय रुपये का संसार की मुद्राओं के विपरीत पुनर्मूल्यन कर दिया जाय तो ऐसी दशा में भारतवर्ष को लगभग १८३ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें निश्चित मात्रा में आयातों के लिये १८३ करोड़ रुपये कम देने पड़ेंगे। इस धन राशि का प्रभाव हमारे वैदेशिक विनिमय कोष (Foreign Exchange Fund) पर भी बड़ा स्थाय्यप्रद होगा और उपरोक्त कम दिये जाने वाले करोड़ों रुपये का भार इसे नहीं भेलना

पड़ेगा। मरने आयात में देश की आर्थिक दशा कुछ उन्नत हो सकेगी क्योंकि सस्ते आयात का अर्थ रहन-सहन के मूल्य में कमी होना है जिसकी कि आज भारतवर्ष में अत्यंत आवश्यकता है। हमारे यहाँ रहन-सहन का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा नीचा होने लगा है। कारी मूल्यमूलक है जिसका कि विशेष कारण महंगे आयात हैं। यदि पुनर्मूल्यन में आयात मूल्य सस्ते हो जायें तो सचमुच देश के मध्यम वर्ग की दशा कुछ सन्तोषजनक हो सकती है।

निर्यात—जिस प्रकार पुनर्मूल्यन से हमें आयात सस्ते पड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे निर्यात भी पुनर्मूल्यन के पश्चात् विदेशों को महंगे पड़ेंगे और हम उनसे आजा की अपेक्षा उनकी मुद्रा में अधिक कीमत ले सकेंगे। अर्थ यह है कि हमारे निर्यात की वस्तुओं को जिनका कि उपभोग अमेरिका आदि देशों के लिए अनिवार्य-सा है या पुनः राष्ट्रीयकरण की योजना में हो गया है, अधिक डालर मिलेंगे। जूट का माल, मँगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका दुर्लभ मुद्रा वाले देशों की प्रति वर्ष हमारे यहाँ से आयात करना पड़ता है। भारतवर्ष को पटसन की चीजों में तो एक प्रकार का सर्वाधिकार प्राप्त है। पाँच-सायने वाले देशों की भी यदि उन्होंने पुनर्मूल्यन नहीं किया हम महंगे निर्यात भेजकर काफी रुपया कमायेंगे। पटसन का माल, भुइयुइ, मँगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारी-मारी माया में दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को हमारे यहाँ से निर्यात की जाती है। पुनर्मूल्यन करने से इस निर्यात पर अधिक डालर कमाए जा सकेंगे। स्टर्लिंग-क्षेत्र वाले देशों की भी, यदि उन्होंने पुनर्मूल्यन नहीं किया, तो हम महंगे निर्यात भेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे।

(ख) भारत-पाक व्यापार

अवमूल्यन के पश्चात् हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से व्यापार में कम लेना और अधिक देना पड़ा है। यदि हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक लेन-देन को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पुनर्मूल्यन इसमें मूल्य महायक हो सकता है। हम पाकिस्तान से अधिकतर अच्छा जूट, रुई, राल व लम और आल आदि मँगाने हैं जिस पर हमें ४४ प्रति शत अधिक देना पड़ता है अर्थात् पाकिस्तानी १०० रुपये के माल के बदले में १४४ रुपये चुकाने पड़ते हैं। यदि

भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन कर दिया जाय तो हमें पाकिस्तान से माल मँगाने पर काफी बचत हो सकती है। निम्नांकित तालिका इस बात की पुष्टि कर रही है :—

पुनर्मूल्यन भारतीय रुपये के आधार पर पाकिस्तान से किए जाने वाला आयात लागत में अनुमानित बचत-निर्देशक तालिका*

वस्तु	अनुमाननः लागत जून १९५२ तक के समय के लिए (रुआइ रुपये)	३०.५ प्रतिशत के हिसाब से आयात लागत पर बचत
पटसन	२५.००	२०.०२
रुई	५१.०४	१८.०४
खान १ चर्म	७.४०	१.२०
योग	१४१.४४	४९.२६

पुनर्मूल्यन के विरोध की युक्तियाँ

(१) जैसा कि पहिले बताया गया है रुपये के पुनर्मूल्यन से हमारे आयात सस्ते हो जायेंगे। यदि यह दलील पूर्ण सत्य हो तो कहना ही क्या? सस्ते आयात को दलान को स्वीकार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्न, पटसन व रुई आदि के आयात हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ये वस्तुएँ हमें किसी भी दर पर विदेशों से मँगानी पड़ेंगी। हमारी इस कमजोरी को अमेरिका व पाकिस्तान पण्यतया समझते हैं व इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसलिए इस सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती कि भविष्य में भी, चाहे हम रुपये का पुनर्मूल्यन कर दें, ये देश किन्हीं इन्जिम साधनों से (निर्यात कर लगाकर) हमें सस्ते आयातों का सुअवसर नहीं देंगे। अतः सब वस्तुओं के आयात सस्ते होने की सम्भावना कोरा स्वप्न है जो शायद कभी भी हितकर मिन्न न हो। निरोधियों का कहना है कि पुनर्मूल्यन के कारण यदि आयात सस्ते भी हुए तो १८३ करोड़ रुपये का लाभ तो सन्देहजनक है।

* इंस्टर्न इकॉनोमिस्ट के सौजन्य से

(२) पीछे बताया गया है कि पुनर्मूल्यन करने से भारत के निर्यात व्यापार द्वारा भारी-भारी मात्रा में विदेशी मद्रा बचाई जा सकेंगी। किन्तु यह इतनी सरलता से इसे दुर्लभ व मुलभ मद्रा उपलब्ध होने लगें तो कौन श्रमाग्रा देश इस अवसर का उपयोग नहीं करेगा। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। इसे यह नहीं भुलाना चाहिए कि यदि हमारे निर्यात निरन्तर संक्षेप रहे तो अमेरिका आदि देशों के उपभोक्ता बहुत कम मात्रा में इनका उपयोग करेंगे जिसका अर्थ यह होगा कि हमारे निर्यात व्यापार में कमी होने लगेगी; स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देश, जिनसे हमारा अधिकांश व्यापार होता है, हमारे यहाँ से माल मँगाना बहुत कम कर देंगे। पुनर्मूल्यन के विरोधियों का कहना है कि हमारे कुछ निर्यात ऐसे हैं जिनका डॉलर-मूल्य बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह बात स्मृति-निर्यात की समस्या वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकती। योरोपीय देशों की पुनःशास्त्राकरण की योजना में भी काफी कटौती कर दी गई है इसलिए अनिवार्य वस्तुओं का निर्यात भी कम मात्रा में होने लगेगा। हमारे निर्यात की सारी वस्तुएँ विदेशों के लिए अत्यन्त आवश्यक नहीं हैं। इसलिए पुनर्मूल्यन के कारण बड़ी हुई डॉलर कीमत पर समर्थ है विदेशवाले हमारी कई चीजों को न पसंदें। इन सब का सारांश यह है कि पुनर्मूल्यन से देश के निर्यात व्यापार को, अधिक डॉलर बनाने वाले निर्यातों को दृष्टिगत रखते हुए भा, कुछ क्षति हो सकती है जिसके लिए वर्तमान परिस्थिति में देश कभी भी राजी न होगा।

(३) पुनर्मूल्यन के समर्थकों का कहना है कि पुनर्मूल्यन के द्वारा भारत-पाक व्यापार में भारत को पारिस्थान में आयात करने में लाभ रहेगा। इस बात की पुष्टि के लिए पीछे अंकित भी दिए गए हैं। इन अंकितों को मान्यता देने समय हमें दूसरे सत्य का भी अनुसरण करना चाहिये। पाकिस्तान में किए जाने वाले आयातों में कच्चे जूट का आयात ऐसा है जिसमें कि उस देश का सर्वाधिकार सा प्रत्यक्ष है। जेल्फे में तो ताजिकान में अक्टूबर २२-२२ बगैर कच्चे की बचत बड़ा मुद्दा बनती लगती है पर पाकिस्तान भी आर्थिक दृष्टि से अपने राष्ट्रीय हितों को देख सकता है। हम अपने रुपये का पुनर्मूल्यन करके पाकिस्तान में आज की छविदा सत्ता पटमन पसंदें और उसका माल बनाने में हमें आगे उतका निर्यात करें—इतना ही हो क्या पाकिस्तान

बैठा बैठा देखता रहेगा ? क्या पाकिस्तान इस दुधारी तलवार पर कटने मरने को राजी हो जायगा ? कदापि नहीं। पाकिस्तान अपने निर्यात की कीमत बढ़ा सकता है और सम्भवतः कच्चे पटसन के बारे में अपने हित को दृष्टिगत रखते हुए यह मनचाही भी बरतने लग सकता है। ऐसी दशा में पिछली तालिका में अंकित अनुमानतः बचत अपूर्ण सत्य साबूत होगा। यह तो बड़ी साधारण सी बात है कि पाकिस्तान कच्चा पटसन सस्त भाव पर देकर पटसन का माल आज से ३० प्रतिशत अधिक मूल्य पर क्यों खरादेगा। पिछले २४ महीनों का अनुभव इस बात का परिचायक है कि हमारा जूट उद्योग पाकिस्तान से आये कच्चे माल को सदा तरसता है। ऐसी स्थिति में यह सोच लेना भी असंगत नहीं जान पड़ता कि ज्यों ही हम भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन करेंगे त्योंही पाकिस्तान में कच्चे पटसन के भाव बढ़ जाएंगे और हमारी तालिका की प्रस्तावित बचत एक वर्णन सी रहेगी।

यदि पुनर्मूल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाले प्रभावों की हम थोड़े समय के लिये ताक में रख दें तो भी देश के वाणिज्य बजट पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में निर्यात कर (Export Duty) से पिछले वर्षों में मानगुजारी की कार्पा सहायता हुई है वरन् १९५२-५३ के आय-व्यय पत्रक में भी इस कर से सहायता होने की कानि आशा है। भारतीय निर्यात की वस्तुओं को विदेशों में उपलब्ध ऊँचे भावों पर बेचने के लिए यह कर लगाया जाता है, जिसका लाभ देश की सरकार को होता है। यदि रुपये का पुनर्मूल्यन कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः ही मँहगे हो जायेंगे और इसकी आवश्यकता न रहेगी। इसका अर्थ यह होगा कि करोड़ों रुपये की आय, जो कि सरकार को इस करके द्वारा होती थी, तब वह उससे बंचित रह जायगी।

पुनर्मूल्यन का विरोध करनेवालों की अन्य ठोस दलीलें

जैसे तो पुनर्मूल्यन के होने वाले प्रभावों को जाँचते समय ही पुनर्मूल्यन के विरोधियों की दलीलों को ध्यान में रखा गया है किन्तु उनके आतिरेक यह अन्य दलीलें भी वे समय-समय पर रख रहे हैं :—

(१) विश्व की डॉलरहोल आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम अपनी मुद्रा का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिये। आज के भारतीय निर्यात-रुमा में शाति होने पर रुक भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यदि कोई अस्थायी लाभ वैदेशिक व्यापार में उठाना भी हो तो निर्यात-कर के शस्त्र द्वारा ही उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। निर्यात-कर को आवश्यकता-नुसार घटा-बढ़ा कर भी हम काम चला सकते हैं।

(२) यह योजना कि पाकिस्तान को अमूल्यन न करने से बहुत लाभ हुआ है इसलिए भारत को भी रुपये का पुनर्मूल्यन कर लेना चाहिए, कोई निर्विवाद सत्य नहीं है। योरुप में पुनः शस्त्रीकरण की योजना, कोरिया युद्ध, व विश्व की अधमरी आर्थिक-स्थिति के कारण विदेशों में पाकिस्तान के कच्चे माल की सदा माँग रही है। किन्तु भारत को परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। अन्न की समस्या को दूर करने के लिए भारत को भारी-भारी आयात करने पड़ रहे हैं—इस परिस्थिति में रुपये का पुनर्मूल्यन न करना ही हितकर है।

३) जब रुपये का अमूल्यन किया गया तब इसी बात को लेकर कि हमारा अधिकांश व्यापार स्टर्लिंग-क्षेत्र के देशों से है इस काम की बुद्धिमानों का कदम बताना गया था। आज यदि स्टर्लिंग-क्षेत्र के देश पुनर्मूल्यन न करें तो भारतीय मुद्रा का पुनर्मूल्यन इस बात को बताएगा कि या तो अमूल्यन करते समय हमने अपनी दीर्घ बुद्धि का परिचय दिया था और यदि वह ऐसा नहीं था तो स्टर्लिंग-क्षेत्र के साथ अपने व्यापार का अद्वेष्टता करके हम आज अपनी कुण्ठित बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्रौढ हो चुके हैं इसलिए हमारे एकाकी पुनर्मूल्यन से उन सम्बन्धों को गहरी चोट लगने की संभावना है।

(४) आए दिन किसी अस्थायी आर्थिक स्थिति से साधारण सा लाभ उठाने की चेष्टा को साफल बनाने के लिए हमें अपनी मुद्रा की विनिमय-दर से विलंबाङ्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान का ठेस लगती है और हमारे भविष्य में किए जाने वाले प्रत्येक 'निश्चय' को सदा 'निर्बल' और 'अस्थायी' शब्दों से टुनकारे जाने की संका बनी रहती है।

रुपये के पुनर्मूल्यन का विरोध करनेवाला की सबसे बड़ी दलील यही है कि पुनर्मूल्यन से होने वाला लाभ निर्यात कर लगा कर भी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु निर्यात कर लगाकर ही लाभ उठाने की नीति कोई स्थायी उपाय नहीं कहा जा सकता। उसे भी समय-समय पर बदलना पड़ेगा जैसे कि आज विनिमय दर को बदलने का मार्ग की जा रही है। विनिमय दर तो उद्देश्य पूर्ति का एक साधन मात्र है। उसे बदल लेने से हम अपना उद्देश्य नहीं बदल लेते हैं। इसलिए हम चाहे मद्रा की विनिमय दर बदलें या निर्यात-कर—उनके बदलने में सिद्धान्त रूप से हमारे सम्मान और अपमान में कोई अन्तर नहीं पड़ता। निर्यात कर के विरुद्ध एक और भी दलील है। यह कर हमें निर्यात करने में लाभ दिला सकता है परन्तु इससे हमारे आयात करते होने की समस्या पूर्ण नहीं हो सकती। इस समय हमें इस बात की आवश्यकता है कि सस्ते आयात करक अन्न की कमी पूरी की जाय तथा देश का उद्योगीकरण किया जाय और यह तभी हो सकता है जबकि रुपये का पुनर्मूल्यन न हो। अतः वर्तमान परिस्थिति में अपने हितों को ठुकरा कर ही रुपये का पुनर्मूल्यन किया जा सकता है।

सब परिणामों का ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि रुपये का पुनर्मूल्यन इस समय हमारे हित में नहीं है। पुनर्मूल्यन हमारे समाज के कुछ विभागों के लिए लाभकारी होगा, परन्तु अन्य विभागों को बहुत हानि पहुँचायेगा। अब तो भारत में भार गिर गए हैं, इसलिए रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न और भी कम हो जाता है। इससे अतिरिक्त, शेष ५ सार में मद्रा रुकाव की प्रवृत्ति उदित हो जाने के कारण, जो दैंगनैण्ड की बैंक दरों में हाल की भारी वृद्धि से स्पष्ट है, रुपये का पुनर्मूल्यन अव्यवहारिक भी हो सकता है। इन सब परिस्थितियों से अतः भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन देश के लिए हितकर न होगा।

वित्तमन्त्री का आन्धायी निर्णयात्मक वक्तव्य

पुनर्मूल्यन के इसी विवादग्रस्त प्रश्न को लेकर भारत का माननीय वित्त-मन्त्री श्री दशमुख ने एक वक्तव्य देते हुए बताया है कि अभी हम पुनर्मूल्यन

न करने का निश्चय कर चुके हैं क्योंकि इसी में देश का हित है। किन्तु इस निर्णय का अर्थ यह नहीं कि हमारा यह निर्णय अमिट और स्थायी हो। यदि परिस्थितियों ने हमारे अनुकूल करवट ली तो सम्भव है हम भविष्य में इस प्रश्न को सरकार के सामने फिर विचार करने को रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा बैठवाई गई पुनर्मूल्यन समिति के अभिप्रेक्षण में भी वित्त-मंत्रों ने इसी बात पर जोर दिया था कि इस प्रश्न को अभी छुआ न जाय वरन् समय पड़ने पर फिर उस पर विचार किया जाय।

जैसे तो संसार भर के अर्थशास्त्रियों ने सर स्टफर्ड क्रिस्म की उस घोषणा को भी सुना था कि 'पौण्ड का अवमूल्यन मेरी लायक पर होगा' किन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने स्वयं ही पाँड़ पावने के अवमूल्यन की घोषणा कर दी। वित्त मंत्री माननीय श्री देशमुख के वक्तव्य को भी हम उस स्तर पर ले सकते हैं किन्तु फिर भी सरकारी निश्चयानुसार बहुत ही निकट भविष्य में भारतीय रुपये के पुनर्मूल्यन की सम्भावना बहुत कम है।

आज समस्त संसार में आर्थिक दरारें पट रही हैं, प्रत्येक देश उपलब्ध अवसर का आर्थिक उन्नति के लिए निरोधन कर रहा है, कभी अमेरिका की पुनः शस्त्रीकरण की योजना में कटौती की जाती है तो कभी सारा यूरोप शस्त्रीकरण पर तुला हुआ है। ऐसी उमसमानी दशा में संसार के किसी भी भूकम्प के धड़के से भारत सरकार द्वारा रुपये के पुनर्मूल्यन की घोषणा हम किसी भी दिन सुन कर विस्मय में नहीं पड़ सकते।

३५--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और भारत

आज ससार का प्रत्येक देश यह चाहता है कि वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उच्चा हो तथा वहाँ के सभी लोग राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ काम करें। परन्तु यह तभी हो सक्ता है जबकि ससार के सभी, और सभी नहीं तो अधिकांश देश मिलकर काम करें, उनकी आर्थिक तथा मुद्रा नीति ऐसी हो तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न हो। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि उन देशों की मुद्राओं का आपस का विनिमय दर स्थायी रहे और उसमें कोई असाधारण उतार चढ़ाव न हो। युद्ध के पश्चात् तो इस बात की और भी आवश्यक महत्वपूर्ण और आवश्यक समझा गया है कि ससार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। जिससे युद्ध में बिगड़े हुए राष्ट्र युद्ध के पश्चात् अपना अपना पुनर् संगठन और आर्थिक-निर्माण कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्धकाल में ही अनेक योजनाएँ बनाई गईं। एक योजना इंग्लैण्ड ने बनाई जिसके अन्तर्गत 'अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ' (International Clearing Union) बनाने का प्रस्ताव किया था। दूसरी योजना अमरीका ने बनाई जिसमें 'अन्तर्राष्ट्रीय स्थायिक कोष' (International Stabilization Fund) बनाने का सुझाव दिया था। ये दोनों योजनाएँ १९४३ में प्रस्तावित की गईं। १९४४ में इंग्लैण्ड और अमरीका ने मिलकर एक सम्मिलित योजना बनाई जिस पर विचार करने के लिए ब्रेटनवुड्स (Brettonwoods) नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ४४ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पास किया कि ससार के सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए दो मुद्रा संस्थाएँ बनाई जाएँ। सभी देशों की सरकारों ने इस योजना को मान लिया और दो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाएँ बनाई गईं। उनमें से एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक। यहाँ हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्ययन करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के निम्न उद्देश्य हैं :—

(१) संसार के देशों में मुद्रा सम्बन्धी षट्का पैदा करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने तथा उत्पन्न करने की सुविधाएँ देना जिससे कोष के सभी सदस्य देश अपना-अपना आर्थिक विकास कर सकें और अपने-अपने आर्थिक साधनों का विदेशन करके देशवासियों को भरण काम दे सकें ।

(३) सदस्य देशों की मुद्राओं की आपस की विनिमय दर का प्रबंध करना तथा विनिमय दर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना ।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान लेने देने में सहायता करना तथा किसी भी सदस्य देश में लगाए गए विदेशी-विनिमय सम्बन्धी नियंत्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधन न हो ।

(५) सदस्य देशों की भुगतान सम्बन्धी विषमताओं को दूर करने के लिए विदेशी मुद्राएँ दफ्तर सदस्य-देशों की सहायता करना ।

(६) जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भुगतान सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना ।

इस प्रकार मुद्रा-कोष का एकमात्र उद्देश्य सदस्य-देशों को विदेशी-विनिमय सम्बन्धी सुविधाएँ देना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति हो और इसके द्वारा सदस्य देश अपना-अपना अधिक से अधिक आर्थिक विकास कर सकें । यह ध्यान रहे कि मुद्रा-कोष युद्ध में दिष्ट लिए गये देशों का भुगतान सुकृजों में या युद्ध के कारण नष्ट हुए देशों के आर्थिक नष्ट निर्माण में कोई सहायता नहीं करना और न इसका यह उद्देश्य है ।

वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रैटनवुड्स सम्मेलन में भाग लिया था तथा, जिन्होंने ३१ दिसम्बर १९४५ से पहिले कोष का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था, कोष के मौलिक-सदस्य माने जाते हैं । इनके आतिरिक्त और दूसरे देश भी कोष के सदस्य बन सकते हैं । कोई भी सदस्य-देश लिखित गुणना देकर कोष में अपना सम्बन्ध तोड़ सकता है । यदि कोई सदस्य देश

कोष के प्रति अपने कर्तव्य न निभाए ता कोष का अधिकार है कि वह उस सदस्य को अलग कर दे। प्रत्येक सदस्य की कोष में कुछ राशि निश्चित कर दी गई है। जिसे 'काटा' (Quota) कहते हैं। प्रत्येक सदस्य देश का अपने कोटे की राशि कोष में जमा करना पड़ती है। 'काटे' इस प्रकार नियत किए गए हैं—

	डॉलर में (०००,०००)		डॉलर में (०००,०००)
अमरीका	२७५०	बेल्जियम	२०५
इंग्लैण्ड	१०००	आस्ट्रेलिया	२००
रूस	६२००	बार्जीन	१५०
चीन	५५०	जैकोस्लाविया	६२५
फ्रांस	४५०	पॉलैण्ड	१२५
भारत	४००	अफ्रीका	१००
यूनेडा	३००	अन्य देश	१०० में कम
नेदरलैण्ड	२७५		

प्रत्येक सदस्य का अपना काटा बदलवाने का अधिकार है। कोष को भी अधिकार है कि वह पाँच वर्ष के बाद सदस्य-देश की अनुमति लेकर उसकी कोटा राशि में फरक बदल कर सक्ता है। कोटा प्रत्येक देश के स्वर्ण कोष तथा सुद्र पुर्य के विदेशी व्यापार में ध्यान में रख कर निश्चित किए गए हैं। सदस्यों को अपने काटे की राशि कोष में जमा करनी पड़ती है—यह राशि इस भाँति जमा करनी होती है—

(१) कुल 'काटे' का २५% या सदस्य देश के स्वर्ण तथा डॉलर-कोष का १०%, इन दोनों में जो भी कम हो, साने व रूप में जमा करना पड़ता है।

(२) बाँचे का शेष भाग सदस्य देश को अपनी अपनी मद्राओ या किस्मू-रिंटियों में जमा करना पड़ता है।

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध करने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक सचालक समिति तथा एक प्रबन्ध मन्त्रालय है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य-देश

द्वारा चुने हुए एक गवर्नर तथा स्थानाग्न-गवर्नर होते हैं जो पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु अवधि समाप्त होने पर इनको फिर चुना जा सकता है। संचालक समिति में १२ संचालक होते हैं जिनमें ५ उन देशों के होते हैं जिनको अधिक से अधिक 'कोटा'-राशि नियत की गई है, २ अमरीका-गणतन्त्र द्वारा चुने हुए होते हैं तथा ५ अन्य दूसरे सदस्य-देशों द्वारा चुने हुए होते हैं। संचालक-समिति एक प्रबन्ध-संचालक चुनती है जो कोष के दिन-प्रतिदिन के काम की देख-भाल करता है। प्रबन्ध संचालक को मत देने का अधिकार नहीं होता परन्तु आवश्यकता के समय प्रबन्ध-संचालक अपना निर्णायक-मत (Casting Vote) दे सकता है।

मुद्रा-कोष का प्रधान कार्यालय अमरांका में है। कोष का आधा सोना अमरीका में रखा गया है तथा ४०% सोना अन्य बड़े 'कोटा' वाले चार देशों में रखा गया है और शेष सोना अन्य देशों में रखा गया है।

सभी सदस्य-देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं के सम-मूल्य (Par Values) निश्चित कर दिए हैं। ये सम-मूल्य (Par Values) या तो सोने के अनुपात में निश्चित किए गए हैं और या अमरीका के डॉलर के अनुपात में रखे गए हैं। जब कोई सदस्य-देश कोष में से विदेशी-विनिमय या सोना खरीदता या बेचता है तो उसका मूल्य इन्हीं सम-मूल्यों के हिसाब से चुकाया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मुद्राओं की आप्रम की विनिमय दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते और दर स्थायी बनी रहती है। सदस्य-देशों की मुद्राओं के इन सम-मूल्यों में परिवर्तन भी किया जा सकता है परन्तु यह परिवर्तन मुद्रा-कोष की सलाह से ही हो सकता है। सम-मूल्यों में परिवर्तन करने की निम्न व्यवस्था की गई है :—

- (अ) कोई भी सदस्य-देश अपनी मुद्रा के सम-मूल्य में १०% तक की फेर-बदल बिना कोष की सलाह के भी कर सकता है।
- (ब) यदि इसमें अधिक फेर-बदल करनी हो तो उसके लिए कोष से आश लेने की आवश्यकता होती है। कोष को इस विषय में अपना निर्णय ७२ घंटे के अन्दर दे देना पड़ता है।

- (स) मुद्राओं के सम-मूल्यों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबकि भुगतान विषमता व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अड़चनों को दूर करने के लिए उसकी आवश्यकता हो।
- (द) कोष की सहाह के बिना सम मूल्य परिवर्तन करने वाले सदस्य देश को दण्ड (जुर्माना) देना पड़ता है।

इस प्रकार सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दर सोने या डॉलरों के आधार पर निश्चित की गई हैं। सोना ही एक प्रकार से इन देशों की मुद्राओं के मूल्य की माप दण्ड (Measuring Rod) है, अर्थात् सभी मुद्राओं के मूल्य सोने पर आश्रित हैं।

सदस्य देश मुद्रा-कोष से लेन देन का काम अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों, राज्य कोषों तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं द्वारा करते हैं। कोई भी सदस्य देश अपनी मुद्रा या सोना देकर बदले में कोष से दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकता है परन्तु कोष विदेशी मुद्रा तभी बेचता है जबकि—

(१) कोष को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश को उसकी वास्तव में आवश्यकता है और वह उसे कोष के आदर्शों की पूर्ति करने में लगाएगा।

(२) कोष के पास उस विदेशी मुद्रा की कमी न हो।

कोई भी सदस्य देश एक वर्ष (बारह महीने) में अपने 'कोटा', के २५ प्रतिशत से अधिक राशि को विदेशी मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता तथा वह देश कुल मिलाकर अपने 'कोटा' के २०० प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता।

कोष से ली हुई राशि कोष के उद्देश्यों को छोड़ अन्य किसी काम में नहीं लगाई जा सकती। केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए या विनिमय-दर स्थायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम में लाई जा सकती है।

यदि किसी समय कोष में किसी भी सदस्य देश की मुद्रा की कमी हो जाय तो कोष उस मुद्रा को दुर्लभ-मुद्रा (Scarce Currency) घोषित कर सकता है। ऐसा करते समय यह आवश्यक है कि कोष एक रिपोर्ट तैयार करे

और सभी सदस्यों को सूचित कर दे कि अमुक मुद्रा अमुक कारणों से 'दुर्लभ मुद्रा' घोषित कर दी गई है। दुर्लभ-मुद्रा घोषित करने के बाद कोष का यह कर्तव्य है कि वह उस मुद्रा का प्राप्त करके पूर्ति करने का प्रयत्न करे। इसके लिए चाहे तो कोष उस सदस्य-देश में, जिसकी मुद्रा दुर्लभ घोषित की गई है, भेजा देकर उसकी मुद्रा खरीद ले और चाहे उसमें उधार ले ले। और यदि ऐसा सम्भव न हो तो अन्य किसी सदस्य देश से मोने के बदले में दुर्लभ-मुद्रा खरीदकर उसकी पूर्ति करे जिससे उस मुद्रा का अभाव दूर हो जाय।

मुद्रा-कोष के उद्देश्यों और आदर्शों की पूर्ति के लिए सदस्य-देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं—

१. सदस्य-देश मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध और रोक-थाम न लगावे।
२. वे मुद्रा सम्बन्धी नीति में किसी प्रकार का पक्षपात न करें।
३. वे कोष के आदेशों का पालन करें तथा जो कुछ भी सूचना कोष के अधिकारी माँगें उस तुरन्त कोष को भेजते रहें।
४. वे सम-मूल्य से अधिक या कम-दर पर सोना न खरीदें और न बेचें।

परन्तु कोष ने सत्रांति काल में विदेशी-विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण लगाने की स्वीकृति दे रखी है। कोष बनने के पाँच वर्ष तक सदस्य-देश विदेशी विनिमय पर रोक-थाम लगा सकते हैं परन्तु इसके पश्चात् रोक-थाम लगाने के लिए कोष से आज्ञा लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई सदस्य-देश कोष बनने के पाँच वर्ष के बाद भी कोष की आज्ञा के बिना विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगायेगा तो कोष को अधिकार होगा कि वह उस सदस्य-देश को कोष में से निकाल दे। परन्तु परिस्थितियों वरा कोष ने ३१ मार्च १९५२ के पश्चात् भी विदेशी-विनिमय सम्बन्धी रोक-थाम लगाए रखने पर सदस्यों को अनुमति दे दी है। इसी प्रकार कोष ने गत वर्ष सोने को निश्चित मूल्य से अधिक दर पर प्रीमियम के साथ क्रय-विक्रय करने की भी स्वीकृति दे दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों तथा क्रिया-प्रणाली का अभ्यसन करने से ज्ञात होता है कि कोष का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्तम

करना है। कोष का यह उद्देश्य सराहनीय है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नत होने से ही ससार के भिन्न-भिन्न देशवासियों को भरपूर काम मिल सकता है और तभी उनका रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। अगर सुदृढ-स्थिति देशों की आर्थिक उन्नति करनी है तो यह आवश्यक है कि उनके वैदेशिक व्यापार को उन्नत बनाया जाय क्योंकि तभी ससार के करोड़ों नगरियों का रोटी कपड़ा मिल सकता है। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा-कोष प्रयत्नशील है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी संस्था है जिसने द्वारा ससार भर की मुद्राओं की निनिमय दर को स्थायी रखने का प्रयत्न किया जायगा जिससे ससार के सभी देश आर्थिक उन्नति कर सकें। यह एक ऐसा साधन है जिसमें ससार के अनेक देशों की मुद्राएँ जमा रखी जायेंगी जिससे देनदार देश अपने लेनदार-देश की मुद्रा खरीद कर उसका भुगतान चुका सकें। इसके द्वारा भुगतान चुकाने वाले देशों का मुविधा हो जायगी क्योंकि अब उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोष का काम विदेशी मुद्राएँ उधार देना नहीं है वरन् विदेशी मुद्राएँ बेचना है। विदेशी मुद्रा बेचकर कोष सदस्य देशों की आवश्यकता पूर्ण करता है जिससे वे अपनी कठिनाइयाँ का सरलता से सामना कर सकें।

अब कोष के बन जाने से आगामी भविष्य में ससार के देशों का विदेशी-निनिमय पर नियन्त्रण लगाने की अधिक आवश्यकता नहीं रहगी, ऐसी आशा है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ अब कोष के द्वारा पूर्ण हो जाया करेंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एक प्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी मुद्राओं की खरीद बेच करता है परन्तु अपने लाभ के लिए नहीं वरन् सदस्य-देशों के हित के लिए। कोष सदस्य देशों की मुद्राओं के सम-मूल्यों को स्थिर रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ससार भर की मुद्राओं की निनिमय दर स्थायी बनाई जा सकती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई न हो।

मुद्रा-कोष ने सोने को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी सदस्य-

देशों ने अपनी अपनी मुद्रा का सम मूल्य सोने में व्यक्त किया है। इससे सोना सब देशों की मुद्राओं का माप-दण्ड बन गया है। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संसार में वही स्वर्ण-प्रमाण आ गया है जो १९३१ से पहिले अनेक देशों में था। हाँ, इतना अवश्य है कि कोष का उद्देश्य वही है जो स्वर्ण-प्रमाण का होता था, जैसे (१) संसार की मुद्राओं के बीच आरम की अदल-बदल की सुविधाएँ देना, (२) मुद्राओं के मूल्यों में स्थिरता लाना। इस प्रकार कोष और स्वर्ण-प्रमाण के उद्देश्य एक ही से हैं परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन भिन्न-भिन्न हैं। स्वर्ण-प्रमाण किसी और प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था और कोष किसी और प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। अतः यह कह सकते हैं कि कोष ने एक विशेष प्रकार का स्वर्ण-प्रमाण संसार को दिया है जिसके अन्तर्गत सोना मुद्राओं का मूल्य-मापक है। परन्तु सोने के सिक्के नहीं बनाए जाते।

भारत और कोष

जिस समय मुद्रा-कोष की योजना पर ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर विचार हो रहा था तो भारत के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे। भारत के प्रतिनिधि मण्डल में निम्न व्यक्ति थे—सर जैरमी रॉसमेन, सर चिन्तामणि द्वारकादास, सर गियोर्जो ग्रेगरी, सर पलमुखम चेट्टी, ए० डी० शराफ तथा बी० के० मदन। प्रतिनिधि मण्डल ने ब्रेटनवुड्स कांफ्रेंस में ही इस योजना को मान लिया और इसके बाद भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया और रुपये का सम-मूल्य भी घोषित कर दिया। भारत ने रुपये का सम मूल्य ३.८५२ ६० प्रति डालर अथवा ०.२६८६१ ग्रेन्स स्वर्ण प्रति रुपया निश्चित किया।^१ इस प्रकार भारत मुद्रा-कोष का 'मौलिक-सदस्य' बना रहा। मुद्रा-कोष

^१ अब रुपये के डालर मूल्य में कमी हो जाने के कारण रुपये का सम-मूल्य १ ६० = २१ सेण्ट = ०.१८६६२१ ग्रेन्स स्वर्ण रह गया है। इस दर से सोने का मूल्य १६६.६६७ रुपये प्रति औंस है। यह परिवर्तन सितम्बर १९४६ से हुआ है जबकि रुपये का आमुल्यन कर दिया था।

में रुस के सम्मिलित न होने के कारण भारत अब पाँच बड़े-बड़े सदस्यों में गिना जाता है क्योंकि इसका 'कोटा' (Quota) चार देशों का छोड़कर सबसे अधिक है। भारत को मुद्रा-कोष में सम्मिलित होने से निम्न लाभ हैं—

(१) भारत को मुद्रा कोष से आवश्यक मात्रा में विदेशी मुद्राएँ मिलती रहेंगी जिनसे भारत को विदेशों से पूँजीगत माल आयात करने के लिए आवश्यकता होगी। मार्च १९४८ से मार्च १९४९ तक भारत ने कोष से लगभग ६,२०,००,००० डॉलर लिए थे जो भुगतान-रुतुलन के काम आए।

(२) कोष के द्वारा उन देशों का जो स्टर्लिंग क्षेत्र में नहीं हैं भारत की मुद्रा मिलती रहेंगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बढ़ाते रहेंगे और भारत का माल उन देशों में निर्यात होता रहेगा।

(३) मुद्रा कोष का 'मौलिक'-सदस्य बनने से भारत कोष के नीति निर्माण में हाथ बँटा सकेगा जिससे उसकी स्थिति बढेगी।

इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य बन गया और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए। भारत ने कोष से ६६'६८ मिलियन डॉलर लिए। इसके व्याज में १९५०-५१ में ६८ लाख रुपये कोष को चुकाए गए तथा १९५१-५२ में कोई ५५ लाख चुकाए। कोष की सदस्यता स्वीकार करने के बाद हमारी मौलिक पद्धति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनको कार्यान्वित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट में संशोधन किए गए। एक संशोधन के अनुसार भारतीय मुद्रा का अन्य सदस्य-देशों की मुद्राओं में बहुमुखी परिवर्तनशीलता स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक अब अपने कोष में स्टर्लिंग के साथ-साथ अन्य देशों की मुद्रा भी रखता है एवं इनका प्रत्यक्ष विपक्ष कोष की शर्तों की निश्चित दरों पर किया जाता है। दूसरे, कोष की सदस्यता के साथ साथ हमारे रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध टूट गया है। और अब हमारा रुपया स्वतन्त्र है (इसे आगे 'हमारा रुपया' लेख में पढ़िए)। तीसरे, विदेशी मुद्राओं में भारतीय रुपये की महत्तम एवं न्यूनतम दर में कोष द्वारा निश्चित दरों के आधार पर तत्क्षण-लेनदेन में १ प्रतिशत से अधिक अन्तर न होगा। चौथे, रिजर्व बैंक किसी भी देश की सरकारी

सिक्युरिटियों का क्रय-विक्रय कर सकता है, बशर्ते कि वह देश कोष का सदस्य हो। पवित्र, विदेशी-विनिमय की वर्तमान स्थिति में नियंत्रण करने के लिए एवं उसका महत्तम उपयोग करने के लिए १९४७ में एक कानून विदेशी-विनिमय-नियंत्रण-ऐक्ट पास किया गया जो अभी तक चल रहा है।

३६—विश्व बैंक और भारत

द्वितीय युद्ध के पश्चात् युद्ध ध्वंसित देशों के पुनर्मङ्गल तथा अवनत देशों की आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो गया कि ससार के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक मौद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूँजी तथा पूँजीगत माल देकर सहायता कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रैटनवुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक बनाने की योजना स्वीकार की गई। विश्व बैंक के निम्न उद्देश्य रखे गए—

१. सदस्य-देशों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन बढ़ाने में पूँजी का प्रबन्ध करना, युद्ध में बिगड़े हुए देशों के आर्थिक-कलेवर को उन्नत बनाने की सुविधाएँ देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में सहायता करना।

२. उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सदस्य-देशों को अपनी पूँजी तथा कोष में से राशि उधार देना; एक देश के पूँजीपतियों को दूसरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गये ऋणों की गारण्टी करना।

३. दीर्घकालीन (Long term) ऋण देना तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए लोगों या देशों की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सके।

४. सदस्य देशों के बीच आपस में पूँजी का लेन-देन बढ़ाना जिससे पूँजी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके और अधिक उपयोगी तथा आवश्यक योजनाएँ सबसे पहिले पूरी की जा सकें।

५. अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रबन्ध करना कि युद्धकालीन असाधारण परिस्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाय और सभी देश एक दूसरे की सहायता से उन्नत हो जाएँ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की आर्थिक उन्नति करना है। इसके लिए बैंक एक देश के पूँजीयताओं को दूसरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करेगा। यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पूँजी प्राप्त न कर सके तो बैंक अपनी पूँजी तथा कोष में से सदस्य देशों को राशि उधार देगा।

बैंक की पूँजी—बैंक की अधिकृत-पूँजी (Authorized Capital) १०,००,००,००,००० डॉलर है। इसमें से ६ १०,०० ००,००० डॉलर तो उन सदस्य-देशों के लिए निश्चित किए गए जो ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने उसी समय बैंक का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। शेष पूँजी आगे बनने वाले सदस्यों को निश्चित कर दी गई थी। पूँजी में १०,००० हिस्से हैं और प्रत्येक हिस्सा १०,००० डॉलर के बराबर है। बैंक की पूँजी में सदस्य देशों को हिस्से निश्चित कर दिये गये हैं जिन्हें कोटा (Quota) कहते हैं। कोटा इस प्रकार है।

अमरीका	२,४३,५०,००,००० डॉलर
इंग्लैण्ड	१,००,००,००,००० डॉलर
नर्वे	६,००,००,००० डॉलर
फ्रांस	४५,००,००,००० डॉलर
भारत	४०,००,००,००० डॉलर

अन्य देशों के कोटे भी इसी प्रकार निश्चित कर दिए गए हैं जो भारत के कोटे से कम राशि के हैं।

बैंक में कुल मिलाकर ४८ राष्ट्र सदस्य थे परन्तु १४ मार्च १९५० को पोलैण्ड इससे अलग हो गया। इस समय ४७ राष्ट्र इसके सदस्य हैं। रूस इसका सदस्य नहीं है। ३१ मार्च १९५० तक बैंक की प्राधिकृत-पूँजी ८,३३,६०,००,००० डॉलर के बराबर थी। प्रत्येक सदस्य-देश को अपने-अपने कोटा का २०% भाग बैंक में जमा करना पड़ता है जिसमें से २% सोने में जमा करना पड़ता है तथा १८% सदस्य-देश की अपनी मुद्रा में जमा करना होता है। कोटे का शेष भाग उस समय लिया जाने का निश्चय है जबकि बैंक को उसकी आवश्यकता हो। जिन सदस्यों ने ३१ दिसम्बर १९४५ को कोष की

सदस्यता स्वीकार का भी वे ही देश इस बैंक के भी मौलिक-सदस्य माने जाते हैं। अन्य देश भी इसका सदस्य बन सकते हैं। जो सदस्य मुद्रा कोप को छोड़ देते हैं वह इसके सदस्य भी नहीं रह सकते। जो सदस्य बैंक के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते उन्हें बैंक से निराल दिया जाता है। परन्तु कोई सदस्य मुद्रा काप का सदस्य न रहने पर भी ७५% मतों से बैंक का सदस्य रह सकता है। निम्नित सूचना देकर कोई भी सदस्य बैंक से अग्रना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है।

ऋण देने की कुछ शर्तें—बैंक सदस्य-देशों का नीचे लिखी शर्तों पर ऋण देता है—

(१) जबकि उधार माँगने वाले सदस्य देश को अन्य किसी प्रकार से उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जबकि ऋण माँगने वाले सदस्य-देश की सरकार उस ऋण की गारंटी करे, तथा (३) जबकि ऋण लेने वाले सदस्य-देश उसे उसी काम में लगाएँ जिन कामों के लिए ऋण दिया गया है।

बैंक केवल आर्थिक पुनर्संगठन तथा विकास की योजनाओं के लिए ही ऋण देता है। ऋण लेने से पहिले सदस्य देश को ऐसी योजनाओं की एक सूची बैंक के पास भेजनी पड़ती है। ऋण देने से पहिले बैंक इस बात की पूरी पूरी छानबीन कर लेता है कि ऋण लेने वाला सदस्य देश ऋण का भुगतान वापिस चुका सकेगा या नहीं। ऋण देने से पहिले बैंक ऋण चाहने वाले सदस्य-देश की आर्थिक योजनाओं का भली भाँति निरीक्षण कर लेता है। इस काम के लिए वह केवल कागजी-कार्यवाही से हा सन्तुष्ट नहीं होता बरन् अपने प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाओं की भली भाँति जाँच पड़ताल करा लेता है। ऋण देने के बाद भी बैंक समय समय पर इस बात की जाँच करता रहता है कि जिस काम को ऋण दिया गया है वह उसी काम में लगाया जा रहा है या नहीं। श्री होर ने जो, बैंक के उपाध्यक्ष थे, अपने व्याख्यान में बतलाया था कि कोई भी ऋण किसी सदस्य देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि (१) उस योजना की जिसने लिए ऋण लिया जा रहा है ऋण लेने वाले सदस्य-देश के आर्थिक निर्माण में कठिन आवश्यकता हो न हो। (२) वह योजना निश्चित समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो (३) उस योजना पर

विशेषज्ञों को सम्मति न ले ली गई हो। श्री होर ने भारत आकर इस बात को स्पष्ट किया कि “बैंक अधिक उपयोगी तथा अति आवश्यक योजनाओं पर ही सबसे पहिले विचार करता है और यह भी देखा है कि ऋण लेने वाला सदस्य-देश ऋण लेकर निश्चित समय के पश्चात् उसे लौटा भी सकेगा या नहीं।”

बैंक ने २५ जून १९४६ से अपना कार्य आरम्भ किया। दिसम्बर १९४८ तक कुल १६ देशों ने ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र भेजे जिनमें से फ्रांस को २५० मिलियन, नीदरलैण्ड्स को १९५ मिलियन डॉलर, मैक्सिको को दो ऋण ३५ मिलियन डॉलर तथा फिलिपाइन्स को १५ मिलियन डॉलर के ऋण दिए गए। ३० अक्टूबर सन् १९४६ तक बैंक ने जो ऋण दिए वह अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका से स्पष्ट हैं—

विश्व बैंक और भारत

भारत ने बैंक से अभी तक तीन ऋण लिए हैं जो इस प्रकार हैं —

१. पहिला ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का मधुच राज्य तथा घनाडा से रेलवे एजिन खरीदने के लिए लिया गया था। यह ऋण १५ वर्ष की अवधि का है। इस पर ३% व्याज तथा १ प्रतिशत कमोशन प्रतिवर्ष भारत को देना है। इस ऋण का भुगतान अगस्त १९५० से आरम्भ हुआ। इस ऋण में से १,७०,००,००० डॉलर की खरीद केनेडा से तथा १,००,००,००० डॉलर की खरीद अमेरिका से करना निर्दिष्ट किया गया था तथा शेष आवश्यकता के लिए रक्त दिया गया था। यह ऋण १८ अगस्त १९४६ को मिला था।

२. दूसरा ऋण १,००,००,००० डॉलर का २६ सितम्बर १९४६ को कृषि विकास एवं मुधार के लिए स्वीकृत किया गया था। इसकी अवधि ७ वर्ष है। इस पर २½% व्याज तथा १ प्रतिशत कमोशन प्रति वर्ष लिया जायगा। इसका भुगतान १ जून १९५२ से आरम्भ होगा। इस ऋण से भारत सरकार ने अमेरिका से ट्रैक्टर खरीदे हैं जो बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने में काम आ रहे हैं।

३. तीसरा ऋण १५ अप्रैल १९५० को १८५ मिलियन डॉलर का दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कोरासे बिजली-घर बनाने के लिए दिया

३० अक्टूबर १९४६ तक प्रयोजन के अनुसार दिए गए ऋण (षट्क हजार अमरीकन डॉलरों में)

प्रयोजन— देश	रुप		उद्योग		यानायात्रा		निवृत्त शक्ति लागत, विजली भंडारों का यंत्र		अन्य-य	योग
	रकबात	यंत्र + नहरें यंत्र	रकबात	यंत्र	यंत्र	यंत्र				
मस	२८,०००	२,३००	१७६,१००	११,०००	३३,३००	६००			—	२,५०,०००
नीदरलैंड		३०,८००	६०,०००	५३,१००	७८,१००					२,२२,०००
डेनमार्क		७,५००	१६,६००	६,८००	४,८००					४०,०००
लसमबर्ग	६,०००			७,५००	४,५००					१२,०००
बेलजियम				१०,३००					११०	१६,०००
स्विट्जरलैंड				१२,६६०					१,३०७	१६,०००
निली		२,८००								३६,०००
मंगरीको										७६,०००
मालि										५६,०००
कोलंबिया		५,०००								६२,६००
*भारत		१०,०००							१८,६००	२,७००
युगोस्लाविया				२,७००						
योग	३२,०००	६८,४००	२६१,६००	१,०६,०५०	१,८६,८६०	१,०७,६६३			१,६६७	७,३६,६००

*क ने ये ऋण अपनी पूँजी में से दिए तथा दूसरे ऋणों की गारंटी भी की।

*अभी ६० मिलियन डॉलर के ऋण और मिलने वाले हैं।

गया है। इस ऋण की अवधि २० वर्ष है। इस पर ३% व्याज तथा १% कमीशन प्रति वर्ष दिया जायगा। इसका भुगतान १ अप्रैल १९५५ से आरम्भ होगा।

इस प्रकार बैंक से भारत ने कुल मिलाकर ६,२५,००,००० डॉलर के ऋण लिए हैं, जिनमें से १२,००,००० डॉलर रद्द करा दिए। अब भारत को ६,१३,००,००० डॉलर के ऋण चुकाने बाकी है। ये ऋण हमारी औद्योगिक एवं अन्य विकास की योजनाओं को देखते हुए बहुत कम हैं। अभीगत वर्ष बैंक के प्रधान मि० ग्लेक ने भारतका दौरा करके घोषित किया था कि 'भारत के साधन प्रचुर हैं और इनका विदोहन करने के लिए बैंक और भी प्रयत्न दे सकेगा।' इससे सात होता है कि बैंक से भारत के प्रति सान्त्वनी हुई है। सरकार को चाहिए कि चौंके ऋण के लिए बैंक से आन्वीत करके विकास की योजनाओं को प्रगति दे।

बैंक के सामने अविकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ी भारी समस्या है। बैंक को इन देशों की ओर काफी ध्यान देना चाहिए। यदि शीघ्र ही इन देशों के आर्थिक-विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया गया तो ये शीघ्र ही समाजवादी अर्थ-तन्त्र की ओर झुक जाएंगे। चीन के आर्थिक विकास के लिए रूस ने १% व्याज दर पर ऋण दिया है। अतः बैंक को भी उदार होकर ऐसे विद्युत् राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ है उससे तो यह स्पष्ट है कि विश्व बैंक अपने प्रकार की एक अद्भुत संस्था है जो संसार के अधिकांश राष्ट्रों को, जो युद्ध के कारण लुप्त हो गए हैं, सहायता देती है। सभी राष्ट्रों के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के उद्देश्यों की लेजर चलने वाली यह पहली ही संस्था है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा निटल्ली पूँजी राष्ट्रों के हित में काम लाई जा सकती है। यह एक प्रकार का ऐसा सुरक्षित पुल है जिसके द्वारा पूँजीपतियों की पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में पहुँचती है। बैंक राष्ट्रों के आर्थिक और राजनैतिक स्वास्थ्य को बल देने वाली संस्था है जो युद्ध के कारण बिगड़ गया था। बैंक एक प्रकार का संघ है जिसमें अनेक राष्ट्र सदस्य हैं और सब सदस्य मिलकर प्रयत्न लेने वाले सदस्य का भार बाँट लेते हैं। लार्ड कीन्स ने इसके विषय में एक बार कहा था, "इस संस्था से होने

वाले लाभों को आसानी से नहीं आँका जा सकता। राष्ट्रों के विकास के लिए इससे उन्हें साधन प्राप्त होंगे, लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक सहयोग होगा—भुगतान सुलभ होगा। इतने बड़े पैमाने पर स्सार के प्रश्न को एक साथ लेकर चलने वाली संस्था आज से पाँचले कभी स्थापित नहीं हुई।”

बैंक का भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष की सफलता पर निर्भर है। बैंक तभी सफल हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पारस्परिक परिवर्तता (Convertibility) हो और यह बात बाप की सफलता पर निर्भर है। बैंक की सफलता उसके प्रबन्ध एवं संचालन की विशेषताओं पर भी निर्भर है, लेनदार देशों की राजकीय नीति पर भी निर्भर है एवं युद्धोत्तर-काल में सभी राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर है। प्रत्येक मृण की जमानत व साख श्रृंखला लेने वाले सदस्य देश की भुगतान करने की इच्छा एवं शक्ति ही है। परन्तु यदि उधार लेने वाला ही अपनी नीयत गिरा दे तो ससार की कोई भी सस्था तथा कितने ही राष्ट्रों का कितना ही सहयोग सफल नहीं हो सकता।

जो कुछ भी परिस्थिति आज है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बैंक विश्व के आर्थिक कल्याण की भावना लेकर आया है। ससार में उत्पादन के लिए साधनों की कमी नहीं, जन सरया का अभाव नहीं और इच्छा की भी कमी नहीं, कमी केवल पूँजी की है। परन्तु केवल पूँजी भी अकेली सहायता नहीं कर सकती। आवश्यकता तो राष्ट्रों को पारस्परिक सम्पर्क में लाने की है। बैंक का उद्देश्य राष्ट्रों तथा पूँजी दोनों को समीप लाना है। अतः यदि राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग किया तो जो कुछ आज आवश्यकता है मिलकर रहेगा—स्थायित्व, उन्नति एव प्रगति।

३७—हमारी वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था

मुद्रा-मंडी के दोष

हमारी वर्तमान मौद्रिक-व्यवस्था देश के पेन्ड्राय बैंक—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रबन्धित होती है। देश में तीन प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित हैं—

(१) धातु-मुद्रा, (२) पत्र-मुद्रा, (३) साख-मुद्रा।

धातु-मुद्रा अर्थात् सिक्के सरकारी टंकशालों में बनाए जाते हैं। जनता को धातु के बदले में सिक्के बनवाने का अधिकार नहीं मिला हुआ है—केवल सरकार के लेखे पर ही सिक्के बनाकर चलाए जाते हैं। छोटी-बड़ी राशि के अनेक प्रकार के सिक्के देश में काम आते हैं, जिनमें रुपया, अटली, चवली, दुवली, इकली, अधला और पैसा सम्मिलित हैं। द्वितीय युद्ध से पूर्व एक समय था जबकि रुपया, अटली, चवली तथा दुवली चाँदी की बनी होती थीं, परन्तु आज तो ये सब गिल्ट की बनाई जाती हैं। युद्ध काल में चाँदी का अभाव होने के कारण ऐसा करना पड़ा था। जनवरी १९४२ से दो पैसे का सिक्का, जिसे अधला कहते हैं, बनने लगा है। पैसे तोँचे के बने होन हैं। सिक्कों का लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। देश में रुपया ही प्रमाणिक-सिक्काएँ तथा प्रमुख-मुद्रा माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सिक्के सहायक-सिक्के कहे जाते हैं।

१९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने पर नोट चलाने का काम इसी बैंक को सौंप दिया गया। अब यही बैंक नोट चलाती है। इस समय हमारे देश में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोट चलते हैं। २, ५, १०, १०० रुपये के नोट परिवर्तनीय-नोट हैं जिनके बदले में रिजर्व-बैंक सिक्के देने का पक्का देती है। १ रुपये के नोट अपरिवर्तनीय-नोट हैं जिन्हें भारत सरकार का निच-विभाग छाप कर चलाता है। एक और दो रुपये के नोट द्वितीय युद्धकाल में चलाए गए थे और आज भी चलते हैं। एक रुपये के नोटों के बदले में सरकार सिक्के देने का बचन नहीं देती। प्रतिनिधि रूप कागज़ के नोट (Representative Paper Money) हमारे देश में नहीं चलते।

नोट चलाने के लिए अब हमारे देश में “बैंकिंग-सिद्धान्त” का पालन किया जाता है जिसके अनुसार देश के केन्द्रीय-बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) को नोट चलाने का एकाधिकार मिला हुआ है। रिजर्व बैंक बनने से पहिले देश में “करेंसी सिद्धान्त” का पालन किया जाता था जिसके अनुसार सरकार नोट चलानी थी।

नोट छापकर चलाने में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया “आनुपातिक-कोप प्रणाली” का पालन करती है। इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से पहिले रिजर्व बैंक को नोटों के बदले में एक संचित-कोप रखना पड़ता है जिसमें सोना, सोने के सिक्के, विदेशी सिक्कूरिटीज, रुपया तथा रुपये की सिक्कूरिटीज रखी जाती हैं। चलाए जाने वाले नोटों के कुल मूल्य के बदले में संचित-कोप का कम-से-कम ४०% भाग सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी-सिक्कूरिटीज में रखना पड़ता है। इसमें भी हर समय कम से कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना या सोने के सिक्के रखना अनिवार्य है। संचित कोप का शेष ६०% भाग रुपया, रुपये की सिक्कूरिटीज या अन्य देशी विलों में रक्खा जा सकता है। १९४६ से पहिले, जब अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोप नहीं बना था, रिजर्व बैंक को अपने संचित-कोप में स्टलिङ सिक्कूरिटीज रखकर उनके बल पर नोट चलाने का अधिकार था। परन्तु जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप का सदस्य हो गया तो रिजर्व बैंक केवल स्टलिङ सिक्कूरिटीज के बल पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सब सदस्य देशों की सिक्कूरिटीज के बल पर नोट चला सकता है। अब हमारे देश की नोट-व्यवस्था काफी लोचदार है। चूँकि १ जनवरी १९४६ से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण हो गया है इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा नोट चलाने का उत्तरदायित्व अब सरकार का भी उत्तरदायित्व बन गया है।

संक्षेप में भारत की वर्तमान नोट व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(१) परिवर्तनीय और अनिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोटों का चलन,

(२) नोट चलाने के बैंकिंग सिद्धान्त का पालन, तथा

(३) ‘आनुपातिक कोप’ प्रणाली के अनुसार नोटों का प्रचलन।

इन तीनों विशेषताओं के कारण देश की नोट-व्यवस्था में लोच आ गई है।

साख-व्यवस्था

भारत में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है जितनी अमरीका तथा यूरोप के अन्य देशों में पाई जाती है। न तो हमारे देश में बहुत सी साख-संस्थाएँ (बैंक आदि) हैं और न साख-मुद्रा (चेक, बिल आदि) का ही अधिक चलन है। देश के कुछ व्यापारिक केन्द्रों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर आदि में साख-संस्थाएँ भी हैं और साख-मुद्रा का भी प्रचार बढ़ गया है; परन्तु देश के आन्तरिक भागों में साख का लेन-देन व साख मुद्रा का चलन ना के बराबर है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है—वे लोग चेकों, बिलों तथा अन्य साख-मुद्राओं का लिखना तथा उनका प्रयोग करना ही नहीं जानते। दूमेरे, यहाँ के लोग राशि को इकट्ठा करके संचित करने में विश्वास करते हैं। वे न तो आपस में ही उधार लेने-देने हैं और न बैंकों में ही जमा करते हैं। बैंकों ने भी साख-व्यवस्था को उन्नत बनाने का अधिक प्रयास नहीं किया है। जिन बैंकों ने साख के लेन-देन लिए भी वे व्यापार की परिस्थिति से घोंगा टाकर नष्ट हो गए। हमारे देश में साख उन्नत न होने का सचम बड़ा कारण यह है कि पिछले वर्षों में हमारे देश की बैंकिंग-व्यवस्था बड़ी अस्त-व्यस्त रही। न तो देश में कोई केन्द्रीय बैंक था जो साख-नियंत्रण का काम करता और न बैंकिंग कम्पनी कानून ही था जो बैंकों पर अधिकार रखता। अब हमारे देश में केन्द्रीय बैंक भी है और बैंकिंग कानून भी बन गया है। अब केवल एक बात की आवश्यकता है कि लोगो को साख बनाने के लिए उनको साख-मुद्रा का प्रयोग सिखाया जाय तभी देश की साख-व्यवस्था उन्नत बनाई जा सकेगी।

भारतीय मुद्रा-मण्डी के दोष

भारतीय मुद्रा-मण्डी कई भागों में विभाजित है। इन भागों में न तो संगठन है और न आपसी सहयोग ही है। इतना ही नहीं, इस मण्डी में कुछ अर्थ तो ऐसे हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग तो दूर, उल्टी प्रतियोगिता है। स्वदेशी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक प्रतियोगिता रहती है और वे स्वतन्त्र रूप से रुपये का लेन-देन करते हैं। इसी के साथ-साथ इम्पीरियल बैंक भी

अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतिपाङ्गी है क्योंकि इस बैंक को कानून से कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधाएँ मिली हुई हैं।

मुद्रा-मण्डी में ऋण प्रदायक सरथाओं का अभाव है। पाश्चात्य देशों की भाँति कोई भी सस्थाएँ ऐसी नहीं हैं जो विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की आवश्यकतानुसार राशि की पूर्ति कर सकें। ऋण देने के लिए मुद्रामण्डी में आवश्यक मात्रा में राशि भी नहीं रहती। मुद्रामण्डी में न लोच है और न स्थायित्व ही है।

मण्डी के विभिन्न अंगों का किसी भी प्रकार सहयोग न होने के कारण व्याज की दरों में बहुत उन्चावचन रहता है। कहीं पर व्याज दर ऊँची होती तो कहीं बहुत नीची। इसी प्रकार किसी व्यवसाय में ऊँची होती है तो किसी व्यवसाय में नीची दर पर उधार मिलता है।

मण्डी में बैंकिंग सुविधाओं का भी अभाव है। देहातों में जहाँ बैंकों की बहुत आवश्यकता है, बैंक हैं ही नहीं। हमार यहाँ ६२,५०० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक कार्यालय है जबकि अमेरिका में ७००० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक कार्यालय है।^१

अन्य देशों की भाँति हमारी मुद्रा-मण्डी में बिलों का बहुत ही कम उपयोग होता है तथा बिलों की कटौती की सुविधाएँ भी नहीं हैं क्योंकि रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बिलों की कटौती करता है जो मान्य हों तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हों।

३८—अन्तर्राष्ट्रीय प्रांगण में हमारा रुपया

(एक नवीन परिवर्तन)

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में हमारा रुपया सदैव से इंग्लैण्ड की मुद्रा — स्टर्लिंग के साथ बँधा हुआ रहा। भारत के शासक-श्रेष्ठों ने देश में राज-नैतिक आधिपत्य तो जमाया ही साथ ही साथ देश की मुद्रा-व्यवस्था को इस प्रकार संचालित किया कि हम मौद्रिक क्षेत्र में भी उनका मुँह देखते रहे। जैसे और जब वे चाहते तैसे और तभी हमारे रुपये को विनिमय दर में फेर-बदल कर दिया करते थे। हमारे रुपये का भाग्य विदेशी मुद्रा के साथ बँधा हुआ था। जब-जब उस मुद्रा में कोई फेर-बदल होती तो उसका पाव हमारा मुद्रा को भी भोगना पड़ता था और इस प्रकार हमारे व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता था। यही कारण था कि १९२० के पश्चात् भारत के अनेक व्यापारी दियानिया बन गए। १९२५ में भी हिल्टन यंग कमिशन ने रुपये का भाग्य स्टर्लिंग के साथ बँधना निश्चित किया था। १९३१ में इंग्लैण्ड में स्वर्ण-प्रभाव डूट जाने पर हमारे रुपये को स्वर्ण-हीन स्टर्लिंग के साथ बँधना पड़ा। १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बन जाने पर भी इस परिस्थिति में कोई फेर-बदल नहीं हुई। चरन् रिजर्व बैंक को कानून के अनुसार रुपये के बदले में स्टर्लिंग की गरीद-बेच करने का दायित्व और दे दिया गया। उस समय रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पैसे थी और रिजर्व बैंक १ शि० ६ १/२ पैसे प्रति रुपये की दर से स्टर्लिंग गरीदता तथा १ शि० ५ १/२ पैसे प्रति रुपया की दर से स्टर्लिंग बेचा करता था। समय-समय पर अनेक बार रुपये के स्टर्लिंग के साथ गठबन्धन परवाद-विवाद होते रहे और पक्ष तथा विपक्ष में तरह-तरह की युक्तियाँ दी जाती थीं परन्तु कोई परिणाम न निकला। और भी, रिजर्व बैंक ऐक्ट की धारा ३३ के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि स्टर्लिंग गिस्सूरिटियों के बल पर भारत में नोट चलाए जा सकते हैं। इसी व्यवस्था का तो यह दुष्परिणाम था कि गत मुद्राकाल में भारत की विदेशी सरकार रिजर्व बैंक के कोष में स्टर्लिंग गिस्सूरिटियों के ढेर लगाती रही और देश में नोट

छाप कर चलाती रही जिससे हमारे देश में मुद्रा-स्फोति हुई, वस्तुओं के भाव आकाश तक जा लगे और देशवासियों का वस्तुओं के अभाव में नारकीय यातनाओं का सामना करना पड़ा।

परन्तु अब परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। मुद्रा के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोष बनने से और भारत सरकार द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार लेने से हमारा रुपया अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में अब किसी भी देश की मद्रा विदेश के साथ बँधा हुआ नहीं है। १२ दिसम्बर १९४६ का भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार की और उसी दिन से हमारा रुपया सञ्चलन हो गया। कोष के विधान के अनुसार रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सोने तथा अमरीकन डॉलरों में व्यक्त करने काप में निश्चित कर दिया गया। एक रुपया ०.२६८६०१ ग्राम सोने के बराबर घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में १ अमरीकन डॉलर ३७.८५२ रुपयों के बराबर निश्चित किया गया। इसी प्रकार काप के सभी सदस्य देशों ने अपनी अपनी मद्राओं का मूल्य सोने तथा अमरीकन डॉलरों में व्यक्त करने कोप के अधिनारियों के पास भेज दिया। इस प्रकार ससार के अधिकांश देशों, जो कोप के सदस्य हैं, की मुद्राएँ एक प्रकार से साने से सम्बन्धित हो गईं और उनका पारस्परिक विनिमय अनुपात भी साने के माध्यम द्वारा निकाला जाने लगा। भारत सरकार ने अपने रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य रक्खा वही इंग्लैण्ड की सरकार ने १ शि० ६ पै० का रक्खा। इस प्रकार साने के माध्यम का रखे कर आज भी १ रुपया १ शि० ६ पै० के समान है। भारत सरकार यदि चाहती तो उस समय अपने रुपये का स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन कर सकती थी और आज भी वह कोप के नियमानुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। परन्तु सरकार ने अपने देश के आन्तरिक और वैदेशिक व्यापार के हित में रुपये के स्वर्ण-मूल्य में परिवर्तन न करना ही उचित समझा।

रुपये का स्वर्ण-मूल्य निश्चित करने से हमारा रुपया, अन्य मुद्राओं की भाँति पूर्ण रूपेण 'स्वतन्त्र' है। परन्तु 'स्वतन्त्र' शब्द का यह अर्थ नहीं कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी भी समय कितनी भी मात्रा में और किसी भी विदेशी-मुद्रा में रुपये को बदलवा सके। 'स्वतन्त्र' शब्द का अर्थ तो यह है कि

भारत सरकार अपने देश के हितों को सामने रखकर रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा करते समय उसे, कोय को छाँड़ अन्य किसी बाह्य सरकार से आशा या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। १९४६ से पहिले तो रुपये की विनिमय-दर में परिवर्तन करने के लिए इंग्लैण्ड की सरकार से आशा लेना आवश्यक था और स्टर्लिङ्ग में परिवर्तन होने के साथ साथ हमारे रुपये में भी स्वतः ही परिवर्तन हो जाते थे। आज यह बात नहीं है। यदि आज स्टर्लिङ्ग के मूल्य में कोई घटा-बढ़ी हो या हो जाय तो उसका रुपये पर भी प्रभाव पड़े यह आवश्यक नहीं है।

कुछ लोग समझते होंगे कि चूँकि अब भी १ रुपया १ शि० ६ पैसे के बराबर है तो रुपया स्टर्लिङ्ग पर आश्रित होगा, यह बात नहीं है। इसका कारण तो यह है कि हमने १ रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य दिया है वही इंग्लैण्ड का सरकार ने १ शि० ६ पैसे का दिया है इसलिए १ रुपया १ शि० ६ पैसे के बराबर है। दूसरे, हमारा अधिकारा व्यापार इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देशों के साथ होने के कारण हमने अदल बदल तथा भुगतान सम्बन्धी सुविधाओं की दृष्टि से अपने रुपये का मूल्य शि० ६ पैसे में व्यक्त करने की प्रथा बना रखी है अन्यथा हमारे ऊपर इंग्लैण्ड का या स्टर्लिङ्ग का पहिले की भाँति कोई दबाव या जोर-जबरदस्ती नहीं है। हम जब भी चाहें अभी रुपये का मूल्य स्टर्लिङ्ग में व्यक्त करना बन्द कर सकते हैं। मुद्रा-कोय की समस्या के साथ हमारा स्टर्लिङ्ग से नाता टूट गया है। यह नाता टूट जाने के कारण अब रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैण्ड या ऐन्ट की धाराओं में भी परिवर्तन कर दिए गए हैं। ऐन्ट की धाराएँ ४० और ४१ को रद्द करके एक नई व्यवस्था की गई है कि रिजर्व बैंक पहिले की भाँति अब केवल स्टर्लिङ्ग ही नहीं परन्तु मुद्रा-कोय के सभी सदस्य-देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय कर सकता है परन्तु यह क्रय विक्रय २ लाख रुपये से कम मूल्य की मुद्राओं या नहीं हो सकता। मुद्राओं का क्रय विक्रय केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है और अधिकृत-व्यक्ति ये ही होते हैं जिन्हें सरकार १९४७ के विदेशी-विनिमय कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकार देती है। इसी प्रकार ऐन्ट की धारा ३२ में भी परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि बैंक मुद्रा-कोय के सभी सदस्य देशों की

सिक्यूरिटीयों के बल पर नोट छापकर चला सकती है। पहिले की भाँति अब नेचन स्टर्लिंग सिक्यूरिटीयों के बल पर ही नहीं कोप के सभी सदस्यों की सिक्यूरिटीयों के बल पर नोट छापे जा सकते हैं। ऐक्ट की धारा १७ में भी स्टर्लिंग के स्थान पर विदेशी-सिक्यूरिटीयों या विदेशी विनिमय शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऐक्ट में फेर बदल करके हमारे रुपये की स्वतन्त्रता वैधानिक बना दी गई है। स्टर्लिंग में रुपये का विनिमय मूल्य यद्यपि आज भी १ शि० ६ पेंस है लेकिन हमारी आर्थिक एवं मौद्रिक परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का अधिकार हमारी सरकार को है।

१९४६ में स्टर्लिङ तथा अन्य मुद्राओं के साथ साथ हमारे रुपये का जो अवमूल्यन किया गया उससे कुछ लोगो को अभी यह सदेह बाकी है कि हमारा रुपया स्वतंत्र नहीं बरन् स्टर्लिंग पर ही आश्रित बना हुआ है। परन्तु ऐसा समझना उनका भ्रम है। जैसा कि रुपये का अवमूल्यन शीर्षक लेख में बताया गया है, हमारी सरकार ने स्टर्लिङ की देखा-देखी या इंग्लैंड के दबाव में आकर रुपये का डॉलर मूल्य कम नहीं किया था। बरन् वह तो स्वतन्त्र सरकार का अपने स्वतन्त्र-रुपये के लिए देश के हित में एक स्वतन्त्र-कदम था। इंग्लैंड ने डॉलर-संकट को टालने के लिए स्टर्लिंग का अवमूल्यन किया था तो हमने भी अपने सामने आए हुए डॉलर संकट को दूर करने तथा अपने वैदेशिक व्यापार को बढाकर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया। यदि हमारी सरकार यह उचित समझती कि रुपये का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए तो अवमूल्यन करने के लिए उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने अवमूल्यन नहीं किया तो क्या किसी ने उसे अवमूल्यन करने के लिए बाध्य किया? अवमूल्यन करते समय वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि रुपये का अवमूल्यन किसी भी शक्ति के दबाव के कारण नहीं बरन् देश के वैदेशिक व्यापार की वृद्धि के लिए किया जा रहा है।

अब कुछ दिनों से फिर पुनर्मूल्यन की लहर दौड़ने लगी है। लोगों का अनुमान है कि स्टर्लिङ की दर में फिर फेर-बदल की जायगा। यदि ऐसा

दुआ तो भारत सरकार भी रुपये के साथ यही मन्दर-नीति बरते यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है स्टर्लिंग के पुनर्मूल्यन पर भारत-सरकार भी वैसा ही करे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि रुपये का स्टर्लिंग के साथ गठबन्धन है वरन् उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि देश के हित में सरकार रुपये की दर में परिवर्तन करने को तैयार है। यदि स्टर्लिंग के पुनर्मूल्यन पर सरकार उचित न समझे तो रुपये की दर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परन्तु इसका निर्णय सरकार देश के प्रमुख व्यापारियों, उद्योगियों तथा अन्य विशेषज्ञों से तात्-मेल रखकर ही कर सकती है। राजनैतिक-स्वातन्त्रता के साथ-साथ मौद्रिक स्वातन्त्रता भी हमारे पास है—इस जैसा चाहें उसका उपयोग करें। यदि हमने इस ओर स्वातन्त्र्य दग उठाये तो अत्यन्त ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रांगण में हमारी मुद्रा का सम्मान बहुत बढ़ जायगा।

३६—हमारा वैदेशिक व्यापार

समस्याएँ और सम्भावनाएँ

गत महायुद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण ससार के सम्मुख विभिन्न आर्थिक समस्याएँ उपस्थित हुई, जिनसे परिणामस्वरूप ससार का पिछला आर्थिक संगठन बदल सा गया। अमरीका, कनाडा आदि कुछ देशों ने अधिक वैभव और समृद्धि प्राप्त की। उनकी आर्थिक स्थिति और भी बलवती और विकासमयी बनी। ब्रिटेन तथा यूरोप के देश महायुद्ध की विघ्नसात्मक क्रियाओं से प्रतिफल तथा उपनिवेशों के समाप्त होने से अधिक संकट का सामना करने लगे। उनके आर्थिक ढाँचे ने क्षीणता ही प्राप्त न की, उनमें विशङ्खलता भी आई। उनके अतिरिक्त भारत आदि अन्य एशियाई देश हैं जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर अपनी औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का रूप देने में सलग्न हैं। इस प्रकार महायुद्ध ने पश्चात् ससार के तीन भिन्न भाग विविध आर्थिक ढाँचों को लेकर आगे बढ़े। यद्यपि सबका नक्ष्य राष्ट्रीय आर्थिक संगठन था, फिर भी उन्होंने भिन्न समस्याओं को हल करने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल साधनों को अपनाया। ससार के बहुभाग की आर्थिक स्थिति को डाँढ़ाडान देकर अमरीका इस तथ्य पर पहुँचा कि ससार ने लघुभाग की समृद्ध बहुभाग का संकट मिटाये बिना अनेक समय तक ठिकी नहीं रह सकती। अतएव उसने यूरोप के युद्ध से विघ्नस्त देशों के आर्थिक ढाँचे के बिखरे हुए अवयवों को पुनः संगठित करने में सहायग दिया। उसके सहायग के कारण यूरोप के देशों ने अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्स्थापन अति शीघ्र किया। उत्पादन बढ़ने लगा और आज कुछ वस्तुओं का उत्पादन ससार की आवश्यकता से भी अधिक है। यह सहायग अब भारत आदि अन्य एशियाई देशों को भी प्राप्त होने लगा है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है वह इस सहयोग द्वारा कृषि और उद्योग का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उनके उत्पादन में वृद्धि अवश्य ही करेगा। इससे अन्न के आयात में कमी और निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की आशा की जा सकती है।

ब्रिटेन आदि अन्य देश अमरीका के सहयोग पर ही निर्भर न रहे। उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा युद्ध के अनन्तर थोड़े हूँ मंडियों को फिर प्राप्त करने के लिए राज्यकर (क्रिस्वल) तथा चलन (मोनेटरी) दोनों ही साधनों को अपनाया। आयात न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार नियमित किया गया और निर्यात को हर प्रकार से बढ़ावा दिया गया, किन्तु, युद्ध-काल में मुद्रारक्षीति और वस्तु तथा सेवाओं की अल्पव्यता के कारण उपभोक्ताओं की मंचित मांग विम्फुटित हो उठी और पलस्वस्व, आयात में भी वृद्धि होने लगी। इसमें लेखा-मंजुलन की कठिनाई उगम्यत हुई। इसे दूर करने के लिए सभी व्यापारिक घाटेवाले देशों ने कुछ कारवाहियों की, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान विनिमय और परिमाणामक निबंधनों का है। ये दो निबंधन अमरीका आदि देशों में भी बरते जा रहे हैं। भारत आदि कई देशों ने मुद्रा का अव-मूल्यन किया। इसमें लेखा-संतुलन की कठिनाई कुछ समय के लिए दूर अवश्य हो गई परन्तु विदेशी माल की एक इकाई के लिए उन्हें एक निहाई माल अधिक देना पड़ा। संसार के प्रायः सभी देशों ने युद्ध से पूर्व कुछ देशों में बरती जानेवाली द्विदेशिक व्यापार-प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी दो देश पारस्परिक समझौता करने हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार आयात-निर्यात के 'कोटा' निश्चित करने हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार के नियमित व्यापार में लेखा-मंजुलन में सरलता होती है। भारत का व्यापार अभी स्वतन्त्र नहीं है। भारत सरकार अपनी नीति बदलने में देर नहीं करती और द्विदेशिक समझौतों को स्थान में रखने हुए लायस्वस्व देती है। इस गूढ़म वर्णन में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज संसार का व्यापार राज-नीतिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल नियमित और नियमित है।

संसार की आम समस्याओं के अतिरिक्त भारत के सामने कुछ विशेष समस्याएँ भी आईं जिनके कारण उसके व्यापार के ढाँचे में बड़ा अन्तर आया। युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में कमी होने से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारतीय उद्योगपतियों ने समय में लाभ उठाया और उद्योगों के विकास के साथ नये उद्योगों को भी स्थापित किया। युद्ध के पश्चात् भारत से उपभोक्ता वस्तुएँ भी निर्यात होने लगीं। १९४६ के आयात-निर्यात के देशनांकों

से ज्ञात होता है कि आयात का देशनाक २४४ और निर्यात का २६० था (१९३८-१००) । दुःख है कि राजनीतिक परिस्थिति ने साथ न दिया और व्यापार की गति गिरने लगी । देश-विभाजित होते ही भारत के आर्थिक संगठन में ऐसे परिवर्तन आये जिनका व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा । यह भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें उसके आयात निर्यात की नई कहानी आरम्भ होती है । उसे पटसन, रूई और अन्न के लिए विदेशों पर आश्रित होना पड़ता है । यह सत्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकट प्रयास कर रहा है और पटसन तथा रूई के उत्पादन को काफी अधिक बढ़ा लिया है । अन्न का प्रश्न ही उसकी आर्थिक स्थिति की एक विचित्र पहली बना हुआ है । निम्न तालिका भारत के बढ़ते हुए व्यापार को बताती है :—

मूल्य का देशनांक

साल	आयात			निर्यात			
	खाद्यवस्तु	कच्चा	निर्मित	कुल खाद्यवस्तु	कच्चा	निर्मित	कुल
	व तम्बाकू	माल	माल	व तम्बाकू	माल	माल	
१९४८*	१०७	१०४	८६	६६	११०	१०२	६७ १०१
१९५०	१०४	११३	६६	१०३	१२७	११४	१०३ ११०
१९५१*	११२	१५७	१००	१२७	१५५	१४८	१६४ १५७

मात्रा का देशनांक

१९४८*	१००	११४	१२१	११५	११७	६७	८८	१०२
१९५०	७१	११२	७६	८८	१०६	१०३	११२	११५
१९५१*	१३६	१०८	६०	१०५	११५	१२८	११६	१२१

उपर्युक्त तालिका भारत के आयात-निर्यात के मूल्य तथा उसकी प्रमात्रा के पिछले तीन सालों में घटान-बढ़ाव को प्रदर्शित करती है । साथ ही वह हमारे व्यापार के ढाँचे पर भी प्रकाश डालती है । घटाव बढ़ाव का एक मात्र

* दस माह की औसत

कारण देश की माँग और प्रदाय शक्ति ही नहीं है, इस सम्बन्ध में संसार की प्रदाय स्थिति, वस्तुओं का मूल्य तथा राजनैतिक वातावरण—ये सभी बातें ध्यान देने योग्य हैं ।

किसी भी देश का आयात और निर्यात उसके आर्थिक ढाँचे पर निर्भर है । भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने से उसे न पिछड़ा हुआ देश ही कहा जा सकता है और न उसका नाम उन्नतिशील देशों की सूची में ही आता है । उसने उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और अब वह बड़ी मशीनों तथा कलों के लिए कारखाने स्थापित कर रहा है । इस औद्योगिक उन्नति के कारण उसके व्यापार के ढाँचे में भी परिवर्तन आया । उसके निर्यात की सूची से कुछ मर्दे शोभन हो चुकी हैं और अनेक की प्रमाणा में कमी आ गई है । निम्न-तालिका निर्यात की स्थिति प्रस्तुत करती है :—

कुछ वस्तुओं का निर्यात (मासिक औसत)
(प्रमाणा)

वस्तु	१९४६	१९५०	१९५१
रई (००० टन)	४	३	२'५
रूई कपड़ा (करोड़ गज)	३'६	६'३	८'६
बोरी (न० करोड़)	३'७	२'६	३'३
हयसेन (करोड़ गज)	१०'४	६'२	६'०
मूँगफली (००० टन)	५	८	४
अनमौ "	५	५	३
ग्वाल "	२	१	१'५
लोहा "	५	२	५
मैंगनीज "	४५	३१	३०
अभ्रक (टन)	११५०	१३५०	२५८०
चाय "	१८३५४	१४७३२	१५१७६
लाग "	१७५०	२५५०	२०००

इन वस्तुओं के अतिरिक्त सिलाई की मशीनें, काँच का सामान, चीनी, खेती के औजार, बिजली का सामान, ऊनी कपड़ा, दरी, रसायन आदि कई निर्मित वस्तुएँ विदेशों को भेजी जाती हैं।

यों तो छोटा बड़ा विविध प्रकार का सामान आयात किया जाता है, मुख्य उपभोक्ता वस्तुएँ निम्न तालिका में दर्शित की गई हैं —

कुछ वस्तुओं का आयात (मासिक औसत)

(प्रमाणा)

वस्तु	१९४६	१९५०	१९५१*
कागज (टन)	६६५०	५४५०	६५५०
रुई कपड़ा (००० गज)	१७	१७	१३
सूती कपड़ा (००० गज)	७६१३	५७४	७६७
सूत (००० पौंड)	१६७५	२६२	१०६
मिट्टी का तेल (००० गैलन)	१६०२०	१८५४८	१८७२६
पेट्रोल	१४०२१	१६१५४	१७७१६
खाद (००० टन)	१७	४०	११
अन्न	२१३	१३२	३३८

देश के आयात की सूची यहाँ पर समाप्त नहीं हो जानी। भारत की वर्तमान विकासमय औद्योगिक नीति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि कुछ उपर्युक्त मदें शीघ्र ही इस सूची से ओझल हो जाएँगी। किन्तु देश के प्राकृतिक साधनों पर ध्यान देने से यह छिपा न रह सकेगा कि तालिका में कुछ ऐसी मदें हैं जिनका आयात भविष्य में बढ़ेगा। इनके अतिरिक्त भारत मशीन और उपभोक्ता वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चा माल भी आयात करता है। इनमें से कुछ वस्तुओं के आयात का शान निम्न आँकड़ों से दिया जा सकता है :—

* दस माह का औसत

(करोड़ रुपये)

अप्रैल-नवम्बर

वस्तु	१९४६	१९५०	१९५१
मशीनों की वैल्यूिंग	०.८	०.७	१.३
रसायन	६.३	५.४	१२.१
लोह भाण्ड	५.१	३.१	४.२
मिजर्जी के यंत्र	१०.२	६.८	६.४
मशीन आदि	७५.३	५७.६	३७.६
फैरस धातु	६.८	११.७	१३.५
नान-फैरस धातु	१३.०	१६.८	१३.५
दवाइयाँ	६.२	५.६	१०.२
लारी, ट्रक आदि	४.५	२.१	१.४
मोटरें	२.३	२.१	२.७

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से भारत के आयात-निर्यात का ढाँचा बदल रहा है। भारत अब केवल कच्चे माल या प्रदायक न रह कर उसे चोर बाजार के भाव पर भी खरीद कर स्वयं आयात करता है और उपभोक्ता आदि वस्तुओं को तय्यार कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों को भी भेजता है। पंच-वर्षीय योजना पर ध्यान देने से यह विदित होता है कि अगले पाँच वर्षों में भारत के व्यापार का ढाँचा आज के सदृश्य मिश्रित न रह कर स्पष्ट रूप ग्रहण करने लगेगा। भारत के आयात की सूची से रेल के इंजन, कई प्रकार की मशीनें, मोटर, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की प्रमाणा नही के बराबर रह जायगी। साथ ही भारत रूई तथा पटसन में भी आत्म निर्भर बन जायगा। उसकी निर्यात सूची में मशीन, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की संख्या और प्रसार प्रमाणा दोनों में वृद्धि होगी। यह सब तभी सम्भव है जब भारत में राजनैतिक स्थिति बनी रहे और सरकार तथा उद्योगपति एक दूसरे के सहयोग द्वारा पंच-वर्षीय योजना को सकल बनायें और देश के उद्योगीकरण को वृद्ध और विखाल रूप दें।

४०—राष्ट्रीय आय

हमारी प्रति-व्यक्ति आय का एक अध्ययन

बिस्वी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की द्योतक होती है। प्रगतिशील राष्ट्रों की वार्षिक आय उत्पादन बाहुल्य के कारण स्वतः ही अधिक होती है तथा उद्योग-धन्धों की दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय समूचे उत्पादन की ही द्योतक नहीं, राष्ट्रीय आय के वितरण पर भी बंध प्रकाश डालती है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्र की सम्पत्ति के वितरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। राष्ट्र के आर्थिक जीवन के उतार-चढ़ाव प्रति व्यक्ति आय द्वारा जाने जाते हैं। आर्थिक आयोजन की दृष्टि से आर्थिक जीवन के इन परिवर्तनों को जानने के लिए राष्ट्रीय आय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय के आँकड़ों द्वारा समाज के रहन-सहन के स्तर का पता लगाया जा सकता है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि राष्ट्र के विभिन्न वर्ग उन्नति पर हैं अथवा अवनति की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में, जहाँ के निवासियों का रहन-सहन निम्नतर है, जहाँ के लोगों का स्वारय बहुत गिरा हुआ है, जहाँ लोगों को पोषक आहार तो क्या पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं, इस बात की कल्पना आवश्यकता है कि राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति जानी जाय। ऐसी स्थिति में यदि सरकार राष्ट्रीय आय का सही-सही ज्ञान प्राप्त कर सके तो उसे देश की आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए कोई भी टोस कदम उठाने में कानी योग्य मिल सकता है और तभी वह लोगों की कर-क्षमता का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके क्षमता के आधार पर कर-प्रणाली का आयोजन कर सकती है।

गत वर्षों में हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति जानने के अनेक प्रयत्न होते रहे हैं। सबसे पहला प्रयत्न १८६७-७० में किया गया था जब डा० दादाभाई नोरोजी ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त किए थे। इसके

परवान् समय-समय पर अनेक प्रयत्न होते रहे । समय-समय पर प्रति व्यक्ति आय के जो आँकड़े प्राप्त किए गए, वे इस प्रकार हैं:—

वर्ष	आँकड़े प्राप्त करनेवाले व्यक्ति या संस्था का नाम	प्रति-व्यक्ति आय (रुपये में)
१८६७-७०	दादाभाई नौरोजी	२०
१८८२	लार्ड क्रोमर	२७
१८८१	ई० ए० हॉर्न	२८
१८८८	डिग्बी	१७ ८
१८८८-१८९०	डिग्बी	१२ ८
१८९०	फर्जन	३०
१८९३	सर थार० गिफ्टिन	३०
१८९१-९२	डा० बालकृष्णन्	२९
१८९१	ई० ए० हॉर्न	४२
१८९३-९४	घादिया और जोशी	४४-८
१८९०-९४	शाह और ग्वाभाता	३८
१८९१-९२	शाह और ग्वाभाता	६७
१८९५	वकील और मुरजन	७४
१८९१	किण्डले शिराज	६३
१८९१-९२	डा० राय	६५
	ग्रामीण	५१
	नागरिक	१६६
१८९७-९८	सर जेम्स प्रिग	५६
१८९८-९९	'कॉमिर्स' साप्ताहिक के एक लेख द्वारा १८-१२-१८४३	६६
	ग्रामीण	४७
	नागरिक	२००
१८४२-४३	'कॉमिर्स' के एक लेख द्वारा	१४२
	ग्रामीण	६१

वर्ष आँकड़े प्राप्त करने वाले व्यक्ति या
संस्था का नाम प्रति-व्यक्ति आय
(रुपये में)

	नागरिक	४८३
१९४३ ४४	दिल्ली के एक साप्ताहिक 'इस्टर्न इक्वॉनॉमिस्ट'	१३६
१९४४ ४५	"	१३६
१९४५ ४६	"	१३७
१९४६ ४७	"	१४३
१९४७ ४८	"	१६०
१९४८ ४९	"	१८६

उक्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिए गए आँकड़ों में काफी अन्तर और विषमता है। इसका एक कारण यह है कि समय समय पर मूल्य-स्तरों में, जिनके आधार पर ये आँकड़े ज्ञात किए गए थे, काफी अन्तर रहता था। दूसरी बात यह रही कि किसी विशेषज्ञ ने अपनी जाँच पड़ताल का क्षेत्र छोटा रखा और किसी ने बहुत विस्तृत—किसी ने समूचे भारत के आँकड़े प्राप्त किए तो किसी ने किसी स्थान विशेष के। इसमें आँकड़ों में अन्तर रहा। एक बात और है। इन आँकड़ों को निकालने में अन्वेषकों ने पक्षपात से भी काम लिया। जो अन्वेषक यह दिखाना चाहते थे कि अगरेजी राज्य में देश की आर्थिक उन्नति हुई है, वे ऊँचे आँकड़े निकालते रहे और जो अन्वेषक इसके विपरीत सिद्ध करना चाहते थे, उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के नीचे आँकड़े निकालने की चेष्टा की। इसने अतिरिक्त हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण रही है। आँकड़े प्राप्त करने की सरल और वैज्ञानिक पद्धति का अभाव होने के कारण प्राप्त किए गए आँकड़ों को बिल्कुल विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। फिर भी जा कुछ आँकड़े इस समय प्राप्त हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत की उत्पादन शक्ति और इस पर आधारित राष्ट्रीय आय बहुत कम है। देशवासियों का निम्नतर जीवन स्तर इस बात का एक प्रमाण है। अन्य देशों की तुलना में तो हमारी राष्ट्रीय

आय बहुत ही कम है। प्रो० कोनिन क्लार्क ने विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय इकाई' के आचार पर प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक आँकड़े दिए थे जो इस प्रकार हैं :—

देश	अन्तर्राष्ट्रीय इकाई
अमरीका	१३=१
इंग्लैण्ड	१०६६
आस्ट्रेलिया	६८०
फ्रांस	६८४
जापान	३५३
भारत	२००

हो सकता है कि प्रो० क्लार्क के ये आँकड़े नितान्त सत्य न हों परन्तु हममें सन्देह नहीं कि अन्य पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत नीची है।

युद्ध का प्रभाव

युद्ध के कारण देश में उद्योग-धंधों को जो प्रोत्साहन मिला और उसके फलस्वरूप लोगों के रोजगारों में जो बढ़ोत्तरी हुई उसमें सामान्यतः यह धारणा बन गई है कि देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। परन्तु विशेषज्ञों ने १९३६ से १९४५ तक के जो आँकड़े इकट्ठे किए हैं उनसे यह धारणा बिलकुल ग़लत सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में दिल्ली के साप्ताहिक 'इस्टर्न इकॉनॉमिस्ट' के शोध विभाग ने कुछ आँकड़े गंकलित किए हैं। उनसे ज्ञात होता है कि १९३६ में प्रति व्यक्ति आय ६७ रुपये थी परन्तु यह घट कर १९४५-४६ में ६३ रुपये रह गई। उक्त पत्र से लिए गए आँकड़ों से यह बात और भी अधिक स्पष्ट होती है—

१९३६-४० ४०-४१ ४१-४२ ४२-४३ ४३-४४ ४४-४५ ४५-४६

१. प्रति-व्यक्ति ६७ ७० ७५ ११२ १३८ १३६ १२७
आय (रुपयों में)
१०-१८

२. निर्वाह-व्यय (बंबई) १०० १०५ ११७ १६० २२७ २१६ २१७
(आधार १९३६ = १००)

३. निर्वाह-व्यय ६७ ६७ ६६ ७० ६४ ६४ ६३
बंबई से सम्बन्धित
प्रतिव्यक्ति आय

इस तालिका में बंबई के निर्वाह व्यय को ही आधार माना गया है क्योंकि देहातो के सम्बन्ध में जीवन-व्यय के आँकड़े उपलब्ध हैं ही नहीं और यदि उपलब्ध भी हों तो उनसे सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता। देहात में लगभग सात करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उत्पन्नित कृषि-पदार्थों पर कोई अधिकार नहीं है। वे केवल खेतिहर-मजदूर हैं। उन्हें कृषि पदार्थों की मूल्य-वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इस विषय में बुडहेड अकाल कमीशन का मत देना आवश्यक है। कमीशन का मत है कि साधारण कृषकों को मूल्य वृद्धि से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला है—कुछ वृद्धि हुई है—परन्तु इसके साथ-साथ कृषक ने लगान, ऋणाया और ऋण चुकाने के लिए अपने उत्पादन का बहुत कम भाग बाजार में बेचा है (अतः उन्हें मूल्य-वृद्धि से कोई अधिक लाभ नहीं मिला है)। कमीशन के इस मत पर यह माना जा सकता है कि देहातो में प्रति व्यक्ति आय में कोई हास नहीं तो कोई वृद्धि भी नहीं हुई है।

प्रति मनुष्य आय के हास के कारण जानने की उत्कण्ठा होना स्वाभाविक है क्योंकि राष्ट्र के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के सारे आयोजन इसी पर निर्भर करते हैं। केवल जर्मनी, जापान और इटली को छोड़कर ससार के सभी देश युद्ध-पूर्व के बराबर औद्योगिक उत्पादन करने लगे हैं और हमारा देश आगे बढ़ने की जगह पीछे ही हटता रहा है। अमरीका में तो युद्ध पूर्व स्तर से ७० प्रतिशत और अधिक उत्पादन होने लगा है। निरसन्देह यातायात की कठिनाई, कारखानों की युद्धकालीन पूट और औद्योगिक हड़तालें हमारी उन्नति में बाधक हुईं उनके कारण समय समय उत्पादन कार्य रुका है परन्तु ये सब बातें तो कुछ न कुछ अंशों में प्रत्येक देश में हुई हैं। हमारे देश में कल पुर्जों की यदि कमी थी तो साथ ही अन्य देशों में युद्ध के कारण जो नाश हुआ

उससे हमारा देश वंचित रहा । अन्य देशों की तरह हमारा देश भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकता था । देश का विभाजन और तत्जनित कठिनाइयाँ निहसन्देह एक मुख्य कारण हैं परन्तु विभाजन के पूर्व के आँकड़ों से स्पष्ट है कि युद्धकाल में भी प्रति-मनुष्य आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । इससे सिद्ध होता है कि हास के कारण राजनैतिक न होकर आर्थिक है । हमारे देश के आर्थिक ढाँचे का वर्तमान संगठन ही हमारी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है । देश के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं । इन साधनों का औद्योगिक उपयोग करने के लिए देश में पर्याप्त जनशक्ति है । यदि कोई कमी है तो केवल आर्थिक संगठन की है । जब तक यह जन-शक्ति प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करती तब तक अधिकतम उत्पादन सम्भव नहीं । श्रमिक पूर्ण उत्साह और कुशलता से सभी कार्य करेगा जब उसे यह विश्वास हो कि उसे अपने धर्म का प्रतिफल अवश्य मिल जायगा । दुर्भाग्य से देश में अभी ऐसी कोई युक्ति नहीं निकाली गई जिसे श्रमिक वर्ग में इस प्रकार का विश्वास तथा संन्योप उत्पन्न होना । इस प्रकार के विश्वास का अभाव औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है । यह तथ्य निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है:—

भारत में औद्योगिक उत्पादन

वस्तु	१९१५-१६	४६-४७	प्रतिशत हास
रूती कपड़ा (दस लाख गजों में)	४६५१	३८६३	१७
रूत (दस लाख पीडों में)	५८४	४७०	१४
इस्पात (निर्मित टन १०००)	१३३८	११६०	२१
इस्पात (कच्चा टन १०००)	१२६६	११६६	८
कोयला (टन १०००)	२६५४३	२१२१८	१३
सीमेंट (टन १०००)	२१४६	२०१६	६

वस्तु	१९४५-४६	४६-४७	प्रतिशत हास
शक्कर (हंडरवेट १०००)	१०२३०	८६६६	१५

श्रमिक वर्ग के असहयोग का हमें दूसरा सबूत हड़तालों की संख्या तथा उसके फल स्वरूप नष्ट हुए दिनों में मिलता है :—

हड़ताएँ

वर्ष	हड़ताओं की संख्या	काम करने के नष्ट हुए दिन
१९३६	४०६	४६६३
१९४०	३२२	७५७७
१९४३	७१६	२३४५
१९४४	६५८	३४७५
१९४५	८२०	४०५४
१९४६	१६२६	१२७००
१९४७	२१६६	१५८८०

श्रमिक वर्ग में जब तक सन्तोष और विश्वास उत्पन्न नहीं होता और जब तक उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी तभी वृद्धि होगी जब कृषि मगटन में आमूल परिवर्तन किए जाए। कृषि प्रणाली की ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्राकृतिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अन्य देश उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हमें भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहिले उसका हास रोकना होगा और फिर उसमें वृद्धि की जायगी। भारत सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रीय आय समिति बैठाई थी। इस समिति ने वर्तमान स्थिति का अध्ययन करके राष्ट्रीय आय बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। यहाँ समिति की रिपोर्ट पर तर्क करना वाछनीय नहीं है। यहाँ केवल कुछ सुझावों की ओर संकेत करना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी से सके।

भारत की प्रति मनुष्य आय में जो हास आरम्भ हो गया उसे रोकने के लिये निम्न कार्य आवश्यक है :—

मुद्रास्फीति वर्तमान आर्थिक मंदक का मुख्य कारण है। जबतक इस पर नियंत्रण नहीं होगा मूल्यस्तर को ऊँचे उठने से नहीं रोका जा सकता। अन्तः सरफार को जनता की अनिच्छित क्रयशक्ति 'सरलस पचेजिंग पावर' को कम करने के प्रयत्न करने चाहिये तथा साथ ही पत्र-मुद्रा की राशि भी निश्चित कर देनी चाहिये।

केवल मुद्रा सम्बन्धी मुद्धारों से ही समस्या नहीं सुलभ सकती। राजस्वनीति में भी निश्चित परिवर्तन करने होंगे। गत दस वर्षों से केन्द्रिय आय-व्ययक (बजट) में घाटा चला आ रहा है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय आय-व्ययकों को सन्तुलित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुद्रा तथा राजस्व सम्बन्धी मुद्धारों के अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि का सुसंगठित तथा दृढ़ प्रोग्राम कार्यान्वित करना चाहिये। जब तक देश में उपभोग्य वस्तुओं की कमी है कितने ही प्रयत्न किए जाएँ, प्रति मनुष्य वार्षिक आय में वृद्धि नहीं हो सकती। उत्पादन वृद्धि के हेतु प्रत्येक उद्योग में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाय जो मिन मालिकों और मजदूरों के मध्य के झगड़े निपटा सके। कुछ बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के प्रबन्ध में भूमिकों को भी शामिल किया जाय, विशेषकर राष्ट्रीय उद्योग धंधों में। प्रत्येक उद्योग-धंधों में विशेषज्ञों और कलागुशल व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए जो उस उद्योग की उत्पादन वृद्धि की योजनाएँ बनाती रहे तथा उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में मार्गदर्शन कराती रहे। विदेशों से पूँजीगत माल मगाने की एक योजना तैयार करनी चाहिए तथा यह जनि करनी चाहिए कि अमेरिका और इंग्लैण्ड को छोड़ कर हम छोटे देशों जैसे ग्रीडन, स्विटजरलैण्ड, जापान, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि में कौन-कौन सी मशीन, कल-पुर्जे मँगवा सकते हैं।

उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ हमें वितरण की वर्तमान विषमताओं को दूर करना है तथा बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का इस प्रकार से वितरण करना होगा जिससे उद्योग, व्यक्ति, स्थान किसी भी दृष्टि से विषमता उत्पन्न न हो। १९४७-४८ में कुल राष्ट्रीय आय का ५६.२ प्रतिशत भाग कृषि इत्यादि द्वारा उत्पन्न किया जाता था तथा २१.३ प्रतिशत उद्योग धंधों द्वारा। इस असन्तुलित अवस्था का अन्त तभी हो सता है जब कृषि पर से जनसंख्या का भार दूर किया जाय

और गाँवों में छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय। इसी प्रकार शहर और गाँव के मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय में बड़ी विषमता है। बम्बई के साप्ताहिक 'कॉमर्स' ने अनुमान लगाया है कि १९४७-४८ में शहर के मजदूर की औसत आय ४४३ रु० थी और गाँव में काम करने वाले मजदूर की केवल १७१ रु० थी। इस प्रकार की विषमताएँ जब तक हमारे आर्थिक जीवन में उपस्थित हैं तब तक प्रतिशत मनुष्य आय में कोई विशेष वृद्धि सम्भव नहीं है। शहर और गाँव के बीच के वर्तमान असंतुलन को केवल ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है और तभी वितरण की समस्या को मूलतः सुलझाया जा सकता है।

४१—विदेशी पूँजी का प्रश्न

देश के कोने-कोने में एक लहर सी व्याप्त है कि शीघ्रातिशीघ्र भारत का औद्योगीकरण हो। छोटे नागरिक से लेकर चोटी के नेता तक, समाज-मुधारक से लेकर राजनीतिज्ञ तक, कलाकार से लेकर अर्थशास्त्री तक 'उत्पादन बढ़ाओ' के नारे झूलन्द कर रहे हैं। परन्तु औद्योगिक विकास सम्बन्धी वृहद् योजनाओं को कार्यान्वित करने में हम पूँजी की समस्या को लेकर अटक जाते हैं। पूँजी के मुख्य स्रोत दो हैं—(१) आन्तरिक अथवा भारतीय पूँजी, (२) बाह्य अथवा विदेशी पूँजी। यद्यपि प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में आन्तरिक पूँजी घाती रही फिर भी हमारे मुख्य धंधों में विदेशी पूँजी का ही विशिष्ट स्थान रहा है। यदि देखा जाय तो विदेशी पूँजी के इतिहास से हमारे देश का गत डेढ़ सौ वर्ष का इतिहास बधा हुआ है। विदेशी शासकों (अंगरेजों) ने भारत को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही परतन्त्र नहीं बनाया परन्तु उन्होंने इसे आर्थिक शोषण का क्षेत्र बनाए रखवा। प्रारम्भ में लगभग ७० वर्षों तक भारत से कच्चा माल इंग्लैण्ड के कारखानों के लिए रीन्या गया और पक्का माल भारत के बाजारों में लाकर बेचा गया। इस दुहरे शोषण के क्रम में विदेशी पूँजी का पूरा हाथ था और सरकार का उसे पूर्ण प्रोत्साहन और संरक्षण मिला हुआ था। धीरे-धीरे भारत में ही विदेशी पूँजी के आधार पर नए उद्योग-धंधे आरम्भ किए गए। देश की पूँजी को 'अपर्याप्त' तथा 'संकुचित' कह कर भविष्य में भी अनन्त काल तक देश का शोषण करने की भावना में विदेशी पूँजी का देश में विनियोग किया जाता रहा। विशाल कारखाने, निर्माणियाँ, बैंक, बीमा कंपनियाँ आदि संस्थाएँ विदेशी पूँजी से स्थापित की जाती रहीं। रेल, कोयले, चाय, कहवा, रबड़, कपास, पटसन इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी अतुल मात्रा में लगाई गई। इन उद्योगों के द्वारा करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष औद्योगिक लाभ के रूप में इंग्लैण्ड और अन्य देशों को जाता रहा। यही नहीं, विदेशी पूँजी द्वारा संगठित तथा विदेशी सरकार द्वारा संरक्षित उद्योगों के कारण राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में काफी बाधा

आई। अनुल पूँजी, उत्तम संगठन तथा सरकारी सरक्षण के कारण वे सदा ही शक्तिशाली रहे और स्थानीय उद्योगों से प्रतियोगिता करते रहे। इस विषय में आरम्भ से ही भारतीया का विरोध रहा और राष्ट्रीयता की आग फुँकते ही यह विरोधी भावना और भी प्रबल होती गई। १९२१-२२ में इस प्रश्न को सरकारी तौर से 'फिसनल कमीशन' को सौंप दिया गया। १९२५ में फिर विदेशी पूँजी के प्रति नीति-निर्धारण के लिए सरकार ने एक विदेशी पूँजी समिति स्थापित की। इस समिति के भारतीय सदस्यों ने अपनी सम्मति प्रकट की कि भारतीय उद्योग धंधों का विकास विदेशी पूँजी की अपेक्षा भारतीय पूँजी के द्वारा ही किया जाय। भारत को विदेशी पूँजी के इतने कटु अनुभव रहे कि देश में पूँजी की कमी होते हुए भी सनाहकार योजना बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था "श्रौद्योगीकरण के लिए देश में ही पूँजी प्राप्त हो सकेगी और उद्योग धंधों का संचालन के लिए विदेशी पूँजी की प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता नष्ट होगी। निस्सन्देह श्रौद्योगिक कुशल कारीगरों की ओर पूँजीगत मान की आवश्यकता होगी परन्तु उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त विदेशी पूँजी को स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेशी पूँजी के एक बार जम जाने पर उसे उखाड़ना पड़ित हो जाता है।"^१ इन ऐतिहासिक कारणों के अतिरिक्त विदेशी पूँजी के विरुद्ध कुछ सैद्धान्तिक कारण भी रहे हैं।

हमारे देश में विदेशी पूँजी एक भारी सख्या में लगी हुई है। १९३० में 'इकॉनॉमिस्ट' नामक पत्र ने अनुमान लगाया था कि भारत में अंगरेजी पूँजी का मूल्य ७०० करोड़ पौण्ड था। १९३३ में ब्रिटिश एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत में अंगरेजी पूँजी १००० करोड़ पौण्ड आंकी थी जो इंग्लैण्ड की विदेशों में विनियोगित पूँजी का लगभग एक चौथाई था। श्री बा० आर० शेनाय महोदय के अनुसार मार्च १९४५ में भारत स्थित विदेशी पूँजी २२७५ मिलियन पौण्ड के लगभग थी जो किंचित अतिशयोक्ति से मुक्त नहीं है क्योंकि इस अनुमान में विदेशी हाथों से भारतीय हाथों में स्थानान्तरित होने वाले व्यापारों का लेखा नहीं लगाया गया था। हम जानते हैं कि सन् १९३६ से

^१ एंडर्राजरी प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट—१९४७ पृ० स० १७ १८

भारत स्थित विविध उद्योगों का भारतीयकरण होना आरम्भ हो गया था और जैसे-जैसे बुद्ध तीव्रातितीव्र होता गया वैसे-वैसे उसकी गति में भी प्रगति आती गई यहाँ तक कि सत्ता हस्तान्तरित होने के साथ ही विदेशियों ने अपने को भारतीय उद्योग क्षेत्र से मुक्त करना चाहा और उन्होंने उनको अपने-पूँजे भागों पर विजय भी कर दिया। बम्बई के कपास मिल, कलकत्ते तथा निकटवर्ती प्रदेश की जूट मिलें भारतीयों के हाथों में आ गईं। परन्तु यह कहना सर्वथा न्याय संगत है कि देश में विदेशी पूँजी काफ़ी बड़े परिमाण में विद्यमान है। यद्यपि अब भारतीय पूँजी उत्तरोत्तर निडर होती जा रही है तो भी बक, जलपान, रेल, बीमा, चाय, कढ़वा, गान इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी का प्राधान्य एवं मोतबाना है।

विदेशी पूँजी भारत में निम्न भिन्न-भिन्न रूपों में आई है और विद्यमान है :—

(अ) विदेशियों ने भारत के व्यापार तथा उद्योग प्रमदनों के हिस्से गरीद रंगे हैं या प्राण-पत्र ले लिये हैं जिनके अनुसार हिस्से पर लाभदा और प्राण पत्रों पर वृद्धि देश से बाहर जाती रहती है। इतना ही नहीं विदेशी हिस्सेदारों के हिस्से इतनी अधिक नग्या में हैं कि उनकी अधिकता के कारण प्रमदनों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध भी लगभग विदेशियों के हाथ में आ गया है। जैसे 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' में अधिकांश हिस्से विदेशियों के ही हैं।

(ब) विदेशी धनपतियों ने भारत निवासियों को अल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन ऋण दे रंगे हैं जिसके द्वारा विदेशी पूँजी भारत में आ गई है। भारतनिवासियों ने इसी धन राशि से उद्योग चला रंगे हैं और विदेशी पूँजी पर वृद्धि विदेशों को चली जा रही है।

(क) विदेशियों ने अपनी पूँजी में हमारे देश में या तो अचल सम्पत्ति गरीद ली है और या अपने ही स्वामित्व में या भारतीयों की साभेदारी में व्यापार और उद्योग धंधे चला रंगे हैं जिनका पूर्ण प्रबन्ध, मंचाजन तथा नियंत्रण विदेशियों के ही हाथ में है, जैसे बॉयले की गानें, चाय के बाग। 'ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन' भी विदेशी पूँजी का ही उद्योग समूह है।

विदेशी सरकारों ने भारत सरकार को भी कुछ धन राशि उधार दे रखी है जिससे विदेशी पूँजी ने हमारे देश में स्थान पा लिया है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय दल बन्दी और पिछले इतिहास के कटु अनुभवों के बावजूद भी देश को अब विदेशी पूँजी की आवश्यकता है। उत्पादन की कमी, बढ़ती हुई जनसंख्या, लाघान के वितरण में असामाजिक तरीकों का उपयोग इत्यादि के कारण राज्य सामग्री एवं पूँजीगत माल दोनों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। देश को स्वावलम्बी तथा बलिष्ठ बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए 'कृषि के यन्त्रकरण' और 'देश के औद्योगीकरण' की योजनाएँ देश के सामने विशाल रूप लेकर खड़ी हुई हैं। इस काम के लिए देश को कितनी पूँजी की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि पूँजी सम्बन्धी आवश्यकता निश्चित योजनाओं, उनको कार्यान्वित करने की गति तथा वर्तमान और भविष्य में होने वाली देश की आर्थिक क्षमता इत्यादि पर निर्भर करती है। ये सभी बातें अनिश्चित हैं। अतः कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी योजना कमिशन ने अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए १७६३ करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इतनी बड़ी राशि एक साथ ही हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमें विदेशों पर आश्रित रहना ही होगा। दूसरे, युद्धकालीन और युद्धोत्तर कालीन आर्थिक परिस्थितियों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि देश में पूँजी निर्माण की गति सन्तोषजनक नहीं है। किसी भी देश के मध्य वर्ग के द्वारा ही सब से अधिक पूँजी निर्मित होती है परन्तु बढ़ते हुए मूल्यस्तर और ऊँचे निर्वाह-व्यय के कारण मध्य वर्ग सचय तो क्या करता, निर्वाह-व्यय चलाता रहा है, यही उसके लिए श्रेय की बात है। युद्धकाल में जो कुछ संचय हुआ वह असाधारण आर्थिक स्थिति के कारण ही हो पाया है। वास्तव में साधारण अर्थ व्यवस्था में उस प्रकार का संचय सम्भव ही नहीं है। कृषक वर्ग ने या तो अपना कर्ज चुकाया है या जो कुछ भी वह बचा सका, उसे सोने चांदी के जेवरों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जहाँ तक धनी वर्ग का सम्बन्ध है, उसके बारे में अनेक

सन्दिग्ध बातें हैं। जिन्होंने ईमानदारी से कहा था और दिखाव रखा, उनके लाभ का बहुत बड़ा अंश आया-कर या व्यापार-कर के रूप में निकल गया। अतः उनके मन्वय की दर अधिक नहीं रही। जिन्होंने असामाजिक रीतियों से धन कमाया वे अपने संचित धन को दबाकर बैठे हैं जिससे राशि डॉ० पट्टाभ मोतारमैया ने लगभग १०० करोड़ रुपये के बताई भी। यह दबाया हुआ धन मुले आम बाजार में नहीं आ सकता। उक्त कारणों से पूँजी-बाजार की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी व्यय-व्यय भी अधिक नहीं जारी जाये और अनेक प्रान्तीय सरकार पूँजी जुटाने में अपने को असमर्थ पा रही हैं।

कुछ समय के लिए यदि यह मान भी लें कि पूँजी की आवश्यकता हमारे देश में हो पूरी हो जायगी तो भी मशीन, कल-पुर्जों और कलाविदा और वैज्ञानिकों की आवश्यकता देश में पूरी नहीं हो सकती। हमारे देश में मशीन और कल-पुर्जें बनाने के उद्योग नहीं के बराबर हैं। अनेक कारणों से अब तक उद्योगीय पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग-धंधे ही आगे बढ़ पाये हैं। बुनियादी उद्योग-धंधों की अब तक निम्न अर्थदलना की गई है। फलतः भारत मशीन और कल-पुर्जों के लिए आज भी और कम से कम आगामी पंच वर्षों तक विदेशों पर निर्भर रहेगा। उदाहरण के लिए सिंचाई के साधन, जल-विद्युत् उत्पन्न करने की मशीनें, कृत्रिम तान बनाने के यंत्र, ट्रेक्टर, सड़क चुटने के रोलर, यातायात सम्बन्धी इंजन, मशीनें और कल-पुर्जें इत्यादि विदेश से ही मँगाने पड़ते हैं। केवल मशीन और कल-पुर्जें मँगाने से ही हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो जायगी। हमारे यहाँ औद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा की कमी के कारण कुशल प्रबंधकों एवं भूमिकों की बहुत कमी है, विशेषज्ञ तो वास्तव में नाममात्र की ही हैं। लगभग चार वर्ष पूर्व भारत सरकार ने भी पॉर्ड, बेसन, डेविस आदी की विशेषज्ञों द्वारा औद्योगिक शिक्षा का पर्यवेक्षण कराया था। इन विशेषज्ञों के निम्न निष्कर्ष थे :—

(१) भारत में इंजीनियरी और कुशल औद्योगिक प्रबंधकों की निम्न कमी है। उद्योग-धंधों के प्रारम्भिक आयोजन में लेकर साधारण क्रियाओं तक के लिए कुशल कलाविदों की आवश्यकता है।

(२) कुशल भूमिकों के अभाव के कारण भूमिकों की कार्यक्षमता और काम करने की गति अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है।

(३) यन्त्र, बिजली से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार के कलपुर्जों की कमी और कलाकौशल सबकी शिक्षण संस्थाओं की कमी देश के औद्योगीकरण के मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई है।

देश ने औद्योगीकरण में तीन प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी:— विशेषज्ञ, प्रबंधक और कुशल भूमिक। प्रत्येक अवस्था में हमें पहले दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होगा। तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी हमें कुछ अंशों में विदेशों से सहायता लेनी होगी। केवल कुशल भूमिकों की ट्रेनिंग देने के लिए ही हमें नितने प्रयत्न करने की आवश्यकता है, यह टेक्नीकल सहायकार समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भ में प्रति वर्ष १६,००० कुशल भूमिकों की आवश्यकता होगी जिनके लिये लगभग ३२,००० स्थानों (सीट्स) का प्रबंध करना होगा।

ग्राह्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भरता, पिनास योजनाओं के लिए पूँजी की आवश्यकता तथा मर्चान्त और कलपुर्जों और कलाविदों की कमी के कारण भारत को विदेशी पूँजी की सहायता लेनी ही होगी। यह आवश्यकता आर्थिक इतिहास की दृष्टि से कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत, फ्रांस, इटली तथा दक्षिणी अमरीका के औद्योगिक विकास खासकर रेल यातायात के विकास के इतिहास से स्पष्ट है कि किसी भी देश को जब पूँजीगत माल की जरूरत होती है तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश से उद्धार ग्रहण करना होता है। इस प्रकार पूँजी तथा पूँजीगत माल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

“Thus the two types of exports of capital goods and of capital funds were closely interrelated even in those cases where the sale of goods for export did not precede the granting of loans or was not anticipated at the time...movements of capital funds and of capital goods were inter-dependent.” इस उदाहरण से

स्पष्ट है कि यदि हम औद्योगीकरण करना है तो हमें विदेशों से मशीन और कलपुर्जे मँगाने होंगे और यदि मशीन, कलपुर्जे मँगाने हैं तो विदेशी पूँजी का सहारा लेना होगा ।

भारत सरकार की नवीन नीति^१

विदेशी पूँजी सम्बन्धी सरकार की नीति की घोषणा करते समय पं० नेहरू ने कहा कि अभी तक देश की राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम विदेशी पूँजी के नियन्त्रण और नियमन पर जोर देते आ रहे हैं । परन्तु अब देश की परिस्थिति बदल चुकी है । अतः विदेशी पूँजी का देश के हित में लाभकारी उपयोग ही अब नियमन का उद्देश्य होना चाहिये । पं० नेहरू ने स्वीकार किया कि विदेशी पूँजी की केवल इसीलिए आवश्यकता नहीं है कि देश में पूँजी संकट कम हो रहा है, परन्तु इसके अतिरिक्त हमें विदेशों से मशीन, कल-पुर्जे और औद्योगिक कलाविदों की भी आवश्यकता है जो केवल विदेशी पूँजी के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं । अतः सरकार ने विश्वास दिलाया है कि ब्रिटिश अथवा अन्य विदेशी पूँजी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायी जायगी । सरकारी नीति को हम मुख्य चार भागों में बाँट सकते हैं :—

(१) वर्तमान उपयोग-धर्मों में लगी हुई विदेशी पूँजी पर सरकार कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगायेगी जो भारतीय उपयोगों पर लागू न हो । अर्थात् वर्तमान विदेशी पूँजी और भारतीय पूँजी में सरकार कोई भेद भाव नहीं करेगी । भविष्य में भी सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी जिससे वारंवारिक लाभ के आधार पर विदेशी पूँजी भारत में आ सके । परन्तु इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रकार की पूँजी—भारतीय अथवा विदेशी—को सरकार की औद्योगिक नीति स्वीकार करनी होगी और उसी के अनुसार चलना होगा ।

(२) विदेशी पूँजी देश में लाभ कमा सकेगी और साधारणतः विदेश को लाभ भेजने पर भी कोई रोक नहीं लगाई जायगी परन्तु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी ।

^१ ६ अप्रैल १९४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित

यदि किसी विदेशी पूँजी के उद्योग को सरकार हस्तान्तरित करेगी तो सरकार उचित हानिपूर्वक देगी।

(३) साधारणतः उद्योग धर्मों के स्वामित्व और प्रबन्ध में भारतीय नागरिकों का मुख्य हाथ होगा और असाधारण अस्थिति में सरकार विशेषाधिकार के अन्तर्गत राष्ट्र हित की दृष्टि से किसी भी उद्योग को हस्तान्तरित अथवा नियन्त्रित कर सकती है। यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई बड़ा अपवाद निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि एक निश्चित काल के लिए विदेशी पूँजी का किसी उद्योग विशेष पर राष्ट्र हित में स्वामित्व आवश्यक समझा गया तो सरकार इसने लिए आज्ञा प्रदान करेगी, प्रत्येक मामले पर राष्ट्र हित की दृष्टि से ही विचार किया जायगा। यदि आवश्यक योग्यता के भारतीय भूमिक न मिलें तो विदेशी कारखाने विदेशियों का नौकरी दे सकते हैं, परन्तु साथ ही साथ ऐसे कार्यों के लिए इन कारखानों को कुशल भारतीय भूमिक और कलाविद तैयार करने होंगे।

(४) भारतीय उद्योग धर्मों को प्रोत्साहन देना, भारत सरकार की निश्चित नीति है। परन्तु आज भी और भाविष्य में भी देश के औद्योगीकरण में ब्रिटिश पूँजी के लिए बहुत क्षेत्र रहेगा।

भारत सरकार की इस नीति से विदेशी पूँजी के विषय में जो अनेक भ्रमात्मक तथा सदिग्ध बातें थीं, वे अब दूर होती जा रही हैं और विदेशी पूँजीपतियों में प्रकार प्रकार के जो भय पैले हुए थे वे अब समाप्त होते जा रहे हैं। शनैः शनैः विदेशी पूँजी देशी पूँजी के साथ सामेदारी में आने लगी है। विदेशी पूँजी देश में भिन्न भिन्न प्रकार से लाई जा सकती है। या तो विदेशी स्वयं लावे, भारतीय विदेशों से ऋण लें या सरकार ही विदेशी सरकार या अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण ले। कैसे भी हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे “पूँजी आवे परन्तु पूँजीवाद न आवे।” इसके लिए ऋणों द्वारा या सामेदारी में विदेशी पूँजी लेना हितकर होगा। परन्तु भारतीयों के द्वारा विदेशी ऋण लेने के भूतकाल में बड़े दुष्प्रसिद्धि हुए हैं। अधिक वृद्धि दर पर ऋण मिले हैं और या तो व्यक्तियों ने अपने अपने लक्ष्यों पर ऋण लेकर उन्हें उत्पादन कार्य में न लगाकर अन्य किसी प्रकार नष्ट कर दिया है और यदि उत्पादन कार्य में लगाया

भी है तो उनके पास समुचित योजना न होने के कारण उस पूँजी का सुयोग्य प्रयोग न हो सका है। इसलिए सरकार को ही विदेशी पूँजी लाकर देश में वितरित करनी चाहिए। इस कार्य के लिए सरकार को एक "राष्ट्रीय-विनियोग समिति" की स्थापना करनी चाहिए। यह समिति देश में उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक विदेशी पूँजी, विदेशी सरकार से या विदेशी जनता से उधार ले और फिर उसको देश की आवश्यकतानुसार देशी व्यापारियों या उद्योग-पतियों को उत्पादन वृद्धि के लिए बाँट दे और इस बात का निरीक्षण रहे कि यह राशि प्रस्ताविक कार्य में ही लगायी जा रही है या नहीं। इस योजना से विदेशी पूँजी का सदुपयोग होगा, पूँजी कम वृद्धि पर मिलेगी और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। साथ ही साथ उसके भुगतान का भी प्रबन्ध रहेगा जिससे विदेशी पूँजी के ढूँढ़ने की आशंका नहीं रहेगी। समिति का यह कर्तव्य होगा कि देश की आवश्यकताओं को सही-सही समझे और तभी पूँजी उधार ले।

इस योजना के अनुसार कार्य और भी सरल होगा। विश्व बैंक की स्थापना से इस काम में भारी सुविधाएँ आगई हैं। यह बैंक सदस्य देशों की सरकारों को या सरकारों की गारंटी पर अन्य संस्थाओं को ऋण देता है। भारत सरकार ने इस बैंक से तीन ऋण ले लिए हैं और चौथा ऋण भी मिलने वाला है। इस प्रकार विदेशी पूँजी शनैः शनैः आती जा रही है। भारत विदेशी पूँजी से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। देश को उन्नत बनाने में विदेशी पूँजी की अनिवार्य आवश्यकता है। परन्तु केवल यही ध्यान रखना है कि कहीं इतिहास फिर न दोहरा जाय। कहीं विदेशी पूँजी के साथ-साथ विदेशी सत्ता न आ जाय। पूँजी का सदुपयोग हो। विदेशी पूँजी आवे परन्तु पूँजीपति न आने पावें।



४२—पूँजी-निर्माण का प्रश्न

किसी भी अर्विकसित देश को सदैव यह मान कर चलना पड़ता है कि वहाँ आर्थिक विकास के अनेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कच्चा माल, एनिज पदार्थ, विद्युत शक्ति और धन आदि अनेकानेक साधन इतनी प्रचुरता में उपलब्ध हैं कि कुशल साधक के अभाव में उनका आवश्यक विदोहन नहीं हो पाता। यहाँ कुशल साधक का अर्थ केवल एक निपुण प्रबन्धक से ही नहीं है, वरन् एक ऐसे प्रबन्धक से प्रयोजन है जो आवश्यक पूँजी लगाकर उच्च बिरतरे साधनों का उपयोग कर सके, उनका विदोहन कर सके तथा देश को समृद्धिशाली बना सके। निष्कर्ष यह है कि देश को मुज़ी, सम्पन्न और समृद्धिशाली बनाने के लिए पर्याप्त पूँजी की बहुत आवश्यकता है। यह तो मतभेद हो सकता है कि पूँजी होने पर ही देश समृद्धिशाली हो सकता है या पूँजी केवल समृद्धिशाली देश में ही मिल सकती है। किन्तु किसी भी प्रकार का निश्चय कर लिया जाय, पूँजी की समस्या सदा हमारे देश में बनी रहती है। पूँजी की समस्या का मूल आधार पूँजी निर्माण की समस्या है। जब तक किसी वस्तु का निर्माण ही न हो तो उस वस्तु की समस्या कैसे बन सकती है। अतः पहिली समस्या वस्तु की नहीं वरन् वस्तु निर्माण की है—पूँजी की नहीं वरन् पूँजी निर्माण की है।

पूँजी-निर्माण के लिए धन-संचय की परम व प्रमुख आवश्यकता होती है। यदि धन-संचय ही न किया जाय तो पूँजी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसे उद्योग-धंधों में कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए धन-संचय कब और कैसे सम्भव होता है—यह सोचना आवश्यक है। सामान्यतः वह निम्न बातों पर निर्भर होता है :—

- (१) संचय की योग्यता (क्षमता),
- (२) संचय की इच्छा,
- (३) संचित धन को पूँजी के रूप में उपयोग करने के साधन।

संचय करने की योग्यता में अर्थ यह है कि लोगों की आय और व्यय में कितना अन्तर है। यदि व्यय में आय अधिक है तो अवश्य ही उस अन्तर तक संचय करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में है किन्तु यदि व्यय इतना है कि आय पूरी नहीं पड़ती तो संचय करने की योग्यता तो छोड़िए अयोग्यता पर करने लगती है। अतः जिस व्यक्ति की आय उसके व्यय में कम है वह अपनी वर्तमान आय पर ही नहीं पर संचित राशि पर रहने लगता है अन्यथा दूसरों से श्रृण लेकर अमी बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति में संचय करने की योग्यता भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह संचय कर ही लेगा। इसके लिए उसकी इच्छा का बलवती होना भी आवश्यक है। किसी व्यक्ति की धन संचय करने की इच्छा कई बातों पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से अपनी मतानय सम्बन्धियों के प्रति प्रेम, समाज में सम्मान पाने का भावना तथा उसका आदत साथ पर्याप्त इच्छा का काम करती है।

धन संचय की क्षमता और इच्छा दोनों होने पर भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन हो ही जायगा। यदि दिन-दहाड़े देश में हाकें डाले जाते हों, चोरी की जाती हों तथा दिए हुए धन की वापस प्राप्त करने की न्यायालयों द्वारा कोई सुविधा न हो तो भला कोई धन-संचय करके मिर दंड क्यों मोल लेगा? यदि धन की सुरक्षा के बारे में सुविधाएँ भी हों तो भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह धन पूँजी का रूप ले चुका है और उपलब्ध नामों में उसका उपयोग हो रहा है। जब तक उपयोग करने के साधन न हो जब तक सचा पूँजी-विनियोग सम्भव नहीं हो सकता। इसके लिए बैंकों की आवश्यकता होती है तथा सड़-बड़े उद्योगों की आवश्यकता होती है जहाँ संचित-धन का सदुपयोग किया जा सके। जब धन का आर्थिक रूप में सदुपयोग होने लगता है तब ही उसे पूँजी कहते हैं और यही है पूँजी निर्माण की समस्या निकलती है।

अनेक अर्थशास्त्री आज इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि हमारे देश में पूँजी-निर्माण की गति धीमी है और पूँजी आवश्यकता में बहुत कम है। पूँजी-निर्माण की गति राष्ट्र की उप्रति या अग्रगति पर निर्भर होती है। या यों कहिये

कि राष्ट्रीय आय पर निर्भर होती है। भारत जैसे प्रजातन्त्रवादी देश में पूँजी जम्मा करने के साम्यवादी सिद्धान्तों को लागू करना तो वैसे ही सम्भव नहीं है इसलिए जो कुछ यहाँ की बचत है या संचय करने की क्षमता है उसी से पूँजी-निर्माण हो सकता है। इस बारे में 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ नैशनल मिस्ट' नामक साप्ताहिक पत्र ने दो वर्ष पूर्व सारे देश को विस्मय में डाल दिया था यह कहकर कि "वास्तव में हम बचत या पूँजी बना नहीं रहे हैं बल्कि समूचा राष्ट्र अपनी संचित-राशि पर ही जीवित रहने लग गया है।" यह समझने की बात है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे यहाँ के बैंकों में जमा किया हुआ धन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है यहाँ तक कि १९४८ में बैंकों में जमा राशि में से १२ करोड़ रुपये वापिस निकाले गए और १९४९ में निकाले जाने वाली राशि की मात्रा इतनी बढ़ी कि बैंकों ने १०४ करोड़ रुपये तक जा पहुँचे। यही नहीं, बड़े बड़े उद्योगों के अनेक अंशों के मूल्य भी गत वर्षों में बहुत नीचे गिर गए। अंशों के मूल्य १९४६ में शिखर पर थे तत्पश्चात् पूँजी निर्माण के अभाव में गिरने लगे। निम्न तालिका से इस बात की पुष्टि होती है :—

	२० जून १९४६	२० जून १९४८
टाटा डेपॉजिट	३६४०	११५२
बम्बई डेपॉजिट	३२७७	९२३
ए० सी० सी०	२७७	१९८
विमको	७६७	१५०
सेण्ट्रल बैंक	१६२	७५

इसी प्रकार देश में नव-निर्मित बड़े उद्योगों की स्वीकृत पूँजी भी उत्तरोत्तर कम होने लगी। सन् १९४६ में यह पूँजी २३९ करोड़ रुपये थी किन्तु सन् १९४७ व सन् १९४८ में यह पूँजी क्रमशः १९८ करोड़ व ११७ करोड़ रुपये ही रह गई। सन् १९४९ के आँकड़े इनसे भी अधिक निराशाजनक हैं।

इन उक्त बातों और आँकड़ों से सारांश यह निकलता है कि राष्ट्र की वर्तमान बचत शक्ति बिल्कुल नहीं है और जो कुछ पहले था भी वह बड़ी द्रुतगति

के साथ न्यून होनी जा रही है। इसके कारणों के बारे में हम आगे के स्तम्भ में विचार करेंगे।

वर्तमान आवश्यकता :—वर्तमान पृथ्वी निर्माण के बारे में सोच लेने के पश्चात् हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में तनिक विचार कर लेना है। हमारी कुल वार्षिक बचत कितनी होनी चाहिए ? यह प्रश्न जैसे तो बड़ा जटिल है किन्तु इसका लगभग अन्दाज लगा लेना अधिक कठिन नहीं। बम्बई योजना के अनुसार साधारण गणित के आधार पर यह धन लगभग ७०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। दूसरा धी कोलिन क्लार्क नामक विद्वान् का मत है कि यह धन १००० करोड़ रुपये होना चाहिए। इस बारे में श्री भी अनेक मतभेद हैं किन्तु सर्व मान्य मतानुसार यह धन हम ५०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष मान सकते हैं।

वैसे तो प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय के बारे में कोई सरकारी व पूर्ण-तया मान्य आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु मध्यम योजना के अनुसार यह आय ₹५५) या जो आँकड़े के स्तर पर लगभग ₹८०) होती है। दूसरी ओर सन् १९४६ में 'ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट' (Eastern Economist) के अनुसार शहरों में काम करने वालों की वार्षिक आय ₹८५) तथा गाँवों में काम करने वालों की वार्षिक आय ₹८८) थी। यदि हम ₹८०) वार्षिक आय के अनुसार भी लें तो हमारी कुल राष्ट्रीय आय लगभग ५५०० करोड़ रुपये होती है, यदि हमारी वर्तमान जनसंख्या ३६ करोड़ हो। उक्त आय में से प्रत्येक व्यक्ति यदि लगभग १०% आय बचाने लगे तब करीब ५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। किन्तु इतनी कम वार्षिक आय में से इतनी अधिक बचत की आशा रखना मर्यादा निर्धारक है। हम और अधिक से अधिक २% की बचत १०० करोड़ रुपये की ही आशा की जा सकती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आय में से हो सके वाला पैसा-निर्माण निश्चित रूप से अपर्याप्त है।

अप्याप्त पूजा-निर्माण के कारण :—अप्याप्त पूजा-निर्माण का कारण कम आय भी है, विन्तु भक्तोपवनक आय होने पर सुख भन भजन भी हो।

जाता है जैसा कि भारतवर्ष में हुआ है। इतना होते हुए भी मन्विन धन पूँजी के रूप में नहीं आ सकता है और पूँजी निर्माण इस प्रकार अशभव हो जाता है। इस देश में पूँजी निर्माण न हो सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(१) भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इतनी कम है कि धन संचय की योग्यता लगभग नहीं के बराबर है।

(२) युद्धकाल में कमाने हुए धन का औद्योगिक दृष्टि से पूँजी-निर्माण नहीं हो सका क्योंकि कमाने वालों ने उस धन से सोने-चांदी के जेवर बनवाये और करोड़ों रुपये मकानों आदि अचन सम्पत्ति पर व्यय कर दिए।

(३) उद्योग धंधों के शेयरों में पूँजी लगाना धीरे-धीरे बन्द होने लगा क्योंकि औद्योगिक संस्थाओं के वार्षिक लाभ पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए। सर पदमवति सिंघानिया के इस वक्तव्य में बहुत कुछ सचार्ड जान पड़ती है जो इन्होंने हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक की पँचवीं वार्षिक बैठक में ११ जून सन् १९४८ में दिया कि पिछले दस वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय मुद्रिफन से १०० प्रतिशत बढ़ी है परन्तु सीधे करों की वृद्धि ८००% हो गई है। कुछ करों की छूट मिलने पर भी इनका बोझ वार्षिक आय कर इतना पड़ता है कि लोग औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों को खरीदने में निराशा दिखाने लगे हैं।

(४) कुछ सरकारी नीतियाँ ऐसी रहीं हैं जिनने प्रभाव ऐसा पड़ा कि देश में कुछ विद्वानों के अनुसार 'पूँजी की हड़ताल' हो गई। बड़े उद्योगों के बारे में सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति ने इस ओर बढ़ा बुरा प्रभाव डाला। वास्तव में राष्ट्रीयकरण हो जाना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है पर इस बारे में बरती गई अनिश्चितता सबसे हानिप्रद सिद्ध हुई है। यदि सरकार को महंगाी तथा नरम नीति, जो बाद में प्रकट हुई, पहले ही स्पष्ट कर दी जाती तो पूँजी-निर्माण में बहुत कुछ सहयोग मिल जाता।

(५) युद्ध काल में अनेक व्यापारियों ने सट्टेबाजी, काले बाजार, रिश्वत खोरी तथा अन्य निंदनीय मार्गों से पैसा कमाया था। इसलिए वे अपने पैसों

की पूँजी के रूप में लगाने में सदा दिव्यकने रों अन्यथा उन पर कुछ दृष्टिगणना मोव दिया जाय ।

(६) बहुत दिनों तक औद्योगिक संस्थाओं में मुनाफा बढ़ने की दर ६% ही रही । यह आय बहुत कम समझी गई ।

(७) युद्ध काल में आय का बंटवारा उसे धीरे बंटवारे लगा । प्रत्यक्ष वर्ग की मनवा में आय इटकर कृषकों तथा श्रमिकों की जेबों में जाने लगी । यह वर्ग स्वभारतः ही अधिक खर्चीला रहा आतः पूँजी नहीं बना सका । यदि थोड़ा बहुत धन भंडार भी हुआ तो उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन नहीं हो सका ।

(८) देश के विभाजन के कारण करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई तथा करोड़ों रुपये का घाटा स्ट्राक-वर्कमें हो कर आ गया ।

इस प्रकार ऐसे अनेक कारणों से देश में पूँजी निर्माण नहीं हो सका । इस बारे में मुख्यतः हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए । प्रथम तो यह कि देश की प्रति व्यक्ति आय सदा से इतनी कम रही है कि साधारण व्यक्ति पूँजी बढ़ाने में अपनी शक्ति का कौंसे टोम खर्च नहीं दे सकता । दूसरी यह कि यदि किसी व्यक्ति या वर्ग-संयोग की आय में वृद्धि हो भी गई तो वह सरकारी बंदोबस्त-मन्थारा नीतियों की अनिश्चितता के कारण से अपनी खर्च आय को पूँजी के रूप में लगाने के बजाय जमा करना ही उचित समझने लगे । तीसरी यह कि इन वर्गों में कुछ कृषकों और श्रमिकों का आय में काफी वृद्धि भी हुई और उसका पूँजी के रूप में उपयोग करने की उनकी इच्छा होने हुए भी वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनमें आवश्यक विश्वास भरने वाला प्रचार नहीं हो सका ।

भविष्य के लिए सुझाव — कुछ टोम सुझाव रखने के पहले हम दो विशेष बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए जो वास्तव में हमारे सुझावों के उद्देश्य हैं । इन्हीं दो बातों को दृष्टिगत रख हमें सुझाव देने चाहिए । यह सुझाव दो बातें इस प्रकार हैं :—

(अ) देश में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय कैसे बढ़ाई जाय ? हमें शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय-आय में वृद्धि की जाय ।

(ब) बढ़ती आय को संचय करने की शिक्षा दी जाय तथा उसको पूँजी

रूप में लगाने के अनेक तथा भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध किये जाएँ।

उच्च दो बातों का ध्यान में रखते हुए पूँजी निर्माण के लिए निम्नान्वित सुझाव दिए जा रहे हैं —

(१) देश में ८०% जन संख्या कृषि पर जीवन यापन करती है इसलिए सर्व प्रथम हमारा ध्यान कृषकों का आर हो आकर्षित होना चाहिए। उन्हें केवल पिजूल-खर्च से ही नहीं बचाना है बल्कि उनकी अन्य आदतों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। केवल धन को संचय करने रखने की उनका आदत पर शिक्षा व शस्त्र से आक्रमण करना चाहिए। यह तो सत्य है कि स्वभाव सरलता से जाना नहीं है किन्तु यदि उचित प्रयत्न किए जाएँ तो इस ओर सफलता भिन्न सक्ती है। कई बार देखा गया है कि कृषकों के गाड़े हुए नोटा में दामक लग गई थी। क्या यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का व्यर्थ नाश नहीं है? यद्यपि बहुत ही निकट भविष्य में अधिक सरलता न मिल सके किन्तु फिर भी यदि सरकार चाहे तो इस ओर बहुत कुछ कर सकती है।

(२) अमिश्र वर्ग की सम्पत्ति यद्यपि सीमित है किन्तु उन्हें कम मूल्यों के शेयर आदि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(३) मध्यम श्रेणी की आर्थिक स्थिति इन दिनों बड़ी चिन्तनीय है, किन्तु पूँजी लगाने वालों का अधिक सख्या भी इसी वर्ग में है। इसलिए व्यापार आदि के स्थानीय तथा प्रांतीय बंधन हटाकर मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को ठोकर देने का अदृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। इस मध्यम श्रेणी के लोगों की वार्षिक आय वृद्धि के लिए यदि सरकार को कोई काम भी हटाने पड़े तो ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि यही वर्ग हमारे समाज का मतुलन बनाए रखता है।

(४) बड़े बड़े उद्योगों का बढावा दिया जाना चाहिए। विशेष सुविधाएँ देकर उत्पादन वृद्धि करानी चाहिए तथा कुछ करों की छूट भी आवश्यक है, यदि पूँजी लगाने वालों में बड़े उद्योगों के प्रति विश्वास जगाना है।

(५) गाँवों में सहकारी बैंकों की स्थापना की जाय तथा नई शाखाएँ खोली जाएँ। इस प्रकार के बैंकों से देहाती भारत की सम्पत्ति का पूरा उपयोग उठाया जा सकता है यद्यपि पिछले वर्षों में सहकारी बैंकों को बढावा दिया

गया था पर फिर प्रगति कम होने लगी । इसलिए सरकार को ऐसे बकों की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए ।

(६) बीमा कर्पानियों को भी अपने प्रतिनिधियों को देहातो में भेजना चाहिए ताकि वहाँ की जनता को नये नियमों से आकर्षित कर बचत करने का ढंग बताया जा सके और इस प्रकार उसका सदुपयोग भी सम्भव हो सके ।

(७) सरकार को अपनी नीति के बारे में विस्तृत स्पष्ट रहना चाहिए । बड़े उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न पर, उनके राष्ट्रीयकरण की समस्याओं पर तथा अन्य कर आदि मसलों पर हमारी सरकार के मंत्रियों को अपनी नीति में उलझने नहीं डालनी चाहिए । केवल प्रभावशाली भाषण ही प्रगति के चिन्ह नहीं हो सकते हैं । भाषण आवश्यक हैं पर ऐसा कि जिनसे आर्थिक समस्याएँ जाटल होने के बजाय कुछ सुलभती हो । सरकार को एक ऐसे विभाग को भी जन्म देना चाहिए जो देश में पूँजी-निर्माण के बारे में कुछ प्रचार करे तथा "बचत करो आन्दोलन" को बड़ी तजी से कार्यान्वित कर दे ।

समय दे सारे साधनों का विदोहन और मुक्तावा की कार्यान्वित करने के पश्चात् भी हम अपनी आवश्यकतानुसार पूँजी इस देश में प्राप्त न कर सकें । निश्चित रूप से पूँजी के लिए कुछ वगैरे तक हमें विदेशों की सहायता लेनी पड़ेगी और लेनी भी चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक । इन सब का अर्थ यह नहीं कि हम अपने देश में पूँजी निर्माण के कार्य को गतिहीन कर दें क्योंकि इसी के बल पर हम अपने देश को प्रगतिशील बना सकते हैं ।

४३—औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन

[Industrial Finance Corporation]

महत्त्व—वैसे ता वैदेशिक पूँजी के लिए हमारी नित्य प्रति नी प्रताप्ता, तथा उस सम्मान पूर्णक प्राप्त कर, उसका अधिसाधिक उपयोग उठाने क लिए आये दिन के प्रयास, प्रस्ताव व प्रेरणाएँ हा यह स्पष्ट करने को पर्याप्त है कि देश में पूँजी का अभाव है, किन्तु गत वर्षों का अनुभव यह बताता है कि बड़े बड़े उद्योगों के लिए, एक नहीं अनेक उदाहरणों में, पूँजी प्राप्त करने हेतु उक्त 'पूँजी का अभाव' केवल अभाव हा नहीं पर लगभग अनाल सिद्ध हुआ है। दीर्घ कालीन व अल्प कालीन तथा स्थायी व कार्यशील सभी प्रकार की पूँजी के लिए बड़े उद्योगों का बाधाएँ होती रहीं है व समय समय पर निराशा व असफलता भी उ-हं देखनी पड़ी है। इसका मुख्य कारण चाहे पूँजी वालों का सरकारी ऋण पत्र के प्रति या जन उपयोगी संस्थाओं के शेयरों के लिए सुरक्षा व आश की दृष्टि से अधिक चाव रहा हो, किन्तु बड़े उद्योगों के विकास में सदैव इस प्रकार की नीतियाँ बाधक रही हैं। हमारे यहाँ के बैंक तथा अन्य वित्त संस्थाओं की शक्ति, साधन व साहस भी बड़े उद्योगों में पूँजी लगाने में नर्बल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना का सभी वग व विभाग ने स्वागत किया है। इसलिए निस्सङ्कोच यह निर्णय दे देना कि ऐसे कॉरपोरेशन की स्थापना सामयिक आवश्यकता ही नहीं वरन् ऐतिहासिक महत्त्व भी रखती है कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

कॉरपोरेशन की स्थापना—कई वर्षों पूर्व औद्योगिक वित्त आयोग ने सन् १९१८ में विकास की समायोजनाओं को दृष्टिगत रख, देश में औद्योगिक बैंकों की स्थापना पर बड़ा बल दिया था। इसी प्रकार वैदेशिक पूँजी कमिटी (External Capital Committee) ने सन् १९२४ में देश की औद्योगिक वित्त समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक संस्थाओं (Specialist Institutions) की स्थापना की वकालत की थी, किन्तु कई राजनैतिक व आर्थिक कारणों से उक्त प्रस्ताव को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पर भूतपूर्व प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियाँ से प्रेरित

हो माननीय आर० के० राणमुखम चौधरी ने भारतीय-संसद में श्रीयोगिक विन कारपोरेशन की स्थापना के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। २७ मार्च सन् १९४८ को गवर्नर-जनरल की ओर से इस बिल पर स्वीकृति मिली तथा १ जूलाई सन् १९४८ से कारपोरेशन का कार्य प्रारंभ हुआ।

पूँजी का ढाँचा :—कारपोरेशन की आविकृत-पूँजी १० करोड़ रुपये है। इस पूँजी को २० हजार शेयरों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक शेयर का मूल्य ५ हजार रुपये है। इन शेयरों को खरीदने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार, विज्ञेय बैंक, प्रमाणित बैंकों (Scheduled Banks), बीमा-कम्पनियों, पूँजी लगाने वाले ट्रस्टों तथा इसी प्रकार की विन संस्थाओं को है। उक्त शेयरों पर केन्द्रीय सरकार की गारंटी भी है। यह तो स्पष्ट ही है कि कारपोरेशन के शेयर खरीदने व पूँजी में योग देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं है पर केवल उक्त संस्थाओं को है जो विन की समस्याओं से सम्बन्धित हैं।

उद्देश्य तथा अधिकार :—कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश में श्रीयोगिक विकास को सहायता पहुँचाना है। किन्तु विकास का अर्थ केवल नई उद्योगशालाएँ खोलने से ही नहीं है। आज हमारे यहाँ एक ओर जहाँ नई उद्योगशालाओं की आवश्यकता है तो दूसरी ओर चालू उद्योगों के युक्ति-मंगल वैज्ञानिकन (Rationalisation) की बात भी अपना पूरा महत्व रखती है। श्रीयोगिक सम्पत्ति की प्राप्त पूँजी (Paid up Capital) का लगभग सारा भाग मशीन भूमि व अन्य औजारों के खरीदने में ही चला जाता है व समय पर कार्यशील-पूँजी (Working Capital) की बड़ी भारी कमी पड़ जाती है, जिसका कारण उद्योग की सकलता के लिए पातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए कारपोरेशन का उद्देश्य है कि चालू व नवीन सार्वजनिक कम्पनियों को मध्य कालीन व दीर्घ कालीन सागर उपलब्ध करे। किन्तु वे उद्योग जो बुनियादी उद्योगों की श्रेणी में हैं या वे उद्योग जिनका कि राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, उक्त सहायता के भागीदार नहीं बन सकते।

कारपोरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे निम्नांकित अधिकार प्राप्त हैं —

(१) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऐसे कर्ज पर गारंटी देना—

(अ) कि जो २५ वर्ष से पूर्व ही लौटा दिया जायगा।

(ब) कि जो सार्वजनिक बाजार में प्राप्त किया गया है।

(२) औद्योगिक संस्थाओं के शेयर व ऋण पत्र बेचने का जिम्मा लेना।

(३) उक्त (१) व (२) व गारंटी दी गई सुविधाओं के लिए कमिशन पाना।

(४) ऐसे शेयर, ऋण पत्र व बॉण्ड आदि का सम्पत्ति के तौर पर रखना जो कि बेचने का जिम्मा लेने (Underwriting) हेतु प्राप्त किये गये हों। किन्तु ऐसे शेयर, ऋण-पत्र व बॉण्ड आदि शीघ्रातिशीघ्र बेचने पड़ेंगे, यदि ऐसा सम्भव हो सके, परन्तु इनकी रखने की मियाद अधिक से अधिक ७ वर्ष है, इस लिए प्राप्त करने व ७ वर्ष बाद तो अवश्य ही शेयर आदि को बेचना पड़ेगा।

(५) औद्योगिक संस्थाओं को कर्ज या अधिम धन देना या उनके ऋण पत्र स्वीकृत करना। किन्तु ऐसे कर्ज, अधिम-धन, ऋण पत्र अधिक से अधिक २५ वर्ष में लौटाये जाने वाले होने चाहिये।

उक्त (१) व (५) में सुविधाएँ तभी दी जा सकती हैं जब वे पर्याप्त गिरवी से सुरक्षित किये जा चुकें हों।

प्रबन्ध.—साधारण देल-रेगुल व निर्देशन का कार्य एक संचालक-परिषद (Board of Directors) के अधीन है जो एक कार्यकारिणी कमेटी तथा प्रबन्ध संचालक की सहायता से होता है। यह आशा की गई है कि संचालक-परिषद दोस व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुकूल कार्य करेगी। परिषद की कार्य पूर्ति में मन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य पर किया निर्णय व दिया गया निर्णय परिषद को अंतिम रूप से मान्य होगा।

सुरक्षा के साधन — औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए किसी ऋण को वापिस प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन को बहुमुखी अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई संस्था अपने इकरार का निभाने में असफल रही है, या भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली सूचना या व्योरा देता है, या रखने की गई सम्पत्ति का सुरक्षा से

नहीं रख सके हैं, या ऐसी संपत्ति का मूल्य २० प्रतिशत से अधिक कम हो गया हो व सस्था क्षतिपूर्ति करने के लिए गिरवी न दे सके हो, या गिरवी रखी हुई मशीन आदि को अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है या अंत में मंचालक-परिपद की राय में कारपोरेशन के हितों की रक्षा करना आवश्यक हो गया हो तो परिपद दिए गए श्रृंखला को तुरंत वापिस लौटाने का नोटिस दे सकती है। यदि कोई औद्योगिक संस्था उक्त नोटिस का पालन न करे तो परिपद द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति जिना-न्यायाधीश की सहायता से उसकी सारी संपत्ति को बिकवा सकता है या अपने अधिकार में ले सकता है। यदि ऐसे मुचालक अधिकार कारपोरेशन को न प्राप्त हों तो इसका कार्य समुचित ढंग पर चलना भी कैसे संभव हो सकता है ?

लाभ-वितरण :—कारपोरेशन के नियमों में यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि कारपोरेशन एक बचत-कोष कायम करेगा। संदेहास्पद श्रृंखला, संपत्ति का मूल्य-हास तथा अन्य इस प्रकार के व्यापारिक घाटों के लिए धन निश्चित कर चुकने पर यदि कोई लाभ बच जाय तो कारपोरेशन शेयर-अधिकारियों को मुनाफा बाँट सकता है, किन्तु इस मुनाफे की दर उस समय तक, सरकारी गारंटी से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त बचत-कोष का धन कारपोरेशन की प्राप्त-पूँजी के समान न हो जाय।

कॉरपोरेशन द्वारा किए गए प्रयत्नों का व्यौरा

कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास में स.ग. मुविधा प्रदान कर सहायता देना रहा है। इसका कार्य १ जूलाई सन् १९४८ में प्रारम्भ हुआ था, अतः अब तक के, २० जून सन् १९५१ तक के, तीन वर्षों में कारपोरेशन ने अनेक प्रकार की औद्योगिक संस्थाओं को श्रृंखला दिए हैं।

अपने जीवन के प्रथम वर्ष में कारपोरेशन ने कुल मिला कर लगभग ३ करोड़ ४२ लाख रुपये श्रृंखला दिए तथा दूसरे वर्ष में लगभग ३ करोड़ ७७ लाख रुपये के श्रृंखला दिए गए। ३० जून १९५१ को समाप्त होने वाले वर्ष में कारपोरेशन ने ४ करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के श्रृंखला रखी हूँ विष्। श्रृंखला अधिकतर कपड़ा उद्योग, सीमेंट, इंजीनियरिंग, तेल उद्योग, ऊन, रेशम उद्योगों

तथा अन्य आवश्यक मूल उद्योगों को दिए गए ।

विगत वर्षों में कारपोरेशन ने करोड़ों रुपये के ऋण औद्योगिक सस्थाओं को दिये हैं । ऐसे ऋणों को प्राप्त करने के लिए अनेक निवेदन पत्र कारपोरेशन ने पास पहुँचे हैं किन्तु अधिकांश को ऋण देने में कारपोरेशन असमर्थ रहा है । कारपोरेशन की ओर से इस असमर्थता के लिए कई कारण वापिक रिपोर्टों में दिए गए हैं । मुख्य इस प्रकार हैं ।

योजना का अभाव — कई उदाहरणों में ऐसी योजनाएँ कारपोरेशन को भेजी गई हैं जिनमें तांत्रिक पहलुओं व वित्त-समस्याओं पर पूर्ण विचार नहीं किया गया है । अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें यह भी नहीं बताया गया है कि भूमि, इमारत, मशीनरी आदि अन्य व्यक्तिगत विभागों पर अलग अलग कुल कितनी खर्च होगी । ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है, जहाँ मशीन आदि इसलिए खराद ली गई हैं कि वे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो रही हैं । उनकी उपयोगिता पर तनिक भी नहीं सोचा गया । ऐसी अधूरी वागजा योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का अभाव रहना स्वाभाविक ही है । उत्पादन की समस्याओं के बारे में जो औद्योगिक सस्थाएँ केवल मन चाहे आधार पर, बिना किसी विशेषज्ञ की सम्मति के ही यदि आगे बढ़ चलीं तो इसका नाम योजना नहीं कहा जा सकता । मँग और पूर्ति की समस्याओं पर तो अधिकांश सस्थाएँ पर्याप्त रूप से सोचने में असमर्थ रही हैं । अतः ऐसी दशा में कारपोरेशन के लिए अधाधुन ऋण दे सकना कैसे सम्भव हो सकता है ?

अपर्याप्त साधन .— कुछ औद्योगिक सस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनकी पूँजी आवश्यकता से बहुत कम है । ऐसी स्थिति युद्ध काल में संभवतया उनके समुचित विरास में बाधक न होती क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के ऋणों से व उपलब्ध पूँजी से काम चलाया जा सकता था । किन्तु अब युद्धोत्तर काल में मुद्रा स्थिति भी कम हो गई है, ऋण भी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो भला कम पूँजी वाली औद्योगिक सस्थाएँ कैसे पनप सकती हैं ? ऐसी सस्थाओं को ऋण देकर उनके लिए अहित करना है । कुछ उदाहरणों में यद्यपि प्राप्त पूँजी पर्याप्त भी तो सस्था की अधिकांश सम्पत्ति गिरती रहती जा चुकी थी । ऐसे

उदाहरणों का अभाव नहीं है जहाँ संस्था के सारे शेयर संस्थापकों को उनसे ली गई संपत्ति के बदले में दिए गए हैं, पर ऐसी संपत्ति बहुत ही अधिक मूल्यों पर प्राप्त की गई है। कहीं-कहीं तो संस्थाओं की अणु के लिए की गई माँग उनकी आवश्यकताओं से भी कम है और ऐसी दशा में यदि कारपोरेशन जी पोज कर भी उन्हें अणु प्रदान करे तो भी उनका उन्धान नहीं हो सकता।

इन दो विशेष कारणों की वजह से कारपोरेशन को कई शैथिलिक संस्थाओं को अणु देने में कठिनाई हुई, किन्तु इस दशा में ऐसे उद्योगों को, जो बिना किसी गुणवत्ति योजना के व पर्याप्त साधनों के आगे बढ़ने हैं, निराश करना उचित कहा जा सकता है। इतना होने हुए भी कारपोरेशन ने मरुद्ध अणु देकर कई उद्योगों को सकलता की करवट बदलने का अवसर दिया है। अभी कारपोरेशन का यह बाल-जीवन ही है इसलिए सतर्कता और ठोस व्यापारिक विद्वानों का स्याग करना इसके लिए समय नहीं अन्यथा इसका स्वर्य का अस्तित्व भी अस्थाया हो सकता है जो कि शैथिलिक विकास के हित में नहीं कहा जा सकता।

कारपोरेशन के कार्य-क्रम व कार्य-प्रणाली की आलोचना

अनेक अणुओं की स्वीकृति देने पर भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि कारपोरेशन के बारे में आलोचना के शब्द कहे नहीं जा सकते। जहाँ पिछले तीन-चार वर्षों में इसने कुछ कार्य किया है, यहाँ कई प्रयत्न असफल भी रहे हैं, आदुरे भी रहे हैं और अव्याप्त प्रयत्न भी किए गए हैं। अतः कारपोरेशन के लिए यह आलोचनाएँ समय-समय पर होनी रही हैं।

कारपोरेशन का प्रारम्भ इतना अच्छा नहीं रहा है जिससे कि हम प्रेरित होकर प्रशंसा कर दें। प्रथम वर्ष में १५६ आवेदन-पत्र अणु के लिए आए जिनमें से केवल २१ को अणु दिया गया व प्रथम वर्ष यानी १० जन १९६६ तक कुल अणु ३,४२,२५,००० रुपये का दिया गया। ईंग्लैंड के कारपोरेशन ने १३३ आवेदन पत्रों को अणु दिया, जहाँ भारत में केवल २१ को स्वीडिशि मिली। कनाडा ने प्रथम वर्ष में ६७ आवेदन पत्रों पर सहायुभूतिपूर्ण चिन्ता किया व आस्ट्रेलिया के बैंक ने प्रथम वर्ष में ही १०३३ अर्जियाँ स्वीकार की।

इसलिए आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व कनाडा में प्रथम वर्ष में स्वीकृत आवेदन पत्रों से सिद्ध हो रहा है कि भारत दौढ़ में बहुत पीछे है।

(२) कारपोरेशन द्वारा दिए गए ऋणों पर व्याज की दरें समा सस्थाओं के लिए समान रही हैं, जो असंगत जान पड़ना है क्योंकि सभी औद्योगिक सस्थाओं की आर्थिक स्थिति व सफलता समान नहीं हो सकती और न है। इसलिए प्रत्येक सस्था के ठासपन और भविष्य को दृष्टिगत रखकर ही व्याज की दर निर्दिष्ट करनी चाहिए। समानता के सिद्धान्त को व्याज की दरों में प्रज्ञा कर ठास व्यापारिक सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है।

(३) ऋण के आवेदनपत्रों पर विचार करते समय कारपोरेशन इस बात से अधिक प्रभावित हुआ है कि जिस कम्पनी के शेयर का मूल्य बाजार में अधिक है और जिसका नहीं है। किन्तु 'शेयर की कीमत' का मापदण्ड अनेक प्रभावित करने वाले कारणों में से एक हो सकता है पर मुख्यतः यही कारण नहीं है जिनसे प्रभावित होना चाहिए। किसी भी कम्पनी या औद्योगिक सस्था का पिछले वर्षों का प्रभाव, वर्तमान आय शक्ति, प्रबन्ध सुचारुता, व भाव्य की सभावनाएँ आदि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे प्रभावित होना भी आवश्यक है। अतः केवल शेयर के अधिक मूल्य से प्रभावित होना दापपूर्ण है।

(४) आधकाश ऋणों की अवधि, जो कि कारपोरेशन ने औद्योगिक सस्थाओं को दिए हैं, केवल १२ वर्ष की है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ १५ वर्ष की अवधि के लिए भी ऋण दिया गया है। किन्तु औद्योगिक सस्थाओं की विकास अवधि इस १५ वर्ष के समय से कहीं अधिक होगी अतः यह अवधि बहुत कम है। कारपोरेशन के नियम व अनुसार भी ऋण की अवधि २५ वर्ष तक की हो सकती है लेकिन इस नियम का अभी तक उपयोग नहीं उठाया गया है।

(५) कारपोरेशन की ओर से अभी तक कोई आर्थिक शोध विभाग नहीं खोला गया है जिसका बड़ी आवश्यकता है। कारपोरेशन का कार्य बचन प्रेमासन या अर्द्ध-व्यापिक जाँच पड़ताल करना रहा है किन्तु इसे अपने ग्राहकों का अपनी अमूल्य परिपक्व सम्पत्ति भी देनी चाहिए।

(६) शेयर जारी देने का अधिकार केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाओं व केन्द्रीय सरकार की ही प्राप्त रहा है अतः यह जन साधारण की संस्था नहीं कहی जा सकती । कई लेखकों की धारणा है कि कारपोरेशन के शेयर प्रत्येक व्यक्ति व संस्था के लिए उपलब्ध होने चाहियें, किन्तु इसका विपरीत दृष्टिकोण भी है जो हम आगे चलकर निर्वेगे ।

(७) कारपोरेशन का अणु केवल सार्वजनिक औद्योगिक संस्थाओं को मिल सकता है, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी संस्था जो सार्वजनिक नहीं है, किन्तु उद्योग व व्यापार से सम्बन्ध रखने वाली है तो भी वह कारपोरेशन द्वारा अणु नहीं ले सकती । अतः सामेदारी के व्यापार व निजी उद्योगों वाले अना विकास करने में कारपोरेशन के द्वारा दिये जाने वाले अणुओं में वृन्तित कर दिये गए हैं ।

प्रत्युत्तर :—आलोचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं मार्ग-दर्शन की रेखा भी मिलती है । किन्तु सारी बातें न सही हैं और न सार-पूर्ण ही हैं । यदि कारपोरेशन अपने शेयरों को सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए केवल अपने नाम के आगे एक जनवादी विल्ला लगाने के लिए ही उपलब्ध कर दे तो लाभ के विपरीत हानि और अनर्थ अधिक होगा । हमें ज्ञात है कि गिजन बैंक के शेयर क्योंकि सभी के लिए खुले थे इसलिए वे जन्द पूँजीयनियों के हाथों में और वे भी एक दो राज्यों में एकत्रित हो गए थे । अतः जनवाद का प्रचार करने वाले प्रयत्नों से हमें पूँजीवाद का प्रमाद मिला । इसलिए कारपोरेशन के शेयर केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाओं के लिए होना ही दितकर है ।

जहाँ तक कारपोरेशन के प्रारम्भ का प्रश्न है, वह अन्य देशों व सम्पूर्ण कुछ कम आशामय लगता है । किन्तु हमें अपने देश की गति और आर्थिक साधनों का भी आलोचना करने समय ध्यान करना पड़ेगा । हमारे देश में आर्थिक साधनों व वित्त का अभाव ही नहीं है पर औद्योगिक दृष्टिकोण से समूचा देश भी उन्नत राष्ट्रों के मुकाबिले अविश्वसित है अतः निराश होने की कोई बात नहीं है ।

कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही सार्वजनिक उद्योगों की विक-

सित करना है, बढावा देना है, अतः साभेदारी के व्यापार व निजी उद्योगों की मॉग को उचित भी समझ में नहीं आ सकती ।

आशापूर्ण भविष्य — अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा व आस्ट्रेलिया आदि सभी देशों की औद्योगिक मस्याओं को वित्त की सहायता देने वाली विशिष्ट संस्थाएँ हैं । हमारे यहाँ भी ऐसे औद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना देश व उज्ज्वल औद्योगिक भविष्य की परिचायक है । कारपोरेशन को सदा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे वातावरण को जन्म देना चाहिए कि सभी उद्योगों का विश्वास उसमें बना रहे । अपने संचालकों के उद्योगों को अधिक ऋण स्वीकार कर अथवा आजकल की प्रचलित प्रान्तीय भावना में बसकर कारपोरेशन उन्नात का सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है और जनता के अविश्वास का चिह्न बन जायगा पर विश्वास है कि देश के सुयोग्य प्रबन्धकों के संचालन में यह कारपोरेशन देश के औद्योगिक दीप की विकास रूपी वित्त बाती को सदा प्रज्वलित रखने में समर्थ ही नरों पर सफल भी हो सकेगा और इसी में हमारे आर्थिक उत्थान का स्वर्णिम प्रभात उगेगा ।

४४—जन-वृद्धि की समस्या

आज मे लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व माल्थस नामक एक प्रसिद्ध समाज शास्त्री ने कहा था कि 'किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के जीवन-यापन के साधनों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामिति-गति^१ से बढ़ती है और जीवन-यापन के साधन गणित-गति^२ से बढ़ते हैं। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या पर स्वाभाविक-प्रतिबन्ध लगाकर उसे रोकना चाहिये अन्यथा दैवी-प्रभोप जैसे अग्नि, बाढ़, भूचाल आदि अपना काम आरम्भ कर देते हैं और जनसंख्या को जीवन-यापन के साधनों के गंतुलन में बना देते हैं।' माल्थस के ये शब्द आज हमारे देश की परिस्थितियों में बरे उतर रहे हैं। वहाँ भूचाल आ जाते हैं, जिससे गाँव के गाँव धरातल में समा गए हैं तो कहीं प्रचण्ड अग्निकाण्ड के द्वारा जन और सम्पत्ति का अपार विनाश हो रहा है। कहीं बाढ़ के कारण गाँव के गाँव बह जाते हैं तो कहीं चारे और अन्न जल के अभाव में पशु और जन-शक्ति नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार वहाँ पानी की कमी है, कहीं अन्न का संकट है और वहाँ चारे का अभाव है; कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अना-वृष्टि है। कहने का अर्थ यह है कि द्रुतगति से बढ़ती हुई जन संख्या को प्रभुत जीवन-यापन के साधनों के गंतुलन में लाने के लिए देव अपना काम करने लगा है। इसका कारण स्पष्ट है। विद्वले अनेक वर्षों से हमारे देश की जन संख्या में रोक टोक बढ़ती चली जा रही है। न कोई नियम है, न समय है और न भविष्य में होने वाले दुपरिणामों का भय ही है। जन संख्या इस प्रकार बढ़ती रही है।

समस्त भारत की जन संख्या

(दस लाखों में)

वर्ष

१८७२

१८८१

२०६'१६

२५३'८६

^१ ज्यामिति-गति—२, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८ ...

^२ गणित-गति—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८... ..

वर्ष	जन संख्या (दस लाखों में)
१८६१	२८७ ७१
१९०१	२६३ ३६
१९११	३१५ १५
१९२१	३१८ ६४
१९३१	३५२ ८०
१९४१	४०० ००
१९४१ (केवल भारत मध्य)	३१६ ०१
१९५१ (केवल भारत मध्य)	३६२ ८२

इसका अर्थ यह है कि प्रति दस वर्षों में १४ प्रतिशत जन संख्या बढ़ जाती है। गत वर्षों में यह ४० लाख प्रति वर्ष से भी अधिक बढ़ रही है। १९३६-४० में प्रकाशित लीग ऑफ नेशन्स के अरब्-कोष के अनुसार समस्त संसार की जन संख्या २,१४५२,००,००० थी अर्थात् समस्त संसार के लगभग पन्द्राश मनुष्य हमारे देश में हैं। भारतवर्ष का क्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रफल का आधा है किन्तु यहाँ की जन संख्या वहाँ से लगभग तिगुना है। चीन को छोड़कर भारत की जनसंख्या संसार के सब देशों में अधिक है परन्तु चीन का क्षेत्रफल भी भारत के क्षेत्रफल से तीन गुना है। जन संख्या की वृद्धि का एक साधारण सा कारण यह है कि यहाँ पिछले कुछ वर्षों से शिशु-मृत्यु-संख्या और साधारण मृत्यु-संख्या दोनों में कमी आ गई है। १९२१ में शिशु मृत्यु संख्या १६५ प्रति मील तथा साधारण-मृत्यु संख्या ३१ प्रति मील थी जो १९४१ में घटकर क्रमशः १५८ और २२ हो गई। पिछले दस वर्षों में तो स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी अनेक योजनाओं के कारण मृत्यु-संख्या में और भी अधिक कमी होने का अनुमान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा का विकास होने के कारण मृत्यु-संख्या और भी कम होती जा रही है। फिर, कुछ वर्षों से बाल-विवाह निरोधक कानून और जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन के फल स्वरूप जन्मसंख्या में भी कुछ कमी हुई है। परन्तु जन्म संख्या फिर भी ऊँची है और मृत्यु संख्या जितनी कम नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक से तत्सम्बन्धी कुछ आँकड़ों का ज्ञान होता है।

देश	जन्म संख्या (प्रति हजार)	मृत्यु संख्या (प्रति हजार)
मिश्र	४३.५	२१.३
कनाडा	२६.८	६.२
अमेरिका	२२.४	६.६
भारत	२६.८	१६.०
जापान	३३.२	११.६
फ्रान्स	२१.०	१३.८
इटली	१६.२	६.७
इंग्लैंड	१६.१	११.७
आस्ट्रेलिया	२२.०	६.५

इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि मृत्यु-संख्या में कमी हो जाने पर भी यह अभी मिश्र को छोड़ सबसे अधिक है। इसमें स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि जन-वृद्धि की समस्या हमारे देश में जन्म वृद्धि की समस्या है और इस समस्या का हल जन्म-वृद्धि को रोकने में है। इस विषय में क्या करना चाहिए इसका विचार आगे करेंगे। यहाँ समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करें कि जन्म-संख्या अधिक क्यों है? विराह यहाँ आवश्यक माना जाता है और कम उम्र में ही विराह हो जाता है। हमारे यहाँ १८-२० साल का लड़का और १६ साल की लड़की विवाह कर लेते हैं जब कि इंग्लैंड में यह आयु क्रमशः ३०-२५ है। देश की गरीबी और मनोरंजन के कम साधनों के कारण भी यहाँ जन्म का अनुपात अधिक है। अशिक्षा के कारण भी लोग सन्तति नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। यों सन्तति-नियंत्रण सामाजिक दृष्टि से बुरा और हीन भी समझा जाता है।

केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं धनत्व की दृष्टि से भी हमारे देश में विपत्ति है। जनसंख्या के धनत्व से हमारा तात्पर्य किसी देश में प्रति वर्ग मील निवासियों की संख्या से है। स्पष्ट है कि जनसंख्या का धनत्व दो बातों पर निर्भर होता है (१) जनसंख्या, (२) क्षेत्रफल। देश का क्षेत्रफल लगभग

स्थिर है परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पक्ष स्वरूप देश में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान बन जाने के कारण तो एक विस्तृत और उपजाऊ भू-प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया परन्तु उसके समानुपात में जनसंख्या कम नहीं हुई। इससे भारत सभ में जन संख्या का घनत्व और भी अधिक हो गया है। पाकिस्तान, चीन, अमरीका और रूस मक्रमशः प्रति वर्ग मील आबादी २१०, १२२, ५० और २३ है और भारत में प्रति वर्ग मील २६६ व्यक्ति रहते हैं। इसमें जन संख्या के घनत्व की असाधारणता प्रतीत होती है।

जनसंख्या के विराट रूप और गहन घनत्व को देख कर प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश में जनाधिक्य है? यह प्रश्न बड़ा जटिल और विवादास्पद है। अर्थशास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने इसकी कई कसौटियाँ निर्धारित की हैं। 'सर्वोत्तम जनसंख्या' के सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश की जनसंख्या इस 'सर्वोत्तम सीमा' से अधिक बढ़ जाय तो कहा जाता है कि वहाँ जनाधिक्य है। परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में "सर्वोत्तम जन संख्या" क्या है—यह ज्ञात करना न सम्भव है और न युक्तियुक्त। तो यदि 'सर्वोत्तम जनसंख्या' का ज्ञान ही न हो सके तो कैसे कहा जाय कि भारत में जनाधिक्य है या नहीं। परन्तु फिर भी कुछ ऐसी कसौटियाँ हैं जिनसे जनाधिक्य का मान किया जा सकता है। माल्थस की कसौटी यह है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि के क्रम में जन्मसंख्या पर कोई प्रतिबन्ध न हो और बच्चों की संख्या बढ़ती जाय तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जानी है। केनन् का कहना यह है कि यदि जनसंख्या इस अनुपात में बढ़ रही है कि उसके कारण समस्त देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती जाय, और देश के प्राकृतिक साधनों का महत्तम उपयोग नहीं कर पाय तो यह मानना चाहिए कि जनसंख्या उस देश में बहुत बढ़ गई है। सार यह है कि सामान्यतः निम्न तीन कसौटियों से जनाधिक्य का अनुमान-मान लगाया जा सकता है—

(१) यदि स्वामयिक प्रतिबन्धों के अभाव में जनसंख्या द्रुतगति से बढ़ती जा रही हो, (२) राष्ट्रीय आय की असाधारण वृद्धि में निकट भविष्य में

कोई तीव्र सम्भावना न हो, (३) नैसर्गिक-प्रतिबन्धों (देवी-प्रकोपों) ने अरुना काम आरम्भ कर दिया हो अर्थात् देश में जगह-जगह पर अग्नि, भूकाल, बाढ़, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि देवी प्रकोप होने लगे हो जिनसे जान मान की हानि होती हो। इन तीनों ही कसौटियों पर देखने से भारत में जनसंख्या का आधिक्य का अनुमान होता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मृत्यु संख्या अधिक है पर जन्मसंख्या उससे भी अधिक है। पुराने समय में जनसंख्या पर जो मर्यादाएँ थीं वे भी अब नहीं रही हैं। पुष्ट के लिए स्त्री की मृत्यु के पश्चात् ही नहीं बल्कि उसके जीवित रहते हुए भी और विवाह कर लेने की प्रथा पहिले में ही थी। अब तो गुधार के आदेश में स्त्रियों में भी पुनर्विवाह होने लगे हैं। संतानोत्पत्ति एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। सति-निमह के उदायो का ज्ञान और प्रचार नहीं है। मारांश यह है कि स्वाभाविक प्रतिबन्धों के अभाव में जन्म संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे, यहाँ के निवासियों को विदेशों में जाकर बसने की सुविधाएँ नहीं हैं बल्कि अपने लोग विदेशी सरकारों की नीति के कारण विदेशों से आना रहन सहन छोड़ कर उल्टे भारत में आने लगे हैं। ताल स्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

राष्ट्रीय आय को देखने पर भी कुछ ऐसे ही निन्द्य निम्न हैं। लगभग तीन-चौगई जन संख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। जहाँ भूमि परिमित हो, गहरी कृषि का प्रचार न हो, कृषि-गुधार के मार्ग में अन्याय बाँटनाइयों हो, कृषि की शक्ति मन्द हो, उद्योग गान्धिन्य और व्यवसाय गुप्त और अशक्त हो, पूँजी का निरन्तर अभाव हो, विदेशी प्रायोगिता का निरन्तर भय लक्ष्य हो, कुशल विशेषज्ञों की भारी कमी हो यहाँ राष्ट्रीय आय के जनसंख्या के अनुपात में बढ़ने का आशा एक दुराशा ही है। जहाँ तक दुर्भिक्ष, बाढ़, अग्नि, भूकाल अरुना बार बार प्रलयकारी प्रभाव दिया चुके हैं और दिया रहे हैं।

इन बातों से अनुमान होता है कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है। परन्तु फिर भी इस पर मत भेद है। कुछ लोग देश में जनसंख्या के घटने में

तो कुछ का कहना है कि देश के प्राकृतिक और आर्थिक साधनों में वर्तमान जनसंख्या से भी अधिक संख्या को पालन करने की शक्ति है परन्तु कमी केवल यह है कि इन सुप्त साधनों का महत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे पक्ष के समर्थक हैं। उनका कहना है कि देश के प्रचुर साधनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान जनसंख्या भी कम है। अतः साधनों का विदोहन करने के लिए और जन संख्या की आवश्यकता है। कुछ लोगों का विचार है कि संसार में मनुष्य एक मुँह और दो हाथ लेकर जन्म लेता है। यदि पालने के लिए एक मुँह बढ़ता है तो काम करने के लिए दो हाथ बढ़ते हैं। फिर जीवन-यापन के साधनों की कमी कैसे? जनाधिक्य क्योंकर? उनका यह कथन सिद्धान्ततः ठीक है। परन्तु उसमें एक भूल है। क्या वह व्यक्ति अपने दो हाथों से अपने जीवन-यापन की पूर्ण और आवश्यक सामग्री उत्पन्न करता रहता है? उत्तर मिलता है नहीं। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होते हैं—उसकी शक्ति और कार्यक्षमता की कोई सीमा होती है तथा वह केवल हाथों से ही सामग्री नहीं उपजा सकता या बना सकता। उसे कुछ सहायक-साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन उसे पर्याप्त मात्रा या संख्या में उपलब्ध नहीं होते और वह फिर जनाधिक्य का कारण बन जाता है। हम पंडित नेहरू की इस बात से सहमत हैं कि देश के साधन प्रचुर हैं परन्तु सुप्त पड़े हैं। उनके विदोहन के लिए शक्ति की आवश्यकता है। परन्तु केवल जन शक्ति की ही नहीं, जन-शक्ति की सहायक शक्तियाँ भी। यदि ऐसा किया जा सकता निश्चय ही भारत-भूमि पर इससे भी अधिक जनसंख्या का पालन हो सकता है। परन्तु प्रश्न तो यही है कि जन-सहायक-शक्तियाँ कैसे प्राप्त हों? प्रयत्न किए जा रहे हैं—कृषि भूमि की साम्राई बढ़ाई जा रही है, कृषि पर यन्त्रों की सहायता ला जा रहा है, सहायक-उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तथा पैसा निष्कन करके उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि हमारी ये सब योजनाएँ सफल हुईं तो जनाधिक्य का भय टल जायगा।

परन्तु इससे भी समस्या पूर्ण रूपेण हल नहीं होती। आखिर उत्पादन जब तक बढ़ाया जा सकता है? सुप्त साधनों का कितना विदोहन किया जा

सकता है ? इन सब की कुछ न कुछ मर्यादाएँ हैं । जन्म मरणा को रोकने की बात को टाल कर उत्पादन बढ़ाने की ही मान करना जनवृद्धि की समस्या को हल करने का श्रधूरा उपाय ही रहेगा । अतः यह भी आवश्यक है कि द्रुत-गति से बढ़ी चली जा रही जन्म मरणा पर लगाम चढ़ा दी जाय । जब सरकार गुरु मरणा को रोकने के लिए मार्वाजनिक स्वास्थ्य की अनेकों योजनाओं को लेकर खड़ी है तो जन्म मरणा को भी रोकने के लिए कुछ करना वांछनीय और आवश्यक है अन्यथा समस्या मुलभूत के बदले और उत्पन्न सकती है । जन्म मरणा को रोकने के लिए दो उपाय हैं—(१) सरकार द्वारा, (२) जनता द्वारा । सरकार सन्तति निग्रह की शिक्षा को प्रोत्साहन दे, जहाँ लोगों का उसका ज्ञान मिल सके—चल-चित्र दिखाए जाएँ, भाषण कराए जाएँ तथा निग्रह-केन्द्र खोले जाएँ । सरकार यह सब कुछ कर रही है । विदेशी विशेषतः मि० स्टोन की सलाह पर देश के कई स्थानों पर सन्तति-निग्रह केन्द्र खोल कर प्रयोग किए जा रहे हैं । इसका है कुछ परिणाम निकलेगा । सरकार शिक्षा को भी प्रगति दे क्योंकि इसके बिना स्वयं जनता निग्रह का महत्व नहीं समझ सकती । इसके अनिच्छित मनोरंजन के साधन भी जुटाए जाएँ । कुछ लोगों का सुझाव है कि 'कॉन्ट्रासेप्टिक्स' का प्रयोग देश में बढ़ाया जाय । परन्तु इस प्रकार अस्थायिक और नैसर्गिक उपायों से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की सम्भावना है । महात्मा गांधी स्वयं इसके पक्ष में न थे । उनका कहना था कि इस प्रकार जनता में व्यभिचार फैलने की शंका बनी रहेगी और दूसरे भारी भ्रान्तान भी निर्वचन बन जायगी । इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि लोग स्वयं समझे, समस्या की गम्भीरता को पहचानें और सवाने-गति पर स्वयं प्रतिबन्ध रखें । यह समस्या ऐसी है जिस पर कानून द्वारा ही काबू नहीं पाया जा सकता । इसके लिए स्वा-युक्तों का पारस्परिक सहयोग ही अनिवार्य है । सरकार तत्सम्बन्धी सुविधाएँ दे जैसा शिक्षा का प्रसार, मनोरंजन के अन्य साधन, सन्तति-निग्रह की महत्ता की शिक्षा आदि, आदि, । समस्या का हल तो केवल Moral Restraint 'जनता के स्वाभाविक नियंत्रण' में है । सभी जन्म संख्या कम हो सकती है और सभी रहन-सहन का स्तर उठ सकता है ।

४५—आर्थिक आयोजन

हमारे सिद्धान्त एवं आदर्श क्या हो ?

आर्थिक आयोजन कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। प्रथम महायुद्ध में पहिले तो आर्थिक आयोजन कुछ सैद्धान्तिक अथशक्तियो का विचार मात्र हो माना जाता था। पर १९३० के पश्चात् यह एक महत्वपूर्ण विषय बनने लगा। सारियट रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो आर्थिक प्रगति की उससे ससार के अनेक देशों की भारी विस्मय हुआ और वे आर्थिक आयोजनों के पुरोगमों में पुत्रने लग। द्वितीय युद्ध के कारण अनेक राष्ट्रों ने आर्थिक उत्थार का जो विध्वंस हुआ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य आवश्यकता समझी जाने लगी। युद्धोत्तर काल में ससार के अनेक राष्ट्रों ने आर्थिक आयोजन किए। आज कुछ युद्ध घसित देश आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं और कुछ अवनत देश आर्थिक संगठन में व्यस्त हैं। हमारे देश की आर्थिक समस्या बहुतही है जहाँ युद्ध निरुद्ध आर्थिक कलेवर को भी संगठित करना है और देश के मुक्त आर्थिक साधनों का विदोहन करने कृषि और उद्योग को उन्नत बनाकर सतुलन उत्पन्न करना है।

आधुनिक युग में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकार चाहे एक तन्वीय हो अथवा जन तन्वीय, कोई भी देशव्यापी नीति पुरोगम और आयोजन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो। आर्थिक आयोजन में अनेक नीतियों और कार्य शैलियों का समावेश होता है और ये सभी नीतियाँ और कार्य शैलियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, परन्तु इन्हें कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें जनता के विश्वास का पान बनाया जाय। इस आदर्श का महत्व १९२७ में होने वाले 'विश्व आर्थिक सम्मेलन' के उस प्रस्ताव से ज्ञात होता है जिसमें यह मुझाया गया था कि "ससार के आर्थिक निर्माण के लिए सम्मेलन को भिन्न भिन्न देशों की सरकारों और शासन सूत्रों पर ही आप्रित नहीं रहना चाहिए वरन् जनमत का आधार

बनाना चाहिए क्योंकि इसी पर योजना की सफलता निर्भर होगी है"। हमारे यहाँ योजना कमोशन ने भी इस बात को भली-भाँति समझा है और अपनी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रकाशित करने समय स्पष्ट कर दिया है कि 'योजना की सफलता जन विश्वास एवं जन सहयोग पर निर्भर है'।

आर्थिक आयोजन आर्थिक समूहों को पर व्यावहारिक क्रिया है जिसके द्वारा श्रम, व्यापार और उद्योग के सभी भिन्न-भिन्न गुणों को मिलाकर एक व्यवस्थित और संगठित इकाई बना दिया जाय, जिसमें एक निश्चित अधि के अन्दर प्रस्तुत आर्थिक साधनों का विरोधन करके देशवासियों की आवश्यकताओं के महत्तम मन्तोष की पूर्तिप्राप्ति प्राप्त की जा सके। इस क्रिया के सफल संचालन के लिए एक ऐसे संचालक की आवश्यकता होगी जो भिन्न-भिन्न गुणों की कार्यशैली निर्धारित करे और उत्पादन एवं उपभोग में समुचित उत्पन्न करे। स्पष्ट होता है कि आर्थिक आयोजन के तीन प्रमुख उद्देश्य होने चाहिये। प्रथम, प्रस्तुत सभी आर्थिक साधनों का महत्तम विरोधन; द्वितीय, उत्पादन एवं उपभोग में आवश्यक तथा अनुकूल समायोजन; और, तीसरा, देशवासियों की आवश्यकताओं की महत्तम पूर्ति। ये तीनों उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब देश भर की सारी आर्थिक क्रिया एक केन्द्रित संचालन शक्ति के अधीन हो। आर्थिक आयोजन के द्वारा उत्पादन की कुशलता, आर्थिक जीवन की स्थिरता तथा वितरण की समानता लानी होती है। जहाँ तक उत्पादन की कुशलता का प्रश्न है, आयोजकों को चाहिए कि वे ऐसा आर्थिक कार्यक्रम बनाए जिसमें उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ जन मर्त्या को भी भगुर कार्य मिलता रहे तथा उत्पादन का स्तर भी ऊँचा हो। कुछ लोगों का गवाह है कि विशाल यंत्रों द्वारा ही उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा; परन्तु यह बात निरान्त सत्य नहीं। भारत जैसे देश में, जहाँ जनमर्त्या का आधिक्य है, उत्पादन की कुशलता जन-शक्ति के द्वारा ही बढ़ानी होगी, यंत्रों के द्वारा नहीं, अन्यथा योजना का भय बना रहेगा। इसी प्रकार वितरण की समानता के लिए भी आयोजकों को भली भाँति जान लेना चाहिये। वितरण की समानता का यह अर्थ नहीं कि सभी को समान मिलता रहे या सभी समान रूप से धनी

वा बगाल रहे। यह बात संभव भी नहीं हो सकती। जबतक मनुष्य मनुष्य की योग्यता, कार्यशैली, भ्रमशक्ति, मानसिक गुण व शारीरिक गठन भिन्न भिन्न हैं तब तक उनकी कार्य करने की शक्ति भी भिन्न भिन्न होगी और उनके उत्पादन की स्तर भी अलग अलग होगा, वितरण में भी असमानता होगी। अतः वितरण की पूर्ण और स्थायी समानता की कल्पना करना असंभव नहीं तो असंगत प्रयत्न बान पड़ता है। वितरण की समानता से बसल यही सम्भला चाहिए कि ऐसा आर्थिक कलेवर बने जिसमें सभी को सब कार्य करने के लिए समान अवसर प्राप्त हों, मानव मानव का शोषण न करे, मानव प्राकृतिक साधनों का शोषण करे। आर्थिक जीवन की स्थिरता व विषय में भी एक विशेष बात है। स्थिरता ऐसी न हो जिससे जीवन की गति रुक जाय और आर्थिक क्षेत्र में ऐसे भारी भारी परिवर्तन हो जिससे आर्थिक कलेवर को किसी भी प्रकार की हानि हो।

किसी भी आर्थिक योजना का रूप निर्धारित करने से पूर्व आर्थिक साधनों का देश की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का सिंहावलोकन करना अत्यन्त आवश्यक है। योजना ऐसी हो जिससे क्रांति का आभास न मिले वरन् शनैः शनैः युग परिवर्तन हो। न तो प्रस्तुत आर्थिक कलेवर को छिन्न भिन्न करने की ही आवश्यकता पड़े और न क्रांतिकारी माता-पिता ही उत्पन्न करने की चेष्टा की जाय। यथा संभव निम्न बातों का समावेश करने का प्रयत्न होना ही चाहिए—

(१) योजना का आधार वैयक्तिक उपक्रम (निजी उद्योग) ही हो परन्तु आवश्यकतानुसार इसे लोक उपक्रम द्वारा स्थानापन्न कर दिया जाय। जिस क्षेत्र में लोक नियंत्रण की आवश्यकता जान पड़े वहाँ वैयक्तिक उपक्रम का स्थान न दिया जाय। परन्तु वैयक्तिक उपक्रम भी सर्वथा स्वतन्त्र न रहे। सभी वैयक्तिक उपक्रमों पर सरकार का न्यूनधिक नियंत्रण रहना ही चाहिए।

(२) योजना का जनता पर बलात् न लादा जाय। जनता का योजना के सिद्धांतों में एक उसका भविष्य में पूरा-पूरा विश्वास हो। हमारे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक योजना सरकार और जनता सभी का माया हो और उसका व्यवहार लोकतन्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हो।

(३) योजना का स्वरूप शनैः-शनैः विकसित होता रहे, जिसमें आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ व आर्थिक मर्यादें एक दूसरे के समीप आती जाएँ और उनका विकास भी एक निर्धारित शृंखला और उपक्रम के अनुसार हो। कोई भी योजना आरंभ में ही पूर्ण नहीं करी जा सकती। उसकी रूपरेखा समय की गति के साथ-साथ तथा मजबूती के किनारे-किनारे विकसित होनी चाहिये।

(४) योजना लचकदार होनी चाहिये जिसमें भविष्य में आनेवाली आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों के सम्मुख उममें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें। आर्थिक योजना को पूर्ण कहकर आर्थिक जीवन को स्थायी बनाना होगा जबकि आर्थिक जीवन में समयानुसृत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आयोजन की प्रमुख विशेषता यह है कि “उसमें उत्तरोत्तर विकास हो और विकास के साथ उसे पूर्ण बनाया जाय।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोजन सरकार और जनता के उन मरुत प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा राष्ट्र और संसार की परिवर्तनशील उत्पादन की परिस्थिति में आर्थिक कुशलता लाने का सकल प्रयास किया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि आर्थिक योजना ‘राष्ट्रीय’ होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र को एक शून्य इकाई मानकर आयोजन हो, अन्य राष्ट्रों के साथ उसका कोई संबंध न रहे। ऐसी विचारधारा भातुक हृदय की उपज है और व्यापारिकता से अधिक पीछे है। शून्य इकाई पर आधारित राष्ट्र की आर्थिक योजना का कोई व्यापारिक मूल्य नहीं और न वह हितकारी हो सकती है। राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाने समय अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजन का अत्यन्त ध्यान में रखना होगा। योजना की सकलता में जितनी राष्ट्रीय जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है उतनी ही अन्तराष्ट्रीय सहयोग की भी कल्पना करनी होती है। प्रो० टामस व प्रो० सेलिगमेन भी इस बात की समीक्षा करते हैं और प्रो० टोयनबी ने तो यहाँ तक लिखा है कि “अन्तराष्ट्रीय सहयोग की कल्पना किये बिना बनाई गई आर्थिक योजना न केवल व्यर्थ होती है वरन् भयंकर हानि का कारण भी बन सकती है।” अतः यह आवश्यक है कि आर्थिक योजना यदि अन्तराष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित नहीं होती है तो कम से कम अन्तराष्ट्रीय सहयोग

की आशा करते हुए अन्य राष्ट्रों के आर्थिक वायुमंडल से मेल खाती हुई अवश्य होनी चाहिए। वर्तमान युग में, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मोद्रिक प्रणालियों, कच्चे माल का आश्रय, पके माल को रखाने के लिए विदेशी बाजारों की व्यवस्था पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है ता आर्थिक योजना में इन सभी व्यवस्थाओं का पूरा पूरा आयोजन आवश्यक माना जाता है।

हमारा देश तो आर्थिक योजनाओं की एक प्रयोगशाला रहा है। देश के आर्थिक आयोजन के विषय में भिन्न भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। कुछ लोगों का विचार है कि देश का औद्योगीकरण की आरंभ लेजाना चाहिये और कुछ साबते हैं कि देश की उन्नति कृषि पर ही आधारित है। श्रीमती वैरा आइन्स्टे ने अपनी पुस्तक "भारत का आर्थिक विकास" में दलाल की है कि देश में एक सन्तुलित नीति की आवश्यकता है जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को समुचित स्थान प्राप्त हो।" भारत की किसी भी आर्थिक योजना में दो समस्याएँ आती हैं, पहली जनसंख्या का आकार एवं उसकी वृद्धि दर और दूसरी सन्तुलित आर्थिक ऋण। इन्हा दोनों समस्याओं पर भावी आर्थिक योजना का आधार आधारित होना चाहिए। जनसंख्या की समस्या पर ही भावी भारत का आर्थिक भविष्य अवलम्बित है। जनसंख्या का समस्या देश की वह विस्मृत समस्या है जिसे यदि शांति हा न मुनकाया गया तो देश के कितने ही ठोस आर्थिक पुराणम आगे चल कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। अतः आर्थिक योजना का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि बढ़ता हुआ जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रण में लाया जाय और जनसंख्या एवं उत्पादनमात्रा में किस प्रकार सन्तुलन पैदा हो।

सभी मानते हैं कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारा भार है। लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर अवलम्बित है। और यह भी सत्य है कि अभी तक उत्पादन पूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा। यदि वैज्ञानिक साधनों द्वारा उत्पादन बढ़ाया गया तो समस्या यह पैदा हो सकती है कि कृषि से उठाई गई जनसंख्या क्या कार्य करे? इस जनसंख्या को औद्योगिक साधन तलाश करने होंगे और इस प्रकार कृषि व उद्योग के सन्तुलन का प्रश्न भी हल करना होगा।

योजना कमिशन ने इन दोनों प्रश्नों को सामने रखकर योजना तैयार

की है और योजना का रूप काफी सुझौल बनाया है। उस योजना की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन अगले निबन्ध में किया गया है।

आर्थिक आयोजन को एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता अन्न-समृद्ध की होती है जिनके आधार पर आगामी कार्य शैली निर्धारित की जा सके। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का कहना है कि जीवन के किसी भी पहलू में अनुमान-अंशों की आवश्यकता होती है और ये अनुमान-अंश योजना का माग प्रदर्शन करते हैं। डाक्टर मार्शल का विश्वास है कि “अर्थशास्त्र वह मिट्टी है जिसकी सहायता से ईंटें तैयार की जाती हैं।” आर्थिक योजना बनाने से पूर्व हम बात की आवश्यकता है कि ‘उत्पादन-गणना’ हो। उत्पादन-गणना का तात्पर्य है कि आर्थिक साधनों का, आर्थिक नियात्रों का, जनसंख्या के विभिन्न उद्देश्यों का एक देश में आशा कीत अन्य उद्योग प्रयोगों का अनुमान लगाया जाय और लक्ष्य बनाकर उसरी पूर्ति के प्रयत्न किये जाएँ। सभी लक्ष्य-प्राप्ति की कल्पना की जा सकती है। हमारे देश में अनेक योजनाएँ बनीं, परन्तु अक्षरमूढ़ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अन्ततः प्रस्तुत साधनों में अधिक ईंटें निर्माण करने के विषय में सोचा गया और लक्ष्य-पूर्ति न हो सकी। वर्तमान योजना कमीशन ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। देश के साधनों के विषयसन्धीय और यथाशक्ति पर्याप्त आँकड़े प्राप्त करके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अक-समृद्ध के पश्चात् हमारे देश में आर्थिक-आयोजन में भारतीय कृषि की योजना का प्रथम लक्ष्य बनाना आवश्यक है। कृषि अब भोजन का साधन ही नहीं बरन् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं औद्योगिक विकास का भी एक योग हो चला है। अतः हमारी किसी भी योजना में देश की कृषि-भूमि की मानव-जीवन होनी चाहिए। भूमि का मानव इस दृष्टिकोण से हो कि विभिन्न भागों में कौनसी जलज कुशलता से पैदा की जा सकती है और हमका मानव करते-समय देश की स्थानीय आवश्यकताओं और निर्यात-आवरण-कताओं दोनों बातों को सामने रखता जाय। उत्पादन वृद्धि के साधनों को तो सोचना होगा ही परन्तु उन सबको देश में ही उत्पन्न करना भी योजना

प्र लक्ष्य होना चाहिए। वृत्ति की उन्नति के साथ-साथ प्रामोक्षति की ओर भी योजना का पूरा लक्ष्य हो, क्योंकि भारत की कोई भी आर्थिक योजना तबतक पूर्ण नहीं कही जा सकती जबतक कि भारत के ७,००,००० गाँवों के पुनरुत्थान का कार्य-क्रम न बनाया जाय। प्रामोक्षति की योजना में सहकारी उद्योगों एवं सामाजिक सुविधाओं को पूरा पूरा स्थान मिलना चाहिए। आर्थिक क्लेवर को दृढ़ करने के लिए जनता का शिक्षित बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा का आर्थिक पुरोगम में विशेष स्थान हो, जिससे जनसाधारण योजना का महत्व समझें और उसे कार्यान्वित करें। अत आर्थिक, योजना केवल अर्थसाध्य ही न हो, वृत्ति के केवल एक ही पहलू को स्पष्ट न करे, वरन् योजना को अपनाते बहो सभी श्रेणी के लोगों के जीवन की चतुर्मुखी उन्नति का लक्ष्य हो। इतना ही नहीं, ये सभी क्रियाएँ एकसाथ चलें, जिससे किसी भी क्षेत्र में कमी न आने पावे। योजना का अगला अंग उद्योग-विकास है। उद्योग क्षेत्र में विशाल उद्योगों को भी स्थान हो और यह उद्योग (कुटीर धंधे) भी सम्मिलित हो। केन्द्रीयकरण की योजना भारत में अधिक उपयोगी सिद्ध न होगी। जहाँ विशाल क्षेत्र है, अनन्त साधन हैं, असंख्य जनसंख्या है, विकेन्द्रीकरण की योजना ही हितकर होगी। यह उद्योगों का उत्थान दो दृष्टिकोणों से होना चाहिये—बेकारी को दूर करने कार्य-स्रोतों की वृद्धि के लिए तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए। प्राचीन युग के यह उद्योग यद्यपि देशवासियों को काम दे सकते हैं परन्तु आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ाते। इस क्षेत्र में आयोजकों को जापान, स्वीटजरलैण्ड, जर्मनी आदि देशों की ओर देखना चाहिए। विद्युत का विकास हो, यंत्रों का प्रयोग बढे और कार्यकुशलता में वृद्धि हो। उत्पादन इतना हो कि राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही, बाह्य देशों में भी कुछ निर्यात किया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना जीवन रक्षा के विषय में नीति निर्धारित करे, पूँजी संगठन का भी पुरोगम हो, ग्रामों में अधिभरण सुविधाएँ हो और देश की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो। सारांश यह है कि योजना ऐसी हो जो देश को चारों ओर से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाँध दे। योजना कमीशन ने इन्हीं सिद्धान्तों और आदर्शों को सामने रखकर देश के लिए

पंचवर्षीय योजना बनाई है जिसमें कृषि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। फिर उद्योगों, समाज सुधार, शिक्षा आदि मूल बातों की भी व्यवस्था की गई है। योजना की विस्तृत रूपरेखा अगले निबन्ध में है। आशा है पाठक उसका अध्ययन के साथ समझने की चेष्टा करेंगे।

४६—पंचवर्षीय योजना—एक रूपरेखा

१९१० से पहले हमारे देश में आर्थिक आयोजन का कोई क्रमबद्ध उपक्रम नहीं था। उस समय आर्थिक आयोजन का विषय केवल सिद्धान्त की वस्तु ही समझा जाता था। परन्तु तीसा की मन्दी से देश के आर्थिक स्तर में जो उलट फेर हुई उससे निश्चित योजनानुसार देश का आर्थिक विकास करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। रुस ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो आर्थिक प्रगति की उससे सत्तर के देशों की आस्था आर्थिक आयोजन में जमने लगी। द्वितीय युद्ध काल में युद्ध के कारण जो आर्थिक विकलता पैदा हुई उससे तो आर्थिक आयोजन के विकास में और भी अधिक बढ़ावा मिला। युद्धोत्तर काल में लगभग सभी मुख्य देशों ने आर्थिक आयोजन करने निश्चित योजना-नुसार काम करना आरम्भ कर दिया।

भारत में आर्थिक आयोजन का क्रमबद्ध आरम्भ १९३५ से आरम्भ होता है जबकि कांग्रेस महासमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय-आयोजन समिति स्थापित करके देश के आर्थिक विकास की एक विस्तृत और क्रमबद्ध योजना बनाने का निश्चय किया था। १९४४ में देश के अग्रगण्य उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए 'बबई योजना' के नाम से एक योजना देश के सामने रखी। इसके पश्चात् 'पोपिल्स-योजना' तैयार हुई तथा आचार्य श्रीमदाश्वयण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की हुई एक 'गांधी-योजना' देश को दी। इन योजनाओं से प्रभावित होकर तथा देश की आवश्यकताओं को समझकर उस समय की विदेशी सरकार ने भी एक आर्थिक आयोजन विभाग खोला तथा स्वर्गीय श्री आर्देशर दलाल को योजना एवं विकास सम्बन्धी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् जब देशी सरकार ने भारत के विधान में 'कल्याणकारी राज्य' की कल्पना निर्धारित की तो यह आवश्यक समझा गया

कि देश के आर्थिक साधनों का जमा-वर्धन करके एक ऐसी योजना बनाई जाय जिसके अनुसार देश का आर्थिक विकास किया जा सके और स्वतन्त्र देशवासियों को भरपूर काम तथा पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं निवास की सुविधाएँ मिल सकें। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने मार्च १९५० में एक 'योजना कमीशन' नियुक्त किया। इस कमीशन के अध्यक्ष देश के प्रधान-मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा सदस्यों में श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री-वी० टी० कृष्णमाचारी, श्री निन्तामणि देशमुख, श्री जी० एल० मेहता, श्री आर० के० पाटिल हैं। कमीशन ने लगभग १५ महीने तक देश की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करके 'पंचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा' देश के सामने रखी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तीन भागों में बाँट दिया है— पहले भाग में उन सिद्धान्तों का वर्णन है जो कमीशन ने योजना तैयार करने में अपनाए हैं। दूसरे भाग में योजना की मूल बातों पर विचार किया गया है तथा तीसरे भाग में योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है।

रूस की पंचवर्षीय योजनाओं की भाँति इस योजना में देश के सभी आर्थिक पहलुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें आर्थिक विकास के केवल जन-पहलू पर ही विचार किया गया है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकार किस प्रकार १९५१-५२ से १९५५-५६ तक आर्थिक विकास पर आवश्यक धन राशि व्यय करेंगी। जहाँ तक व्यक्तिवादी उद्योगों का सम्बन्ध है कमीशन ने केवल ऐसी परिस्थितियाँ ही बनाने का आह्वान किया है जिनके अन्तर्गत व्यक्तिवादी उद्योग धन्धों को उन्नत करने से भरपूर लाभ प्राप्त हो सकें।

योजना के अन्तर्गत पाँच वर्षों में सरकारी क्षेत्र पर देश के आर्थिक विकास के लिए १७६६ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमानित व्यय-राशि दो अंशों में बाँट दी गई है। पहिले अंश के अन्तर्गत १५६३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस राशि से प्रधानतः उन विकास योजनाओं को पूरा किया जायगा जिन्हें सरकार ने वर्ष

मान में अपने हाथ में ले सकता है। इतना व्यय करने के पश्चात् कमीशन का अनुमान है कि देशवासियों को जीवन की वे सब अनिवार्य वस्तुएँ मिलने लगेंगी जो उन्हें युद्ध पूर्व काल में मिलती थीं। दूसरे अंग के अन्तर्गत ३०० करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे। इस राशि से आर्थिक प्रगति एवं उन्नति की ओर बढ़ा जायगा। कमीशन ने विलहान १४६३ करोड़ रुपये के अनुमानित-व्यय की रूपरेखा सरकार के सामने रखी है। यह राशि इस प्रकार व्यय की जायगी,—

	१६५१ ५६ (पाँच वर्षों में) व्यय राशि (करोड़ रुपये में)	कुल राशि का प्रतिशत (१६५१ ५६)
कृषि एवं ग्राम्य विकास	१६१ ७०	१२.८
सिंचाई और शक्ति	४५०.३६	३०.२
यातायात एवं संचार साधन	३८८.१२	२६.१
उद्योग	१००.६६	६.७
सामाजिक सेवाओं में व्यय	२५४.२२	१७.०
पुनर्वास	७६ ००	५.३
विविध	२८.५४	१.६
योग	<u>१४६२.६३</u>	<u>१००.०</u>

(अ) कृषि

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि योजना कमीशन ने अपनी योजना में कृषि को सर्व प्रथम स्थान दिया है। और दिया भी क्यों न जाय? देश की ८० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर अवलम्बित है। बड़े बड़े उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर आश्रित हैं अन्न का देश भर में भारी अकाल चल रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि को प्रथम स्थान मिलना कोई ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिए। अन्य योजनाओं की भाँति, जिनका उल्लेख पीछे किया गया है, इस योजना में आँकड़ों के बड़े-बड़े आशावादी पुनः नहीं बनाए गए हैं वरन् व्यावहारिकता, वास्तविकता और आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक

वस्तुओं को यथास्थान दिया गया है। कुछ लोगों का मत है कि जब योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर कुल व्यय का ३०%, यातायात एवं संचार पर २६% तथा समाज सेवाओं पर १७% व्यय होने का अनुमान है तो फिर उद्योगों के विकास पर ही केवल ७% क्यों? ये आलोचक इस बात को भूलते हैं कि देश कृषि प्रधान है जहाँ कृषि की उन्नति पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरे, औद्योगिक विकास के लिए तो अभी व्यक्तिवादो क्षेत्र भी पड़ा हुआ है। अतः योजना में कृषि को जो स्थान दिया गया है वह उपयुक्त ही है। योजना के अनुसार कृषि-विकास पर जो व्यय होगा वह इस प्रकार है—

	प्रथम दो वर्षों में (१९५१-५३) (करोड़ रुपये में)	कुल पाँच वर्षों में (१९५०-५६) (करोड़ रुपये में)
कृषि	६०८	१३६६
पशु रक्षा, चिकित्सा एवं दुग्धशालाएँ	६७	२२५
वन-विकास	३२	१०१
सहकारिता	३०	७२
मछली उद्योग	१४	४४
ग्राम्य-विकास	४०	१०६
योग	७६१	१६१७

इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का अनुमान है कि पाँच वर्षों के पश्चात्, योजना समाप्त होने पर १,५०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई होने लगेगी, ४०,००,००० एकड़ भूमि फिर कृषि योग्य बन जायगी तथा १५,००,००० एकड़ भूमि का कृषीकरण होने लगेगा। इतना करने पर कमीशन ने उत्पादन सम्बन्धी निम्न लक्ष्य निर्धारित किए हैं—

	(०००)
अन्न	७,२०० टन
पटसन	२,०६० गांठें

कपास	१,२०० गाँठें
तिलहन	३७५ टन
शकर	६६० टन

ये लक्ष्य भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए अलग अलग निश्चित कर दिये गए हैं जिससे राज्य सरकारें इन्हें प्राप्त करने में सचेत और जागरूक रहें। भिन्न-भिन्न राज्यों के लक्ष्य इस प्रकार हैं —

	अन्न (टनों में)	पटसन (४०० पौंड की गाँठों में)	कपास (२६२ पौंड की गाँठों में)	तिलहन (टनों में)	शकर (टनों में)
			(हजारों में)		
आसाम	३११	४४०	—	—	५०
बिहार	८७६	३६०	—	८५	५०
बर्मा	३६७	—	१६८	६३	३४
मध्य प्रदेश	३४७	—	१२८	२७	—
मद्रास	८३४	—	२१८	१४२	७८
उड़ीसा	२६५	२००	—	—	—
पंजाब	६५०	—	७६	—	५७
उत्तर प्रदेश	८००	३३०	४६	६१	४१०
पश्चिमोत्तरप्रदेश	७६७	७००	—	—	११
हैदराबाद	६३३	—	८८	४६	—
मध्य भारत	३००	—	६१	६.५	—
मैसूर	१५६	—	७५	—	—
पटियाला और पू० पंजाब रिया-					
सती मघ	२४६	—	५६	—	—
राजस्थान	८६	—	७५	—	—
सौराष्ट्र	६४	—	१५६	१५	—

ट्रायनकोर-

कोलीम	१४१	—	—	—	—
अन्य राज्य	२६०	—	१७	—	—
योग	<u>७१०२</u>	<u>२०६०</u>	<u>१२००</u>	<u>३७५०</u>	<u>६६०</u>

अन्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए कमीशन ने अरानी योजना में सिंचाई का विकास करने, रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाने, अच्छे तथा उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग बढ़ाने तथा बंजर-भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने की योजनाएँ बनाई हैं। इन उपायों के द्वारा अन्न-उत्पादन बढ़ाने के जो आँकड़े कमीशन ने निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार हैं —

विभिन्न साधनों द्वारा अन्न-उत्पादन बढ़ाने
के अनुमानित आँकड़े

योजना	अधिक अन्न-उत्पादन (००० टनों में)
१. बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं द्वारा	२,२७२
२. छोटी सिंचाई-योजनाओं द्वारा	१,६३२
३. भूमि को उपजाऊ बनाकर तथा कृषीकरण की योजनाओं द्वारा	१,५२४
४. खाद तथा अन्य रासायनिक पदार्थों को बढ़ाने की योजनाओं द्वारा	५८४
५. उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग बढ़ाकर	३७०
६. अन्य योजनाओं द्वारा	५२०
	<u>कुल ७,९०२</u>

भारतीय किसान को वर्षों की अनिश्चितता से बचाने के लिए कमीशन ने योजना में सिंचाई के भरपूर साधनों की व्यवस्था की है। सिंचाई पर ४५० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है जिससे शक्ति का भी विकास होगा और सिंचाई भी हो सकेगी। पाँच वर्षों में प्रति वर्ष इस मद पर इस प्रकार व्यय होगा —

वर्ष	व्यय (करोड़ों रुपया में)	अधिक भूमि परसिचाइ (एकड़ों में)	अधिक शक्ति उत्पादन (किलोवाट में)
१९५१-५२	६६	१५,५०,०००	१,४४,०००
१९५२-५३	११२	२७,१०,०००	३,७३,०००
१९५३-५४	१००	४५,२५,०००	८,८६,०००
१९५४-५५	७७	६७,२५,०००	१०,००,०००
१९५५-५६	५३	८८,३२,०००	११,२४,०००
अन्त में	—	१,६५,०१,०००	१६,३५,०००

(घ) उद्योग-धंधे

औद्योगिक क्षेत्र में कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगों की क्षमता के अनुसार भरपूर उत्पादन किया जाय। उद्योगों पर कमीशन ने इस प्रकार व्यय करने की व्यवस्था की है —

	प्रथम दो वर्षों में मिलाकर (१९५१-५३)	पूरे पाँच वर्षों में मिलाकर (१९५१-५६) (करोड़ रुपयों में)
विशाल उद्योगों पर	३८.१	७६.५
बुटीर एवं छोटे उद्योगों पर	४.८	१५.८
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शाोध पर	२.४	४.६
खनिज विकास पर	०.३	१.१
योग	<u>४५.६</u>	<u>१०१.०</u>

इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का विश्वास है कि पाँच वर्षों के बाद ४,५०,००,००,००० गज अधिक मिला के कपड़े का तथा १,६०,००,००,००० गज अधिक हाथ करघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सरेगा। इसी प्रकार योजना में व्यक्तिवादी उद्योगों तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं —

Name of industry	Unit	1950-51		1955-56 (estimated)	
		Installed capacity	Production (1950)	Installed capacity	Production.
Agricultural implements -					
i) Pumps (centrifugal)	Nos.	37,407	30,292	86,801	78,126
ii) Diesel engines	Nos.	11,826	4,596	51,326	46,193
Alcohol:					
i) Power	'000	12,868	4,497	21,118	19,006
	Bulk Galls.				
	'000	2,949	3,436	2,949	2,654
ii) Rectified spirit	Bulk Galls.	8,290			
	Tons	4,000	3,600	25,000	20,000
Aluminium (primary)	Nos	35,000	3,840	35,000	25,000
Automobile (manufacturing only)	'000 tons	3,276	2,613	5,140	4,631
Cement					
	Million lbs	1,646	1,174	1,671	1,600
Cotton textiles :					
i) Yarn		4,722	3,665	4,741	4,500
ii) Cloth (mill)	Million yards				
		123	52	216	179
Fertilizers :					
i) Superphosphate	'000 tons	74	47	129	100
ii) Ammonium sulphate	'000 tons				
Glass and glassware :					
i) Hollow-ware	'000 tons	211	86	232	174
ii) Sheetglass	" "	12	5	36	27
iii) Bangles	" "	35	16	35	17

Name of industry	Unit	1950-51		1955-56 (estimated)	
		Installed capacity	Production (1950)	Installed capacity	Production
Heavy chemicals :	'000 tons	150	102	230	180
i) Sulphuric acid	" "	54	44	86	78
ii) Soda ash	" "	19	11	33	29
iii) Caustic soda	" "	706	523	766	690
Matches	cases	140	109	212	165
Paper and paper board	tons	55,613	2,622	65,200	3,075
Salt		(Acres)	('000 tons)	(Acres)	('000 tons)
Soap	'000 tons	269	102	288	270
Steel (finished)	" "	1,071	1,005	1,659	1,315
Sugar	" "	1,520	1,100	1,540	1,500

(म) यातायात एवं मंचार

योजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में सब प्रकार के यातायात एवं मंचार साधनों का विकास करने की व्यवस्था की गई है। इस पर दस प्रकार व्यय किया जायगा—

प्रथम दो वर्षों में कुल पाँच वर्षों में मिलाकर
(१९५१-५३) (१९५१-५६)
(करोड़ों रुपये में)

रेलवे पर	८०	२०००
सड़कों पर	१७६	६३७
सड़क-गाहनों पर	४६	६६
जल-जहाजों पर	८७	१५६
हवाई जहाजों पर	३७	१५६
बन्दरगाहों पर	५३	१०८
आन्तरिक जल मार्गों पर	—	०२
ढाक एवं तार-रिमाम पर	१२८	४००
आकाशवाणी पर	६	३५
समुद्रवार यातायात पर	४	१०
अन्य	३	६

(द) समाज-सेवाओं पर

योजना के अन्तर्गत समाज-सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत हुए लोगों के कल्याण तथा समाज-सुधारों की भी व्यवस्था की गई है। कमिशन ने इन कामों पर निम्न प्रकार व्यय करने का अनुमान लगाया है :—

प्रथम दो वर्षों में कुल पाँच वर्षों में मिलाकर
(१९५१-५३) (१९५१-५६)
(करोड़ों रुपये में)

शिक्षा	४४५	१२३१
स्वास्थ्य	३३७	८३६

	प्रथम दो वर्षों में मिलाकर (१९५१-५३)	कुल पाँच वर्षों में मिलाकर (१९५१-५६) (करोड़ों रुपये में)
ग्रह व्यवस्था	६५	२२८
श्रम-कल्याणकारी कार्यों में	२५	६७
पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में	७०	१८०
योग	<u>९७१</u>	<u>२५४२</u>

औद्योगिक स्थानों पर मजदूरों को घरों का उचित प्रबन्ध करने के लिए कमीशन ने श्रमिकों, उद्योगपतियों एवं सरकार द्वारा मिली जुली एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत २५,००० घर प्रतिवर्ष बनाए जाया करेंगे तथा पाँच वर्ष में कुल मिलाकर १,२५,००० घर बनाए जाएँगे। पंचवर्षीय-योजना में औपधि-निर्माण तथा औपधि वितरण की भी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

× × × ×

उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने १४६३ करोड़ रुपये की जो पंचवर्षीय योजना दी है उसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस प्रकार व्यय करेंगी।

	प्रथम दो वर्षों में मिलाकर (१९५१-५३)	पाँच वर्षों में मिलाकर (१९५१-५६) (करोड़ रुपये में)
--	---	--

केन्द्रीय सरकार	३१५.६	७३४.०
‘अ’ राज्य-सरकारें	२४६.४	५५६.६
‘ब’ राज्य सरकारें	७६.७	१७१.०
‘स’ राज्य-सरकारें	६.७	२८.२
कुल योग	<u>६५४.७</u>	<u>१४६२.८</u>

राज्य-सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाओं पर इस प्रकार व्यय करने के निश्चय किए हैं :—

(करोड़ रुपये)

'स' राज्य

पंचवर्षीय योजना

३३१

व' राज्य

'अ' राज्य

आसाम	१२५	हैदराबाद	४०५	अजमेर	१६१
बिहार	११७	मध्य भारत	२२८	भोजपुर	३६७
बुन्दे	१२०४	मेसूर	३६६	बिलासपुर	०४२
मध्य प्रदेश	४३७	पटियाला और पूर्वो पंजाब	८३	बुर्ग	०५३
मद्रास	१३७०	रियासती रूप	१५२	दिल्ली	६०२
उड़ीसा	१५०	राजस्थान	२१५	हिमाचल प्रदेश	४४८
पंजाब	१५५	सौराष्ट्र	२६१	कच्छ	२६८
उत्तर प्रदेश	६११	द्रागनकोर कोर्नान	२६१	मनीपुर	१००
पश्चिमी बंगाल	६८८			त्रिपुरा	१५०
योग	५५६७		१७१०	त्रिपुर प्रदेश	६३६
					२८३०

योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आवश्यक पूँजी किस प्रकार प्राप्त करेंगी—इसकी भा रूपरेखा पंचवर्षीय योजना में दे दी गई है। केन्द्रीय सरकार आवश्यक पूँजी निम्न साधनों से प्राप्त करेगी—

	(करोड़ रुपये में)
१. रेवेन्यू लेखों पर बचत (२६ करोड़ रु० प्रतिवर्ष)	१३०
२. रेवेन्यू लेखों में से विभिन्न-योजनाओं के विकास को अलग निकाली हुई राशि	११८
३. पूँजीगत लेखों से प्राप्त राशि	
(१) जन अणु से	३५
(२) बचत योजनाओं से	२५०
(३) अन्य साधनों से	७८
४. रेलों की आय में से रेलवे विकास के हेतु निकाली हुई राशि	३०
योग	<u>६४१</u>

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार से ६४१ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकेगी—इसमें से २११ करोड़ रुपये राज्य सरकारों की सहायता के रूप में दे दिये जाएँगे। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार अपने लेखों पर कुल मिलाकर ४३० करोड़ रुपये व्यय करेगी। राज्य सरकारें अपने हिस्से के ४८० करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त करेंगी :—

	(करोड़ रुपये में)
१. रेवेन्यू लेखों का आधिक्य	८१
२. भिन्न-भिन्न विकास-योजनाओं पर व्यय करने के लिए अलग निकालकर रखी हुई रकम	२७५
३. विकास-योजनाओं के हेतु पूँजीगत लेखों से प्राप्त राशि—	

(१) जन श्रृंग	७६
(२) अन्य माधन	४४
योग	४८०

इस प्रकार राज्य सरकारें ४८० करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी। १९९ करोड़ रुपये उन्हें केन्द्रीय सरकार में मिलेंगे। कुल मिलाकर ६६९ करोड़ रुपये वे व्यय कर सकेंगी।

इस प्रकार केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलाकर ११२१ करोड़ रुपये का प्रबन्ध कर सकेंगी। प्रश्न यह है ३७२ करोड़ रुपये का प्रबन्ध कहाँ से होगा ? इसके लिए कमीशन का सुझाव है कि यह राशि कोलम्बो योजना के अर्थोत्पादक, वेनेडा और न्यूजीलैंड से प्राप्त होगी। कुछ राशि अमेरिका से अन्न-श्रृंग के रूप में भी मिलने का अनुमान लगाया गया है। यदि फिर भी काम न चले तो कमीशन का सुझाव है कि उसकी पूर्ति हमारे पीछे पावनों में से लेकर की जायगी। कमीशन ने आवश्यकतानुसार विदेशों से श्रृंग लेकर योजना को पूरा करने की सिफारिश भी की है बशर्ते कि उस विदेशी श्रृंग से हमारी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार की हानि न आए।

योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अभी कुछ वर्षों तक अन्न आयात की आशा की गई है। कहा गया है कि प्रांत व्यक्ति को प्रति दिन १४१ ग्राम भोजन देने के लिए कम से कम ३० लाख टन अन्न आयात करना पड़ेगा। यद्यपि यह बात हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की है परन्तु फिर भी सन्तोष करना पड़ता है कि योजना के अनुसार धीरे-धीरे यह आयात कम होता जायगा और देश अन्न के मामले में स्वायत्त बने जायगा। कमीशन ने मूल्य-नियंत्रण बनाये रखने की भी सिफारिश की है क्योंकि इसके बिना उत्पादन-वृद्धि के अभाव में मूल स्तर अनुकूल नहीं रह सकेंगे। सबसे बड़ी बात इस योजना में यह है कि हमारे अर्कड़े लक्ष्य अभाव और अत्यावहारिक नहीं है। कमीशन ने जन-विश्वास तथा जन सहयोग की भी आशा प्रकट की है क्योंकि इसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं बनाई जा सकती।

४७—कोलम्बो-योजना

दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रहने वाले लोगों के रहन सहन का स्तर सदैव से बहुत नीचा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये देश बहुत पिछड़े हुए हैं। लोगो को भोजन, कपड़े और निवास तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की नितान्त कमी रही है। न यहाँ शिक्षा है और न पाश्चात्य देशों की भाँति उत्पादन के प्रचुर साधन हैं। युद्ध काल में इन देशों की आर्थिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। गत पाँच वर्षों में इन देशों में जो राजनैतिक हलचल हुई हैं उनसे यहाँ के निवासियों को आर्थिक उन्नति करने का कुछ सहारा मिला है। संसार के आर्थिक दृष्टिकोण से इन देशों का बहुत महत्त्व है। इन्हीं देशों में, संसार भर की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल पैदा किया जाता है। युद्ध पूर्व काल में तो इन देशों में पटसन और रबर का एकाधिकार था और संसार में चाय के कुल उत्पादन का तीन चौथाई से भी अधिक, दोन का दो तिहाई से भी अधिक और तेल निलहनों का एक तिहाई से भी अधिक भाग अन्य योरोपीय देशों को भेजा जाता था। परन्तु शनैः शनैः इन देशों की स्थिति बिगड़ती गई। कॉमन-वैल्थ देशों ने अब भला प्रकार समझ लिया कि इन देशों को उन्नत किये बिना कॉमन वैल्थ व अन्य देशों का औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। अतः कॉमन वैल्थ देशों के विदेश मंत्रियों ने जनवरी १९५० में कोलम्बो में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में राजनैतिक शान्ति बनाये रखन तथा संसार के आर्थिक विकास के लिए बहुमुत्ती व्यापारिक प्रणाली स्थापित करने के लिए इन देशों का आर्थिक विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विस्तृत याजना बनाने को सम्मेलन ने कॉमन वैल्थ सनाहकार समिति बना दी। इस समिति ने दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए एक ६ वर्षीय याजना तैयार की जा १९५१ के मध्य से लागू

कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, लंका तथा मलाया और ब्रिटिश बोरिनियो के टापुओं के आर्थिक विकास की योजनाएँ सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार व्यय करने का अनुरोध किया गया है।

विकास योजनाओं का विश्लेषण
(०००,००० पौण्डो में)

	भारत	पाकिस्तान	लंका	मलाया और ब्रिटिश बोरिनियो	योग
कृषि विकास पर	४५६	८८	३८	१३	५९५
यातायात और संचार	५२७	५७	६२	२१	६६७
शक्ति-स्रोतों पर	४३	५१	८	२०	१२२
उद्योग और खनिज	१३५	५३	६	—	१९४
समाज उन्नति पर	२१८	३१	२८	५३	३३०
योग	१३७९	२८०	१०२	१०७	१८६८

योजना में उल्लिखित देशों में विशेषतः कृषि, यातायात और शक्ति विकास पर जोर दिया गया है। अन्न तथा औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यही प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। इन मदों पर अनुमानित राशि का ७० प्रतिशत व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों पर कुल व्यय का १० प्रतिशत लगाया जायगा। शेष राशि समाज सुधारों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और निवास सम्बन्धी सुविधाओं में व्यय की जायगी। योजना समिति ने यह भली प्रकार समझ लिया था कि सामाजिक उन्नति के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा अतः उन्होंने सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है।

योजना पूरी होने पर निम्नलिखित परिणाम मिलेंगे, यह अनुमान लगाया गया है :—

- (१) १,२०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर कृषि होने लगेगी।
- (२) ६०,००,००० टन अधिक अन्न उतारा जा सकेगा।
- (३) १,२०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी।

(४) ११,००,००० जिलोवाट अधिक विद्युत् उत्पन्न की जा सकेगी ।

योजना समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रकार १९५७ के अन्त तक (जब यह योजना समाप्त होगी) इन देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर में कोई विशेष और उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु लोगों के गिरते हुये जीवन स्तर को थाम कर उन्नति की ओर ले जाया जा सकेगा । एशियाई देशों को यह संतोष होने लगेगा कि ससार के अन्य देश उनकी आर्थिक उन्नति के प्रति सचेत और जागरूक हैं । यही नहीं, इस योजना के द्वारा इन देशों में भारी आर्थिक विकास की प्राथमिक आवश्यकताएँ, पूरी करके भविष्य के लिए सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी ।

योजना को कार्यान्वित करने में एशियाई देशों को कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी । यह आवश्यकता इस प्रकार पूरी की जाएगी । एक, योजना सम्बन्धी देशों में ही ट्रेनिंग की सुविधाएँ बढ़ा कर; दूसरा, विदेशों से कुशल विशेषज्ञ भेजा कर । कुशल विशेषज्ञ भेज कर सहायता देने का काम इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अन्य देशों के जिम्मे रक्खा गया है । इस विषय में दूसरी समस्या आवश्यक पूँजी प्राप्त करने की है । इसके लिए योजना के अनुसार विदेशों से पूँजी प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है । विदेशों से पूँजी इस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी । योजना सम्बन्धी देशों की विदेश-स्थित पूँजी को लाकर, विदेशों में पूँजीपतियों से ऋण लेकर, विदेशी सरकारों से ऋण लेकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय-संस्थाओं से ऋण लेकर ।

कोलम्यो योजना और भारत

इस योजना में भारत के आर्थिकविकास को प्रमुख स्थान मिला है । योजना के अनुसार लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने तथा उत्पादन बढ़ाकर बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्तुलन उत्पन्न करने के स्थिति रखे गये हैं । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह सुझाया गया है कि :—

(१) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी विकास योजनाएँ अरनाई जाएँ जिनसे सिंचाई के साधन तथा गाँवों में विजनी की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें ।

(२) खाद्य, रासायनिक पदार्थ तथा कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग बढ़ाकर भूमि की उपज बढ़ाई जाय ।

(३) गावागाव की सुविधाओं को विकसित और उन्नत बनाया जाय ।

(४) उद्योगों की कार्य-समय के अनुसार भारपूर उत्पादन दिया जाय तथा माटे और इस्तेमाल का उत्पादन बढ़ाया जाय ।

(५) गाँवों में बेरोजगार लोगों का तथा कुम्हनों को उनके खाली समय में काम देने के लिए छोटे और बड़े मन्थों को प्रोत्साहन दिया जाय ।

उक्त योजनाओं में से अनेक मदों पर पहले से ही काम चालू कर दिया गया है । अतः कोलार्यों योजना में उन सब योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है । योजना के अन्तर्गत भारत सरकार इस प्रकार व्यय करेगी :—

करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	%	योजनाएँ	
				पुरानी	नई
कृषि	६०८०	४५६	३१	१०४	२७
गावागाव-सुधार					
(अ) रेलवे ४८००	७०२७	५२७	३८	२७	१५
(ब) हाइवे १०६६					
(ग) प-दरगाह ११०					
अ-य १०१८					
शक्ति विकास	५७१	६३	३	२७	१
उद्योग और व्यापार	१८००	१३५	१०		२८
सांसाधन विकास				२६	
(अ) सिंचना ११६४	७६१३	६०८	१६	१०५	५०
(ब) निर्यात १८३					
(ग) रक्षा ५१५					
अ-य १०७१					
योग	१८३६६	११७६	१००	२८४	१३७

२ अप्रैल १९५२ को भारत के लिए मंत्री ने इस योजना का अन्तर्गत १८५० करोड़ रुपये का ओर व्यय निश्चित किया है उसको बढ़ाकर २३०० करोड़ रुपये तक १९५२

कर दिया है। वित्त मंत्री का अनुमान है कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए सम्भव है और अधिक व्यय करना पड़े। ऐसी अवस्था में सहाय विकास योजनाओं सम्बन्धी जो काम किया जाएगा उस पर व्यय बटने में इस योजना के अन्तर्गत कुल २५०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। वित्त-मंत्री ने कोलम्बो योजना में एक मूल सशोधन यह किया है कि नदी-घाटी योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने के लिए ५० करोड़ रुपये और अधिक व्यय किये जाएंगे। मूल योजना में १०६० करोड़ रुपया विदेशों से प्राप्त करके व्यय करने की व्यवस्था थी। सशोधित योजना में यद्यपि योजना का कुल व्यय २३०० करोड़ रुपया कर दिया गया है परन्तु विदेशी पूँजी की रकम १०६० करोड़ रुपये ही है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में तीन नदी घाटी योजनाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं। दामोदर घाटी योजना जिस पर ५०० मिलियन रुपये व्यय होंगे। हीराकुण्ड योजना जिस पर ३०० मिलियन रुपये व्यय होंगे। नाङ्गल-भाखरा योजना जिस पर ७५७ मिलियन रुपये व्यय होंगे। इन योजनाओं पर परले से ही काम चालू है। कोलम्बो योजना में इनसे सम्मिलित करने से और अधिक बढ़ावा मिला है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर ६० लाख एकर नई भूमि पर सिंचाई होगी और ७ लाख ८ हजार किलोवाट अधिक बिजली ली जा सकेगी। योजना में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सरकार के Integrated Crop Production Plan को दिया गया है जिसमें भूमि का कृषिकरण करके, कृषि का यन्त्रीकरण करके, उत्तम कोटि की खाद और बीज लगाकर तथा सिंचाई के साधन बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जायगा। अनुमान है कि १९५६-५७ के अन्त में जब यह योजना पूर्ण होगी तो ३० लाख टन अधिक अन्न, १ लाख ६५ हजार टन अधिक कपास, ३ लाख ७५ हजार टन अधिक पटसन तथा १५ लाख टन अधिक तिलहन उपजाये जा सकेंगे। यानायात का मुविधाएँ बढ़ाने में केवल रेलों पर ४८०० मिलियन रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इससे अन्तर्गत देश में नई लाइनें डाली जाएंगी जहाँ-तहाँ पुल बनेंगे, इन्जिन और डिब्बे बनाये जाएंगे तथा कुशल श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए मुविधाएँ दी जाएंगी। औद्योगिक-क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उत्पादन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। अनुमान है कि

इस योजना द्वारा ५ लाख टन अधिक इस्पात प्रति वर्ष पैदा किया जाया करेगा। योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को भी यथास्थान मिला है। हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने १० लाख पौण्ड देकर हमारे देश में औद्योगिक संस्था स्थापित करने के लिए, काम आरम्भ कर दिया है। जैसा कि याचना के आँकड़ों से ज्ञात होता है १६५६ ५७ के अन्न तक १६ औंस प्रति व्यक्ति भोजन तथा १५ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा प्राप्त हो सरेगा जबकि इस समय केवल १० गज प्रति व्यक्ति कपड़ा और १२ औंस प्रति व्यक्ति भोजन नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार कोलरबो योजना द्वारा हमारे आर्थिक विकास को एक नई प्रगति मिलेगी। पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ इस योजना को भी चालू करने में सरकार के सामने कोई कठिनाई नहीं है। वास्तव में कामन-वैल्थ देशों ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के विकास का कार्यक्रम बनाकर एक सामूहिक और आवश्यक कदम उठाया है। यह तो ठीक ही है कि इन देशों का आर्थिक विकास होगा अन्य देशों को कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत बनेंगे परन्तु साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि एशिया पर आई हुई राजनैतिक आँधी टल जाएगी। यदि हमी उचार इन देशों के उत्थान के विषय में सोचा जाता रहा तब तो ठीक है अन्यथा न मालूम फिर किस दिन यह देश साम्यवाद की ओर मुक्त जाएँ।



४८—मन्दी की ओर

१९३६ में युद्ध आरम्भ होने पर वस्तुओं के भाव ऊँचे चढ़न लग गये। युद्ध समाप्त होने तक ऊँचे ही बने रहे। युद्ध समाप्त होने पर आशा की जाती थी कि वस्तुओं के भाव कुछ नीचे हाग जिससे सामान्य जनता को, विशेषतः मध्यम वर्ग का, कुछ सुलभ होगा, परन्तु आशा खरल आशा ही बना रही। यही नहीं, युद्धात्तरकाल में भाव और भी अधिक ऊँचे हो गए जिससे मध्यम वर्ग तिनमिला उठा। वैसे तो व्यापार चक्र के सिद्धान्तों के अनुसार १९४६ ५० में मन्दी हो जानी चाहिए थी परन्तु कौरिया, न युद्ध ने तथा उसके कारण उत्पन्न हुई अमरीका, इङ्गलैण्ड तथा अन्य देशों का पुनर्शास्त्रीकरण तथा माल संग्रह की योजनाओं ने मन्दी को आने से रोक दिया और बदले में तेजा बढन लगी। परन्तु मार्च १९५२ में मन्दी का घड़ा फूट निकला। कीमतों में कल्पना तीन कमी के कारण देश भर में भारी तहलका मच गया। सोना चाँदी, तिनहन, दाल, काली मिर्च, गुड़, चीनी, मसाले तथा फिराने की अन्य वस्तुओं की थोड़ी कीमतों में भारी कमा आ गई। सोने चाँदी के मूल्यों में तो जबर्दस्त गिरावट आ गई थी। दिल्ली में ५ मार्च को सोने का भाव ७१ रुपये से ७० रुपये तक रहा और चाँदी १५५ रुपये के भाव से बिनी, सामान्य जनता अपने आभूषण बेचने के लिए बाजारों का चक्र फाटने लगी। बैरों में जमा सोने-चाँदी पर बैंक जमा करने वालों से हानि की प्रति करने के लिए हट करने लगे तथा हानि की प्रति न होने पर बैंक अपने पास जमा किए हुए सोने-चाँदी को बेचने लगे। फिराने की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा यह ५ मार्च के दिल्ली के भावों से ज्ञात होता है—सोठ का भाव ११० रुपये में ५५ रुपये तक, दालों का भाव ३० रुपये से २ रुपये मन तक, मिर्च ५० रुपये से ३० रुपये, धनियाँ ८० रुपये से ४० रुपये तक तथा हल्दी ४५ रुपये से ३० रुपये तक हो गये। पटियाला में मिर्च ३५ रुपये से गिरकर २५ रुपये हो गई। काली मिर्च कोचीन में ३००० रुपये प्रति गाठ से गिरकर ३ दिनों में ही २५०० रुपये रह गई।

२५ फरवरी को दिल्ली में निरहन का भाव ३५० रुपये प्रति इन्डियेट था जो ५ मार्च को १२८ रुपये तक गिर गया।

हाफुड में १ जनवरी को गुड का भाव १८ रुपये मन था जो ५ मार्च को ६-७ रुपये प्रति मन रह गया। कोचीन में गोले के तेल का भाव तान १८ नों में ४८० रुपये से नीचे गिर कर ३१२ रुपये रह गया। मूंगफली का तेल २६ फरवरी को २६५ रुपये प्रति मन मिल रहा था, जब ५ मार्च को २२० रुपये में भी नहीं बिक पा रहा था। खुधियाने में सरसा का तेल २१ रुपये में गिरकर ११ रुपये हो गया। चीनी जो फरवरी में १ रु. १२ आने पर तक बिक रही थी मार्च में १५ आने प्रति सेर बिकने लगी। इस प्रकार देश भर में वस्तुओं के भाव नीचे हो गए। उत्पादक और व्यापारी-क्षेत्रों में त्राहि त्राहि मच गई।

जयपुर बाजार की भी यही हालत रही। भाव निरन्तर गिरते गए। २८ फरवरी को टाटा डिफेंड का भाव १६७६ रुपये था किन्तु ५ मार्च को निम्नतम भाव १५६५ रुपये हो गया। वनस्पति धी और साबुन के भाव भी २५-३० प्रति शत गिर गए।

कपड़ा-बाजार में ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के भाव सबसे पहिले गिरने आरम्भ हुए। इसके बाद सूती कपड़ों के दाम भी गिरने लगे। सरकार ने कपड़े के निरन्तरण पर से नियंत्रण तोड़ दिया परन्तु फिर भी कपड़े के माहक नहीं मिल रहे थे। बारदाने के भाव मन दो महीनों में ५० से १०० प्रतिशत तक गिर गए।

प्रायः सभी व्यापारिक शहरों में उधल-पुधल सी मची हुई थी। रसदार वही नहीं मिलता, बिकवाल सब बन गए और सब जगह घम रहे थे। कीमतों के निरन्तर गिरते जाने तथा सोने की दुर्लभता से बहुत से व्यापारी पबरा उठे थे। बहुतों के दिवालिया निम्नक गए, बहुतों के टाट उलट गए और अनेकों के दिवालिया बन जाने की आशंका प्रतीक्षण बनी हुई थी। बहुत से नगरों में तो तारोबार कई दिनों तक बन्द रहा। वायदे के मोदे बन्द कर दिए गए। सोने चांदी के वायदे के लेन-देन रोक दिए गए। स्टॉक एक्सचेंज बन्द करने पड़े उद्योग-पतियों ने उद्योग-कारखानों में उत्पादन का काम बसा दिया। सरकार से अनु-रोध किया जाने लगा कि वह कौद कटोर बंदम उठाकर कीमतों को बढ़ावा दे। इस असाधारण मन्दी का प्रभाव भिन्न भिन्न वर्गों पर भिन्न भिन्न प्रकार से

पड़ा। वेतन-भोगी वर्ग, उपभोक्ता-समुदाय एवं मध्यम वर्ग ने भावा की मन्दी जाते देख सन्तोष की साँम ली। ये वर्ग पिछले १२-१३ वर्षों से ऊँचे भावों की कठोर चक्की में इस प्रकार पिस रहा था कि मन्दी की हवा पाकर इसने प्राण लौट आए। सोचने लगा कि मन्दी किसी प्रकार स्थायी बनी रहे जिसमें खाने, पीने, पहिनने आदि की वस्तुएँ सरलता में सस्ती प्राप्त होती रहें। इसके विपरीत व्यापारियों, मगहकर्त्ताओं, उद्योगपतियों तथा काला-बाजार करने वाले वर्गों पर मन्दी में गहरी चोट लगी। उनमें माल के नफे कम हो गए, काला बाजार करने का स्रोत समाप्त हो गया तथा व्यापार में अघाघुन्ध लाभ कमाने के अग्रसर समाप्त हो गए। इसी कारण उन्होंने सरकार से प्रार्थना की, प्रतिनिधि मण्डल भेजे, मुक्तार दिए तथा अन्य सभी कुछ प्रयत्न किए कि किसी प्रकार सरकार गिरते हुए भावा की रोक कर मन्दी को दूर करे। परन्तु सरकार ने तब तक एक न सुनी। रिक्त मंत्री तथा उद्योग और वाणिज्य-मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया था कि “मन्दी सरकार के प्रयत्नों का परिणाम है इसलिए उसे दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती”। यह जान कर उद्योगपतियों ने एक नई चाल अपनाई। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि मन्दी के कारण उनका माल पड़ा हुआ है इसलिए वे अपने कारखानों को बन्द किए देते हैं। सरकार ने उनकी धमकी स्वीकार करनी और जनता को मिथ्यास दिलाया कि इस प्रकार उत्पादन में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं होगा। इतना अग्रसर है कि सरकार ने गुड़ चीनी का निर्यात खोल दिया जिसमें भाव कुछ कसते जा रहे थे। दूसरे, सरकार ने कुछ वस्तुओं, जैसे जूट तथा जूट का सामान, पर निर्यात कर आधा कर दिया तथा तिलहन एवं तेल पर भी निर्यात कर की छूट दी। परन्तु जैसा कि सरकार ने बतलाया है यह सब कुछ मन्दी को दूर करके भाव उठा करने के लिए नहीं किया गया या बरन् भुगतान विपमता को दूर करने के लिए, निर्यात-वृद्धि के लिए किया गया था। कुछ भी हा, सरकार का चाहिए था कि इस आए हुए अवसर को हाथ से न जाने देती और गिरते हुये भावा की स्थायी बनाने का प्रयत्न करती।

इस मन्दी के कारणों पर सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं। बायदे के लेन-देन में जनता का विस्थापन न रहना इसका

एक कारण बताया जा रहा है। बाजार में समशीत मान की निकामी एवं बैंकों द्वारा सिक्यूरिटियों पर श्रुण देने से इनकारों भी इसका एक प्रधान कारण दीखता है। बैंकों ने अपने व्यापारियों को नोटिस दिया कि वे अपना सोना ले जायें और बैंकों का हिस्सा माफ कर दें। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो सोना बाजार-भाव में बेच दिया जायगा। बेचारे व्यापारी अपना निकालने के लिए माल बेचने पर विवश हैं—अन्य माल का भाव गिरत जा रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सोने-चर्दी का उत्पादन बढ़ने से उनका भार गिरने और उन भावों के साथ-साथ बाजार के अन्य क्षेत्रों में भी मन्दी आ गई। १९५० और १९५१ में सोने-चर्दी का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

—सोना—		
वर्ष	मात्रा	मूल्य
१९५०	१९६६१५ ग्राम	५६२१२४५४ रुपये
१९५१	२२६२३१ ग्राम	३१७१६८६५ रुपये
—चौदी—		
१९५०	१५६७६ ग्राम	६७६२२ रुपये
१९५१	१७१८० ग्राम	८४१८४ रुपये

सभी लोगों का मत है कि बाजार में मन्दी आना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्य तो यही है कि यह इतनी देर से क्यों आई और इतनी तेजी के साथ क्यों आई। प्रसिद्ध उद्योगपति के. डी. जलान ने कहा था कि 'मन्दी में हमें कोई घबराहट नहीं है वरन् घबराहट हम मान में है कि यह इतनी तेजी के साथ एक दम आकर गड़की हो गई, जिससे हमें अपना घर मजाने का अथकाश भी न मिल सके'। यदि सब पट्टा जाय तो मन्दी का भीजरोपण उभी दिन हो गया था जिस दिन भारत सरकार ने बैंक-दर १% से बढ़ाकर ३३% कर दी थी और बैंकों की गुली बाजार जियाओं पर पाबंदी लगा दी थी। बाजार में पहिले ही रुपये की कमी थी। भारत सरकार को १ अरब रुपये कर्ज मांगने पर केवल ५० करोड़ रुपये मिला था। ऐसे समय में बैंक-दर बढ़ाने से जो थोड़ा बहुत रुपया बाजार में था वह भी खिंच आया। अमेरिका ने भारी मात्रा में माल समझ कर लिया था। अब उसे आवश्यकता नहीं रही थी।

अतः मान नी खरीद कम होने से उसके दाम गिरने आरम्भ हो गए। इसलिए यह स्वाभाविक था कि बैंक माल रखकर दिए गए रुपये की चिन्ता करते। माल के दाम कम हो जाने से लोग बैंकों का रुपया हजम कर जाते और बैंक को भारी हानि रहती। इसलिए ऋण देने में बैंकों को उदारता छोड़नी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ है कि बाजार में रुपये की कमी हो गई और जब रुपये की कमी हुई, तो वह महंगा हो गया अर्थात् चीजें सस्ती होने लगीं। ज्यों-ज्यों रुपये की कमी होती गई बैंक अपना रुपया बचाने की अधिक चिन्ता करने लगे और रुपया देने में न केवल अनुदार होने गए, अपितु अपना दिया हुआ रुपया भी व्यापारियों के पास से लेने का प्रयत्न करने लगे। व्यापारियों का रुपये का जरूरत हुई, उन्हान गोदाम का माल बेचना शुरू किया। खरीदार कोई न रहा, विक्राल सब बन गये। चीजों के दाम गिरने लगे। बाजार में धराहट काम करती है। एक स्थान पर एक चीज के दाम गिरने लग तो दूसरे स्थान पर दूसरी चीजों के दाम भी गिरते गए। यही हुआ और ग्लोब जोर शोर से हुआ। मन्दी की आग देश भर में दौड़ गई।

बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी और उद्योगपति श्री चुर्ननाल मेहता ने एक लेख में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि चीजों की कीमतों में कमी की नींव ७ नवम्बर ५९ को रखी गई थी, जबकि ब्रिटेन में सरकार ने बैंक की व्याज-दर बढ़ा कर मुद्रा प्रसार पर रोक लगा दी थी। गिर्ज बँक ने भी उसकी नकल की और बैंक दर बढ़ा दी। उसी समय सरकारी बजों के सम्बन्ध की गेट बैंक की घोषणा से उनका मूल्य ६८॥) रु. से गिरकर ८०) रु. रह गया था। वे मूल्य और गिर जाते यदि बैंक ८०) रु. पर सरकारी बजों को खरीद न कर लेता।

मन्दी का दूसरा कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे माल के संग्रह में एक दम कमी भी है। उसने जब माल खरीदना बन्द किया, तो व्यापारियों ने नुकसान की आशंका से अपना माल निरालना शुरू किया। यहाँ रुई जमा हो गई, भारत सरकार ने १ लाख गॉट बगाल रुई बाहर भेजने की अनुमति दे दी किन्तु उसे खरीदने वाले ही नहीं मिले। यही हाल तेलो व तिनहन का

गा। निदेशों में इसकी मॉग ही नहीं थी। अब भारत में व्यापारों बहुत घटने लगे और अपने सौदाग बाली करने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि बैंकों ने उनके माल पर कपया अधिक समय तक देने से इनकार कर दिया। बैंक भी क्या करते। माल के दाम कम हो जाने से उनका रुपया दूबने का भय था। पारे की भारत में प्रतिवर्ष २००० बैरल जहूरत रहती है, किन्तु भारत में २५००० बैरल तक जमा था। इसी तरह रम, मैमीरल, आदि भी, जिनकी मंगा बहुत अधिक जमा थी बाजार में मॉग कम हो जाने से बाहर निरलने लगे।

स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा। स्टॉक के कारण शेयरों का भाव अब तक स्थिर रहा था। टाटा डेपॉजिट शेयरों के बारे में सरकार नई शर्तों कंपनी के साथ कर रही है, यह अफवाह उद्घाटन कृष्ण मट्टेबाजो ने शेयरों के दाम कुछ दिनों में ही १७५० रु. से बढ़ाकर १६८० रु. तक कर दिये थे। लेकिन जब इन अफवाहों की पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हुई, इसलिये टाटा डेपॉजिट शेयरों के मूल्य एक दम गिरने लगे। पदार्थों के नुकस गिरने का प्रभाव पारे शेयर-बाजार पर पड़ा। भी मंगला ने मन्दी का स्वागत किया है और आशा प्रगट की है कि जो काम सरकार वर्षों समय करने पर भी न कर सकी, वह अब स्वयं हो गया।

रिजर्व बैंक द्वारा विरलेपण

मन्दी के कारणों का विरलेपण करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने निरला है कि उसकी निर्मेशरी मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय कारणों पर है जिनमें से मार्च १९५१ में अमेरिका के सामरिक वस्तुओं के संलग्न कार्यक्रम में कमीशन प्रधान है। जून १९५१ में कोरियाई विराम-संधि वार्ता प्रारम्भ होने के बाद विरारट का रुप और अधिक स्पष्ट हो गया और धीरे-धीरे अन्य वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ता गया। इसके अतिरिक्त और भी अन्तर्राष्ट्रीय कारण हुए जैसे, (१) पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी गई, (२) अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री-सम्मेलन के प्रयत्नों से कुछ दुर्लभ कच्चा माल अधिक मुलभ होता गया, (३) कुछ दुर्लभ वस्तुओं का सारे संसार में मिलाकर उत्पादन बढ़ा। इन सब कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दीले एक गए जिसका

प्रभार हमारे बाजारों पर भी पड़ा ।

जहाँ एक ओर अन्तराष्ट्रीय कारणों से देश में कमजोरि गिर रही थी वहाँ दूसरी ओर ठीक उसी समय भारत सरकार ने भी मूल्यों को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाये तथा सरकार ने अग्रणी व्यापार नीति में कुछ परिवर्तन करके नीजा का अधिक सुलभ बना दिया और साथ ही उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयत्न किया । देशी कारणों में मन्दी के निम्न कारण थे — (१) १९५१-५२ के संशोधित बजट में सरकार को भारी बचत, (२) विदेशी व्यापार के भुगतान में असंतुलन और भारी माना में अन्न का आयात, (३) नवम्बर १९५१ में बैंक-दर में वृद्धि, (४) आगामी फसल के अनुकूल समाचार, और (५) किसी किसी राज्य में वस्तुओं के अन्तराष्ट्रीय आयातों की सुविधाएँ ।

प्रश्न यह है कि क्या इस मन्दी से कुछ लाभ हुआ ? असल बात तो यह है कि हम सभी मूल्यों के चढ़ाव से परेशान थे और उन्हें कम करने की मनौती मनाते थे । वही सब कुछ हा गया । अन्न तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह मन्दी क्या रूप लेगी और कब तक रहेगी ? कुछ दिनों से वस्तुओं के भावों में कुछ तेजी आने लग गई है । आवश्यकता तो इस बात की है कि इसे स्थायी बनाया जाय । इस व्यापक समाधारण मन्दी के कारण यदि किसी प्रकार अन्न के भाव भी कम हो जाते तो संतुलन अधिक रहता, क्योंकि हमारी वही सबसे मूल वस्तु है । अन्न के भावों में मन्दी के बिना ऐसी भी मन्दी अधूरी ही रहेगी ।

४६—वाणिज्य शिक्षण—मूल समस्या

आज हमारे जो नवयुवक स्कूलों व कालेजों से वाणिज्य शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं उनका यही उद्देश्य रहना है कि कहीं पर कार्यालय में जूकें हो जाए या कहीं बैंक अथवा बीमा कम्पनी में लेखापाल बन जाए। वे १०० रुपये और कभी-कभी इससे भी कम राशि के वेतन में अपने जीवन को दूसरों के हाथ बेच डालने में बिल्कुल नहीं हिचकते जबकि उनके बी. कॉम. और एम. कॉम. पास करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे वाणिज्य-शास्त्री एवं वाणिज्य-विशारद बनकर स्वयं देश के बड़े व्यापारों में और शामलों और सामान्य जनता को भी मार्ग प्रदर्शन करेंगे। परन्तु ऐसा नहीं होता। आज कितने ऐसे बी. कॉम. और एम. कॉम. हैं जो अपना निज का व्यापार करने में समर्थ हो सके हैं? उत्तर मिलता है 'कोई नहीं'; और यदि हैं भी तो केवल एक-दो। दूसरी ओर देखा जाय तो शान होगा कि देश का सारा व्यापार उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने वाणिज्य का साधारण शिक्षा भी किसी स्कूल में नहीं ली है और वे अपने काम में फिर भी सकल हो सके हैं। प्रश्न यह है कि यह कठिनाई हमारे उन नवयुवकों के सामने उपस्थित हो क्यों हुई कि वे उचित शिक्षा प्राप्त करने पर भी श्रोग्य हो रहे। यह तो हास्य ही नहीं बरन् एक बड़ी विडम्बना व वैषम्य-सा प्रतीत होता है। वृद्ध-निष्ठ लोग देश की वाणिज्य उन्नति में हाथ नहीं बँटा रहे—इसका अर्थ तो यही है कि वाणिज्य शिक्षण में कुछ दोर है और वह उनको अभीष्ट उद्देश्य का प्राप्ति के लिए योग्य नहीं बना पाता। समस्या बड़ी मूल है और विचारणीय भी।

वास्तव में यदि मन पूछा जाय तो वाणिज्य की शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है। विद्यार्थी के मस्तिष्क पर एक बोझा-सा ढालने की चेष्टा की जाती है। उसे भली प्रकार बाल समझने के साधन उपस्थित नहीं किए जाते, गहराई की बातों को तो वे केवल रट लेते हैं और वह भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लोभ से। वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा देने का हमारे देश में कोई

प्रबन्ध नहीं है। हमारे यहाँ वाणिज्य शिक्षा का पाठ्यक्रम अरैमानिक एवं अपूर्ण है। जो कुछ भा टूटा पड़ा एवं अत्याभासक नाम हमें विदेशियों ने दिया हमने समझा कि वही स्वर्ण है और हमारे योग्य है। उसी को अपना लिया। क्या हमारे देश की जनशक्ति, प्राकृतिक वनस्पति, एवं रीति-रिवाजों पर विदेशी गारण्य प्रणालियों घटित हो ही जाएंगी? इस प्रश्न को अभी नहीं सोना। हमारे यहाँ क्या क्या पैदा होता है और क्या क्या व्यापार भर्त्ता प्रसार बढ़ाया जा सकता है और हमें क्या करना चाहिए? ये सब बातें तो हमारे दृष्टिकोण में बाहर की वस्तुएँ रही हैं।

वाणिज्य शिक्षा का माध्यम प्रबन्ध तब अंग्रेजी ही रहा जिसने हमारे नवयुवकों का उससे तत्वज्ञान का समझने में बर्तनाई ही करी रही। यदि स्वदेशी भाषा में वाणिज्य शिक्षा का कार्य किया जाये तो किन्हीं आसानी हो और वाणिज्य, जो नीरस विषय बना हुआ है, सरस हो जाये और साथ ही साथ देश की शक्ति एवं मनन की पूर्ण मितव्ययिता हो। हमारे अशक्त वर्ग को अबतक देश की सरकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए थे। हिन्दी में तो व्यापारिक लेन-देन का काम होता ही नहीं था। हिन्दी में लेखा वर्ग करने वालों को १५ रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। अब सभी लोग अंग्रेजी को अपनाने के प्रयत्न में रहते थे। इधर सरकार चाहती थी कि उनके बर्क मिलते रहें। अब सरकार ने शिक्षा को ऐसा ही बना दिया। पिटुनी सरकार स्वयं व्यापारी वर्ग थी। भारतीयों को व्यापारिक-लेन में उन्नत करते देख उन्हें ईर्ष्या होती थी। फलतः निम्न प्रकार का प्रोत्साहन सरकार ने हमारे नवयुवकों को नहीं दिया। अपनी स्मृति की आर्थिक हीनता, शैक्षिक, यह प्रेम एवं अयोग्यता और दासत्व की भावना ने कारण कई नवयुवक तो निराश कर दिए जाने थे वे प्रत्यक्ष कह कर कि इन बेचारों से साधारण जोड़ना-घटाना भी नहीं आता। यदि वाणिज्य शिक्षा प्राप्त युवकों को थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया होता तो वे आशातीत प्रगति करने में इतने पीछे नहीं रहते।

हमारे देश में अभी तक वाणिज्य शिक्षा का विज्ञान एवं ग्रन्थ विद्यों की शिक्षा से कोई संबंध नहीं रहा है। वास्तविकता तो यह है कि वाणिज्य की

शिक्षा के साथ साथ हमें कई अन्य विषयों की उपेक्षा नहीं करना होगी। यह विषय हैं विज्ञान, रेली, राजनीति एवं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एवं छोटे-से-छोटे व्यापारी का भी यह अनुभव है कि इन बातों का अत्यन्त एवं अप्रत्यक्ष रूप में जानना अवश्य पड़ता है, अन्यथा व्यापार में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। अतः हमारे वाणिज्य के विद्यार्थी यह किन्तु जानने ही नहीं है कि विज्ञान इत्यादि विषयों का वाणिज्य से क्या संबंध है। उदा. मनोविज्ञान भी वाणिज्य में कुछ सहायता कर सकता है। यही कारण है कि कई लोग उन्हें समुचित ज्ञान वाले एवं नीतिज्ञ जानने वाले मानते हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जहाँ अन्य उदा. जैसे सरकारी सहयोग की आवश्यकता है वहाँ वाणिज्य-शिक्षण-व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। तभी हमारे अध्यापक एवं विद्यार्थी इस योग्य हो पायेंगे कि वे मनोविक्षिप्त कार्य कर सकें। सबसे प्रथम तो वाणिज्य के विदेश शिक्षण की आवश्यकता है। सरकार ऐसे शिक्षालयों का निर्माण करे जहाँ पर सब आधुनिक वाणिज्य शिक्षा-संबंधी उपस्थित विषय आवें। अनुभवी अध्यापक ही रहने जायें। यह भी ध्यान दिया जाय कि वहाँ अध्यापक ठीक कार्य कर सकेंगे हैं जिनके अन्य कुछोबी जन पहले से ही व्यापार-कला में निपुण हैं और वे स्वयं व्यापार कर रहे हों। अच्छा हो कि वही विषय उनको पढ़ाने के लिए दिये जायें जिन विषयों के वे विशेषज्ञ हैं। इनकमटेक्स अफिसरी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की मैनेजरी, लिमिटेड कंपनी की डाइरेक्टरी और सेक्रेटरी-गिरी एवं दूसरे प्रकार प्रत्येक विषय के लिए ऐसे अध्यापक हों जो B. Com. और M. Com. की डिग्री रखने के अनिवार्य वाणिज्य संबंधी व्यक्तिगत अनुभव भी रखते हों। अच्छा हो कि वे विदेश विदेशों की भाषा ज्ञान रखें हों।

स्कूलों और कॉलेजों में जहाँ व्यापारिक शिक्षा दी जाती है वहाँ प्रत्येक सामान्य उपस्थित किया जाय। सरकारी भाण्डार, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियाँ तथा अन्य छोटे-बड़े कारखानों में विद्यार्थी काम भीगते रहें और अन्य समय एवं परिधम बचाने के सहायक यंत्रों का प्रयोग भी सीखें। अध्यापक अपनी निगरानी में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ विद्यार्थियों को मतावे और स्वयं उनको वही कार्य करने की आज्ञा दे। विद्यार्थियों के हृदय में ऐसी भावना प्रत्येक दाय

होनी चाहिये कि उन्हें स्वयं आगे चलकर एक बड़ा व्यापारी बनना है। इस प्रकार कार्य करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। अभी सरकार कार्य व्यस्त होने के कारण इधर ध्यान नहीं दे सकती तो फिर दा एक सान हमारे शिक्षा सस्थाओं के अधिकारी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यदि उनमें एक परिवर्तन की भावना हो ता। अध्यापक यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बड़े होन हैं किन्तु जा कुछ भी वे कर सकने हैं कर्तव्य परायण ढाकर दश की सेवा म हाथ बटाते रहें। हमारे देश के कई धनाढ्य सेठों ने इस कार्य में पहल स हा कुछ किया है और आशा है कि वे और अधिक सहयोग देते रहेंगे। शिक्षा-विभाग को चाहिये कि यह बड़े बड़े वाणिज्य शिक्षका का सहयोग और सम्मति लेकर कार्य को बढ़ावे और केवल उन्हीं कालिजों और स्कूलों को वाणिज्य शिक्षा-प्रसार की याजा दे जो पूणत योग्य हों और जहाँ आवश्यक सामग्री और अध्यापक एवं स्थान इत्यादि ठीक हों। कई सस्थाओं में किसी सामा तक इधर काय किया गया है किन्तु वह अपर्याप्त ही है अथवा अस्वाभाविक सा है।

एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाणिज्य शिक्षालय केवल-वहीं प्रस्थापित किए जावें जहाँ पर व्यापार होता हो, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता इत्यादि। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। बहुत-सा बातें तो वे स्वतः ही ज्ञात कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को विशेष अध्ययन के लिए यथाशक्ति विदेशों में भेजा जाय। सरकार एक शिक्षण सस्थाएँ व्यापारिक यात्रा एवं पर्यटन की सुविधाएँ दें। कई-कई माह तक विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाए। इनक साथ में कार्य कुशल अध्यापक भी हो। साथ ही प्रत्येक कारखाने में मार्ग-दर्शक की भी नियुक्ति कारखाना में मालिक करें। ठहरने एवं भोजन की भी व्यवस्था की जावे। शिक्षण सस्थाओं में चित्रचित्र प्रदर्शनों के द्वारा वाणिज्य सब ची बातों का ज्ञान कराया जाय। साथ ही साथ बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योग-पतियों को आमंत्रित किया जावे कि वे आकर वाणिज्य के विद्यार्थियों का व्याख्यान दें और अपने अनुभवों पर प्रकाश डालें।

स्कूल और कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थियों को व्यापारिक सस्थाओं में व्यापारिक काम सीखने के लिए भेजा जाय। विश्वविद्यालय

अपने-अपने वाणिज्य-पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करके यह मान आनि-
 थार्य बना दें कि वाणिज्य की परीक्षा पास कर लेने पर भी डिग्री तब तक न
 दी जाय जबतक कि विद्यार्थी किसी निश्चित अवधि तक व्यापारिक रुग्णाश्रों में
 जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त न करले। इसके साथ-साथ ही वाणिज्य शिक्षा
 का काम हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा किया जाय। अध्यापकों को चाहिए कि
 वे भरसक प्रयत्न करके अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को भी अवनायें। वाणिज्य
 मसम्मा की पुस्तकें हिन्दी में लिखी जाएँ। अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद भी किया
 जाय परन्तु अनुवाद उन्हीं लोगों में कराया जाय जो भाषा के साथ-साथ इस
 विषय को भी भली भाँति जानने हों। प्रायः देखा जाता है कि आजकल वाणिज्य
 की हिन्दी-पुस्तकों की बाढ़ भी आ रही है। परन्तु उनमें से अधिकांश
 बेदुम्ली और अपूर्ण हैं। साधारणतः पुस्तकें या अनुवाद मात्र आ रहा है और
 वह भी उन व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं अनुवाद करना तो जानते हैं परन्तु उस
 विषय से मिलकुल अनभिज्ञ हैं। फलतः यदि भाषा ठीक होती है तो विषय का
 अर्थ उलटा गुलटा होता है। इससे लाभ की अपेक्षा हानि होने लगी है।
 अनुवाद उन्हीं लोगों में कराया जाय जो हिन्दी भाषा भी जानने हैं, और साथ-साथ
 विषय का भी गम्भीर ज्ञान रखने हों जिससे भाषा और भाषा में ताल-मेल बना
 रहे। इसमें निदेशविशालयों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। आजकल
 सबसे बड़ी कठिनाई हिन्दी शब्द-कोष की है। इसके लिए सरकार एक काम
 करे। एक निरोपण-समिति बनाकर शब्द-कोष निर्धारित करे और वही कोष
 पुस्तक लिखने व पठन-पाठन में काम आवे। वर्तमान सरकार ने समिति बनाई है
 परन्तु अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इस विषय में पुस्तक प्रकाशकों
 को भी चाहिए कि वे भाषा और भाषा में मेल बनाने हेतु पुस्तकों का ही प्रका-
 शन करें और प्रकाशित करने में पहिले निरोपणों की अनुमति ले लें। इस प्रकार
 केवल उत्तम कौटि की पुस्तक का प्रकाशन होगा।

हमारी वाणिज्य शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। जो बुद्ध भण्डा
 जाये, लिखा जावे, सब देश का व्यापारिक उन्नति के नाते किया जावे। हमारे
 निज का हित, एवं विदेशी चरित्र दूर हो गया जावे। विदेशी वस्तुओं का

अध्ययन हमारा उद्देश्य नहीं बन सकता वह तो एक मार्ग-प्रदर्शक बन कर एक साधन का कार्य कर सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि विदेशी सिद्धान्तों में हमें कितनी काट छोट करनी है कि वह सिद्धांत हमारे देश की जलवायु, सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशा एवं राजनैतिक वातावरण में ठीक प्रकार से घटित हो सके अन्यथा एक प्रकार की उलझन सी पड़ी रहती है और लोग सफलता नहीं पा सकते। कई विचारधाराओं में आन पल साम्यवाद एवं समाजवाद इत्यादि के गुण गाय जा रहे हैं। हमें यह जान ही नहीं है कि वास्तव में ये विचार हमारे देश के योग्य हैं या नहीं। हमारे जो विद्यार्थी वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं वह भी उलझन में पड़ जाते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। प्रत्येक बात में हमें 'सांख्यिकी' (Statistics) का सहारा दे देना पड़ेगा।

वाणिज्य के विद्यार्थियों का विज्ञान, वृत्ति एवं राजनीति और मनोविज्ञान का भी साधारण ज्ञान रखना होगा। कानिजा एवं स्कूलों, विषयों के विभागों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में निकट का सम्पर्क स्थापित होना चाहिये। बड़े शाक की बात है कि कहीं नहीं पर तो वाणिज्य के विद्यार्थी विज्ञान के अध्यापकों को भी नहीं जान पाते हैं। आज के संसार में हमें सभी प्रकार की योग्यता का एक निगाह में रखना होगा। हम अपनी लिचढ़ी अलग पक्का ही नहीं सकते। किसी भी कार्य को क्या न करें हमें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि हम एक बड़ा कारखाना खोलें तो हमें इंजीनियर, विज्ञान वेत्ता, विधान वेत्ता, राजनीतिज्ञ एवं सभी अन्य प्रकार के जातारों से भी परामर्श करना होगा। आज का व्यापार किसी एक कोठरी में बन्द किया ही नहीं जा सकता है। आज का एक बड़ा व्यापारी राजनीतिज्ञ एवं विज्ञान वेत्ता भी है।

उपराक्त विचारों से हमारा यह अर्थ कदापि नहीं की सभी वाणिज्य के विद्यार्थी व्यापारी ही बन जाएँ और कोई भी वैतनिक रूप से कार्यालयों में एवं कॉलेजों में काम न करें। वास्तव में अध्यापक एवं कर्क भी तो आवश्यक हैं। सच बात तो यह है कि देश के व्यक्तियों की शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जाये। उनको मनोविज्ञान की सहायता से देखा जाये कि प्रमुख व्यक्ति किस कार्य के

योग्य है और फिर वही कार्य उसे दिया जाने किन्तु उस कार्य को करने की उस व्यक्ति में पूर्ण क्षमता आ जानी चाहिये। उसका शिक्षण ठीक प्रकार से किया जावे। वाणिज्य के जो विद्यार्थी ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण न कर सकें वह कार्यालयों में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। किन्तु आज स्थायी व्यापारिक उन्नति के लिए देश को शिक्षित M. Com और B. Com की आवश्यकता है। यदि सभी कुर्क होते रहेंगे तो देश का ध्यानर मुख्य लोगों के हाथ में रहेगा और वह भी आर्थिक रूप में। साथ में देश की शिक्षा का हास होगा। यह एक वाणिज्य-शास्त्री के साथ शुभ नहीं मालूम होता कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी एक साधारण कार्य के लिए अपना जीवन बिता दे। देश के शिक्षा-शास्त्रियों तथा अन्य नेताओं को इस ओर ध्यान देने का आवश्यकता है। वाणिज्य शिक्षा-मुधार की समस्या बड़ी मूल समस्या है इसे हल करने से देश के आर्थिक जीवन का एक पहलू उन्नत होगा।

५०—अर्थ-वाणिज्य की व्यावहारिक-शिक्षा

“यदि इंजीनियरिंग विभाग के स्नातकों को व्यावसायिक प्रशासन और औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में कोई तैयारी नहीं होती तो इससे विपरीत वाणिज्य के स्नातक प्रयोगात्मक शिक्षण से बिल्कुल कारे हैं।”

—राधाकृष्णन् कमेटी

आज शिक्षा का रंगीन उपवन अनेक विद्या के वृक्षों से सजा हुआ है जो असंख्य विषय की शाखाओं से लदे हुए हैं। प्रत्येक शिक्षक, शिक्षित व शिक्षार्थी को इनसे नई सौरभ व नूतन प्रेरणा मिलती है जिसका समाज और राष्ट्र के लिए असाधारण महत्व है। यदि कला व विज्ञान इस उपवन के वृक्ष हैं तो साहित्य, राजनीति, इतिहास, दर्शनशास्त्र (Philosophy), रसायन शास्त्र (Chemistry), भौतिक शास्त्र (Physics), उद्भित शास्त्र (Biology), आदि सरलता से इनकी शाखाएँ कही जा सकती हैं। विश्व निर्माण व आरम्भ से ही वाणिज्य (Commerce) भी किसी न किसी रूप में ऐसा वृक्ष एक विद्यावृक्ष रहा है जिस पर लेखा ज्ञान (Accountancy), व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Practical Economics), मुद्राशास्त्र, व्यापार पद्धति (Business Methods) व अर्थशास्त्र (Statistics) आदि पैली हुई शाखाएँ आज भी समस्त संसार के औद्योगिक विकास व वैज्ञानिक प्रगति का कारण बनी हुई हैं।

वर्तमान युग में आई हुई विज्ञान के चमत्कारों की मयकर बाढ़ वास्तव में तो वाणिज्य के जटिल पहलुओं को ढीला करने के लिए आवश्यक हुई जिससे मानव-जाति का रहन सहन का स्तर ऊँचा करने में एक औद्योगिक क्रांति सम्भव हो सके और भविष्य में हम इसके लिए सचेत रह सकें। प्रत्येक मनुष्य की यह प्रवृत्ति इच्छा है कि वह पिछले दिन से आज और आज से उल अधिन सुखी व समृद्धिशीली हो और अगले दिन उसको और भी अधिन लाभदायक व्यवसाय और उद्योग दिखाएँ। इसके लिए वाणिज्य मानव-समाज की शताब्दियों से सेवा करता आया है और आज भी इसका महत्व विज्ञान की आँधी में छिपाया

नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो वह शिक्षा को अधूरा रख समाज और देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

हय का विषय है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में कला, विज्ञान व वाणिज्य की शिक्षा दी जाती है जहाँ से हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने भावी जीवन को एक सौंच में ढालने का झटूट प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार कला व विज्ञान के छात्र आने वाले राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, कवि, इंजीनियर, डाक्टर व वैज्ञानिक बनेंगे उसी प्रकार वाणिज्य के छात्र भी भावी उद्योगपति, अर्थशास्त्री, व्यवसायी व निपुण कार्यकर्त्ता बनेंगे। कला व विज्ञान को छोड़िए, वाणिज्य का प्रसाद हो देश को फिर 'सोने की चिड़िया' बना सकता है। इसलिए वाणिज्य शिक्षा का स्तर उच्च तथा साधन अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने चाहिएँ।

इतनी आवश्यकता होते हुए भी भारत में वाणिज्य-विद्या की उन्नति और उसके विकास पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के विद्यार्थी पुस्तकों में सब बातों का ठीक तरह से अध्ययन कर लेने पर भी वास्तविक जीवन क्षेत्र में इन्हीं विषयों में घुरी तरह अक्षम रहते हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक वाणिज्य-शिक्षा जो सचमुच व्यवहार और प्रयोग रूप में होनी चाहिए केवल किताब रूप में ही सीमित रह जाती है। हमें आज वाणिज्य शिक्षा में ऐसी प्रगतिशील, व्यावहारिक व प्रयोगात्मक बातों को जन्म देना है जिससे विद्यार्थी केवल किताबों तक ही सीमित न रह कर प्रयोगात्मक व व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा हो सका तो वर्तमान वाणिज्य विश्वविद्यालय संचालक अथवा ही भावी इतिहासकार के धन्यवाद के पात्र होंगे। वाणिज्य-शिक्षा से यदि राष्ट्र की उन्नति में योग देना है तो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए निम्न सुझावों की अवज्ञा करना हितकर न होगा :—

वाणिज्य-संग्रहालय :—

रसायन शास्त्र (Chemistry) के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाएँ (Laboratories) बनायी जाती हैं। उद्भिन् शास्त्र (Biology) के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बड़े-बड़े संग्रहालय (Museums) बनाये जाते हैं जहाँ जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के

प्राणी देखने को मिलते हैं। वहाँ निर्जीव सर्प, चूहे, मछलियाँ, मक्क, व अन्य प्रकार के उड़ने वाले जीवित पक्षियों का भी होना कोई असाधारण बात नहीं। विद्यार्थी जो बाँटें पुस्तका में पढ़ते हैं उनका स्वरूप भी उन्हें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्भूत शास्त्र का छात्र मदन को कभी मछला नहीं बता सकता। परन्तु राय की कमी का न छिपाते हुए हमें लिखना पड़ता है कि हमारे वाणिज्य के किसी भी छात्र के लिए Rotary Duplicator Machine को Rotary Copies बताना कोई बड़ी बात नहीं। वाणिज्य के अनेक विद्यार्थी चाहे बी पी पी के बार में जानते हों परन्तु डाक खाने जाकर बी पी पी. नहीं करा सकते। मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजने में उन्हें पोस्ट मास्टर की सहायता लेनी पड़ती है। डाकखाने में बचत लेखा (Savings Bank Account) खोलना, उसमें से रुपया निकालना व लेखा बन्द करना तो अधिकांश विद्यार्थियों से आता ही नहीं। कक्षालयों में कैश बुक (Cash Book) पर काम करते हैं परन्तु बैंक की Cash Book देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इस अभाव का दोष छात्र पर नहीं थोपा जा सकता। इस दोष और कमी के लिए तो हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ही उत्तरदायी हैं, जहाँ पुस्तक पढ़ाने का प्रबन्ध तो किया जाता है परन्तु प्रयोगात्मक शिक्षा देने की ओर विलुप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इस उत्तरदायित्व का भार चुकाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को वाणिज्य विद्या से सम्बन्धित संग्रहालयों का शीघ्रातिशय प्रबन्ध करना चाहिए। संग्रहालय में ऐसे साधन उपलब्ध हों जिससे विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप में यह देख सकें कि पुस्तक में अध्ययन किये गये कागज पुर्जों (Documents and Instruments) का वास्तविक रूप कैसा होता है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बैंक के नाम चैक काटना, बिल लिखना, ग्राहक को जमा-नोट व नाम नोट भेजना, भिन्न भिन्न प्रकार की फाइलों (Files) का रूख और उनका प्रयोग आदि बातें आकर्षक विधि में बताई जा सकती हैं। यदि इस कार्य को करने के लिए वाणिज्य-विभागा के अध्यक्ष और महाविद्यालयों के आचार्य आज ही त्रत ले लें तो वाणिज्य के विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर से व्यापारिक ज्ञान का अभाव का काला टीका जल्दी ही मिट सकता है और तब वे व्यापार पद्धति में बढ़े बढ़े

उपयोगी अन्वेषण कर राष्ट्र की भलाई भी कर सँगे ।

बैंक की प्रयोगात्मक-शिक्षा :—

चारों ओर फैली हुई बेकारी के बाजार में विद्यार्थी से सीधा बैंक व्यवस्था-पक बनना कौन नहीं चाहता ? यदि ऐसा सफलता की कुंजी थोड़े प्रयत्न व परिश्रम से मिल जाय तो आज विज्ञान के युग में वाणिज्य का महान् सचमुच चौगुना हो सकता है । इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमें कालिजों में ही योग्य शिक्षकों के संरक्षण में छोटे छूटे बैंक आरम्भ कर देने चाहिएँ जिनमें वहाँ के विद्यार्थी ही अपने खाली समय में वर्क, अर्क व व्यवस्थापक बनकर काम करें । इस प्रयत्न की सफलता के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि सब अधिकारी वर्ग, शिक्षक और विद्यार्थी अपना अपना रुपा उम्मी बैंक में जमा करावें । कालिज भी इस बैंक में कुछ जमा करे तथा कालिज के वार्षिक बजट की राशि के मुद्दित रखने का अधिकार भी इसी बैंक को प्राप्त हो । यदि पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया जाय तो यह बैंक कालिज के गन्दरा में चलाई जाने वाली अन्य सहकारी-संस्थाओं की श्रृंग देकर व बैंक प्रणाली के अनुसार अन्य साधनों का विदोहन कर, रुपया जमा करने वालों की पर्याप्त व्याज भी देकर बचे हुए लाभ को विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में बाँट कर उनकी सहायता कर सँगी है । इस योजना के अनुसार यदि बैंक प्रणाली को प्रोत्साहन देकर स्वयं से हित व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अध्ययन काल में ही एक विद्यार्थी बैंक-व्यवस्थापक हो सके तो अधिकारी वर्ग के लिए सचमुच यह एक गर्व की बात होगी । हमसे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना आवेगी और यह व्यवस्था करने की क्रियाओं में दक्ष होने लगेगा जिसकी आवश्यकता इंग्लैंड में उच्च औद्योगिक शिक्षा के लिए स्थापित 'पर्सो कमिटी' (Percy Committee) की राय से स्पष्ट है :—

“अपने अनेक गवाहों की इस राय से हम प्रभावित हुए हैं कि उच्च कोटि का शिक्षित प्रायः औद्योगिक संगठन व व्यवस्था के मिश्रणों से अनभिज्ञ होता है और उसका प्रसासन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने की श्रम भुगत नहीं होता है । हममें संदेह नहीं कि इस क्षेत्र में अनुभव से बहुत सरनने से होता है परन्तु थोड़ा-सा ज्ञान इस प्रकार का भी है जिससे इस प्रकार की शिक्षा मिल

सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय में औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।”

कालिजा में प्रस्तावित बैंक व अन्य सहकारी संस्थाओं का खोजना हम उद्देश्य की ओर पहला कदम होगा। कुछ महाविद्यालयों में ये योजनाएँ सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। परन्तु प्रत्येक वाणिज्य विद्यालय में ऐसी योजना अनिवार्य होना आवश्यक है।

अध्यव्यवसायी देशाटन —

देशाटन का महत्व तो सभी मानते हैं। परन्तु वाणिज्य शिक्षा में अध्ययन की सत्यता खोजने के लिए वाणिज्य यात्रा (Commercial Tours) करना ज्ञान को प्रगति देता है। देश के उद्योगों व उद्योगशालाओं, व्यवसायों व व्यवसायियों तथा अन्य आधारण व्यक्तियों व विचार, बेशभूषा व कार्य प्रणाली के सर्क में आने व कुछ सीखने का अच्छा अवसर वाद्य स्थानों के भ्रमण से ही सम्भव है। देश की यस्त्र, जूट, चीनी व अन्य उद्योगशालाओं की सर्वांगरूपेण देखकर विषय से सम्बन्धित विद्यार्थी अत्यन्त कुछ नयी नयी योजनाएँ बनाकर अपने अमूल्य मुभाव सर्वसाधारण तक पहुँचा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार की व्यापार पद्धति की प्रयोगशालाओं का निष्पक्ष अध्ययन कर एक अध्यव्यवसायी छात्र अपने नये दृष्टिकोण को जनता के विचाराधीन रख सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को दल व टोलियों में आर्थिक सहायता देकर भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष भेजना चाहिए। इससे उनका दृष्टिकोण भी विलुप्त होगा। विदेशों के शिक्षा-अधिकारी इस ओर अत्यन्त उत्साह दिखा रहे हैं। विश्वास है हमारे आचार्य भी इस पहलू को परिपक्व बना कर ही चैन लेंगे।

अवकाश में विकास —

विद्या को व्यावहारिक व बहुमुखी बनाने के लिए शिक्षक को ताक में रख केवल विद्यार्थी का ही विकास करना एक हाथ से ताली बजाना होगा। विद्यार्थी में हर प्रकार की नई सूझ, नवीन स्फूर्ति व नया जोश भरने का भरसक प्रयत्न करने पर भी वह अधूरा ही रहेगा यदि उसके शिक्षक में ये सब गुण विद्यमान न हों। यदि निर्देशक हा नाटक की भारीकियों से अपरिचित है तो नाटक सजाने

बानों का ज्ञान अपूरा रहना बड़ा स्वाभाविक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रोफेसर महोदय भी, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक नई उपयोगी विचारधारा, पुस्तक व प्रणाली से भली भाँति परिचित रहें। उन्हें बालिज में पढ़ाने के लिए कामचलाऊ परिभ्रम से ही मंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। ऐसे प्रतिदिन के परिभ्रम से अवकाश पाकर उन्हें टोस व नवीनतम बातें जानने के लिए अपने कालिज से बाहर देश के किन्हीं बड़े पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं में अध्ययन कर अपनी बुद्धि का विकास करना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार चाकू या तलवार की धार को हमें समय-समय पर तेज करना पड़ता है वही उसी प्रकार हमारे प्रोफेसरों के अध्ययन को पूर्ण व तेज रखना पड़ेगा। इसलिए कालिज के अधिकारियों को आवश्यक होगा कि वे प्रत्येक शिक्षक को निश्चित समय के परवान एक वर्ष का अवकाश देकर अध्ययन के लिए भेजें। हमारा लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना हो जिनमें विश्लेषण और गम्भीर चिन्तन के गुणों का विकास हो सके व जो वस्तुस्थिति का अध्ययन कर प्रभाव पूर्ण निर्णय कर सकें। इसके लिए हमारे शिक्षक यदि कक्षा में दिए जाने वाले भाषण की श्रवण अपनी ताजी जानकारी द्वारा किसी उद्योग व व्यापार सम्बन्धी तात्कालिक विषय पर विचार विमर्श करें तो अधिक उपादेय होगा।

इसी प्रकार की नई प्रणाली को जन्म देकर हम नए ढंग में विद्या, विद्यार्थी व शिक्षक तीनों की प्रगति व विकास में सच्चे सहायक बन सकेंगे। तभी हमारी अर्थ-वाणिज्य शिक्षा पूर्ण बन सकेगी अन्यथा हमारी नवीन औद्योगिक सभ्यता एकांगी रह जायगी; सामाजिक जीवन में एक विषमता उत्पन्न हो जायगी क्योंकि जिनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है उन्हीं को जीवन की आर्थिक समस्याओं पर विचार कर मानवीय समस्या भी मुलभूतनी है। आशा है विश्वविद्यालयों के कुलपति कोलेजों के आचार्य तथा अर्थ-वाणिज्य के शिक्षक इस समस्या के प्रति सचेत रहकर मुलभूतने के प्रयत्न करेंगे।